संपादक राज कपिला उमा कपिला

The state of the s

ात्साहित्य प्रकाशन, दिल्ली

प्रकाशक : सत्माहित्य प्रकाशन, 205 बी चात्रदी वात्राग, दिल्ली । 10006 सर्वाधिकार : सुरक्षित / संस्करण : प्रथम, 2002 / मृन्य · दा मी अपूर्म मुद्रक : नरुला प्रिटर्स, दिल्ली अनुवाद : अलका कीशिक

BHARATIYA ARTHNEETI Ed Raj Kapila & Urria Kapila (Hindi Edition of "India's Economy in 21st Century" published by Acedemic Foundation, Delha) Rs 200 00 ISBN 81-7721-037-8

Published by Satsahitya Prakashan, 205-B Chawn Bazar, Delhi-110006

भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में कार्यरत समस्त कर्तव्यपरायण लोगों को सादर समर्पित

अनुक्रम

7	· ·
आर्थिक संकेतक	18
संस्थागत संकेतक	22
ढाँचागत संकेतक	23
सामाजिक सकेतक	25
प्रगति की राह	26

आजादी के बाद: 1950-1990 खाडी संकट और सुधार : 1990-2000

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में भारत की स्थिति

हम किस दिशा में अग्रसर हैं ?

मौजूदा आर्थिक चुनौतियाँ

2. भारत में उभरती आर्थिक चुनौतियाँ

ा. कुछ सकारात्मक विशेषताएँ

2 वित्तीय अनुशासन 3. पहली पीढी के सुधार 4. दूसरी पीढ़ी के सुधार

3. आर्थिक सुधार . भविष्य के लिए नीतिगत एजेंडा

4 उच्च आर्थिक विकास के लक्ष्य : राजकोषीय अवरोधक

भविष्य की तसवीर

आजादी से पूर्व

1. भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-2000-2020

—वाई.वी. रेड्डी

11

11

12

16

18

27

29

45

45

57

71

75

—विजय केलकर

राकेश मोहन

-मोंटेक एस. अहलूवालिया

प्रादेशिक सरकारों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति उच्च विकास-दर हासिल करने के लिए सबिधत प्रमुख मृद्दे	i,
5. भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान दशा — के.सी. पंत ज्ञान की सुपर शक्ति के रूप में भारत की भूमिक।	104
6. आर्थिक विकास का वित्त-पोपण — सी. रगराजन नई आर्थिक नीति के पहलृ उदारीकरण के बाद की स्थिति वित्त-पोपण कारगर नियमन पूँजी बाजार के म्रोत नए वित्तीय उत्पाद बाहरी सहायता	109
7. बीसवीं सदी के अंत में भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक बदलाव और भविष्य की सभावनाएँ — उमा कियला सेवा-क्षेत्र में अत्यिभक विस्तार उद्योग जगन में सरचनात्मक बदलाय	115
8. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति और बैंकिंग क्षेत्र के सुधार —एस.एस. तारापुर मौद्रिक प्रबंधन के दीर्घकालीन मुद्दे बैंकिंग क्षेत्र में सुधार	121 123 124
9. वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का एजेंडा —एन.ए. मजूमदार बैंकिंग क्षेत्र विकास वैंक पूँजी बाजार ग्रामीण ऋण-प्रणाली निष्कर्ष	128 128 130 131 132
10. कृषि-नियोजन : इक्कीसवीं शताब्दी की चुनौतियाँ तथा अवसर —के.सी. पंत	133

केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति (1980-2000)

	खाद्यान आत्मनिर्भरता	133
	असंतुलित क्षेत्रीय विकास	135
	कृषि विविधीकरण	136
	कृषि में घटता निवेश	137
	भूमडलीकरण	137
11	भारतीय उद्योग जगत् : संरचनात्मक बदलाव, पुनर्गठन, प्रदर्शन	
	तथा हाल की नीतिगत पहल —भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट	135
	उद्योग जगत् मे सरचनात्मक बदलाव	139
	कुछ उत्पादन में क्षेत्रवार सापेक्ष योगदान	141
	हाल मे हुआ सगठनात्मक पुनर्गठन : विलयन तथा अधिग्रहण	
	(एम ए.)	143
	भारत में विलयन ओर अधिग्रहण गतिविधियों मे प्रगति	145
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमां का पुनर्गठन	147
	नवरत्न	149
	लघु रत्न	150
	हाल की नीतिगत शुरुआत	152
	आद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन (1998-99 के दौरान)	157
	हाल का प्रदर्शन (अप्रैल-सितंबर 1999-2000)	158
	चृनिदा उद्योगो का प्रदर्शन	160
	अन्य महत्त्वपूर्ण उद्योग	164
	अनुसंधान तथा विकास	164
	लघु उद्योग क्षेत्र	165
	ओद्योगिक रुग्णता	165
	केंद्रीय क्षेत्र में परियोजनाओं का प्रदर्शन	166
	भार्वजानक क्षेत्र के उपक्रमो (पी एस.ई) का प्रदर्शन	167
	रोजगार	168
12.	नब्बे के दशक में बाह्य आर्थिक चुनौतियों का प्रबंधन :	
	भविष्य के लिए सबक — शंकर आचार्य	184
	1993 का भुगतान संनुलन का सकट	181
	जबरदस्त पूँजी-आवकं का प्रबधन	186

व्यापार उदारीकरण	14
बाह्य ऋण-प्रबंधन	15'
बाहरी खतरों से बचाव	19(
विनिमय-दर प्रबंधन . कुछ विकल्प और मृद्दे	19.
अगले दशक की चुनौतियाँ	103
13. विदेशी मुद्रा-बाजार का विकास तथा प्रबंधन —िबमल जालान	207
14. भारतीय अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण — उमा कपिला	212
क्या है भूमंडलीकरण?	217
भूमडलीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था	215
क्या पूर्वी एशियाई संकट का कारण भूमंडलीकरण था?	215
आर्थिक सुधारों की अध्री कार्यसूची (एजेडे) को पूरा करना	216
कृषि को भी उद्योग के समान दर्जा	217
अनुमधान तथा विकास के लिए वैज्ञानिक आधार मुदृढ़ करना	2" "
शासन में परदर्शिता	218
विश्व व्यापार संगठन में भारत की कारगर भूमिका	218
व्यापार तथा शुल्क संबंधी सामान्य समझौते (गैट) का उरुग्वे दौर	•
और बाद की प्रगति	719

भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-2000-2020

—वाई.वी. रेड्डी

स्वतत्रता-प्राप्ति के बाद, यन् 1950 में योजना शुरू होने से लेकर सन् 1990 में खाड़ी संकट आरभ होने तक की अवधि में, आजादी से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना में व्यापक सुधार हुए। अलबता, प्रोत्साहनों और संस्थागत संरचनाओ

में कुछ अभाव भी रहे, जिनसे बचा जा सकना था। इसी प्रकार बीच-बीच में सूखें की स्थिति, युद्ध और तेल सकट से भी जूझना पड़ा। हमारी अर्थव्यवस्था नब्बें के दशक में छाए गहरे सकट से तेजी से उबरी और विकास के स्तर तथा आधात झेलने

की इसकी क्षमता में नाटकीय रूप से प्रगति हुई; लेकिन आजादी के पचास साल बाद भी गरीबी से निपटने की चुनौती आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

नई सदी में प्रवेश करते हुए हमें ईमानदारी से यह आकलन करना होगा कि विकास, स्थिरता और गरीबी सरीखे सकेतकों के आईनों में हम दूसरे देशों की तुलना में कहाँ हैं ? इसके लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था के इतिहास को मौजूदा

आजादी से पूर्व

अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए सन् 1900-47 की अविध का अध्ययन करना जरूरी है। बीसवीं शताब्दी में आजादी से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने के लिए शिवसुब्रह्मण्यन (1998) द्वारा उद्घाटित तथ्यो पर

विचार करने की आवश्यकता है।

सदर्भों के साथ रखकर देखना होगा।

सबसे पहले मकल घरेलू उत्पाद (जी डां.पी.) को देखें, जो वास्तव में देश की भौगोलिक मीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं तथा मेवाओं का

कुल जोट हैं। उस दौर में जी डी पी में मात्र 0.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई, लेकिन प्रति व्यक्ति और भी कम रफ्तार, मात्र 0.1 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हो सको। सन् 1900-01 म जी डा पा पति व्यक्ति 224 रूएए रहा , दश के -स्वतंत्र होने से कुछ ही समय पहले यह आँकडा मानृत्ती रूप में बढ़कर 233

रुपए तक पहुँचा।

विकास की इस मामुली रफ्तार में भी लंबे वर्षा में अवाल, लुखे और महामारी के चलते कई रुकावटे आई। कुल मिलाकर 47 वर्षों में से 17 वर्ष आसन जी डी.पी. मे और 26 वर्ष प्रति व्यक्ति जी डी पी में गिगदट दर्ज की गई।

सन् 1920 के बाद महामारी पर कुछ हद तक काब्र पा लिया गया आर स्वास्थ्य सेवाओ में सुधार भी हुआ। सन् 1911 में शिए मृत्यु -दर प्रति 1,२०० पर

205 थी, जबकि सन् 1946 में यह घटकर 136 रह गई। शताब्दों के शुरू में प्रत्यंक भारतीय के औसतन 23.8 वर्षों तक जीवित रहने की संभावना थी और सन 1951

तक आते-आते यह आँकडा बढकर 32.1 वर्षों तक पर्ह्च गया।

शताब्दी के दूसरे दशक में प्रत्येक भारतीय के निए प्रनिदिन आंसनन 535 ग्राम भोजन ही उपलब्ध था। यह उपलब्धना सन् 1950 में घटकर 408 ग्राम

प्रतिदिन रह गई। सन् 1901 में प्रति 100 भारतीयों में से 94 व्यक्ति पढ-लिख नहीं सकत

थे। सन् 1941 में यह सख्या घटकर 85 रह गई।

निस्संदेह निर्माण-क्षेत्र ने 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विकास किया। भारतीय रेलवे की मालवाहन और यात्रियों को लाने-ले जाने की क्षमता छह गुना बढ़ गई। संचार तथा सरकारी सेवाओं में भी सामान्य रूप से वृद्धि जारी थी। चैँकि अर्थव्यवस्था मुलतः कृषि-प्रधान थी। इसलिए इन क्षेत्रों में प्रगति का कोई विशय

आजादी के बाद : 1950-1990

प्रभाव देश की स्थिति पर नहीं पडा।

अर्थव्यवस्था को आजादी पूर्व की मंदी की स्थिति से उचारने के िए आजादी के बाद देश में नियोजित आर्थिक विकास की महत्त्वाकाशी योजना शुरू

की गई। उस समय देश दूसरे महायुद्ध और बॅटवारे की जामदी झेलने के माथ-भाथ प्रशासनिक तथा राजनीतिक तंत्र को मजबृत करने की चुनातियों से भी जुझ रहा था।

इन जटिल चुनौतियों के अलावा देश को साठ और सत्तर के दशक में सुखें एवं यूद्ध तथा सत्तर एव अस्सी के दशक के शुरुआती वर्षों में तेल संकट का भी मामना

करना पड़ा। अर्थव्यवस्था का आकलन करते समय इन तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है।

आजादा पृव के युग मे वार्षिक जी डा पा दर 0 9 प्रतिशत स बढकर 4 प्रतिशत तक हो गई. लेकिन विकास-दर में महत्त्वपूर्ण वृद्धि अस्सी के दशक मे हा दर्ज की गई। दरअसल, अस्सी के दशक मे औसत वार्षिक विकास-दर 5 9

प्रतिशत थी, जो उस समय की विश्व की विकास-दर 3 3 प्रतिशत. विकासशीन देशों की 4 3 प्रतिशत और चीन तथा भाग्त को छोड़कर शेष एशियार्ड देशों की 5 1

प्रतिशत की दर से बेहतर रही। दृसरे, आजादी पूर्व अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की नुलना में उतार- चढाव कुछ कम थे और संकट के चार वर्षों के बावजूद सभी वर्षों के दौरान जी डी पी की

विकास-दर में निरतरता बनी रही।

विकास-दर में निरंतरता बना रहा। हालॉकि स्वतंत्रता पूर्व की नुलना में विकास-दर में उल्लेखनीय सुधार

हुआ; लेकिन जनसंख्या में प्रतिवर्ष ओमतन 2 प्रतिशत की वृद्धि होते रहने में प्रति व्यक्ति जी.डी पी. में हर वर्ष 2 प्रतिशन की ही बढ़ोतरी हो सकी। अलबता, स्वतंत्रता-पूर्व के मुकाबले यह विकास बीस गुना था। दरअसल, अस्सी के दशक

में प्रति व्यक्ति जी डी.पी. 3.5 प्रतिशत से अधिक रही।

जहाँ एक ओर स्वतंत्रता-प्राप्ति से पहले भोजन-उपलब्धता में गिरावट दर्ज की गई, वही आजादों के बाद जनसंख्या-वृद्धि के बावजूद भोजन उपलब्धता मन्

1951 में 395 ग्राम प्रतिदिन के ऑकड़े को पार कर 510 ग्राम प्रतिदिन हो गई थी। कृषि के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ और इसकी दर 2 5 प्रतिशत रही,

जबिक हरित-क्रांति के बाद यह बढ़कर 3 प्रतिशत हो गई। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह रही कि यह क्षेत्र काफी हद तक मानसून की मनमानी से मुक्त हो चला था।

यह रहा कि यह क्षेत्र काफा हद तक मानमून का मनमाना स मुक्त हा चला था। उद्योग जगत् में हर वर्ष आमतन 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बड़े स्तर के और भागे उद्योगों की स्थापना से ओद्योगिक विकास में तेजी आई, जिससे

टिकाऊ औद्योगिक विकास की आधार्राशला मजबून हुई। इसी प्रकार सेवा- क्षेत्र भी 5 प्रतिशत की दर से व्यापक हुआ और सत्तर के दशक के उत्तराई से ही इसकी विकास-दर लगभग 6 प्रतिशत रही। जी डी पी की क्षेत्रवार सरचना में धीर- धीरे बदलाव आता रहा। पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि- क्षेत्र का जी डी पी

में योगदान आध में अधिक रहा था, लेकिन अम्मी के दशक के अंत तक आते आते यह लगभग एक-तिहाई ग्ह गया। दूसरी तरफ पेवा-क्षेत्र का योगदान एक तिहाई से बढ़कर दी-तिहाई में अधिक ही गया। इसी प्रकार उद्योग जगत् का

योगदान भी लगभग 15 प्रतिशत में ब्रहकर एक-चोथाई तक जा पहुँचा। आजादी के बाद की अर्लांग में बचन (जी टी गी के अनुपात) में भी भारी वृद्धि दर्ज की गई। पहले डेढ दशक मंा 19 प्रतिश्रत के मुक्ताजल अस्या के दशक में बचत-दर 20 प्रतिशत से कुछ अधिक रही। इसी अविधि में वचत दर भी 13 /

से बढ़कर 22 5 प्रतिशत हो गई।

मुद्रास्फीति के रिकॉर्ड के आईने में देखे तो आजादी के बाद पहल दशक में मूल्यवृद्धि कम, यानी 1 2 प्रतिशत रही। बाद में माठ के दशक में यह बद्कर 6 3 प्रतिशत और सत्तर के दशक में 9 प्रतिशत हो गई। अम्सी के दशक में यह अकिटा लगभग 8 प्रतिशत रहा।

हालाँकि स्वतत्रता पूर्व की स्थित की तुलना में विकास के उपयुंक्त सकत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में गिने जाते हैं, लेकिन इसके वावज़द देश उन लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहा हैं, जो उसने अपने विकास के लिए म्निश्चत किए थे। कम-से-कम पाँच क्षेत्रों में इस तथ्य को आमानी स रखाकित किया जा सकता है—

पहला—आय के मोरचे पर औसत वास्तिवक प्रति व्यक्ति भाग्न को मनर के दशक के अंत तक दोगुना करने का लक्ष्य अम्मी के दशक के अंत में हासिन किया जा सका था।

दूसरा—आर्थिक विकास के बावजृद गरीबी की समस्या 2,400 ग्रामीण क्षेत्रों तथा 2,100 शहरी क्षेत्रों मे काफी हद तक सिर उठाए हुए है। केलोरी फी प्रतिदिन की न्यूनतम आवश्यकता को जुटाने के लिए जरूरी खर्च ऋहन करन मे असमर्थ व्यक्ति को 'गरीब' के रूप मे परिभाषित किया जाता है।

तीसरा—सन् 1990 तक भी देश की आधी आबादी को हम माक्षर नहीं बना पाए थे। सन् 1989-90 मे प्रति 46 छात्रो पर केवल एक प्राथमिक विद्यालय अध्यापक उपलब्ध था।

एक और तथ्य, जो महत्त्वपूर्ण हे, यह है कि स्वतंत्रता पृत्रं शिशु मृत्यु दर प्रित 1,000 पर 136 थी, जो सन् 1990 में घटकर प्रित 1,000 पर 80 रह गई। मन 1990 में जीवन-संभाव्यता औसतन 60 वर्ष थी। 1989-90 में देश की एम चौथाई आबादी की पहुँच शुद्ध पेयजल तक नहीं थी और 87 प्रतिशत लोगों को स्वच्छता की सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा था। अस्सी के दशक के बाद के वर्षी में प्रित 2,520 भारतीयों पर केवल 1 चिकित्सक और औसतन 1,700 भारतीयों पर महज 1 नर्स उपलब्ध थी।

उधर बाहरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की हमारी भरपूर कोशिशों के बावज़ृद भुगतान संतुलन को लेकर कई बाग दबावों का सामना करना पड़ा है। पहले दो दशको तथा जम्मी के दशक के पहल 5 वर्षों के दौरान अमेरिका को होनेवाल निर्यात म बढ़ातरी 5 प्रतिशत से नाचे रहा, जबकि आयात म तंजा से वृद्धि हुई

सातवे दशक मे तथा आठवे दशक के बाद के वर्षों में ही निर्यात के क्षेत्र में देश अपने पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोडने में कामयाब हो सका; लेकिन सातवें दशक मे

ही आयात ने निर्यात को पीछे धकेला था। अंतरराष्ट्रीय पिदृश्य में उस दौर में देश हाशिये पर चला गया। दरअसल, पचास के दशक के शुरू में भारत का निर्यात

विश्व निर्यात का 2 प्रतिशत रहा था, जबिक आठवें दशक के अंत में यह महज 0 5

प्रतिशत रह गया।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि पिछली अवधि के मुकाबले अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कुल मिलाकर उल्लेखनीय अवश्य था, फिर भी चुनौतियों से निषटने मे

यह पूर्ग तरह सक्षम नहीं थी और अस्सी के दशक के आखिरी वर्षों में तो यह

विकास के अनुकृल भी नहीं रह गई थी। विकास-संकेतक बताते हैं कि आजादी से लेकर सन् 1990 तक की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था ने आठवें दशक के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया

लेकिन तब भी उसके सामने संरचनात्मक असंतुलन को लेकर चुनौतियाँ थीं। ये चुनौतियाँ सरचनात्मक गैर लचीलेपन, देश-विदेश में प्रतियोगिताओं का अभाव, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के घटिया प्रदर्शन, वित्तीय समझ की कमी तथा उत्पादकता मयंथी लाभों के अनुपात में प्रोत्साहित करनेवाली ढाँचागत सुविधा के

उपलब्ध नहीं होने के कारण पेश आई। इस अवधि में सरकारी खर्च में बढ़ोतरी ने विकास को आगे बढ़ाने मे

महत्त्वपूर्ण योगदान दिया ओर इसी के समानातर वित्तीय घाटा सातवे दशक में जा डी.पी के 4 प्रतिशत के आँकड़े को तेजी से पार करता हुआ संकटकालीन सन् 1991 में 8.33 प्रतिशत तक पहुँच गया। समस्या केवल वित्तीय घाटे को लेकर नहीं थी बल्कि राजस्व घाटे की भी थी. क्योंकि ऋण लेकर जिन सार्वजनिक उपक्रमो

थी, बल्कि राजस्व घाटे की भी थी, क्योंकि ऋण लेकर जिन सार्वजनिक उपक्रमों को स्थापित किया गया था, उन्होंने पर्याप्त लाभ देना शुरू नहीं किया था। अधिक

वित्तीय घाटे का असर अस्सी के दशक में चालू खाता घाटे के रूप में मामने आया, जा मन् 1991 में सर्वाधिक, जी.डी.पी. का 3.2 प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया। बाहरी

ऋण से भी व्यावसायिक आधार पर निपटने के उपाय किए गए। आठवे दशक में विकास की अधिक दर को कुछ हद तक, आंतरिक तथा बाहरी ऋण में वृद्धि से लाभ पहुँचा; परंतु खाड़ी संकट से सन् 1991 में उपने नबरदस्त भुगतान संतुलन के कारण अर्थव्यवस्था में व्यापक सधार-कार्यक्रम अपरिहार्य बन गए।

खाडी संकट और सुधार : 1990-2000

सन् 1991 के भुगतान संतुलन के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र म व्याप्त सरचनात्मक गैर लचीलेपन को समाप्त करने के लिए अनेक उपाप रिस्प

व्याप्त सरचनात्मक गर लचीलपन को समाप्त करने के लिए अनक उपाय गण गए। उदाहरण के तौर पर, बाजारों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के उद्देशक स आंद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया। वित्तीय क्षेत्र में त्यापक सभार

किए गए और विनियमन तथा निरीक्षण की अधिक कारगर प्रणार्ली गृन की पर बाहरी क्षेत्र में सावधानीपूर्वक उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। विशाय पन देन का असर वित्तीय क्षेत्र पर जिस प्रकार पडता है, उसमें भी फेरचदल किया गर्थ

देन का असर विताय क्षत्र पर जिस प्रकार पड़ता है, उसम भा फरवदत्व । क्या गर्य है, ताकि घाटे के मौद्रीकरण को नियंत्रण में रखा जा सके, जिसमें केदोय बेक । " मौदिक नीति लागू करने में सुविधा गहे। इन उपायों का प्रमुख लक्ष्य धंगल आग

अतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतियोगिता को बढावा देना था। हालाँकि वृहद् आंधर परिनरण

में इनसे कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य देखें गए हैं, लेकिन माथ ही कई लाह की चिताएँ भी व्यक्त की गई हैं।

सबसे पहले तो यह कि नौवे दशक में जी डी.पी की वार्षिक विकास है। लगभग 6 1 प्रतिशत रही। सुधार के बाद की अवधि में अर्थान् सकर आर समायाज

के वर्षों को छोड़कर (1991-92 तथा 1992-93) जर्बाक विकास की देरे कम रही, विकास-दर आठवें दशक के ऑकड़े 5.9 प्रतिशत के मुकायले हम प्रांतशत

दर्ज की गई। दूसरे, जी डी.पी विकास में उतार-चढाव न्यूनतम रहा और खाड़ी मकट

दूषर, जा डा.पा विकास में उतार-चढाव न्यूनतम रहा और खाड़ा मकट के वर्ष अर्थात् सन् 1991-92 के अलावा शेष सभी वर्षों के दोरान जी.डी पी का विकास-दर 5 प्रतिशत से अधिक रही। यहाँ उल्लेखनीय है कि घरेन्न मीरचे पर

अभूतपूर्व राजनीतिक अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रांतन्थ्य स्थाप विवाद, एशियाई संकट, तेल के दामों में वृद्धि आदि सकटों के बावज़द विकास के यह गति न्यूनाधिक रूप में बनी रही। इसी प्रकार, कृषि उत्पादन में उनार जिल्ला की

सामान्य रहा। उधर नौवे दशक के दौरान प्रति व्यक्ति जी डी पी 4 25 प्रतिप्रान का औसत वार्षिक-दर से बढी।

यह तथ्य भी गौर करने लायक है कि सुधारोपरांत सभी वर्धों में सकल प्रम्यू बचत का ऑकड़ा जी डी पी के हिसाब से 22 प्रतिशत को पार कर गया. स्थान

पिछले 40 वर्षों में केवल दो अवसरों पर ही ऐसा हुआ था। वास्तव में, तांक अवसर ऐसे भी आए, जब यह आँकड़ा 25 प्रतिशत के काफी नजदीक पहुँच गया

या इसे पार कर गया। इसी प्रकार, जी डी.पी. की प्रतिशत के हिसाब में देख भी

सकल घरेलू निवेश भी कई बार 26 में 27 प्रतिशत तक हो गया, जबिक पिछले 40 वर्षों के दोंगन केवल दो अवसरों पर यह 24 प्रतिशत को पार कर सका था। दसरी और, सन 1990-98 की अवधि में मुद्रास्फीति की औसत वार्षिक

दर 8.9 प्रतिशत नक बढी, जो आठवे दशक की 8 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर

में अधिक थी। अलबना, सन् 1998-99 तथा मन् 1999-2000 के दौरान मूल्य

वृद्धि की दर काफी हद तक धीमी रही। बाहरी क्षेत्र में बाहरी ऋण और जी डी पी अनुपात सन् 1991-92 के 41

प्रांतशत के मुकाबले घटकर सन् 1998-99 में 23 5 प्रांतशत हो गया। सन् 1990 99 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात की वार्षिक औसत विकास-दर 11 3

99 के दारान वन्तुआ आर सवाआ के 1नयात का वापिक आसत विकास-दर 11 3 प्रतिशत थी, जो अस्सी के दशक की 8.1 प्रतिशत की दर से कही अधिक है। खाड़ी सकट के बाद के सभी वर्षों में चाल लेखा खाता (सी ए डी.) का ओसत जी डी पी

के 2 प्रतिशत से कम रहा। सन् 1998-99 में तो यह जी.डी पी. का मात्र। प्रतिशत दर्ज किया गया। यहाँ यह बात गौर करने लायक है कि इसी अवधि मे सोना समेत

अन्य क्षेत्रों में भी आयात में उदारीकरण की प्रक्रिया लागृ की गई और आयात-निर्यात शुल्क में भी भारी कमी की गई। इस प्रकार नौवें दशक मे देश ने 30 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक

विदेशी मुद्रा का भंडारण किया और वाहरी ऋण में कमी आई। व्यापार मे उदारीकरण का दौर जारी रहा और जी डी पी. मे अधिक विकास-दर्र भी कायम रही।

हमने भले ही अर्थव्यवस्था में काफी सुधार महसृस किए हैं, लेकिन आर्थिक विकास के महत्त्वपूर्ण पक्ष, यानी सामाजिक पहलू पर भी गौर करना जरूरी है।

राष्ट्रीय सामाजिक सेवा (एन एस एम) के सर्वेक्षण के अनुसार सुधारों की

इस पृष्ठभूमि में, यानी मन् 1997 में एक-तिहाई आबादी अपने लिए प्रतिदिन की आवश्यकतानुसार न्यूनतम कैलीरी जुटाने में असमर्थ थी। दसरे सन् 1990-96 में प्रति 100 भारतीयों में से 19 को शद्ध प्रेयजल

दूसरे, सन् 1990-96 में प्रति 100 भारतीयों में से 19 को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं था और 84 की पहुँच स्वच्छता सुविधाओं तक भी नहीं थी।

इमी प्रकार मन् 1990 की तुलना में इस दशक के आखिरी वर्णे में प्रति 1.000 पर 70 की शिशु मृत्यु-दर, 63 वर्ष की जीवन संभाव्यता और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2,496 कैलोरी की आपृर्ति का आँकड़ा देखते हुए कोई विशेष सुधार नहीं

माना जाएगा।

दूसरी तरफ इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि अधिक विकास-दर कुछ
भेजो कर ही सीमित हैं। जबकि अस्य शेंगों में क्लिएम का स्था हता हो काराम है।

भारतीय अर्थनीति *

क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, जबिक अन्य क्षेत्रों में विकास का न्यून स्तर ही कायम है।

सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य तो यह हे कि सपूण सावजनिक क्षेत्र अथात् सरकार एव सार्वजनिक उपक्रमों की बचत लगभग शून्य है। सरकार द्वारा लिये गए ऋण की

मात्रा तथा जिस दर पर यह ऋण लिया गया है, दोनो ही अधिक हैं। उधर विनाय

स्थिति, विशेषकर कुछ राज्यो की, चिंता का विषय बनी हुई ह। संक्षेप में हम कह सकते है कि नौवे दशक के दौरान विकास नथा न्धिग्ता की दृष्टि से महस्वपूर्ण सुधार हुए और बाहरी क्षेत्र में भी देश की स्थिति सुधर्ग

परतु गरीबी और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई चिंताएँ बनी हुई है। यह खात

दीगर है कि एक दशक पहले तक 5 प्रतिशत की जो विकास-दर एक किरम औ उपलब्धि समझी जाती थी. वह अब नीति की विफलता का सुचक मानी जानी है। इससे प्रमाणित होता है कि पहले की तुलना में उम्मीदें बढ़ गई है।

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में भारत की स्थिति

वरीयता तय करनेवाली विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियो द्वारा वरीयता कम सुनिश्चित करने के लिए कवायदें जारी हैं और कई संकेत भी तैयार किए गए हैं। भुमडलीकरण के सदर्भ में इन सकेतकों का महत्त्व बढ़ा है। मोटे तीर पर इन सकेनकों को चार श्रेणियों में बॉटा गया है-

- 1 आर्थिक सकेतक.
- सस्थागन संकेतक.
- 3 संरचनात्मक संकेतक तथा
- 4. सामाजिक संकेतक।

मायने में अंतिम नहीं है। दुनिया भर के कुल नौ राष्ट्रों को ऐसे आधार के रूप में माना गया है, जो विभिन्न देशों की भौगोलिक स्थिति, उनकी आय के प्तरों में व्याप्त अंतर, अर्थव्यवस्था के आकार आदि का समृचित प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देश हैं-भारत, सिंगापुर, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिकां, अमेरिका तथा जापान।

उपलब्धता और प्रासंगिकता के लिहाज से किया गया यह चयन किसी भी

आर्थिक संकेतक

आर्थिक संकेतकों के अंतर्गत आय का स्तर और अवधि-विशेष के दौरान इसके विकास, बचत तथा निवेश-दर के अनुसार इसके विकास करने की क्षमता, बाहरी क्षेत्र का प्रदर्शन आदि शामिल हैं।

म्पप्र रूप से भारत का अर्थव्यवस्था काफी बड़ी है। आकार की दृष्टि से इसका विश्व म ग्यारहवाँ तथा माप के मुताबिक तीसरा स्थान है। अलबत्ता, प्रति व्यक्ति आँकड़ों के लिहाज से भारत दुनिया के निचले राष्ट्रों की श्रेणी मे है। सन्

1999 में भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.डी.), जो दरअसल भारतीय

नार्गारको को प्राप्त होनेवाली सभी प्रकार की आय का कुल योग है, 442 2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। विश्व में यह ग्यारहवें स्थान पर था। इस प्रकार प्रति व्यक्ति

जी एन पी 450 अमेरिकी डॉलर है। इस हिसाब से हमारा स्थान दुनिया मे 162वें क्रम पर है, जो निस्संदेह हमारी श्रंणी के नौ राष्ट्रों के समृह में हमें काफी नीचे खड़ा करता है। चुँकि जी एन पी की यह गणना बाजार विनिमय-दर के हिसाब से की

जाती है। इसलिए कुछ विश्लेपकों ने इस विधि पर इस आधार पर आपित की है कि तलनात्मक वस्तुओं के मुल्यों में उन देशों में अंतर हो सकता है, जो इनका आपसी त्यापार नहीं करते। इन अतरों के समायोजन के बाद 'क्रय-शक्ति समानता'

(पी पी पी.) के आधार पर मापी गर्ड जी.एन पी हासिल होती है। इस प्रकार भारत की जी एन.पी. बढकर 2144) अरब अमेरिकी डॉलर हो जाती है, जो दरअसल अमेरिका के बाद दुमरे स्थान पर है। इसके बावजूद भारत को दुनिया भर के देशों की वरीयता मूची में 153वे म्थान पर रखा गया है, जो इन नो अन्य देशों के समृह

में वह केवल एक देश से ऊपर है।

यहाँ विचारणीय यह है कि भारत का विकास प्रभावशाली रहा है। दरअसल, आठवे आर नौवे दशक में तो इसकी जी डी पी की औसत वार्षिक विकास-दर सिंगापुर ओर चीन मरीखे देशों के समान रही थी, लेकिन पिछले दो दशकों मे जी डी.पी की अधिक विकास-दर के बावजूद प्रति व्यक्ति जी.एन पी. की दृष्टि से भारत का स्थान काफी पीछे है। हमारी आबादी का आकार और इसकी वृद्धि-दर

तथा हमारी आय के सीमित आधार इसके लिए प्रमुख रूप से दोषी हैं। सन् 1997-99 के दौरान बचत तथा निवेश-दर क्रमशः 20 3 और 23 9

प्रतिशत रही, जो कई विकासशील एवं विकसित देशों की दर से बेहतर है; लेकिन अधिक विकास-दर दरशानेवाले देशों, जैसे-सिंगापुर (बचत-दर 51.4 प्रतिशत तथा निवंश-दर 34.5 प्रतिशत) और चीन (बचत-दर 42.5 प्रतिशत तथा निवंश-दर 38 8 प्रतिशत) की तुलना में ये दरें काफी कम हैं। भारत में लगभग संपूर्ण बचत

घरों और निजी क्षेत्र से आती है। सन् 1993-94 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों की बचत मात्र 1 प्रतिशत रही। उल्लेखनीय है कि भारत में बचत का स्तर कम होने का मुख्य कारण मरकारी बचत का राजस्व घाटे के चलते नकारात्मक होना है।

यह बात भी गौर करने लायक है कि निर्वे दशक के दोगन वस्तुआ आ सेवाओं के निर्यात में 113 प्रतिशत की ओसत व्यर्थिक वृद्धि दर्ज की गई भी, जी दरअसल, चीन (13 प्रतिशत), मेक्सिको (143 प्रतिशत) आदि बहुनर्गन प्रत्यन करनेवाले कुछ ही देशों से कम थी। सन् 1998 में बाहरी ऋण नथा जी हो भी का अनुपात 23 प्रतिशत रहा, जो पाकिस्तान, श्रीलका, मेक्सिको मरीखे देशों में भी काफी कम था।

1990 के दशक में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ दी आई। क प्रवाह में भी तेजी आई। सन् 1998 में यह आँकटा 2 अस्य 26 करोड़ अमांचर्की डॉलर तक जा पहुँचा। इस प्रकार सर्वाधिक एफ डी.आई प्राप्त करनेताने 20 विकासशील देशों की सूची में भारत का भी नाम शामिल हो गया। उसके याल गृद सिगापुर (7 अरब 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर), चीन (45 अग्ब 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर), मेक्सिको (10 अरब 24 करोड़ अमेरिकी डॉलर) आदि देशां की न्याम भारत में यह प्रवाह कम ही रहा।

'इंटरनेशनल कंट्री रिस्क गाइड' (आई मी आर जी) द्वारा तैयार जीरिडम् वरीयता के अनुसार मार्च 2000 मे भारत की जोखिम वरीयता 64 3 रही जीर दूरर प्रकार इसका स्थान अपने समृह के दो देशों से ऊपर रहा।

सस्थागत निवेशको की (ऋण-माख) क्रेडिट रेटिंग के मामले में थी क्रमायण यह बात सच है, जिससे ज्ञात होता है कि कोई देश अटायणी में चृक कर मामले हैं।

भूमंडलीकरण के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि प्रौद्योगिकी प्रायः विकास को गित प्रदान करती है। इस दृष्टि से यह देखना होगा कि प्रौद्योगिकी के आलिए नार तथा विदेशों से प्रौद्योगिकी आयात करने के मामले से भारत कितना स्पंक्रस है. या भी कि व्यापार स्थापित करने के लिए देश मे माहौल किस हद तक मदारणार है। विश्व आर्थिक मच (डब्ल्यू.ई.एफ) ने उपर्युक्त स्थितियों को क्रमशः 'प्रौद्योगिकी सूचकांक' तथा 'स्थापना सूचकांक' का नाम दिया है। इन दोनो स वकांकों क मिलाने पर 'आर्थिक रचनात्मक सूचकांक' प्राप्त होता है, जो किसी देश के आर्थिक विकास को प्रदर्शित करता है। सन् 2000 में कराए गए 59 देणों सर्विक्षण में तीनों सूचकांको की सूची में भारत का स्थान 38वाँ था और वह चीन (48वें स्थान) से आगे रहा। हालांकि भारत की तुलना में मेक्सिको मे व्यापार स्थापना का वातावरण कम अनुकूल है और जापान में यह भारत से कुछ ही चेहतार है, परंतु प्रौद्योगिकी आविष्कार के क्षेत्र में इनकी भागीदारी और फानस्वरूप इनका रचनात्मक सूचकांक भारत से बेहतर है।

विश्व आर्थिक मच ने यह स्पष्ट करने के लिए कि कुछ देश दूसरो की तुलना में तेजी से आगे किस प्रकार बढ़ रहे हैं, 'विकास प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक' (जी.सी आई) तैयार किया है, जिसके अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति

आय में भविष्य में होनेवाली वृद्धि को दरशाया जाता है। सन् 2000 में कुल 59 देशों की मुची में इस आधार पर भारत का स्थान 49वाँ रहा था, जबकि चीन,

देशों की मूची में इस आधार पर भारत का स्थान 49वाँ रहा था, जबिक चीन, मेक्सिका तथा दक्षिण अफ्रीका क्रमश: 41वें, 43वें तथा 33वें स्थान पर रहे। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बृहद् अर्थव्यवस्था सबंधी कारकों के अलावा

मृक्ष्म आधिक आधार भी जिम्मेदार होते हैं। इसे मापने के लिए विश्व आर्थिक मच द्वारा तैयार प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक (एम.सी.आई.) के आधार पर 58 देशों में भारत का म्थान 42वाँ है। अलबत्ता, वह चीन (49वे स्थान) से आगे हैं, जबिक मेक्सिको (34वे स्थान) और दक्षिण अफ्रीका (26वे स्थान) पर कहीं आगे हैं।

ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि देश की मौजूदा अधिक उत्पादकता तथा आर्थिक प्रदर्शन को किन कारकों से बल मिलता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा इमें 'चालृ प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक' (सी.सी आई.) का नाम दिया गया है। सन्

2000 में इस आधार पर तैयार 58 देशों की सूची में भारत का 37वॉ स्थान था, जो

मी भी आई के अनुसार 49वे स्थान से कहीं बेहतर है। यहाँ दिलचस्प तथ्य यह है कि हमारे देश की सी सी.आई के अनुसार वरीयता चीन (44वीं) तथा मेक्सिका (42वीं) से अधिक रही, जिससे स्पष्ट हैं कि हमारे वर्तमान विकास की प्रभावित करनेवाले कारक इन देशों के मुकाबले बेहतर हैं। इसके बावजूद वरीयता सूची मे हम निचले स्तर पर ही टिके हए हैं।

किसी देश के बाजारों के खुलेपन को 'उभरते बाजार सूचकांक' से तय किया जाता है। सन् 2000 में इम वरीयता-क्रम में भारत 46वें स्थान पर था और वह केवल चीन से ही ऊपर था। जहाँ तक शेष विश्व के साथ एकीकृत होने की बात है तो भारत इस दूष्टि से पिछड़ा ही कहा जाएगा। इसे मापने के लिए प्रयुक्त होनेवाले 'भूमंडलीकरण सूचकांक' के अनुसार सन् 1993-97 के दौरान भारत के

मंदर्भ मे यह आँकड़ा 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष रहा, जो यकीनन कम कहा जाएगा, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का 'मदी प्रत्याशा' सूचकांक काफी अधिक रहा है। यह चीन, मेक्सिको, अमेरिका, जापान आदि देशों से भी ऊपर दर्ज किया गया। यह सूचकांक उस भरोसे का संकेतक है, जिसके अनुसार किसी देश के बारे में अनुमान व्यक्त किया जाता है कि उसकी अर्थव्यवस्था में गिरावट नहीं आएगी। इससे स्पष्ट

है कि हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर है।

खागत सेकेतक

सभी प्रकार के आर्थिक लेन-देन और सामाजिक प्रावधान कृछ निश्चित मस्थानों के दायरे में किए गए हैं। सस्थागत कारकों का मृल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है और वास्तव में यह विधि फिलहाल शैशवावस्था में है। चूँकि अधिकतर ऑकड़े मत-सर्वेक्षणों के माध्यम से इकट्ठे किए गए हैं, इमिलिए इनके माध्यम से व्यक्त विचारों को भी अतिम न मानकर 'तुलनात्मक' ही कहा जाना चाहिए।

'ट्रासपेरेंसी इंटरनेशनल' तथा गॉटिनान विश्वविद्यालय ने किसी दश के राजनीतिज्ञो तथा सरकारी कर्मचारियों की पारदर्शिता के बारे में वहाँ के व्यापारिक समुदाय की राय के आधार पर विभिन्न देशों की वरीयता मृची तथार की है। इस सूचकाक को 'भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाक' नाम दिया गया है। 'ट्रामप्रेंसी इंटरनेशनल' द्वारा सन् 1996 में 54 देशों में कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर भागत को 46वे स्थान पर रखा गया था, अर्थात् तब इन देशों में भारत नावां सर्वाधिक भ्रष्ट देश था।

शासन-व्यवस्था के संदर्भ में विश्व बैंक ने अपने प्रकाशन 'इडिया— रिड्यूसिंग पॉवर्टी, एक्सलरेटिंग डेवलपमेट (2000) 'के अंतर्गत पॉच प्रमुख मंकेतको का जिक्र किया है। ये हैं—

- 1 सरकारी प्रभावशीलता तथा स्थिरता, जिसके अतर्गत संस्थागत तथा सरकारी स्थिरता समेत सरकारी नीतियों के प्रति आम जनता में संतोष का भाव शामिल रहता है,
- कानून की भूमिका तथा व्यापारिक माहौल, जिसके अंतर्गत भ्रष्टाचार.
 रिश्वत (दलाली), कानून-व्यवस्था, कानूनी अधिकार आदि गार्मिल हैं;
- आम जनता का प्रशासन, जिसे नौकरशाही के स्तर, उसकी मजबूनी तथा उसमें राजनीतिक इस्तक्षेप की मात्रा एवं जवाबदेशी के आधार पर परखा जाता है;
- 4 सार्वजिनक वित्त, जो अन्य बातों के अलावा बजट की गुणवत्ता, खर्च में कुशलता तथा न्यायोचितता और सार्वजिनक वित्त की प्राप्ति एखं प्रबंधन की दृष्टि से जाँचा जाता है.
- 5 निष्कर्ष, जिसके तहत अधिकांश सामाजिक सूचकांक, जैसे—गरीबी, मृत्यु-दर, साक्षरता आदि शामिल हैं। सन् 1995 में विभिन्न देशों के 5 समूहों की तुलना में भारत को उपर्युक्त कसौटियों के आधार पर

परखा गया था। ये समूह हैं—विकासशील देश, कुछ चुनिदा बडे देश, जिनमें चीन, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील तथा पोलैंड हैं दक्षिण-पूर्व एशिया, जिसमें इंडोनेशिया तथा थाईलैंड भी शामिल हें, भारत को छोडकर दक्षिण एशिया, इंग्लैंड और अमेरिका सरीखे

सरकार की प्रभावशीलता तथा उसकी स्थिरता के मामले में विभिन्न देशों के सभी समूहों के मुकाबले भारत की स्थिति काफी खराब है।

औद्योगिक देश हैं।

कानून की भूमिका तथा व्यापारिक वातावरण की दृष्टि से भारत की स्थिति अपने पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों से बेहतर है, लेकिन चुनिदा बड़े देशों तथा आद्योगिक राष्ट्रों की तुलना में भारत की स्थिति बिलकुल अच्छी नहीं कही जा सकती।

आम जनता के प्रशासन के मामले में औद्योगिक राष्ट्रों को छोड़कर शेष देशों के सभी समूहो की तुलना में भारत का स्थान बेहतर है। इसी प्रकार सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में औद्योगिक राष्ट्र तथा चुनिंदा बड़े

देश के समूह हमसे आगे हैं, जबिक भारत की स्थिति शेष समूहों से बेहतर है। सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के रूप में सामने आनेवाले निष्कर्षों की दृष्टि से भी सभी समृहों की तुलना में भारत का प्रदर्शन खराब रहा है।

ढाँचागत संकेतक

परिवहन, बिजली, दूरसंचार, पानी, स्वच्छता आदि टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ढॉचागत संरचना के ये महत्त्वपूर्ण आधार हैं। ये सुविधाएँ आर्थिक गतिविधियों के कुशल तथा प्रभावी प्रवाह में सहायक होने के साथ-साथ जीवन के लिए आधारभृत आवश्यकताएँ जुटाती हैं। यहाँ इन सकेतकों के आईने में भारत तथा अन्य समृहों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा।

सबसे पहले बिजली की स्थिति पर विचार करें। सन् 1997 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत केवल 363 कि.वा. थी। हालाँकि पाकिस्तान के मुकाबले इसमे भारत की स्थिति बेहतर है; लेकिन अन्य देशों की तुलना में यह अच्छी नहीं

कही जा सकती। चीन में यह खपत भारत की खपत से लगभग दोगुनी है। अन्य दक्षिण एशियाई देशों के नक्शे-कदम पर चलते हुए हमने भी प्रेषण और वितरण की प्रक्रिया में काफी मात्रा में बिजली बरबाद की है। सन् 1997 में यह 18 प्रतिशत

प्रक्रिया म काफा मात्रा म ाबजला बरबाद का है। सन् रही, जबकि चीन में यह बरबादी केवल 8 प्रतिशत थी। सन् 1998 में अच्छी हालत में या पक्की सड़कें केवल 45 7 प्रतिशत की , उधर पाकिस्तान (57 प्रतिशत) और श्रीलंका (95 प्रतिशत) आदि देश भी इस लिहाज से हमसे आगे हैं।

देश का रेलवे-तंत्र कुल मिलाकर अच्छी स्थित में हैं। मन 1998 में प्राप्त 10 लाख डॉलर जी डी पी. पर रेलवे ने 137 1 हजार टन किलामीनर माल खेता। यह आँकड़ा जापान (101.7) से बेहतर है, लेकिन अधिक भौगोलिक क्षेत्रें। बान चीन (3048), दक्षिण अफ्रीका (283.3) आदि देशों की तुलना में यह काफी कम है, जो माल-वाहन के लिए रेलवे-तंत्र का इस्तेमाल करते हैं।

सन् 1997 में प्रति 1,000 भारतीयों में से 121 के पाम रेडिया मेर था जबिक समूह के केवल एक देश को छोड़कर शंप सभी देश हम द्रींप से भारत य आगे हैं। श्रीलंका (209) की स्थिति भारत से दोगुनी अच्छी है। उसी प्रकार प्रान 1,000 में से केवल 68 भारतीयों के पास ही टी.वां. संट थे। इस मामले में भारत अपने समृह में सबसे पिछड़ा हुआ था।

सन् 1998 में देश में टेलीफोन की 22 मेन लाइने थीं। इस मामले म सम्र के केवल एक देश से हमारी स्थिति बेहतर थी, जर्बाक चीन (70) हममं काफी आगे था। भारत में टेलीफोन कनेक्शन के लिए औसत प्रतीशा समय एक वर्ष था। यह स्थिति हमें केवल दो देशों से ही आगे खड़ा करती है, जर्बाक चीन आदि दंश के आगे हमें टिक ही नहीं पाते, जहाँ यह समय औसतन एक माह था।

सन् 1998 में देश में प्रति 1,000 गर 2.7 पर्सनल कप्यृटर (पी.सी.) ११। उस् लिहाज से समूह में भारत सबसे पिछड़ा देश था। चीन में यह ऑकड़ा ६० धर जबिक बाकी सभी देश काफी आगे थे। इंटरनेट के मामले में भां स्थित कमोबेण यही थी। सन् 2000 में प्रति 10,000 पर यह आँकड़ा भारत में 0 23, चीन में 0.57 पाकिस्तान में 0 34 तथा श्रीलंका में 0.63 दर्ज किया गया।

भारत अपने विज्ञानकर्मियों तथा इंजीनियरों की भारी फौज के लिए जाना जाता है। सन् 1987-97 के दौरान प्रति 10 लाख भारतीयों पर 149 र्व्याब्त अन्मभान एव विकास (आर. एंड डी) गतिविधियों से जुड़े थे। इस क्षेत्र में भी कंखल एक देश को छोड़कर शेष सभी देशों की स्थिति हमसे बेहतर है। यदि हम अप्रवासी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को भी इस आँकड़े में शामिल कर लें तो भी म्थित में कोई सुधार आनेवाला नहीं है। इसी अवधि में कुल निर्मित निर्यात का 5 प्रतिशत प्रीद्योगिकी से संबंधित था। यहाँ भी हम दक्षिण एशियाई एड़ोसी दंशों को छोड़कर शेष सभी देशों से पिछड़े हुए हैं।

सुरक्षित जलस्रोत तथा स्वच्छता सबधी सुविधाए लोगो के स्वास्थ्य सुधार से जुड़ी बुनियादी ढाँचागत आवश्यकताएँ हैं। सामाजिक संकेतक के अंतर्गत हम पढ़ेगे कि इस मोरचे पर भी भारत का प्रदर्शन खराब रहा है।

उपर्युक्त ढॉचागत संकेतकों को जानने के बाद इस बारे में कोई आश्चर्य नहीं रह जाता कि विश्व आर्थिक मंच ने सन् 1998 के ग्लोबल कपीटीटिवनेस रिपोर्ट में 53 देशों के समूह के सर्वेक्षण (ढॉचागत संदर्भों में) के बाद भारत को 53वें स्थान पर रखा था।

सामाजिक संकेतक

सामाजिक संकेतकों के अतर्गत भोजन, आवास और कपड़े के साथ-साथ लोगों का ज्ञान और उनका स्वास्थ्य भी शामिल है। हमारे समूह के देशों के बीच इनमें से कुछ संकेतकों की तुलना 'मानव-विकास सूचकांक' तथा 'मानव-गरीबी सूचकांक' के माथ करने पर प्राप्त निष्कर्षों से बहुत कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा।

किसी भी देश का महत्त्वपूर्ण सामाजिक संकेतक उसके लोगों की साक्षरता का स्तर होता है। सन् 1998 में हमारे देश में प्रौढ़ साक्षरता–दर मात्र 55.7 प्रतिशत थी, जो पाकिस्तान (44 प्रतिशत) से भले ही बेहतर रही, मगर श्रीलंका (91 1) आर चीन (82.8) के मुकाबले काफी कम थी। युवा साक्षरता की तसवीर भी कमोबेश ऐसी ही है। भारत (71 प्रतिशत) इस क्षेत्र में श्रीलंका (96.5 प्रतिशत) तथा चीन (97 2 प्रतिशत) से काफी पीछे है। यहाँ उल्लेखनीय है कि सन् 1995–97 के दौरान शिक्षा पर सार्वजिनक व्यय जी डी.पी का 3 2 प्रतिशत रहा, जो कई देशों के लगभग वराबर था। साथ ही सन् 1994–97 के दौरान अधिक निरक्षरता–दर के बावजुद शिक्षा–व्यय के दायरे में हमने प्राथमिक–पूर्व, प्राथमिक तथा सेकेंडरी स्तर पर कम, यानी 66 प्रतिशत ही खर्च किया। उधर पाकिस्तान, श्रीलंका आदि देशों ने शिक्षा के इस स्तर पर 3/4 या इससे भी अधिक राशि खर्च की।

शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य भी जनता की बुनियादी जरूरत है। हालाँकि सन् 1990-96 के दौरान हमारी 81 प्रतिशत की पहुँच शुद्ध पेयजल म्रोतों तक थी, लेकिन हम केवल तीन देशों की तुलना में ही बेहतर थे। स्वच्छता तक मात्र 16 प्रतिशत आबादी की पहुँच थी और इस मोरचे पर हम समूह के सभी देशों के मुकाबले पिछड़े हुए थे।

सन् 1998 में प्रति 1,000 पर 70 शिशुओं की मृत्यु हुई। इसी प्रकार मन्

1998 में केवल एक देश की जीवन-सभाव्यता भारत (63 वर्ष) में कम थी , मन 1997 में प्रति एक लाख भारतीयों में से 118 3 प्रतिशन लोग क्षय गेग में पोन्डिन था।

केवल दक्षिण अफ्रीका (242 7) इस मामले मे भारत से पिछड़ा हुआ था।

सन् 1990-97 के दौरान 33 प्रति नवजात शिशुओ का प्रजन ऑगस्ट में कम था। इस मामले में हम पाकिस्तान, श्रीलंका आदि देणों से भी फिछडे हुए उन

जाएँगे, जहाँ यह आँकडा 25 प्रतिशत था। सन् 1997 में केवल दो देश ही ऐसे थे, जिन्होंने भारत द्वारा ∉ापनं प्रत्यक नागरिक को प्रतिदिन 2496 कैलोरीज की आपूर्ति से भी कम मात्रा में केलोरीज

उपलब्ध कराई थी। सन् 1997 में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 59 ग्राम प्रोटीन की खपन भी कम रही। सन् 1990-98 के दौरान हमने स्वास्थ्य-सेवाओं पर जी ही एर

महज 0 60 प्रतिशत खर्च किया, जो अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। सन् 1992-95 के दौरान प्रति एक लाख भारतीयों पर 48 डॉक्टर उपलब्ध

थे। इस मामले में हमारी स्थिति केवल श्रीलका से बेहतर रही।

विश्व वैक ने बुनियादी मानव-विकास के क्षेत्र में औसत उपलब्धि ऑक्स

के लिए 'मानव-विकास सूचकांक' तैयार किया। इसके अतर्गत प्रति व्यक्ति जो 'ईं! मी स्चकांक, शिक्षा स्चकांक तथा जीवन-संभाव्यता स्चकांक को शामित किया

गया। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मन् 1998 में इस क्षेत्र मे भी पहले दा उप-सुचकांकों में केवल एक देश ही हमसे पीछे रहा, जबकि तीसरे युनकाक म

भी हम केवल एक देश की तुलना में बेहतर स्थिति में थे। इस प्रकार सन १९५८ म 'मानव-विकास सुचकांक' के आधार पर भारत का स्थान 128वाँ था।

प्रगति की राह

जहाँ तक विकास-दर का सवाल है, हमने बीसवीं शताब्दी के शुरू है: 50 वर्षों की बजाय बाद के 50 वर्षों में, और उनमें भी आखिरों दो दशकी म बेहतर प्रदर्शन किया है। इस बीच उत्पादन-विकास में उतार-चढ़ाव कम हुए हैं।

झटको को झेलने की क्षमता बढ़ी है। बाहरी क्षेत्र में हमारी स्थित इस दृष्टि सं सुधरी है कि अब विकास पर विदेशी मुद्रा का दवाव नहीं है। इन सबके यायजृद हमारे यहाँ व्यापक स्तर पर गरीबी और निरक्षरता के साथ-साथ स्वास्थ्य और

स्वच्छता की स्थिति काफी खराब है। अभाव और गरीबी के भयंकर समृद्र के बीच सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ रूपी द्वीप भी इस देश में मौजूद हैं। आर्थिक

नीति, विशेषकर नब्बे के दशक की नीतियों ने आर्थिक विकास पर पड्नेवाले

साथ समाज के लिए तय अन्य लक्ष्यों को हासिल करने की आवश्यक पूर्व शर्त भी है; लेकिन अब भी इस बात को लेकर शंका बनी हुई है कि क्या हम विधिवत् ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहे है, जो विकास का निरंतर उच्च स्तर सुनिश्चित करेगी तथा इस प्रकार के विकास के साथ जुड़े न्यूनतम सामाजिक लक्ष्यों की

आर्थिक सकेतको से पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की

अनेक दबावों को दूर किया है। यह अपने आप में एक उपलब्धि होने के साथ-

हम किस दिशा में अग्रसर हैं?

प्राप्ति में भी योगदान देगी?

स्तर के बावजृद बाहरी क्षेत्र में हमारी स्थिति ठीक-ठाक है। यह स्थिती इस बात का प्रमाण है कि विदेशी पूँजी-निवेशकों को कम दिलचस्मी के बावजूद घरेलू निवेशकों का मिला-जुला दृष्टिकोण है। 'वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक सृचकांक' के आधार पर तय हमारी स्थिति से उस विश्वास की झलक मिलती है, जो कम अविध में ही हमारे विकास की रफ्तार को देखकर व्यक्त किया गया है। अलबता 'विकास

प्रतिस्पर्धात्मक सूचकाक' पर हमारी स्थिति से जो तसवीर उभरती है, वह भविष्य मे प्रति व्यक्ति आय में विकास को लेकर आशाजनक नहीं कही जा सकती। अन्य

अधिक तेज गति से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था का बचत तथा निवेश अनुपात काफी अधिक है। पूँजी निर्गत अनुपात से स्पष्ट हे कि हमारी उत्पादकता का स्तर भी सम्माननीय है। पूँजी-प्रवाह के अपेक्षाकृत कम

सकेतकों के संबंध में भी यही स्थिति है कि मौजूदा विकास को गति देनेवाले कारक भविष्य में विकास को बढावा देनेवाले कारकों के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत है। इसके वावजृद इस बात को लेकर पूरा भरोसा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी नहीं आएगी, अर्थात् हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर है। अर्थव्यवस्था की वर्तमान, मध्यम और लंबी अवधि की संभावनाओं को

लेकर मतभेदों को औद्योगिक संकेतकों के सदर्भ में समझा जा सकता है। साक्ष्य व्यक्तिपरक हैं, इसलिए अधिक विश्वसनीय नहीं है। हाँ, भ्रष्टाचार के मामले में अधिक वरीयता क्रम अवश्य चितनीय है, लेकिन इससे भी अधिक चिंता का विषय

अधिक वरीयता क्रम अवश्य चितनीय है, लेकिन इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि सरकार की प्रभावशीलता को कम माना गया है। कानून की भूमिका नथा व्यापारिक माहोल के मामले में स्थिति सतोषजनक भले ही है, लेकिन मौजूदा

संकेतक अधिक विकास-पथ को सुनिश्चित करनेवाले माहौल की गारंटी नहीं दे सकते। सरकार, कानून और व्यापारिक माहौल दरअसल उद्देश्य-प्राप्ति के माधन भर हैं, साध्य जनता की सामाजिक-आर्थिक समन्त्रना है, लांकन मामाजिक आर्थिक संकेतकों के हिसाब से भारत की स्थिति पिछड़ी हुए है।

मध्यम अवधि की संभावनाओं की दृष्टि में हाँचागत क्षेत्र में जुंड मंकतक प्रासिंगक माने जाते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में, चाहे वह विकर्ण का ख्या को या बिजली की बरबादी, भारत की स्थिति काफी खराब है। हाल के वर्षों ने एए सुधारों के बावजूद दूरसंचार के क्षेत्र में भी उसका म्थान पिछा है है 'ए हो उपसंत्र कं बात की मामले में तो हम काफी पीछे हैं। हालाँकि भूनना पौद्यांगकों के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं, मगर घरेल मंगरे पर उसकी पहुँच कम है। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी हो जाती है कि निर्मात निर्मात में प्रौद्योगिकी सबंधी निर्मात का हमारा प्रतिशत भी कम है। भी प्रय का आकलन करते समय हमें इस तथ्य पर गीर करना चाहिए कि विजानकिमयों तथा दर्जानियम की हमारी भारी फीज के बावजूद अनुसंभान तथा विकास के क्षेत्र में उनकी नेन्नी के मामले में हमारा स्थान सबसे नीचे हैं। भूमंडलीय प्रतिस्मर्थात्मक स्वकार पर हमारे 49वें स्थान को ढाँचागत सकतकों के मामले में हमार्ग स्थान में समझा जा सकता है।

देश का साक्षरता-स्तर काफी कम है, हालाँक इस मद में जी ही पी. में प्रतिशत के रूप में होनेवाला सरकारी खर्च अन्य देशों क बराजर ही है। स्थान्छ्य और स्वच्छता के हालात भी अच्छे नहीं हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस दिशा में दूसरे मदों के मुकाबले खर्च भी काफी कम हो रहा है।

कुल मिलाकर, मानव-विकास के क्षेत्र में तो हमारा म्थान कार्या गांछ है ही. देश की बड़ी आबादी की गिनती वंचितों की श्रेणी में होती है। इसके बाब तर स्वास्थ्य तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी खर्च अपेक्षाकृत कम है, हान्तीं के अधिक खर्च का अर्थ सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति नहीं हैं। हममें में आंध्या में लोग मानवीय दु:ख-दर्द और गरीबों की जरूरतों के प्रति काफी हद तक असंवर्ध हैं। यही कारण है कि संगठित क्षेत्र से जुड़े किमंशों के कल्याण तथा उन्हें गिलनंबाकी रिआयतों की कीमतें अपेक्षाकृत अधिक हैं। नीति-निर्माताओं तथा शिक्षाविदों समेत जनमत तैयार करनेवालों को गरीबों के पक्ष में अधिक संवेदी दृष्टिकोण तैयार करने के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। लबी अवधि की विकास-सभावनाओं के लिए सामाजिक चेतना के साथ-साथ सामाजिक विकास के स्वीकार्य स्तर और सरकार की समुचित भूमिका भी आवश्यक है, ताकि हमारे देश का समृद्ध भविष्य स्तिश्वत किया जा सके।

भविष्य की तसवीर

अतीत में हमार प्रदर्शन तथा भूमंडलीय संदर्भ में मीजूदा स्थिति के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राप्त नतीजों को पाँच स्तरों पर देखा जा सकता है।

योजना-युग के बाद से हमारी आवश्यकताओं तथा क्षमताओं की दृष्टि से हमारा प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। भूमडलीय स्तर पर कुल मिलाकर यह ठीक-ठाक ही है और हाल के वर्षों में यह स्थिति लगातार सुधर रही है। विकास के सामाजिक पहलू के मामले में हम पिछडे हुए है। जिन क्षेत्रों में भरोसा जताया जा रहा है, वहाँ अपेक्षित क्रियात्मकता लाने की जरूरत है, ताकि विकास की गति गतिशील रहे।

दूमरे, स्थिरता तथा विकास की मौजूदा संभावनाएँ बेहतर है। ऐसा विनियमीकरण तथा उदारीकरण के रूप में संरचनात्मक रुकावटों को दूर करने से संभव हुआ है। जाहिर है कि मध्यम अवधि के लिहाज से अधिक विकास के लिए इतना ही काफी नहीं है। इस दृष्टि से संस्थागत तथा ढाँचागत मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। यकीनन यह चुनौती काफी जटिल है।

सामाजिक संकेतको के क्षेत्र में तुरत कार्यवाही करने जैसे उपायों की अधिक आवश्यकता है। लोगों मे जागरूकता बढ़ने तथा भूमंडलीय प्रतिस्पर्धा में तेजी आने के बाद अब उनकी न्यूनतम स्वाम्थ्य जरूरतों को पृरा करना या साक्षर बना देना ही पर्याप्त नहीं है। यदि हमें एक राष्ट्र के रूप में गरिमा तथा सम्मान के साथ जिदा रहना है तो तंज गति से कौशल-स्तरों मे वृद्धि करने की क्षमतावाली स्वस्थ आवादी का होना अत्थावश्यक है।

सस्थाओं तथा ढाँचागत तंत्र से जुड़ी मध्यम अवधि की चुनौतियों और सामाजिक विकास जेसी लबी अवधि की योजनाओं के लिए अधिक केंद्रित सरकार की आवश्यकता है, जो प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक सेवाएँ मुहैया करा सके। हमे कम सरकार और अधिक बाजार नहीं, बल्कि बेहतर सरकार तथा वास्तविक बाजार चाहिए। अभी तक हमारे देश का यथार्थ प्राय. शासन और बाजार बनाम गरीब जनता रहा है; परंतु अब हमारी कोशिश जनता के लिए शासन और बाजार या बेहतर सरकार और वास्तविक बाजार तैयार करने की होनी चाहिए।

आनेवाले कल की समस्याओं को बीते हुए कल की रणनीति के सहारे नहीं मुलझाया जा सकता और न ही गुजरे कल की जानकारियों के आधार पर उन्हें समझा जा मकता है। यही कारण है कि हमें और अधिक संख्या में विवेकवर्धिनी तथा विवेकव्यापनी चाहिए।

गरिशिष्ट-1

		ब्रिनंदा दे	चुनिंदा देशों का तुलनात्मक आर्थिक प्रदर्शन	ननात्मक	आर्थिक उ	रदर्शन				
	सूचकांक	भारत	सिंगापुर	चीन प	चीन पाकिस्तान	श्रीलंका द.अफ्रीका	अफ्रीका	मेक्सिको	अमेरिका	जापान
		2	m	4	מ	9	7	00	6	10
1	1 सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी)									1
	(विश्व बैक एटलस विधि)									
	क प्रति व्यक्ति 1999 (डॉलर मे)	450	29610	780	470	820	3160	4400	30600	32230
	ख देशों का वरीयता क्रम	162	6	140	160	137	98	77	00	9
C4	2 सकल राष्ट्रीय उत्पाद (पी पी.पी.)									
	क प्रति व्यक्ति (1999) (डॉलर में)	2149	27024	3201	1757	3056	85.18	7719	30600	2 104
	ख देशों का बरीयता क्रम	:53	*	33	150	130	E.	5.	rī	**
15)	सकल घोल उत्पाद-दर (प्रतिशत मे)									
	₩. 1980-90	30 10	f	4.	6.3	7	0	+	3.0	Ç
	5c- C661 B	9	64 50	5	4	re; 1/1	a	(4)	ne.	p oliti
ớ콧	HATELINE AS SOME SHEET SHEET SHEET									
	が、ないないは、一名からない	\$. !	ړخ	1 4 1/1	*	7	14	3	77	
ŧΛ	一年 日本									
	(山山山 北京中山山山)	2.5	.7: *7 (*)	G. G.	,1,1 1	15. 17. 17.4	Fi Fi	2. 2. 100	4. 4.	

		सकल घरलू बचत (199/–1999)	50.3	514	47.5	7 Ll	18 3	٤/١	8 57	/ 91	30 O	
	တ	8. बस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात की			7	7	0	r c	7,	a	ν. Γ	
		औसत वार्षिक विकास-दर (1990-99) 11.3		l	13.0	17	0 1	G	r T	j	-	
	ø	9 बाहरी ऋण (1998)							1			
* *		(जो.एन पी के प्रतिशत के रूप में)	23.0	ſ	16.4	52.8	54.9	38.9	43.0	t		
गरती	2	10 सकल भंडारण (अरब अमेरिकी										
य अ		डॉलर में)										
र्थनी		1990 中	5.64	27 75	34,48	1.05	0 45	2 58	10 22	173 1		
ਰਿ ¥		1900 H	32.7	76 84	157 73	151	164	6 35	31.78	90 2	286 92	
!	-	11. शद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश										
	•	(अरब अमेरिकी डॉलर में)										
		क वार्षिक औसत (1987-92)	90 0	3 67	4.65	0 23	90 0	-0 024	4 31	46 21	0.91	
		TG. 1998	2 26	7.22	45 5	0.5	0 35	0 37	10 24	193 4	3 19	
	12	12 संयोजित आई सी.आर जी. जेरिखम							1	(
		मरीयता (मार्च 2000)	643	89 0	72.3	543	603	70 5	70.5	0 08	0.78	

🛊 भारतीय अर्थनीति 🛊

D

52.9

6 98

भके स्वास्थ्य पा (जी डां पी. के प्रतिशत के रूप्प में) (1990 -93) ध्र बेहतर जल-धातों तक आबादी की पर्हुंच (प्रतिशत में) (1990 -96) ध्र बेहतर जल-धातों तक आबादी की पर्हुंच (प्रतिशत में) (1990 -96) ध्र बिश्य मृत्यु-टर (प्रति 1,000 ध्र बिश्य मृत्यु-टर (प्रति 1,000 श्र विश्व मृत्यु-टर (प्रति 1,000 श्र विश्व मृत्यु-टर (प्रति प्रति व्यक्ति केलोरी श्र प्रति 1 लाख की आबादी पम मु (1997) श्र प्रति 1 लाख की आबादी पम मु (1997)		6.5 5.9	96	- 100	7	76.8 80	3699 2932		245 177
क्य्य के प्रतिशत के रूप में) 10.6 111 2.0 0.9 14 13.1 (1990-96) 81 100 90 60 46 13.1 (1990-96) 16 100 21 30 52 13.1 (1997) 2496 - 2897 2476 2302 29 14.1 (1997) 31 52 23		2.8	83	99	30	72 3	3097	83	85
क्यय के प्रतिशत के रूप में) 10.6 111 2.0 0.9 -सीतो तक आबादी की ति में) (1990-96) 81 100 90 60 5 आबादी की पहुँच (1990-96) 16 100 21 30 31 पर) (1998) 70 4 31 91 य जीवन संभाव्यता 62.9 77.3 70.1 64.4 7 व्यक्ति केलोसी 2496 - 2897 2476 2: व्यक्ति प्रोटीन की 5.9 - 78 61 में) (1997)		32	70	46	51	53.2	2990	77	59
क्यव के प्रतिशत के रूप में) 10.6 111 20 -सीतो तक आबादी की तत्ते में (1990-96) 81 100 90 5 आबादी की पहुँच (1990-96) 16 100 21 23 (प्रति 1,000 जों पर) (1998) 70 4 31 व जीवन संभाव्यता 62.9 77.3 70.1 6 व्यक्ति कैलीरी सी) (1997) की आबादी पर 48 117 115		4	46	52	16	73.3	2302	52	23
क्यय के प्रतिशत के रूप में) 10.6 111 -सीतो तक आबादी की 10.6 111 100 5 आबादी की पहुँच (1990 96) 16 100 23 (प्रति 1,000 अों परो (1998) 70 4 य जीवन संभाव्यता 62.9 77.3 7 व्यक्ति कैलीरो 1 में) (1997) की आबादी पर 48 117		0.9	9	30	ő	644	2476	61	52
व्यय के प्रतिशत के रूप में) 10.6 -सीतो तक आबादी की 11 (1990-96) 12 (1990-96) 13 (1990-96) 14 (1990-96) 15 (1990-96) 15 (1990-96) 16 (1990-96) 17 (1998) 2496 व्यक्ति कैलीरी 2496 व्यक्ति प्रोटीन की 19 (1997) की आबादी पर		2.0	90	21	31	70 1	2897	78	115
व्यय के प्रतिशत के रूप में) सोतो तक आबादी की ति में) (1990-96) ते आबादा की पहुँच (1990-96) त्र (प्रति 1,000 जों पर) (1998) य जीवन संभाव्यता 6 व्यक्ति केलोरो सो (1997) की आबादा फ		denominal desired in the second	100	100	4	77.3	\$	1	117
स्वास्थ्य पर (जी डां पी. के प्रतिशत के रूप में (1990 -98) बेहतर जल-सोतो तक आबादी क पुर्वेच (प्रतिशत में) (1990 -96) स्वच्छता तक आबादी की पहुंच (प्रतिशत में) (1990 96) शिश्य मृत्यु-दर (प्रति 1,000 जीवित शिश्युओं पर) (1998) जन्म के नमय जीवन संभाव्यता प्रतिदिन प्रति व्यक्ति केलोरो आपृति प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रोटीन की अपृति (ग्राम में) (1997)			8	91	70	629	2496	59	\$
to the fact of the fact of	क स्वास्थ्य पा (जी डो पी. के प्रतिशत के रूप में	(1990-98) बेहतर जल-	पहुँच (प्रतिशत मे) (1990-96) म स्वच्छता तक आबादा की पहुँच	(प्रतिशत में) (1990 96) शिशु मृत्यु-दर (प्रति 1,000	जीवित शिशुओं पर) (1998)	ङ जन्म के तमय जावन सभाव्यता च. प्रतिटिन प्रति व्यक्ति कैलोरी			ज. प्रति । नाख की आबादी पर

10	33.6		7	10		6.0	ſ	724	-+
6	6 4		7	ri M		40	35	11822	Ą
8	25 0		7	f		0	ឃុ	1459	ruje T
7	242 7		ł	€.		45	30	3800	ď
9	35.7		25	5.1		35	ur, M	227	## F
5	3.1		25	57		ı	i	333	٠
4	33.7		6	2.2		45	30	7	۴
ť	57.5		7	5.7		28	26	7944	**
2	118.3		ю ю	2 8		30.0	35	363	ŧ.
-	झ 1997 में प्रति । लाख मे तपेदिक 118.3 57.5 337	अ. जन्म के समय सामान्य से कम	নন্দবালে 1શधुन्य। का प्रांतरात (1990–97)	19 रक्षा-च्यय (जी एन.पी. के प्रतिशत के रूप में) (1997)	20 सर्वाधिक (मार्जिनल) कर दर, प्रतिशत	में (1999 में) ऋ व्यक्तियान	म. जाजास ख. सामूहिक	21. विद्युत् तथा परिवहन क. प्रति व्यक्ति बिजली की खपत	(के डब्ल्यू एच) (1997)
34	ļ 1			-		ारतीय ठ	भ र्य नीति		
34	•				津 커	रताय ठ	મથનાાત	*	

(हजार टन कि मी जो दी प् (पी.पी पी.) के ग्रांत 10 नाख डॉन्तर पर। डे. हवाई यात्रो (1998) 27. मेंचार, यृचना और दिव्हान नथा ग्रीद्योगिको (प्रांत 1000 व्यक्ति)	155.2	رن در	304 × 537 3	54 12 50 44	2 0.3	2833	62.1	213 8 5881 2	101 7
के. रिडवी (1997) खे. टी.बी. मेट (1998) म टेलीफोन मेनलाइन (1998) घ पी सी. (1998) ड. इंटरमेट हॉस्ट प्रति 10,000 पर	121 69 22 22 27	822 348 562 458.4	333 272 70 8.9	98 88 19 39	209 92 28 4 1	317 125 115 47.4	325 261 104 47	2146 847 661 458.6	955 707 503 237 2
(जनवरा 2000) घ. प्रति १० लाख पर आर. एंड डी में	0 23 rts	452 3	0.57	0 34	0 63	39.2	40 9	1940	80%
विशानिक तथा इंजीनियर (1987–97) 149 छ उच्च प्रौद्योगिकी निर्यात (उत्पादन निर्मान के निर्मात (उत्पादन	77) 149	2318	454	72	191	1031	214	3676	4909
ानवात के प्रातशत के रूप में) ज. टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा	2	59	15	0	1	6	19	33	26
पूषा (१४५/) (वषा म्)	0	0 0	0.1	12	63	0 4	8 0	0 0	0.0

भारतीय अर्थनीति क्र

10	16	2 0 Fina
6	60	ख 1998 नोद. देशों के गुलमान्यक अध्ययन के निग्ध अपर्युष्त प्रीकड़ निश्च बंध का खिरक विद्याम रिगोट क्या मानव विकास रिगोट से लिये गए हैं। आजारी मिलने के बार भारताय स्पोट खड़-18 से. टे तथा 3 से त्ये एए हैं।
$\left \infty\right $	-2.5	2 5 1 9 ^{है।} आकाती क्त
7	4 4 2 9 4 3	3.1 1.2 स लिये गाः
9	-78	61 5.3 कास तियोट
22	-5.4	2.5 2.5 1911 मानव कि
4	11.9	साम गियोर न
87	108	5.1 FI fava. fa
2	-75	7.6 निश्य शंक स
जी. जप में)	म में	भीन सक्
की जी एफ. डी. प्रतिशत के रूप में)	ख 1998 केद्रीय सरकार का पूँजीगत व्यय (जी.डी पी. के प्रतिशत के रूप मे) क 1990	कि निवास अप विदेश मुख्या है ते निवंस
सरकार की पी के प्रति	(朝代 新) (新) (新) (新)	नेमक अध्यक्त में के लिए उ
23. कंद्रीय सरकार (जी डी पी के। क. 1990	ख 1998 24 केब्रीय सरकार व (जी.डी पी. के प क 1990	ख 1998 रेजी के गुलमा हर्मां के प्रत्य
23.	24	1

* भारतीय अर्थनीति *

परिशिष्ट 2 सामाजिक आर्थिक सकेतक तथा उनकी व्याख्या

	सृचकांक प्रकार	यह सूचकांक किस नध्य के बारे में आकलन
		करता है तथा उसका अनुमान क्या रहा?
1	प्रौद्योगिकी सृचकांक	ऑकडों तथा सर्वेक्षणों के नतीजों की जॉच के
		आधार पर यह किसी देश में प्रौद्योगिकी के
		स्तर का पता लगाता है। इसके अंतर्गत देश-
		विशेष द्वाग आविष्कारो में सिक्रयता तथा विदेश
		से प्रौद्योगिकी-आयात पर भी विचार किया जाता
		है।
2	स्टार्ट-अप मृचकांक	यह भी प्राप्त आँकड़ों तथा सर्वेक्षणों के नतीजों
		पर आधारित है। यह व्यापार के लिए अनुकूल
		परिस्थितियो की माप करता है।
3	आर्थिक रचनात्मकता	आर्थिक तोर पर प्रभावी आविष्कारों तथा
	मृत्रकांक	प्रौद्योगिकी-इस्तांतरण (प्रौद्योगिकी सूवकांक)
		की जाँच के लिए इसके अंतर्गत उपर्युक्त दोनो
		सृचकांक शामिल किए जाते हैं। पिछले दशक
		में सर्वाधिक रफ्तार से विकास करनेवाले देश
		ही सबसे अधिक रचनात्मक देशों की श्रेणी में
		शामिल रहे। हालाँकि सिंगापुर बड़ा आविष्कारक
		देश नहीं है, इसके वावजृद प्रौद्योगिकी आयात
		के कारण उसकी आर्थिक रचनात्मकता का स्तर
		काफी अधिक है।
4	विकास प्रतिस्पर्धात्मकता	इसका उद्देश्य भविष्य में अर्थव्यवस्था के
		विकास को प्रभावित करनेवाले कारकों की माप
		करना है। कुछ देश अन्य देशों की तुलना में
		अधिक तेजी से अपना समृद्धि-स्तर किस प्रकार
		बढ़ाते हैं, इसकी जाँच के लिए प्रति व्यक्ति
		जी.डी पी. में परिवर्तन की दर मापी जाती है।
		सृचकांक तैयार करते समय उत्पादकता के स्तरीं
		को प्रभावित करनेवाले तत्त्वों के अलावा

5. सक्ष्म आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता मुचकाक

6. मौजूदा प्रतिस्पर्धात्मकता

उत्पादकता में सधार, आविष्कार आदि की ऊची दरों के लिए जिम्मेदार कारको पर भी पीर किया जाता है।

इसके अंतर्गत आर्थिक विकास के स्थम आर्थिक स्तर को मापने का प्रयास किया जाता है। साथ ही, देश-विशेष की व्यापारिक फर्म जिस प्रकार के माहाल में काय करती है, उसकी भी अध्ययन किया जाता ह। उनके अनर्पवंधी का अध्ययन कर मापक्ष मुक्ष्म आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता स मंबंधित एक संगोर्जन नसवीर स्पष्ट रूप सं उधरनी है।

सभ्म आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर इस स्वकांक का तंयार किया जाना है। यह सूचकांक मोजूटा उच्च उत्पादकता और अंतत. मीजदा आर्थिक प्रदर्शन की मापना है। उसके अंतर्गत देश-विशेष की ज्यापारिक फर्मों के व्यवहार तथा उनकी रणनीतियों एव उस दश के व्यापारिक माहाल का अध्ययन किया जाता है। किसी कंपनी के प्रचारान से प्राधित आधुनिकीकरण और ग्लानीतियों को प्रदर्शन करनेवाले उपाय प्रांत व्यक्ति सकल घोल् उत्पाद (जी.डी पी) से सींख्यकीय द्रीप में यबद होते हैं। इन्हें मिलाकर उस कंपनी विशेष के प्रचालन से संबंधित उप सूचकांक तयार किया जाता है। इसी प्रकार, व्यापारिक माहील की गुणवत्ता मयलन, इनपुर की गुणवत्ता, कल-पुर्जी तथा मशीनरी के स्थानीय आपृतिकलीओं को उपलब्धता, आधुनिकीकरण के मंदर्भ में उनके स्तर आदि एवं स्थानीय मौगों के उत्तर प्रति वर्याक्त जी.डी.पी से सांग्रियकीय दीन्द्र से सबद हैं और इन्हें मिलाकर व्यापारिक माहौल

की गुणवत्ता का उप-सूचकाक तैयार किया जाता है। उक्त दोनों उप-सूचकाकों को मिलाने पर मौजूदा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक प्राप्त होता है।

7. मानव विकास सूचकाक

यह एक संयोजित सूचकांक के अंतर्गत आधारभूत मानव-विकास की औसत उपलब्धियों की माप करता है। यह तीन संकेतको पर आधारित है—(क) लंबा जीवनकाल, जो जन्म के समय जीवन-संभाव्यता पर आधारित है, (ख) शैक्षिक प्राप्ति, जो प्रौढ साक्षरता-दर और सकल प्रार्थीमक सेकेंडरी तथा तृतीयक नामांकन अनुपात को मिलाने से प्राप्त होता है तथा (ग) जीवन-स्तर, जो पी पी पी अमेरिकी डॉलर मे प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मापा जाता है।

8. मानव गरीबी सृचकांक

विकासशील देशों के संदर्भ में (एच,पी आई -1) यह सुचकांक एच.डी.आई मे प्रतिबिबित होनेवाले मानव जीवन के तीन आवश्यक पहलओं में कमी पर केंद्रित होता है। पहली कमी उनसे संबंधित है, जिनके 40 वर्षों तक जीवित रहने की संभावना नहीं होती तथा यह प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसरी कमी निरक्षर प्रौढ़ों (पी~2) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। तीसरी कमी के अंतर्गत उन लोगों का प्रतिशत शामिल है, जिनकी पहुँच शुद्ध पेयजल तथा स्वास्थ्य-सेवाओं तक नहीं होती। सामान्य से कम वजनवाले 5 वर्ष से कम आयु (पी-3) के बच्चों का प्रतिशत भी इसमें शामिल होता है। यह सूचकांक उक्त तीनों कारकों के औसत घन (क्यूब) का घनमुल (क्यूब रूट) होता है। औद्योगिक देशों के संदर्भ में ९ पारदर्शिता या भ्रष्टाचार

 उभरते बाजारीं तक पहुँच का सुचकाक

11. मंदी संभाष्यता

12. भूमडलीकरण सूचकांक

(एच.पी आई -2) चार किमर्यों गिनाई जला ह--(क) उन लोगों का प्रतिशत, जिनक 60 वर्षे तक जीवित रहनें की संभावना नहीं हो। (मः) व्यावहारिक रूप में निरक्षर, (मः) ऐसे खेंगा का प्रतिशत, जिनकी आय गरीबी ग्या में कर हा (घ) लंबी अर्बाध की वेगेजगर्म की दर्म सूचकाक उक्त चारों कारकों के स्माधारण आसन घन के घनमूल से प्रान्त होता है।

इसके अनर्गत व्यापारिक तथा मामा चिक जीवन पर राजनीतिज्ञों और सार्वजानक अधिकारिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रभाव का अध्ययन दिया जाता है। इसके अतर्गत 10 अल्ला जल्ला सर्वेक्षणों को शामिल किया जाता है। देशा आ साफ-सुथरे देश का अधिक अंक दिए प्रति है। इसके अंतर्गत 16 संकेतकों पर आधारम बाजार के खुलेपन की मांप की जानी है, जिसमें औसत प्रशुक्क स्तरों, आयान काटा बोद्धिक सपदा अधिकारों से सर्वोध्यत निराम, निर्मन सब्सिडी, सरकारी खरीद नीतियों नथा निर्मण वाधाओं को भी शामिल किया जाता है।

यह किसी देश के अगले वर्ष मंदी के डोर में गुजरने की आशंका पर राव जानने के लिए किए गए सर्वेक्षण पर आधारित होना है। इसके तहत 0 से 7 तक अंक दिए जात हैं। आंधक अंक का अर्थ मंदी से गुजरने की अधिक आशंका को दरशाता है।

इसके अंतर्गत देशों के व्यापार तथा निवंश के लिए खुलेपन, ऋण लेने-हंतु उनकी साख नथा पर्यटन के महत्त्व और विदेशी कामियों के हस्तांतरण को शामिल किया जाना है।

कुल सब्द			59	59	58	58	53	59	54	174 174
Linie	10	21	37 6	23	7	<u>'</u>			13	91
ात्क्रीमिस्ट	6	<u>-</u>	free		N	<i>~</i>	6	,	55	3 0 95 0
किमग्रीर	8	35	23	43	42	34	30	35	38	
ाक तिस ः इ	7	26	19	33	25	26	27	74	23	
तकंकीक	9	l j	ŧ	ı	1	1		,		Q
म्नाभ्भक्शाप	40	į į	1	3)	ŧ	t	t c	53 135	
FlE	4	4 48	46		44	49	40	O		0
र ष्ट्रातम्	w .	n m	7	V 6	*	13		x r		
नारय	200	8 8 8	38		š	42	43	5, A	128	0 53 0
	1. आर्थिक रचनात्मकता सचकांक (2000)	क. प्रौद्योगिकी सूचकांक (2000)	ख स्टार्ट-अप सूचकांक (2000) 2. विकास-प्रतिसर्थात्मक मचकांक (2000)	3. मीजूदा स्पर्धात्मक सचकांक (2000)	4. सूक्ष्म आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक	(1999) ऽ पर्यावरण विनियमन व्यवस्था सूचकांक	(2000) ६ वितीय बाजार आधुनिबीकरण (1990)	चकांक (1996	वकांक (1998)	स्वकांक

* भारतीय अर्थनीति *

		7	m.	4	5	9	7	ထ	6	10	-
	ख. शिक्षा सूचकांक	0.55	0 86	0.55 086 079 044 083 088 084 097	0 44	0 83	0.88	0.84	0 97	0 94	174
	ग जीवन-संभाव्यता सूचकांक	0.63	0.63 0.87	0.75	99.0	0.81	0 47	047 079 086	980		174
Ġ.	9. मानव-गरीबी सूचकांक **	58	1	30	68	35	33	12	18	6	
20	10 मंदी संभाव्यता (जनवरी 2000)										
	(0 計7 帝 朝寺) ***	9	6.3	5.4	ś	t	63	52	52 57 46	46	
7	11. भूमंडलीकरण सूचकांक वार्षिक औसत										
	(प्रकिशत बदलाव) (1993–97)	20	20 60	7.0	ı	•	4.0	-4.5	5.0	9 9	
12.	उभरता बाजार पहुँच सूचकांक (2000) 46	46	86	37	ι	ţ	72	89	ł		
	85 विकासमील तथा 18 औधोगीकृन देशों (जिनसे उ	ममेरिका ज	भ भाषात्र भ	अमेरिका तथा जापान भी सक्द है। के लिए अलग- अलग	के लिए अ	लग- असम	-			Postplan	

^{**} वरीयता क्रम कितम अधिक होगा, अराचार या पारदर्शिता का अभाग उत्तम ही अधिक हंगा। *** यह सङ्गा कितमें अधिक होगा मही संभारयमा रतमें हो वस हेग्गे। * भारतीय अर्थनीति *

परिशिष्ट 4 विभिन्न सामाजिक आर्थिक सूचकाको के सूचना स्रोत

सूचना-स्रोत		मूचकांक का प्रकार/वरीयता
क प्राथमिक स्रोत	1.	विकास प्रतिस्पर्धात्मकता वरीयता (सयोजित
विश्व आर्थिक मच	2.	मोजूदा प्रतिस्पर्धात्मकता वरीयता
	3.	सूक्ष्म आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता
	4.	आर्थिक रचनात्मक मूचकांक
	5	प्रौद्योगिकी सूचकांक
	6	स्टार्ट-अप सूचकांक
	7	पर्यावरण विनियमन व्यवस्था
	8	वित्तीय बाजारों के आधुनिकीकरण का स्त
ट्रासपेरेसी इटरनेशनल तथा		भ्रप्टाचार बोध सूचकाक
गॉटिंगन विश्वविद्यालय		•
विश्व बैंक	1	मानव-विकास सूचकांक
		मानव-गरीबी सूचकांक
		क्रय-शक्ति साम्य वास्तविक जी.डी पी प्रा
		व्यक्ति
	4.	ढाँचागत तत्र संबंधी आँकड़े
	5	सूचना सबंधी आँकडे
	6.	बृहद् अर्थव्यवस्था परिवर्तनशीलता सबधी
	7	सामाजिक-आर्थिक संकेतक संबधी
ख. गौण स्रोत	1	मंदी-संभाव्यता
द इकॉनॉमिस्ट		भूमंडलीकरण सूचकांक में परिवर्तन
		डभरता बाजार-पहुँच सूचकांक
		उभरता बाजार सूचीबद्धता
ग. अन्य स्रोत		
एस शिवा सुब्रह्मण्यन (1998)		स्वतत्रता पूर्व संबंधी सूचना
'ट्वेंटिएथ सेंचुरी इकॉनॉमिक		w a
परफारमेंस ऑफ इंडिया'		

सूचना स्रोत

सूचकाक का प्रकार वरायता

विष्व वैक (2000) इंडिया रिड्यूसिंग पावरटी,	 शासन वर्गयना गरीबी पर नेशनल संपल सर्वे शत्म एक क्या 	. 1
एक्सलरेटिंग डेवलपमेंट'	•	
भारतीय रिजर्व वैंक (1997) की विविध रिपोर्ट खड-18. स -2 तथा 3	सन् 1950 में 1990 है दागन भागी अर्थव्यवस्था एवर्ध मुचन	7
भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण (1999~2000)	मन् 1950 में 1990 के होराव माम्नीः अर्थव्यवस्था मनंभी भन्नन	7

भारत में उभरती आर्थिक चुनौतियाँ

-विजय केलकर

जूदा आर्थिक चुनौतियाँ

पिछले कुछ वर्षों के दोरान विश्व अर्थव्यवस्था में, विशेषकर एशियाई क्षेत्र में आए भारी तुफान के बावजुद भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी हुई है। वास्तव में, सन् 1998 में तो भारत ने दनिया के अन्य देशों के मुकाबले सर्वाधिक विकास-दर दर्ज कराई और इस वर्ष भी विकास-दर पिछले साल की तुलना में अधिक रहने की संभावना है। इसी प्रकार बृहद् अर्थव्यवस्था से जुड़े संकेतकों, जैसे--मुद्रास्फीति तथा विनियम-दर स्थिरता के लिहाज से भी हाल के वर्षों मे भारतीय अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन रहा है। वर्तमान में मुद्रास्फीति दर 4 प्रतिशत से कम है और विनिमय-दर भी अपेक्षाकृत कम है। वस्तुत: इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि नब्बे के दशक के दौरान देश की विकास-दर में कुछ तेजी आई है, लेकिन कुछ कमजोरियाँ भी हैं। गरीबी को शीघ्र दर करने के लक्ष्य को हायिल करने के लिए इन्हें दूर करना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य में विचार करने तथा आवश्यक नीतिगत सुधार और प्रयास शुरू करने की जरूरत है। भारत के आर्थिक इतिहास पर नजर डालें तो यह स्पष्ट है कि हमारी आजादी ने इसके प्रवाह की निरंतरता को प्रभावित किया है। आजादी पाने के बाद से ही देश ने औपनिवेशिक युग की मंदी और आर्थिक पिछडेपन से निजात पाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमें पं. जवाहरताल नेहरू के नेतृत्व में कई प्रतिभावान नेताओं का मार्गदर्शन मिला। विश्व को लेकर उनकी निश्चित समझ तथा संतुलित दृष्टि रही। हमारा लक्ष्य ऐसी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था तैयार करना था, जो अतरराष्ट्रीय पुँजीवादी दबावों से मुक्त होकर काम कर सके। इस दृष्टिकोण से हमारे नेताओं की

आकाक्षाएँ सुस्पाट थीं—वे यथाशीव्र गरीबी ये मुक्ति पाने के निर्मातिर्गात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कायम करना चाहतं थे। उद्यमी वर्ग का कमलोरयों तथा सुचारु रूप से कार्य करनेवाले पूँजी-याजारों के अभाव के चत्ते सरकार का पूँजी जुटाने के कार्य मे तेजी लाने का दायित्व सीपा गया। मण्य ही, भाग तथा बुनियादी उद्योगों की स्थापना की जिस्मेदार्ग भी सरकार का दी गई। यती हतन सार्वजनिक क्षेत्र ही औद्योगीकरण का अगुवा बन गया।

इस नीति से यह लाभ हुआ कि विकास-दर में तेजी आई गामाजिक औद्योगिक ढाँचागत विस्तार हुआ, रक्षा उत्पादन तथा अल्पार्शनिक ग्वंग्यम्परिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण परमाणु और अतिरक्ष क्षेत्रों का प्राद्यांगकीय आन्तर सजदन हुआ।

इस नीति को लागू करने की दिशा में शीघ ही एक बड़ी पंशानी कृषि श्राप्त में हमारी नाकामी के रूप में मामने आई जिसके परिणामण्यस्य पी एहा. 480 खाद्यान्न-आगत पर हमारी निर्भगता हो गई, लेकिन श्रीमती टीटर गांधी ने हरित क्रोंनि के जरिये इस नाजुक कमजोगी पर काकृ प्राप्ता, तांकि देश स्वाद्यान्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बन संके।

ये तमाम उपलब्धियाँ इस लिहाज से भी ऐतिहासिक हैं कि नोव नी उद शागन प्रणाली के अंतर्गत विना औपनिवेशिक गोषण पक्रिया से ओर वनसंस्था विस्फोट की चुनौतियों का सामना करते हुए इन्हें हामिल किया गया। ये उपलब्धियाँ हमारे ऐतिहासिक मापदंडों की दृष्टि स उज्लेखनीय हैं, रात् एशियाई देशो, जैसे-चीन, जापान, कोरिया आदि की समकानीन अर्थव्यवस्थाओं की उपलब्धियों की तुलना में यक्तीनन ऋफ्तं कर है। स्वत्यक्त प्राप्ति के समय भारत की प्रति व्यक्ति आय का स्तर चीन तथा कीरिया के समान ही था, लेकिन उसके बाद इस दृष्टि से ये दोनों ही देश भागत को आफी पीछे छोड चुके हैं। यहाँ तक कि भूमडलीय व्यापार तथा उत्पादन के क्षेत्र मं भी विषय-अर्थव्यवस्था में इन दोनों देशों की हिस्सेदारी हमसे कहीं आंधक है। कोरिया की प्रति व्यक्ति आय 10,550 अमेरिकी डॉलर है जर्माक भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 390 अमेरिकी डॉलर ही है। इसी प्रकार चीन का सकल घरेलू उत्पाद (जी डी.पी) सन् 1997 में 825 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो हमसे दोगुना है। चीन ने पिछले दो दशकों के दौरान 7 प्रतिशन प्रतिवर्ष से अधिक को निरतर विकास-दर के जरिये इसे हामिल किया है। इसी प्रकार दक्षिण एशिया की अन्य चामत्कारिक अर्थव्यवस्थाओं की प्रति

व्यक्ति आय भी पिछले तीन दशकों से भी अधिक समय से हमसे दो-तीन गुना दर्ज की गई है। मानव-विकास सूचकाक के लिहाज से भी इन अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना करने पर हम पिछड़े हुए है। हालाँकि जीवन संभाव्यता तथा अन्य संकेतकों को दृष्टि से हमारी स्थिति में सुधार आया है, लेकिन मानव-विकास सूचकांक को देखते हुए इम इन देशों की गतिशील अर्थव्यवस्था से काफी पीछे ही हैं। इसी प्रकार, जहाँ एक आर इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने गरीबी पर कावृ पाने की दिशा में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया हे, वहीं भागत में दुनिया भर में सबसे अधिक गरीब मौजूद हैं।

इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय तलनात्मक अध्ययन का एक और रोचक तथ्य यह है कि प्रति व्यक्ति आय या मानव-विकास सुचकाक के आधार पर तय जीवन-स्तरों के लिहाज से भारत भले ही पिछडा हुआ है, लेकिन इक्विटी संबंधी सकेतकों, जैसे-'गिनी सुचकांक', जिसके अंतर्गत आय का वितरण तथा अर्थव्यवस्था की खपत शामिल की जाती है, के आधार पर भारत का स्थान दम उच्च विकासशील देशों मे शामिल है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट (सन् 1998) के अनुसार हमारी खपत-वितरण अमेरिकी और अन्य विकसित देशों में आय-वितरण की तुलना में कम न्यायसंगत है। हाल में योजना आयोग के सदस्य प्रो हाशिम के प्रकाशित अध्ययन में भी यही कहा गया है कि 'गिनी मुचकांक' में पिछली योजनाओ की तुलना में भारत का मुधार कम ही सही, मगर हुआ है। खपत-वितरण के उपलब्ध आँकड़ी की गुणवना के मद्देनजर इतना तो कहा ही जा सकता है कि वितरण की स्थिति बिगडी नहीं है। यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि हमारे कई वामपेथी विश्लेषको की गय में भारत आय में असमानता से सबसे अधिक शिकार हुआ है। यह स्थिति लगानार बिगड़ रही है, परंतु उपलब्ध ऑकडे इसका समर्थन नहीं करते। इसी से हमें अपनी आर्थिक समस्या का मूल कारण समझ में आता है। दरअसल, गरीकों के अभिशाप का कारण हमारी प्रति व्यक्ति आय की कमा होना है, जो अपेक्षाकृत कम विकास-दर के कारण है। दूसरे शब्दों में, भारत के सामने हर क्षेत्र में कम उत्पादकता तथा उत्पादकता की कम विकास-दर की समस्या है। देश में निरंतर बनी रही भयंकर गरीबी का मुल कारण भी यही है।

अब महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस स्थिति में हम कैसे पहुँचे, जबकि विकास-प्रक्रिया ने हमारी कम बचतवाली अर्थव्यवस्था को चमत्कारिक ढंग

से उच्च-बचत/उच्च-निवेश अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। हमारी पिछले 50 वर्षों की योजनाओं के दौरान बचत तथा निवेश का ऑकरा सन् 1951-52 में क्रमश. 10.4 प्रतिशत तथा 10.2 प्रतिशत रहने के वावजृद आटर्का योजना के अंत तक दोगुने से भी अधिक बढ़कर 23.1 प्रतिशन और 24.8 प्रतिशत तक जा पहुँचा। दूसरे शब्दों में कहा जा मकता है कि यहे निवंश करने के लिए भारतीयों ने काफी त्याग किया है। परंतृ दम निवंश में यापमी की कुल दर इतनी नहीं बढ़ मकी कि वह गितशील विकामशील अर्थव्यवस्था औ से टक्कर ले सके या गरीबी-उन्मूलन के लिए संसाधन उपलब्ध करा मके।

9. कम उत्पादकता तथा कम विकास के रूप में पैदा हुए इन अनगेपाना के निग अनेक काम जिम्मेदार हैं। यहली महत्त्वपूर्ण कमी अंतरगान्य ज्यापार का अनदेखी रही। इस अनदेखी के चलते हम उत्पादकता बढ़ानेपानी विनम्य सभावनाओं से हाथ धो बैठे। जहाँ तक निर्माण क्षेत्र का सन्ताल है, हमने व्यावसायिक वाहन से लेकर स्टील मिल तक सभी कुछ उत्पादक शृधाना के तहत उत्पादित करने की नीति अपनाई। इसका परिणाम यह मुंआ कि शत्मां कमजोर कड़ी ही पूरी उत्पादन-शृंखला की मजबूती नय करने का आधार बन गई। हमने अनेक प्रकार की गतिबिधियों के क्षेत्रों से जुड़े उत्पादन में हाथ डाला, हालाँकि हम इनमें से कई अन्यों के मुकाबले पांतयांगिना में टिकने की स्थिति में नहीं थे। उदाहरण के लिए, भारतीय उद्यंक उद्योग की भारतीय उत्पेरक ही इस्तेमाल करने के लिए सजबूर करने से एं उत्थंक अद्योग की नुकसान पहुँचा। यही हाल इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का रहा, जहाँ घोल के क्यूरर हाईवेयर के इस्तेमाल को लेकर की गई जिद के चलते मांपरवंबर उद्योग की स्थापित होने में समय लगा।

इन उदाहरणों से यह स्मष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अपने समाभनों के कुशल इस्तेमाल की इजाजत न देकर स्वयं के उत्पादन क्षेत्र के याथ रामने जबरदस्ती की। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं पर ही ध्यान केद्रित रखने की अपनी नीति के कारण हमने उन उभरते गांतणील क्षेत्रों के रूप मे बनी किंद्यों की उपेक्षा की जिनमें जापान सिहत कई पूर्जी एशियाई देश शामिल हैं। तेजी से विकास कर रहे जापान से जिन्द हमते अपने बाहरी व्यापार का नाता जोड़ा होता तो देश के समूचे विकास की अलग तसवीर हमारे सामने होती।

0 इसी प्रकार कृषि-क्षेत्र की भी कुछ हद तक अधिक ठपेश्वा हुई है। नोबेश

पुरस्कार विजता अर्थशास्त्री प्रो ऑर्थर लुइंस ने स्पष्ट किया है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता ही आर्थिक विकास के लाभ सुनिश्चित करती हैं। हमने न सिर्फ कृषि में निवेश, सिंचाई आदि सबद्ध पक्षों को नजरअदाज किया, बिल्क व्यापार की शर्ती की भी कृषि के विपरीत निर्धारित किया। इस मामले में किसान नेता श्री शरद जोशी के इस तर्क में वजन है कि भारत के कृषि-क्षेत्र को नियंत्रणों के वर्तमान दौर से मुक्त करना चाहिए। दरअमल, हम मृल्यवर्धित कृषि के जरिये रोजगार के अवसर बढ़ाने की संभावनाओं से भी चृक गए। इस अनदेखी का गहरा असर विकास-प्रक्रिया पर भी पड़ा। प्रो सुखमय चौधरी ने दरशाया है कि किस प्रकार खाद्यान्त अर्थव्यवस्था के मोरचे पर नाकामी के कारण अंततः विकास-दर धीमी पड़ी है।

हमारे सार्वजिनक क्षेत्रों की कार्य-प्रणाली भी हमारी कमजीरियों का बड़ा कारण बनी है। सार्वजिनक क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करते समय हमने प्रोत्साहनों की भृमिका को नजरअंदाज किया, विशेषकर प्रबंधन तथा नौकरशाही को दिए जानेवाले प्रोत्साहनों को, जिनके जिरये शेयर-धारकों की रक्षम तथा राष्ट्रीय धन को अधिकतम किया जा सकता है। शायद हमारे कानृनी तंत्र ने भी मार्वजिनक क्षेत्र को सरकार का विस्तार मानकर इस समस्या को और अधिक बढ़ाया है। इससे मार्वजिनक क्षेत्रों को जीखिम उठाने की क्षमता का ह्रास हुआ, जो दरअसल किसो भी उद्यमी का प्रमुख गुण माना जाता है। नतीजतन पूँजी जुटाने के मुख्य लक्ष्य को लेकर स्थापित सार्वजिनक उद्यम वास्तविकता में हमारे राजकोषीय संसाधनों पर भारी पड़ने लगे।

लंबी अवधि की विकास-दर पर प्रतिकृत असर डालनेवाला एक और स्रोत मौजूद है। यह है रिआयतें, और फिर रिआयतों पर रिआयतें। इस क्षेत्र में भारी विकास हुआ है। सन् 1971 के बजट में उपलब्ध कुल रिआयतें जी डी पी का 3 प्रतिशत थीं और महज दो दशकों में ही ये चार गुना बढ़कर 12 प्रतिशत तक हो गई। हाल में हुए शोध के अनुसार इन रिआयतों का आँकड़ा जी.डी.पी. का 16 प्रतिशत तक जा पहुँचा है। हालाँकि सभी रिआयतों गलत नहीं कही जा सकतीं; कुछ तो वास्तव मे उपयोगी भी होती हैं। ऐसी रिआयतें भी हैं, जहाँ सामाजिक लाभ सामाजिक कीमतो की तुलना में अधिक हैं, लेकिन इस प्रकार की रिआयतें कुछ रिआयतों के एक-तिहाई अश से भी कम हैं। केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारे सीधे बजट में इनका प्रावधान करती हैं या फिर राजकोणीय घाटे के रूप में इनको ब्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार अपनी कार्यक्षमता से

अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन करनेवाले मार्वजनिक क्षेत्रों के लिए विशायन मान्य हैं। सन् 1950-1997 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों में स्टॉक लियेण व्यक्ति श लाख करोड़ तक जा पहुँचा। यह आँकड़ा दरअसत किताली मान्य एए आधारित है। वास्तव में इन स्टॉक्स का मूल्य कहीं अधिक है, लेकिन उनार ध्रम नाएमा को दर 3 प्रतिशत से भी कम है। यदि ये उद्यम भी क्रणल उनामी की भान प्रदर्शन करते तो वापसी की यह दर दो गुना या तीन गूना अधिक र ती वार अतर भी वास्तव में एक तरह की रिआयत ही है, जिसका नुगायन भाग कर दर दो ही करता है।

- ३. यदि ये रिआयते गरोबों को दी जा रही होती तो शायद कवाय करने आरवन रहता। दरअसल, इन रिआयतों का अधिकाश उन लोगा तक पर्तं व ए रे ए उतने गरीब नहीं है। यहाँ तक कि उर्वरक या खाशान एक पर्वं का ए यहां हाल है। इनका लाभ ग्रामीण गरीबों को नहीं मिलना। सन्न तो यह है कि, उत्तर हमारे सामने भारतीय राजनीति का एक नया मुहाबश सामने आ रहा है है विस्तर रिआयतें विकास की गति की राह में श्वाबट अन गई है।
- 1. प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध रिआयतें तो खराब हैं ही, एरक्ष में ये में में नेकानी रिआयतें और भी ज्यादा नुकमान कर रही हैं। बजर में उनका पानधार पार्ट होने के कारण ये अपारदर्शी हैं। इनके कारण सपार कई एम्स उन्होंगे की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में नुकयान उठाना पड़ा है; बिजर्स, मेंन प्रतिस्पर्ध में नुकयान उठाना पड़ा है; बिजर्स, मेंन प्रतिस्पर्ध में नुकयान उठाना पड़ा है; बिजर्स, मेंन प्रतिस्पर प्रदेश प्रतिस्पर्धा में नुकयान उठाना पड़ा है; बिजर्स, मेंन प्रतिस्पर में हैं लिख प्रताप का नक्ष्मा अन्य कई क्षेत्रों में रिआयनों का नक्ष्मान स्पार का में देखा जा सकता है। ऐसा महसूस क्रिया प्रया है कि अन्या अन्या की उपभोक्ताओं से अलग-अलग कीमते वसूतने से सामाजिक न्याय की नश्य प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह दुर्भाग्य में के दमका परिणाम एकदम उलटा हुआ है। कृषि क्षेत्र को मुप्त बिजर्मी देने के कारण में निर्ण माँग क्षेत्र में बिजरनी के कुशल प्रयोगकर्ता को प्रोत्माहन से बीनत किया निर्ण माँग क्षेत्र में बी इससे वितरण-गुणवता में गिराबट आई। बाजा अर्थव्यवस्था में या तो मूल्य निश्चित किया जा सकता है या फिर गांत्रा तय, परंतु इन दोनों को लंबे समय के लिए निर्धारत नहीं किया जा सकता है या किया जा सकता के ता किसानों के लिए बिजली की आपृति क्षक स्वत्का का काती है. जिससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

औद्योगिक क्षेत्र पर तो इसका और भी प्रतिकृत असर पन्ता है। इस क्षेत्र के लिए बिजली का शुल्क कृषि या घंग्नू क्षेत्रों को तूलना में कई गृना ऑधक ह का भता स अधिक असू न को यह घटना कवल भाग्त में ही देखी जा सकता ह रमय रमण आद्योगिक शत्रा की प्रतिस्पिधात्मकता पर विपरीत अगर पड़ा है, जिसक काण्ण तिर्यात तथा रोजगार के क्षेत्रों में विकास कमजोर हुआ है। इसी प्रकार रेलवे में भी माल-भाड़े के रिआयती यात्री किराए की नृतना में यहां अधिक नय किया गया है। इससे संसाधनों के कुशल इस्तेमाल नथा अंग्यानीय प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर पड़ा है। टेलीफोन शुल्क में हाल में किए एए सुधारों में पहले तक दूरमंचार के क्षेत्र में भी कमोबेश यही रिथित बनी हुई थी।

भारत के विकास पर सबसे अधिक बोल सरकारी खर्चों का है। इसका कारण सरकार का आकार तथा सरकारी अर्थ-सरकारी सगउनों के कर्मचारियों पर होनेवाला खर्म है। एक के बाद एक आए बेतन आयोगों ने कर्मचारियों के देय बेतन में हमेशा चृद्धि की है, जबकि सरकार की भुगतान-क्षमता या फिर इन कार्मयों द्वाग की गई आयूर्ति की गुणवत्ता का खयाल कभी नहीं किया गया। पिछले दिनों बेतन आयोग द्वारा दिए गए फैसले से सरकारी खर्च में जी.डी.पी. के 2 प्रांतशत के बगबर गांश की वृद्धि होने की संभावना है। दरअसल, यह नेतन वृद्धि ही केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के लिए राजकोषीय दबाव का कारण बनी है।

वहने राजस्य तथा राजकांपीय यांट के चलते सरकार द्वारा बाजारों से अधिक ऋण लिया जाता है। इस प्रकार निजी क्षेत्र का निवेश लगातार सिकुड़ता जा रहा है और ब्याज-दर भी बढ़ रही है। वर्तमान में निजी वित्तीय बचत का लगभग 80 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रों में ऋण के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। नतींजतन हमारे सामने नए नोट छापकर मुद्रास्फीति की अधिक दर या अधिक ब्याज-दर में से एक को चुनने का हानिकर विकल्प ही बचा है, जिससे निवेश तथा राजगार विकास के रास्ते बंद होते हैं। इन सबकी अंतिम परिणित विकास-दर में कमी के रूप में होती है। दरअसल, देश की समृद्धि के लिए इस प्रक्रिया को उलटने की जरूरन है।

अब नए दौर के सुधार लागू करने का समय आ गया है। सन् 1991 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव तथा वित्त मन्नी डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए पहले छरण के सुधार दरअसल संकट से प्रेरित थे। अब हम सर्वसम्मति से सुधार लागू कर सकते हैं, ताकि हम किसी भी संकट की स्थिति में उनसे निपटने की कार्यवाही समय रहते कर सकें।

- 19 सर्वप्रथम राजकोषीय सुधार सुनिश्चित कान की दिशा में त्रांगामक ग्यार करने होंगे। ससद् को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधयक उत्तान, चाणिए, ताकि राजस्व और बजट घाटे को सीमित कर अर्थव्यवस्था को ऋण जान में कँमने से बचाया जा सके। कई देशों में इस प्रकार की व्यवस्था को गई है। उक्त विधेयक पारित कर देने से ही राजकोषीय संतृत्तन प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों को विजनी, पानी, पारवहन आदि के प्रयोग-शुल्क में बढोतरी करनी होगी, नाकि निवेश बदाने के तिर संग्यान तैयार हो सके और साथ ही इन सेवाओं में भी सुभार नाया जा सके। य उपाय इन क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रेरित करेंगे, उपभोक्नाओं के लिए खन में कमी लाएँगे तथा प्रतिस्पर्धा को बढावा देकर गुणवान में सुधार हो सीनिश्चन करेंगे।
 - करगा
 इस दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण मुधार मरकार की भूमिका को ना मिर्ग में परिभाषित करने तथा उसका आकार घटान को लेकर किया जा सकता है। सरकार का आकार कम करने का अर्थ पामिक दृष्टि से कम महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का, जिसमें बेकिंग क्षेत्र भी शामिक दे नितंकरण है। सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों मे परमाण ऊर्जा, अंतरिक्ष तथा रक्षा-उत्पादन से जुड़े उद्यम शामिल है। मरकारी तंज के पूर्णाठक के इस कार्यक्रम के तहत सरकार को शिक्षा, रखाख्य और पर्यावरण स्पृथ्धा के क्षेत्र मे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा सरकार को पारदांणता बढाने तथा अच्छा शासन-तंत्र देने की भी पहल करनी होगी।

संसद् को सरकार को आकार-संबंधी नीतियो तथा माकार । अर्थ सरकार एजेसियों से जुड़े कर्मचारियों को देय वेतन मबधी सिद्धात की ममीक्षा करनी होगी। इस प्रकार के प्रयासों से ही राज्य तथा केंद्र की गायकोंग्य मिथान में सुधार सुनिश्चित कर करदाता के धन का सद्दायोंग हो सकता है।

सरकार की भूमिका में सुधार करने पर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रवंशन के लिए नया संस्थागत वाम्तुकार तैयार करना होगा। इस प्रकार पूर्णत आर्थ्यवस्था की पहचान कर हम उस राह पर हैं, अहाँ नीतगत स्थिरता, पारदर्शिता तथा पूर्व आकलन करना काफी महत्त्वपूर्ण है। इस नई व्यवस्था में अमेरिका के फेडरल रिजर्व या बिटन के 'बैक ऑफ इंग्लंड' की

तर्ज पर भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक आजादी देकर नए स्वतंत्र मौद्रिक प्राधिकरण का गठन करना होगा। नए सम्थागत प्राम्त्कार के बनने पर स्वतंत्र नियमन एर्जेसियों, जैस—सेबा ट्राई, मी ई आर मी आदि को भी मजबूत बनाना होगा तथा इनके स्वतंत्र अम्तित्व को स्वतंत्र न्याय व्यवस्था के समकक्ष मानना होगा। ऐसा करने से निवंशको तथा उपभाक्ताओं में विश्वाम बढेगा और इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को भी बढावा मि नेगा।

गजकोपीय मुधार म कम तथा आधिक अवधि की वास्तविक व्याज-दरों में कमी आएगी। वतमान में ये 6-8 प्रतिशत के अभृतपूर्व स्तर पर बनी हुई है। द्वित्या क किसी भी देश में इतनी केंची व्याज-दरों के रहते टिकाऊ विकास-दर की हामिल नहां किया गया है। वास्तविक ब्याज-दरों को 3-5 प्रतिशत के आम पास लाने पर ही अथंव्यवस्था के मभी गक्षों में चमत्कारी विकास देखा जा सकता है।

सुधारों का प्रमुख नन्त उत्पाद बाजारों नथा सेवा-क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और मुक्त प्रवेश एवं अनग्रान्टीय व्यापार को मुक्त करना है। इसका सीधा अर्थ प्रभी की, अध्यत निजी तथा सार्वजनिक उपक्रमों को प्रतियोगिता के समान अध्यस राय नटा करना है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें शृत्क बाधा को दूर करन से संबंधित नीतिगत सुधार लागू करने होंगे। वर्तमान में भारत का शृन्ध दरे विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक हैं। जहाँ एक और एएएया की एनिशील अथव्यवस्थाओं का यह औसत लगभग 5 प्रतिशत है को भारत में नजी लानी होंगी, ताकि शृत्क-दरों को एशियाई स्तर तक घटाया हा सके।

हमां प्रकार गर एक्क बाधाओं को दूर करना भी बेहद महत्त्वपूर्ण है। इसके तहत न्यभाका तथा कृषि उत्पादों पर से शीध ही आपत नियंत्रण हटाने होगे तथा ध्रम् क्षंत्र का अगर्थण खत्म करना होगा, क्योंकि यह क्षेत्र देश को यन बनाए गर्थों, रामधः, खिलौंने आदि श्रम-आधारित उत्पादों के निर्यात मे तेजी से आगं बढ़ने से लेक रहा है। आग्रधण का अथ उन उत्पादों का स्तर कम रखना है, भें अंतरगदाय सापदंद्री की कसीती पर खरे नहीं उतरते। अंतरराष्ट्रीय बाजर पर करना करन के लिए 'गुणवत्ता' तथा 'समय पर आपृति' काफी महत्त्वपूर्ण है। ए अग्रन, गैर शुल्क बाजाओं में 50 प्रतिशत की कभी से देश की जो दो भें का 1,5 प्रांत्रणन लाभ होगा। यह लाभ हर वर्ष जुड़ता रहेगा, यानी रोजगार के अतरगर बढ़ेगे। इसी प्रकार आतरिक उदारोकरण से, जिसमे उन सार्वजिनक क्षत्रों का निजीकरण भी शामिल होगा, जो मध्यवनी वस्तृणं तथा सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं तो हम देखेंगे कि चमन्कारिक डंग में लार मिलेगा। अमेरिका के पिछले 20 वर्षों के अनुभवों को ही देखें, जहाँ विजनी प्राकृतिक गैस उद्योग, एयरलाइंस, सडक परिवहन, रेल परिवहन इत्यांत क्षेत्रा में उदारीकरण के बाद इन क्षेत्रों में जी.डी.पों के 10-15 प्रांतणन नक लाग बढ़ा है। अन्य देशों के अनुभव भी ऐसे ही गहे है। एक अध्ययन में पन चला है कि अर्थव्यवस्था को जी डी पी के 3.4 प्रतिशत तक अगिंग्कन लाभ पत्य सकता है। दरअसल, ये लाभ अर्थव्यवस्था की पराने से मीजृद अमरण क आधार पर ही प्राप्त होंगे। इनके लिए किमी नए भोतिक निवेण या नई एंगा की आधारयकता नहीं है।

5. सुधारों के अगले दौर में कारक बाजारों को भी गापिल करना चर्नहरू। यन 1991 के सुधारों के तहत औद्योगिक लाहमें मिग तथा आयात अवरोधक हटाकर उत्पाद बाजारों के सुधार पर अधिक जार दिया गया था। उस ऋएण श्रम-बाजार, भृमि-बाजार, पूँजी-बाजार, प्राकृतिक संसाधन वाजार वर्गट स्र्वाच्यु कारक बाजारों पर कोई थ्यान नहीं दिया गया। ध्रम बाजागं में मुधार विजेप रूप से महत्त्वपूर्ण है। दरअसल, नई आंद्योगिक क्रांति के बाद के दी। में यसी गतिविधियों में लचीलेपन की जरूरत है। इसका मतलब यह हुआ दि अम बाजारों में लचीलापन आवश्यक है, ताकि कर्पानयां बाजारां की चटानना परिस्थितियों के मुताबिक स्वय को ढाल सके। इन सुभारों के अंतर्गत विनीय बाजारों में भी सुधार जरूरी हैं। इनके तहत महाराष्ट्र की राजगार गारटी योजना की तरह अन्य कई सामाजिक सुरक्षा-तंत्र भी विकस्तित करने होंग। अब समय आ गया है कि उत्पाद-आधारित रिशायतों, जैसे--खाद्यान रिश्रायतों को समाप्त किया जाए तथा इक्विटी में मुधार के स्तिए इसके स्थान पर नकारात्मक आयकर को लाया जाए। इसके साथ ही कार्यकृशनता पर प्रतिकृत असर को भी नियंत्रित रखना होगा। इस प्रकार के नीतिगत उपकरणी में परिणामकारी बदलाव के लिए खाद्यान टिकटों और शिक्षा वाउ वरों के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, ताकि सामाजिक तौर पर पिछड़े और कमजोर नगीं की आवश्यकताएँ पूरी की जा सके। इस नई व्यवस्था में यह माना गया है कि सरकार वित्तपोषक तो हो सकती है, परंतु जरूरी नहीं कि वह इन सेवाओं की उत्पादक भी हो। विभिन्न देशों के विभिन्न चरणों के अनुभव यही साबिन करते हैं कि समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा या मानव- पूँजी

ही सर्वाधिक सफल ह।

प्रथम दौर के सुधार-कार्यक्रम केंद्र के स्तर पर लागू किए गए थे, जबिक अगले दौर के सुधार-कार्यक्रमों को हमारे राज्यों के स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। दरअसल, हमारे राजस्व तथा राजकोषीय घाटे का लगभग 40 प्रतिशत राज्यों के वित्त से सबधित होता है। इनमें सुधार अपेक्षित है। इसी प्रकार सेवाओं के वितरण में भी मुधार की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बुनियादी सेवाएँ राज्यों के स्तर पर हो वितरित की जाती हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी रचनात्मक पहल हुई है। दरअसल, जनता भी अब 'अंतरराष्ट्रीय मोच और स्थानीय पहल' के मुहाबरे को महत्त्व देने लगी है, जिसके चलते विभिन्न प्रादेशिक सरकारों में उद्योगों, विशेषकर सृचना प्रौद्योगिकी जैसे उद्योग को बेहतर सेवाएँ देने की होड़ लग गई है, क्योंकि इसमें भारत की तसवीर बदल देने की भरपर क्षमता है।

नए दौर के सुधार-कार्यक्रमों में अधिक उत्साह तथा तात्कालिकता की जरूरत है। इसका कारण यह है कि हम जनसंख्या की दृष्टि से विशेष संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहे हैं। अगले कुछ दशकों में जनमंख्या की दृष्टि से भारत की विशिष्ट संरचना होगी और पहली बार ऐसा मौका होगा, जब इसके पास विश्व की सबसे अधिक आबादी होगी। जाहिर हे कि इन दशकों के बाद बुढ़ापे की प्रक्रिया में तेजी और कामकाजी आवादी की सामर्थ्य में कमी आएगी। जिस प्रकार अपनी कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलने के लिए तेज गति की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था को भी गरीबी के चंगुल से मुक्त होने के लिए अगले दो दशकों के दौरान दो अंकोंवाली विकास-दर को आवश्यकता है।

जिस प्रकार अन्य वामत्कारिक अर्थव्यवस्थाओं ने इतनी उच्च विकास-दर प्राप्त की है, उसी प्रकार हमें भी कामकाजी आबादी के अधिकतम अंश की मदद से उच्च बचत तथा निवेश-दर कायम रखते हुए श्रम आपृर्ति एवं उत्पादकता बढ़ाकर इस लक्ष्य को संभव बनाना है।

नई शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था दोराहे पर खड़ी है। उसके पास परिस्थितियों को जस-का-तस रखने का विकल्प है, जिसके अनुसार निरंतर गरीबी और कम विकास-दर की स्थिति को कायम रखा जा सकता है या फिर सुधारों की गति बढाकर हम समृद्धि को राह पर भी बढ सकते हैं इस गह पर च नत नर सन् 2020 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,000 डग्लर या 50 000 स्पर स् अधिक हो सकती है। परिणामस्वरूप देश से गरीबी और निरक्षरता का स्पष्ट हो जाएगा तथा जीवन संभाव्यता में भी लगभग 10 वर्ष की, श्रिक्ष हो सकंगा और तब भारत 'आर्थिक सुपर पॉवर' कहलाएगा। फिलहाल मन्त्र किन्म सूचकाक की दृष्टि से हमारी गिनती निचले पायदान पर खंडे 20 देशों में रात है। सन् 2020 में हम ऊपरी 10 पायदानों पर खंडे देशों में गिने उह सक्म निस्संदेह यह सब संभव है, मगर इसके लिए हमें सर्वसम्मान ये लीग्न म सुधारों को अपनाना होगा।

गर्थिक सुधार: भविष्य के लिए नीतिगत एजेंडा

—मोंटेक एस. अहलवालिया

. कुछ सकारात्मक विशेषताएँ

अर्थव्यवस्थाओं में से एक रही।

मौजूदा किमयो तथा उपलब्धियों को ध्यान में रखकर भविष्य के लिए तिगत एजेडा तैयार करना चाहिए। यह स्वाभाविक ही है कि इस विषय पर उचार-विमर्श की सार्वजनिक प्रक्रिया के दौरान अकसर नकारात्मकता पर ज्यादा

ोर दिया जाता है, जो हतोत्साहित करता है; लेकिन सच तो यह है कि नई सदी में वेश करते समय हमारे पास कुछ महत्त्वपूर्ण मजबूत पहलू भी हैं। वे हैं—

क विकास की दृष्टि से हमारा प्रदर्शन अब पहले के मुकाबले काफी बेहतर हैं। आजादी के बाद पहले तीन दशको के दौरान विकास-दर मात्र 3.5 से 4 प्रतिशत ही रही थी। अस्सी के दशक मे भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) 5.8 प्रतिशत की औमत दर से बढा है। आठवी योजना के दौरान (1992-93 से 1996-97 तक) यह 67 प्रतिशत तक बढ़ा तथा नौवीं योजना मे भी यह स्तर बने रहने की

सभावना है। इससे लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था नई नीतियों के अनुसार खुद को ढाल रही है। आमतौर पर इस तथ्य को महसूस नहीं किया जाता कि अस्सी तथा नब्बे के दशकों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से विकास करनेवाली दुनिया की शुरू की 10

ख हमारी जनसंख्या की शैक्षिक किमयाँ पिछले काफी समय से विकास करने की हमारी क्षमता पर बोझ बनी हुई हैं। हम हमेशा ही अपने उच्च कुशलता प्राप्त किमयों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों तथा हाल के वर्षी

में सॉफ्टवेयर प्रतिभाओं पर गर्व करते रहे हैं, लेकिन हमारी अधिकांश आबादी का शिक्षा का सामान्य स्तर काफी कम रहा है। सन् 1951 में प्रौढ़ साक्षरता मात्र 18.3 प्रातशन थो। सन् 1900 स यह अव्कर २६ १ प्रतिशत तथा सन् 1971 में 34.4 प्रतिशत हो गई। इन वर्षों में उमारी निरतर कम विकास-दर का एक कारण यह भी रहा है। उपट्रीय मामी एक सेवा (एन एस एस.) द्वारा कराए गए मर्वेक्षण के अनुसर सन् 1996 97 में साक्षरता की दर बढ़कर 62 प्रतिशत हो गई। हाल्जीक अर दर भी कम ही है, मगर 7-8 प्रतिशत की विकाप दर पार्ट करन उस्तुकृल है।

ग. जनसंख्या-दर लंबे समय तक 2 प्रतिशत में अधिक ग्हमें के कृष्ट अब कुछ भीमी पड रही है। इस क्षेत्र में केरल की उपलब्धियों की प्रीत्मार्गन अब तिमलताडु में भी सुनाई दे गहीं है। लगता है कि अभ प्रदेश भूष्ट कर्नाटक में भी जल्द ही यह इतिहास दोहराया जाएगा। उनमें भारत कर राज्यों में जन्म-दर काफी ऊँवी रही है, लेकिन अब यहाँ भी देशम क्ष्म आ रही है। अनुमान है कि अगले दशक में भागत की जनसंख्या विकास-दर घटकर 1.5 प्रतिशत हो जाएगी।

ये सकारात्मक बदलाव अगले दशक में हमारी विकास संभावना औं पर महत्वपूर्ण असर डालेंगे। अगर जी डी.पी की मो नृटा 6.5 प्रतिशत की विकास के अगले दशक की शुरुआत में 7 प्रतिशत और अन तक 8 प्रतिशत नक बटाई के सकी तो पूरे दशक की विकास-दर लगभग 7.5 प्रतिशत डी मकती है। हमन अन्दित में जो विकास-दर हासिल की है, वह उन सबमें अधिक हे और एंगे विकास के को गति दे सकती है। यदि यह दर समुचित तरीके में वित्तारत होती है तो अगल दशक के अंत तक इससे गरीबी के स्तर में गिरावट स्विश्वित है, यानी यह भा कहा जा सकता है कि इस स्तर की विकास-दर हासिल किए गए जनना के जीवन करा में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती।

अब यह तय करना है कि इस विकास-दर को प्राप्त करने तथा इसका आधार व्यापक करने के लिए हमें किन नीतियों की जरूरत है। युग्दर किर्वत यह है कि आर्थिक नीतियों के मामले में राजनीतिक हलको तथा ऐशेक्य (प्रोफेशनल) वर्ग में आम सहमति वन गई है। आर्थिक मुगारी की लेकर एक आम राय यह भी कायम हुई है कि इन मुधारों को और अधिक सुदृढ़ करने तथा पैना बनाने की जरूरत है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर 'सुधारों की दूमरों पीदीं कहा जाता है, परंतु ऐसा कहना पूरी तरह उपयुक्त नहीं है। दरअसन्दर, ऐसा कारने से यह एहसास होता है कि हमने पहली पीढ़ी के सुधारों की प्रक्रिया सफलतापुनंक

पूरी कर ली ह और अब अगल दौर में कदम रखना है परतु सचाई इसके विपरीत है सुधार सबधा एजेडे का निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वगीकृत करना अधिक उपयुक्त हागा

- इस एजेंडे का पहला विषय राजकोषीय अनुशासन कायम करना है और इस मुद्दे पर व्यापक सहमित भी हैं। दरअसल, ये पहली पीढ़ी के सुधार हैं, जिन्हें हम योजनानुसार कार्योन्वित नहीं कर पाए हैं।
- 2 दूसरी श्रेणी के अतर्गत उन पहली पीढ़ी के सुधारों को रखा जा सकता है, जो कमोबेश सही राह पकड़े हुए हैं, लेकिन अपनी सुधार-नीति के कारण उन्हें हम धीमी चाल में चला रहे हैं।
- 3. वास्तव में, अंतिम श्रेणी के अंतर्गत दूसरी पीढ़ी से संग्रह्म सुधार शामिल किए जा सकते हैं, जो सुधार-प्रक्रिया को उन नए क्षेत्रों तक ले जाएँगे, जिनपर अभी तक ध्यान नहीं दिया जा सका है।

२. वित्तीय अनुशासन

देश के सामने मुँह उठाए खडी वित्तीय ममस्या की गंभीरता को देखते हुए अब इस महलू को इसके व्यापक संदर्भों में समझने की जरूरत है।

सन् 1991 में जब आर्थिक मुधार लागू किए गए थे, तब देश गहरे आर्थिक सकट से जूझ रहा था। केंद्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा इससे पिछले वर्ष में जी डी पी. का 8.3 प्रतिशत ही गया था। सकट का मूल कारण भी यही रहा। समय की नजाकत को देखते हुए राजकोषीय सुधार करने की जरूरत महसूस की गई। पहले ही वर्ष में राजकोषीय घाटे में कमी आई। यह आँकड़ा जी डी.पी का 6 प्रतिशन दर्ज किया गया; लेकिन यह ऑकड़ा भी अधिक था और अर्थव्यवस्था के लिए ससाधन जुटाने तथा ब्याज-दरों में कमी लाने के लिए इस घाटे को और कम करने की आवश्यकता थी। वित्त मत्रालय द्वारा सन् 1993 में जारी दस्तावंज में मध्यम अवधि के लक्ष्य के रूप में राजकोषीय घाटे को सन् 1996-97 तक लगभग 3 प्रतिशत करने की बात कहीं गई। दुर्भाग्यवश यह लक्ष्य कभी भी हासिल नहीं किया जा सका। सन् 1996-97 में वास्तविक घाटा 5 2 प्रतिशत का रहा और सन् 1997-98 के दौरान बढ़कर यह 6 प्रतिशत हो गया। तब से यह दर कमोबेश इसी स्तर पर बनी हुई है। नतीजतन ब्याज-दर काफी अधिक है।

इस बीच राज्यों की, विशेषकर कथित रूप से बेहतर प्रशासनवाले राज्यों की राजकोषीय स्थिति भी पहले के मुकाबले बिगड़ी ही है। राज्यों को केंद्र की तरह बराक टांक ऋण लने की छूट नहीं हाना और टम कारण उनक वार पर स्वतः अकुश लगा रहता है, लेकिन इस वजह से उनके गेर-योजनागत खर्च बढ़ जाते हैं और विभिन्न आर्थिक सेवाओं की आपृति को लंकर नृकसान बढ़तर चला जाता है। इस समस्या की गंभीरता का अनुमान इस बात में हा लगाया जा सकता है कि 1997-98 में सभी राज्य बिजली बोर्डों का कुल घाटा पन 11.000 करोड़ रुपए रहा। इमी प्रकार सिंचाई के क्षेत्र में केवल रख रखाव के खर्चों में मर्याध्त घाटा 20 अरब रुपए रहा। उधर राज्य सड़क परिवहन निगमों का घाटा 10 अरब रुपए ही रहा।

इतने अधिक घाटे को देखकर स्पष्ट है कि प्रार्टीशक सम्प्रांग अपने यो जनागत खर्ची से सर्विधत लक्ष्य पाने में असफल रही। आरखीं ना नना (1992-93 म् 1996-97 तक) में राज्यों का योजनागत खर्च पूर्व-निधारित लक्ष्य में 20 प्रतिहल कम रहा था। पाँचवे वेतन आयोग के असर के कारण नीवी योजना म यह निधित और भी बिगड़ गई है। कुछ राज्यों में तो स्थित उतनी खराव हो चुकी है कि वे अपने कर्मचारियों को ब्रेतन भी नहीं दे पा रहे हैं।

इन स्थितियों में सुधार नहीं करने के पांग्णाम हमार नामन है। आहीं की केंचा आकार हमारी माजूटा ऊँची ब्याज-दर को और बढ़ाएगा, जिससे अवंद्यवस्था में निवेश को और अंततः छोटे उत्पादकों को सबसे अधिक नृक्यान होगा। या जनामन खर्च के स्तर में कमी से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आवश्यक साम भीनक नियंग पर खतरा मँडराएगा और नतीजतन हमारे विकास-लक्ष्य प्रशावित होंगे। हालाँकि इसका अर्थ यह नहीं है कि विकास पूरी तरह में योजनागत खर्च पर निकास या फिर इस प्रकार का खर्च हर दृष्टि से उचित होता है। 7 या 8 प्रिनंशन का विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक अधिकांश निवेश को निजी निवेशकों में जुटाया जाना चाहिए। दरअसल, कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ योजनागत खर्च के स्थान पर निजी निवेश को लाने की जरूरत है। सन् 1990-91 में योजनागत खर्च में केंद्र नथा राज्यों का कुल अनुपात जी.डी.पी. का 11.3 प्रतिशत रहा और वर्तमान में यह घटकर 9 प्रतिशत के आस-पास है। इसके कारण कई क्षेत्रों में निवेश सिक् डा की, जी विकास-दर को 7-8 प्रतिशत तक करने के लिए जरूरी था।

संसाधनों में कमी के कारण कृषि के क्षेत्र में भी विकास की क्षमता पर मीधा असर पड़ा है। गरीबी घटाने की हमारी रणनीति के तहत कृषि विकास को बढ़ाने तथा ग्रामीण विकास का आधार व्यापक करने की जरूरत है। इस मध्य की ग्राप्ति के लिए हमें सिंचाई, भूमि-विकास, मिट्टी एवं नमी मंरक्षण, कृषि अनुसंधान, कृषि-विपणन सुविधाओं के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ संपर्क-सुविधा में सुधार के लिए टेहातों एवं जिले की सड़कों के रख-रखाव और विस्तार हेतु निवेश को अधिक व्यापक बनाना होगा।

स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्रों में, विशेषकर देहातों में तो और भी अधिक निवेश की जरूरत है, तािक हमारे सामाजिक विकास संकेतक अन्य विकासशील देशों के संकेतकों के समतृत्य हो सकें। यह निवेश भी सार्वजनिक उपक्रमों से ही आएगा। अन्य ढाँचागन क्षेत्रों, जैसे—बिजली उत्पादन तथा वितरण, बंदरगाह, हवाई अइडों, दूरसचार, राष्ट्रीय राजमार्गों आदि में निजी क्षेत्र यहले के मुकाबले अधिक बड़ी भूमिका निभा सकते है। अतः इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अलबता इन क्षेत्रों में भी सार्वजनिक निवेश आनेवाले काफी लंबे समय तक महत्त्वपूर्ण वना रहेगा।

इसलिए अगले दशक के राजकोषीय लक्ष्यों के दो पहलू निर्धारित करने चाहिए। हमें राजकोषीय घाटे की आवश्यक रूप से कम करना होगा, ताकि निजी निवंश के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके, लेकिन साथ ही हमें महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजिनक निवंश भी बढ़ाना होगा। सन् 1998-99 के दौरान राज्यां तथा केंद्र का सयुक्त राजकोषीय घाटा जी डी पी. का 8 5 प्रतिशत रहा। वित्त मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि केंद्र के राजकोषीय घाटे को अगले 3 वर्षों में घटाकर लगभग 2 प्रतिशत तक करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अगले 3 वर्षों में राज्यों तथा केंद्र का संयुक्त राजकोपीय घाटा 4 5 प्रतिशत के स्तर तक आना चाहिए। इसके साथ ही हमें केंद्र तथा राज्यों के कुल योजनागत खर्च में मौजूदा स्तर के मुकाबले 1.5 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रयास करने चाहिए। इन दोनों लक्ष्यों को अगले 3 वर्षों के दौरान हासिल करने के लिए जी.डी पी. के 5.5 प्रतिशत या 1.8 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष के लगभग राजकोषीय सुधार करने की आवश्यकता है।

यह सुधार थोडा केंद्र के द्वारा और थोड़ा राज्यों के द्वारा किया जाना है। यहाँ महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अगले 3 वर्षों में 5 5 प्रतिशत का राजकोषीय सुधार कर पाना यकीनन काफी मुश्किल काम है। इसके लिए एक या दो उपकरणों को सुधारने भर से ही काम नहीं चलनेवाला, बल्कि अनेक मोरची पर कार्यवाही करनी होगी। इसमें से कुछ इस प्रकार हैं—

अधिक राजस्य वसूली के लिए कर-प्रशासन में सुधार

भारतीय कर-प्रणाली का अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट होती है कि यह प्रणाली अब पुरानी पड चुकी है और इसमें निहित प्रक्रियाएँ भी काफी जटिल तथा भारी-भरकम हैं। साथ ही दरों की अनेक प्रकार की छूट और विवक्त भिकार के छहे क्षेत्र के चलते करदाताओं द्वारा कर से बचना तथा कर प्राधिकरण द्वारा से कान करना आम बात है। इस प्रणाली में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार क्यारत है और कर अमलों में कमी का प्रमुख कारण भी यहीं है। अन्य देशों के अनुभवों से पना चलना ए कि कर-सुधारों के जिरये कर की दरें बढ़ाए वर्गर थेंडे समय में ही जी ही यों के 3 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त कर-वसूली हो सकती है। इस तरह राजकेंग्यीय स्पृत्य के तहत निर्धारित लक्ष्यों का आधा भाग तो कर-सुधारों की प्रभागी होंके से लाग करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कर प्रशासन से सृधार ओं कराधार को व्यापक बनाने के जुमलों को हटाकर छूट हटाने के लोग प्रभागा कई प्रकार की दरों की संख्या घटाने तथा प्रक्रियाओं के आधुनिकाकरण पर और दिया जाना चाहिए। इस सदर्भ में नई 'कर-सृधार मर्गित' जल्द ही जानी एक्स प्रशासन पेश करेगी।

रिआयतों (सद्सिडी) में कमी

लगभग हर व्यक्ति रिआयतों में कमी ताने की हिमायत करता है, पर पूर्ण मामले में विशेष प्रस्तावों के पेश होते ही यह धन महर्मात नदाय हो आता द इसके बावजूद हमारी प्रणाली में प्रत्यक्ष तथा परोश रिआयतों की माजा ऐसे मना तक जा पहुँची है जहाँ उसे बनाए रखना काफी किन्म है। केंद्र हारा प्रमुख कम से उन्नेक्टों, खाद्यान और चीनी में रिआयत दी जातों है। यन 1999 2000 के बक्त अन्य अनुमानों के आधार पर यह राशि 240 अरब रुपए थी। वास्तव में यह माजा आंगक भी हो सकती है। इसके अलावा उच्च शिक्षा, अम्पताल-मेवाओं, रेज्यात्रियों, राध, संवाओं आदि पर भी भारी रिआयतें दी जातों हैं। मिट्टी तेल पर 80 अरब रुपए तथा एल पी.जी. पर लगभग 40 अरब रुपए की रिआयत दी जा गहीं है। इस रिआयती को सीधे बजट में से न मुहैया कराकर अन्य पेट्रोलियम उन्मादों, असे— पेट्रोल तथा एविएशन ईंधनों में अधिक वसूली के हारा वस्तृता जाता है। वे रिआयते त्रिया स्प से गरीब वर्ग के लिए न होकर वास्तव में उच्च आय वर्ग या औसत उपभोजता के लिए दी जाती हैं; परंतु रिआयतों के बोझ के चलते सरकार उन कार्यक्रमी पर प्रभावी रूप से खर्च नहीं कर पाती, जो व्यापक आधारवाली विकास पिकाया की बढ़ावा देंगे और जिससे व्यापक हित जुड़े हों।

इसी प्रकार प्रादेशिक सरकारों पर भी रिआवनों का भारी बोझ है, जिसे कम किया जाना चाहिए। अधिकतर राज्यों में किमानो को बिजली उसके उल्पादन खर्च की महज 10 या 20 प्रतिशत कीमत पर या मुफ्त उपलब्ध कगई जा गई। है। इसी प्रकार घरेलृ बिजली उपभोक्ताओं और बस यात्रियों से लेकर सिंचाई के पानी और उच्च शिक्षा के बदले भी कम धनराशि वसूली जा रही है।

रिआयतों को पूरी तरह समाप्त करने की बजाय उनमें भारी कमी लाने की जरूरत है नथा कुछ लक्षित क्षेत्रों में इन्हें जारी रखा जाए।

रारकार के आकार में कमी

रेतवं और डाक समेत कई सरकारी विभागों में आवश्यकता से अधिक मानव श्रम को गखा गया है। उसपर सरकारी विभागों की संख्या भी काफी है। उदारीकृत अर्थव्यवस्था में विनियमित तथा नियत्रित अर्थव्यवस्था के मुकाबले काफी कम मंत्रालयों और विभागों की आवश्यकता होती है। पाँचवें वेतन आयोग ने सरकार के आकार में आगामी वर्षों में 30 प्रतिशत तक कमी लान की मिफारिश की है। हालाँकि कई बार सरकार के आकार में कमी के प्रस्तावों का विरोध यह कहकर किया जाता है कि बेरोजगारी की समस्या काफी गंभीर है और सरकारी सेवा मे रोजगार के अवसर बने रहते हैं: लेकिन अनावश्यक मानव श्रम पर खर्च हो रही धनराशि को बवाकर उसे अधिक जरूरी आर्थिक तथा मामाजिक ढाँचागत संरचना में निवेश करने से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में रोजगार के कहीं अधिक अवसर जुटाए जा सकते हैं। हमें यह तथ्य स्वीकार करना हो होगा कि सरकार का उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को कुशलतापूर्वक उपलब्ध कराना है, न कि रोजगार जुटाना।

निजीकरण को बढावा

कई विकासशील देश अपने सार्वजनिक उपक्रमों में व्यापक स्तर पर निजीकरण करने के बाद अपनी राजकोपीय स्थिति सुधारने में सफल रहे हैं। यह विकल्प हमारे लिए भी खुला है। राज्यों को चाहिए कि केंद्र द्वारा पहले ही शुरू की जा चुकी इस प्रक्रिया को अपनाएँ।

योजनाओं की प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण

योजनागत खर्च के तहत प्राथमिकताओं के पुनर्निर्धारण की जरूरत है, तािक संदेहास्पद योजनाओं को हटाया जा सके। कई मूल्यांकन अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि हमारी कई योजनाएँ अच्छे इरादों के साथ शुरू किए जाने के बावजूद अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाईँ या सोमित स्तर पर ही कामयाब रहीं। इस प्रकार वे अंततः कीमतों की दृष्टि से निष्प्रभावी रहीं। इसका कारण योजना का स्वरूप तय करने मे कमी और अपर्याप्त प्रशामनिक क्षमता का होना रहा है। दुर्भाग्यवश इसके बावजूद ये योजनाएँ जारी रहनी हैं और उन संसाधनों

को सोखती चली जाती हैं, जिन्हें दूसरे क्षेत्रों में इम्तेमाल किया जा मकता था। इन् योजनाओं मे जुड़ी प्रशासनिक एजेंसियाँ निहित म्यार्था के तहन उन्हें जारी रावर्ता है ओर योजनाओं की आलोचना की स्थिति में बेहतर प्रशासनिक एवं निगरानी तंत्र कें जरूरत दिखाकर अधिक स्टाक तथा अधिक मंसाधनों की माँग पेण करती है लेकिन तमाम योजनाओं की जाँच नए सिरं से तथा गैर-प्रभावी योजनाओं को नुरह समाप्त करने से जो ससाधन उपलब्ध हो सकेंगे, उनका इस्तेमान अधिक महन्तपुण तथा उपयोगी योजनाओं के लिए किया जा सकता है।

लेकिन इन सुझावों के आधार पर सुधार-प्रक्रिया न्याप करना समन नहीं होगा। प्रत्येक प्रस्ताव को अलगाव में रखकर उसपर जिच्छा करने में विधाद उत्पन्त होने की संभावना है। लेकिन यह भी सन्त है कि जी. डी. पी के 5.5 प्रीनका के बराबर मात्रा का राजकोषीय सुधार इन प्रयामों के बिना नहीं हा सकता: नेकिन दुर्भाग्यवश हमारी मौजूदा व्यवस्था में, जहाँ बजट को लेकर गुर्ग गी.पनीयन बातने की परंपरा का पालन किया जाता है, इस प्रकार के विकल्गों में गुलना भागान काय नहीं है। गुपचुप तरीके से कठिन निर्णय नहीं लिये जा सकते। इनके निर्ण श्राह्मा विमर्श तथा प्रतिक्रियाओं के आदान-प्रदान के द्वारा आम ग्रन्थ तथान करनी होगा।

इस प्रकार के किठन फैसले लेने की जरूरत को इस बान में केटना नमंबें से समझा जा सकता है कि कुछ देशों में बजट प्रस्तुत करने के दौरान हो उन्नले वर्षों के बजट की भी हलकी-फूलकी रूप-रेखा बता दी जातों है। इसमें प्रत्यदा यह होता है कि हमें उन प्रयासों की विस्तृत तमबार दिखाई पड़नी है, जो हमें अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों के लिए अगले 2-3 वर्षों में करने हाते हैं। इस दूजि में होतें तो हमारे वर्तमान प्रयास तभी कुछ कम हो सकते हैं जब हम आनेधान करने के लिए कही अधिक कोशिशों पर अमल की योजना तैयार करें।

3. पहली पीढ़ी के सुधार

राजकोषीय सुधारों के साथ-साथ हमें उन सुधारों पर भी ध्यान देना होगा, जो आरंभ में तैयार की गई योजनानुसार जारी तो हैं. परेतू जिन्हें पूग करने या फिर नए घटनाक्रम के संदर्भ में कुछ हद तक संशोधित करने की जा रत है। औद्योगिक विकित्यानन

औद्योगिक लाइसेंसिंग का उदारीकरण तथा उद्योग की विदेशी निवेश के लिए खोलना पहली पीढ़ी के सुधारों का अहम हिस्सा थे। जहाँ तक केंद्रीय गरकार के नियंत्रणों का सवाल है, यह कहना होगा कि इस दिशा में मंतोपजनक प्रगति हुई है . परियोजनाएँ लागू करते समय निवेशकों को अब भी दिक्कतें पेश आती है, मगर ऐसा राज्यों के स्तर पर होता है। यह क्षेत्र दूसरी पीढ़ी के सुधारों के अंतर्गत आता है। अलवता औद्योगिक विनियमन के कुछ क्षेत्रों मे अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

चीनी उद्योग ऐसा ही एक क्षेत्र हैं। चीनी एक प्रमुख कृषि-आधारित उद्योग हैं। तथा सूती कपडे के बाद इसी उद्योग ने सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराया है। अन्य उद्योगों की तरह चीनी उद्योग के लिए भी उदारीकरण फायदेमंद है, लेकिन मौजृदा दोहरी मूल्य-प्रणाली के चलते इस उद्योग पर अब भी कई तरह के नियंत्रण हैं। किसानों को दी जानेवाली प्रादेशिक सरकारों द्वारा समर्थित कीमतो का संबंध प्राय- बाजार की स्थितियों से नहीं होता। कुल उत्पादन का कुछ हिस्सा लेवी चीनी के तार पर बिना लाभ के मृल्यों पर उपलब्ध कराना होता है। यही नहीं, मुक्त बाजार की चीनी पर भी नियंत्रण रहते हैं। चीनी उद्योग को आयातित चीनी को लेकर शिकायन हैं कि लेवी चीनी जैसी अवधारणा से उसके मुक्त होने के कारण प्रतियोगिता के असमान अवसर हैं, यानी चीनी को नियंत्रण मुक्त करने तथा इस क्षेत्र की बाजार के लिए खोलने के पुख्ता कारण मौजूद हैं। यटि चीनी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी एस.) में शामिल करना जरूरी है तो इसे बाजार भाव पर खरीदना चाहिए तथा बजट में इसका अलग प्रावधान होना चहिए। वस्तृत: चीनी को पी.डी एस. से हटाने की जरूरत है।

इसी प्रकार कीयला क्षेत्र में भी औद्योगिक विनियमन होना चाहिए। यह महत्त्वपूर्ण ऊर्जा म्रोत है। फिलहाल खनन को छोड़कर इस क्षेत्र में निजी निवेश को अनुमित नहीं दी गई है। यदि पेट्रोलियम क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोला जा सकता है तो कोयला क्षेत्र में भी ऐसा किया जाना चाहिए। ऐसा करने से इस उद्योग में प्रतिस्पर्धा में तेजी के साथ-साथ नई प्रौद्योगिकी भी आएगी। चूँकि कोयला-खनन एक कठिन क्षेत्र है और पर्यावरण-संबंधी मंजूरी मिलने में समय लगना निश्चित है। इसलिए यदि हम आगामी 6-7 वर्षों में अतिरिक्त उत्पादन चाहते है तो हमें अभी से इस दिशा में सिक्रय होना पड़ेगा।

उधर लघु क्षेत्रों के लिए कुछ उत्पादों को आरक्षित रखने की नीति पर भी विचार-विमर्श करने की जरूरत है। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि लघु उद्योग क्षेत्र की मदद करने का यह तरीका उचित नहीं है। दरअसल, आमतौर पर इस तथ्य की अनदेखी की जाती रही है कि लघु उद्योगों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में विकास की रफ्तार अनारक्षित लघु उद्योगों की तुलना में कहीं कम रही है। हालाँकि यह बड़ा नाज्क विषय है और इसपर आम सहमति बनाने में समय लगेगा। फिर भी मिले- सिलाए वस्त्री, खिलीनों तथा चमड़ के जुते न्चप्पलों क निर्माण में जुट उस रेग्नी की तुरत प्रभाव में अनारक्षित कर देना चाहिए, जिनमें निर्यात की एथान क्यान माजद है। सन् 1997 में भारत ने 7 कराइ अमेरिकी इत्तर के क्याबर गाँग के निर्माण तथा खल-कृद के सामान का निर्यात किया, जबकि चीन की पर और दे अगव अमेरिकी डॉलर, अर्थात् भारत की तुलना में 120 गुजा अधिक गाँग उनी प्रकार भारत ने 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर मृल्य के जुने चायल निर्यात किया कर निर्मा कर की या हा की की मायत की हालर मृल्य का निर्यात कर भारत के उत्तर अमेरिकी डॉलर मृल्य का निर्यात कर भारत के उत्तर अमेरिकी डॉलर मृल्य का निर्यात कर भारत के उत्तर अमेरिकी डॉलर मृल्य का निर्यात कर भारत के उत्तर का कर की मायत की स्थात कर मात की कियात कर महाने की जिन्यात कर मकते हैं, परित्र मनाई का तो उत्तर बाजारों तक पहुँच न होने की शिकायत कर मकते हैं, परित्र मनाई का नाई की शिकायत कर मकते हैं, परित्र मनाई का नाई की असे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पैठ करने से रोकती गदी हैं।

अर्थव्यवस्था की व्यापार के लिए खोलना

अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार के लिए खोलना भी हमारे स्पूर करे के अहम हिस्सा था। इस क्षेत्र में आवे में अधिक स्थार प्रक्रिया पूर्व को बन्हें है। सरकार ने घोषणा की है कि सन् 2003 तक सभी मात्रात्मक प्रक्रिया हम लिये जाएँगे। फिलहाल घरणबद्ध ढंग से यह किया भी जा गत है। इस प्रक्रेंग में उत्थ्य सीमा स्पष्ट है। भारतीय उद्योग जगत ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। उसर के इस बात के भी संकेत दिए है कि शुल्क दरों की आगामां 3 नर्थों में पूर्व एश्वार्य देशों के मुनाबिक तय किया जाएगा।

हालॉकि कुछ लोग मानते हैं कि गूल्क-दर्ग में कमी के बाद भारतीय उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा के सामने टिक नहीं भाएगा, परत् यह कवान भारता है। पिछले वर्षों में भी शुल्क-दरों में भारों कमी होने के धाकन् का भारतान उद्योग प्रतियोगिता में रहा है। अब ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि आनंबान गर्धों में भी इस प्रक्रिया को जारी न रखा जाए।

विनिवेश तथा निनीकरण

विनिवेश का भी अभी ऐसा नया क्षेत्र हैं, जहाँ सृथारों को और कैने स्तर तक लेकर जाना है। इन सृथारों की शुरुआत 'विनिवेश' की प्रोन्न या में दूर के और इसके बाद भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की ऑश्विकार किस्मेटारी बनी हुई है। संयुक्त मोर्ची सरकार ने गैर स्नियादी तथा गैर मार्मारक दंखी के उपक्रमों में सरकार की अंशभागिता को अल्यमत में लाने की इन्ला जताई थी। वर्तमान सरकार न एक कदम आगे जाकर यह घाषणा कर डाली कि सभी क्षत्रा में सरकार का हिम्सा घटाकर 26 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा। फिलहाल मॉडर्न फृड और बाल्कों में प्रबंधन में बदलाव सहित विनिवेश प्रस्तावों पर कार्य चल रहा है। साथ ही आई.पी सी.एल के लिए सहयोगी की तलाश भी जारी है।

इस बीच जनता के मन में इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि इस दिशा में सरकार की सीमा क्या होनी चाहिए। कई लोगों का मानना है कि सार्वजिनक क्षेत्र के कमजोर उपक्रमों की बिक्री और प्रबंधन में बदलाव टचित है. पग्तु कथित 'नवरत्नो' में सरकार को अपनी अधिकाश हिस्सेदारी नहीं छोड़नी चाहिए। जहाँ तक अधिकांश स्वामित्व का सवाल है, इस बारे में हमे छोड़े बगैर यह स्पप्ट होना चाहिए कि अनेक नवरत्नों के इक्विटी अश में से वाछित राजकोपीय मुधारों का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसिलए जनता को इस बात के लिए राजी करना जरूरी है कि इस प्रकार का विनिवेश या निजीकरण ममाज के लिए शिधक उपयोगी परिसंपत्तियों, जैसे—स्कृल, अस्पताल, ग्रामीण ढाँचागत सुविधाओं आदि के निर्माण में मदद ही पहुँचाएगा। हमें यह भी नहीं मान लेना चाहिए कि विनिवेश से अजित राजस्व को दूसरे सार्वजिनक उपक्रमों में निवेश किया जाएगा। हमें यह समझना होगा कि हमारे लिए सर्वोत्तम क्या है और यदि स्कृल, पुल, सड़कें आदि से अधिक लाभ पहुँचता हो तो हमें निश्चत तौर पर उनका निर्माण करना चाहिए।

हमारी राजकोषीय समस्या को देखकर यह कहा जा सकता है कि यदि सभव हो तो सन् 1999-2000 के दौरान विनिवेश का स्तर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक रखा जाना चाहिए। विनिवेश के प्रति हलकी-फुलकी दृष्टि रखने से इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। हमें विनिवेश के वार्षिक नियोजन को छोड़कर यह तय करना होगा कि अगले 2-3 वर्षों में कितने प्रयासों की आवश्यकता है। इस आधार पर ही हमें उन कंपनियो की पहचान करनी होगी, जिनमें विनिवेश करना है तथा यह भी कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन कंपनियों में किस हद तक विनिवेश करना जरूरी है। सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वह विनिवेश के लिए अलग प्रक्रिया अपनाने तथा इसके लिए अलग इकाई गठित करने के बारे में विचार कर रही है। यह कदम स्वागत योग्य है। इस कार्य में सफलता तभी मिल सकती है, जब उन सार्वजनिक उपक्रमों को सबद्ध मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त कर उन्हें नई इकाई में स्थानांतरित करने की इच्छाशिक्त हममें होगी, जिनका निजीकरण किया जाना हैं। हालाँकि मंत्रालय के विचारों पर भी गौर किया जाएगा। परतु विनिवेश तथा निजीकरण को मृति और तीर तराके तय करने

का अधिकार इस नई इकाई के पास ही होगा।

कपनी के विनिवेश की प्रक्रिया, अर्थात् उसे व्यापक आधारवाले निवसको के हाथों बेचा जाएगा या फिर एक ही खरीदार के हाथों पूरी कंपनी बेच दी जाग्गी

अथवा उसके संचालन में नए सहयोगी को शामिल किया जाएगा, लमें - मृद्रों पर फैसला उपक्रम विशेष को देखकर लिया जाएगा तथा कियी विशिष्ट फसले के

पीछे मौजूद तर्क को पारदर्शी बनाया जाएगा। हमे जनना को भी यह समान जागा। कि सरकार की इक्विटी घटाने से चितित होने की अवश्यकता नहीं है। हमारा लक्ष्य

नवरत्नों को कॉरपोरेट जगत् के सिक्रय अंग क रूप म मजबूत वतानं का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वे सरकार के नियत्रण में ही बाहर हो नाएँ। दर असत एं तर्कों के साथ यह बताया जा सकता है कि वर्ताणित्यक स्वायनता और प्रात्रस्था बाजारों में अपना अस्तित्व सुरक्षित रखने के लिए इन उपक्रमी पर में मारकारी

वर्चस्व को समाप्त करना बेहद जरूरी है। सब तो यह है कि किसी की भी इस बात पर यकीन नहीं है कि स्वामित्व की दृष्टि से मण्जार की भोजूदगी से किसी कंपनी के बाजार-मुल्य में कोई वृद्धि होती है। यह बात मार्गन उद्योग के अर्थ में जितना सच है, उतनी ही भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड (सेल) के घारे में आर उतनी ही भारतीय तेल निगम (आई ओ पी) के बारे में भी।

वित्तीय क्षेत्र के सुधार

रफ्तार में तेजी लाने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व वैंक ने खेमल मॉर्मन द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मापदडों की कसौटी पर खुरा उतरने के लिए बेलिंग क्षेत्र भ विवेकपूर्ण तथा विनियमन मापदंडों का म्तर केंचा उताने की दिशा में मगहनाय कार्य किया है। पूर्वी एशियाई संकट के बाद विनीय क्षेत्र की असजीरिया का लेकर

वित्तीय क्षेत्र मे भी पहले दौर के मुधार जारी है, लेकिन इस प्रक्रिया की

बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर भींकष्य में मभी विकासशान दंशों पर अलग्राधीय एजेसियों द्वारा अधिक ध्यान दिया जाना तय है। हाल्डोंक हमें अभा और आगे जाना है, लेकिन दरारों को पाटने का काम काफी हद तक किया जा नका है।

अगला चरण, अर्थात् यह मूनिश्चित करना कुछ मायनी में श्रांधक काँउन है कि हमारे बैंक, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के खेक नए बापदंडी का परा का क्षे हैं या नहीं, और यह भी कि ऐसा करते समय क्या वे विदेशी और निज़ी क्षेंकों के

साथ प्रभावी तरीके से प्रतियोगिता में डटे रह पाते हैं ? बैंकिंग क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी में बदलाव होने और विशेषकर सूचना पांद्योगिकों के आने से प्रतिस्पर्धा में तेजी

आएगी जो बैक अधिक गतिशील होगे और नई प्रौद्योगिकी को अपनाएगे वे अपनी व्यापक शाखाएँ न होने के बावजूद बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाने में कामयाब हो सकेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जिनकी मजबूती का मुख्य

आधार उनका व्यापक शाखा-तंत्र है, को इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें कई प्रकार से पुनर्गठन के लिए स्वायत्तता तथा लचीलेपन की जरूरत

होगी। उन्हें कर्मियों की भरती तथा प्रोन्नति के मामले में स्वायत्तता की आवश्यकता होगी, बैंकिंग विशेष की उत्पादकता, लाभ आदि की स्थिति के अनुसार उन्हे वेतन-समझोतों पर बातचीत की स्वायत्तता चाहिए और साथ ही अतिरिक्त स्टाफ के

मामले में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी आर एस.) आदि योजनाएँ भी जरूरी हैं। ये सभी काफी जटिल विषय है। इनपर कई निहितार्थ तत्वों तथा आम

जनता की भी पहली प्रतिक्रिया नकारात्मक हो सकती है, लेकिन बैंकिंग प्रणाली के हितों के मद्देनजर हमें इन बदलावों के बारे में दृष्टिकोण बदलने तथा अधिक समझ पैदा करने की जरूरत है। हो सकता है कि इनमें से कुछ समस्याओं से निकट

भविष्य में ही दो-चार होना पडे। वित्तीय क्षेत्र में एक प्रमुख सकारात्मक बदलाव बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के रूप में आया है। इस कदम से निजी क्षेत्र का प्रवेश इसमे हो

सकेगा। मजबूत तथा प्रतिस्पर्धी बीमा उद्योग लबी अवधि की बचत को मजबती

देने के साथ-साथ उपभोक्ता-सेवा में सुधार लाने तथा पूँजी बाजारो के लिए लबी अविध के वित्त-प्रवाह का वाहक बनेगा। ढाँचागत क्षेत्र के वित्त-पोषण के लिए यह अत्यावश्यक है। हमें याद रखना होगा कि इस क्षेत्र में किसी भी नए खिलाड़ी को कोई मुकाम हासिल करने में 5-6 वर्षों का समय तो लग ही जाएगा। अत- नई बीमा कंपनियों द्वारा ढाँचागत प्रणाली के लिए वित्त उपलब्ध कराने की संभावना

इस दशक के दूसरे अर्ध-भाग मे ही है। इससे यह स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया को

यथाशीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

ढॉचागत विकास का निजी वित्त-पोषण

ढॉचागत विकास के लिए निजी निवेश भी पहले दौर के सुधारों में शामिल है, लेकिन इन्हें आगे बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयास करना जरूरी है। वर्तमान के अधिक खुल तथा प्रतियोगी माहौल में तेज रफ्तार से विकास के लिए उच्चस्तरीय

अतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की जरूरत है। इसके लिए उच्चस्तरीय ढाँचागत व्यवस्था चाहिए; लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी सड़के, बिजली, बंदरगाह, दूरसंचार आदि ढाँचागत सरचना अपयोप्त है। मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता की दुष्टि से भी इनमें गंभीर

खासियों है। हालाँकि इन सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक निवंश की महन्वपूर्ण शूमिका वनी रहेगी लेकिन ये आवश्यकताएँ इतनी अधिक है कि इनमें निजी निवंश को भी शामिल करना पड़ेगा। गुणवत्ता में मुधार के लिए निजी निवंश विशेष रूप में महदगार साबित होता है।

विजली तथा दूरसंचार क्षेत्रों को प्रथम दौर के मुधारों के तोर पर निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था और बाद में इन्हें बंदरगानी हजाई अइ हो तथा मह्कों पर भी लागू किया गया। अब तक इसके मिले- जुने नर्ताजे प्राप्त हुए हैं। मुखद समाचार यह है कि इन सभी क्षेत्रों में निवंश आकर्षिण करना भथव हो सका। निजी क्षेत्र द्वारा लगभग 9,000 मेगावाट क्षमता की विजाती तथार की जा चुकी है या इस पर काम जारी है। मेल्युलर फोन तथा दूरसचार की अन्य मृज्यवर्षित मेंबाओं के मामले में भी निजी निवंश में काफी सुधार हुआ है। इसी प्रकार वदरगाहों तथा कोचीन में पिछले दिनो खोले गए देश के पहले मंयुक्त क्षेत्र के स्वाई अइ हे के लिए भी निजी निवंश जुटा लिया गया। जो लग यह कहते हैं कि कुछ भी हामिल नहीं किया जा सका है, उन्हें दरअसल ठीक जानकारी नहीं है। अल्लबना जी गर्ताजे मिले हैं, वे अपेक्षा से कम है। एक बात यह भी है कि इन सभी क्षेत्रों में आलग अलग कारणों से कार्यन्वयन के मामले में गभीर समस्याएँ पेश आई है।

बिजली के क्षेत्र में राज्य विजली बोर्डों की मार्गा हालग के कारण निर्मा बिजली-उत्पादकों के लिए आवश्यक विन जुटाना काफी करिन होना है। दरअमल असगत शुल्क, दरों और वितरण के स्तर पर ही प्रेमण तथा पितरण वरवादी के कारण राज्य बिजली बोर्डों के साथ विश्वसनीयता का मंकट है। इन क्षेत्र की बेहतरी के लिए सुधारों की शुरुआत शुल्क-मुधार तथा वितरण के निर्धासरण में की जानी चाहिए थी। उधर दूरसंचार क्षेत्र को भी कई प्रकार की परेशानियाँ धेरे हुए हैं। दरअसल, नए निजी निवेशकों द्वारा लाइसेंम-शुल्क मरीखें अपने टायित्व न निभा पाने तथा विनियमन प्राधिकरण के अधिकार-क्षेत्र और शांक्नलों की लेकर भी विवाद बने हुए हैं।

इन तमाम मुद्दों को गहराई में जाए बगैर यह कहा जा सकता है कि विनियमित ढॉबागत क्षेत्रों के लिए निजी निवेश जुटाना वाम्लव में कहीं अधिक जिटल कार्य है। निजी निवेशकों को मूल्य-विनियमन का पासन काने के साथ-साथ कुछ बड़े सार्वजनिक उपक्रमों के एकाधिकार से भी जुझना पहला है। पिट शुल्क-व्यवस्था लाभप्रद न हो या फिर जनता की नजरों में से अनुधित हों तो मूल्य-विनियमन के कारण दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसी प्रकार बड़े सार्वजनिक उपक्रमों को एकाधिकार का स्थिति से निपटना भी अपने-आप में मामूली समस्या नहीं है। निजी दूरसचार कंपनियों को अतर-संपर्क के लिए सार्वजनिक दूरसचार प्रणाली के साथ तालमेल बैठाना होता है। निजी बंदरगाहों को रेल-संपर्क के लिए रेलवे से संपर्क साधना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि निजी निवेशकों को ऐसा माहौल उपलब्ध कराया जाए, जिसमें वे इस पूरे खेल के सभी नियमों के बार में कुछ हद तक तो निश्चित हो सकें। इसके लिए सुदृढ़ तथा विश्वसनीय विनियमन एजेसियों की जरूरत है, जो विनियमित शुल्कों का उचित निर्धारण करें तथा निजी निवेशकों के साथ भी न्यायोचित बरताव करें।

हमें अपनी नीतियों की समीक्षा करनी होगी। इन नीतियों को अतरगष्ट्रीय स्तर के अनुकूल बनाने के लिए कई क्षेत्रों में बदलाव करने होंगे। दूरसंचार के क्षेत्र में मरकार ने घोषण को है कि वह भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण (ट्राई) को सुदृढ करने के लिए कानून में संशोधन करेगी। यह एक अहम फेसला है तथा अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर इसे तेजी से लागू किया जाना चाहिए। हमें व्यवस्था की अन्य विनियमन एजेंसियों, जैसे—एस ई आर.सी, टी ए एम.पी. आदि पर भी ध्यान देना होगा, ताकि यह तय किया जा सके कि इन्हें भी मजबूत बनाए जाने की जरूरत है या नहीं।

4. दूसरी पीढ़ी के सुधार

दूसरी पीढ़ी के सुधारों के अतर्गत वे सुधार शामिल हैं, जिन्हें अब तक एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है; लेकिन अगले दशक के एजेंडे में जिन्हें प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

राज्यों में सुधार-प्रक्रिया

केंद्रीय सरकार में सुधारों के बारे में व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श, बहस आदि होती रही हैं, परंतु राज्यों के स्तर पर इन सुधारों को लागू करने की जरूरत पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। दरअसल, आम आदमी का वास्ता आम तौर पर जिन एजेंसियों से पड़ता है, वे प्रादेशिक सरकार के क्षेत्र में आती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि-विस्तार, सिचाई, बिजली-वितरण तथा ग्रामीण, राज्य और जिला सड़कें, शहरी डलाकों में नगर निगम सेवाएँ आदि ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ सरकारों की कार्यकुशलता का सीधा प्रभाव जनता के जीवन पर पड़ता है। ये सभी क्षेत्र प्रादेशिक सरकारों के दायरे में आते हैं।

कुछ प्रादेशिक सरकारों ने विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे—बिजली आदि में सुधार की

आवश्यकता महसूस की है। यह स्वागत योग्य कदम है: एमे गज्यों की मह्या काफी कम हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इनमें विम्नार होगा। इस क्षेत्र म सफलता का मूल मंत्र यह है कि विभिन्न क्षेत्रों को विश्लीय दृष्टि से उपयागी खन्द के लिए प्रयोगकर्ता से उचित शुल्क की वसूनी की जाए। विजनी नथा अन्य सेवाओं पर भी यहीं बात लागू होती है।

राज्यों मे विकास-संबंधी कई समस्याएँ प्रादेशिक सरकारों के राजियोगीय संकट को प्रतिध्वनित करती हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्या मिके सम्भागता को लेकर ही नहीं हं, अतिरिक्त संसाधन जुटाने से उम स्थित में भी कीई लाभ नहीं मिलनेवाला, जबिक हमारी व्यवस्था उन अभ्यापकों को बरपाणन करने के 'ना तैयार है, जो पढ़ाते ही नहीं हैं या स्कुलों में जान ही नहीं।

दुर्भाग्यवश देश के कई भागों में हमागे सरकारी त्ययस्था के एका में गाग्यत्र आई है। इसका कारण कुछ हट तक राजकोषीय सक्तर है, क्योर्गक धनाधान के चलते नैतिकता का पतन हो सकता है। अलबना कई स्थानों पर सरकारों अपन के स्तर में कमी के चलते जवाबदेही तथा प्रदर्शन के न रहने की वजह में ऐसा ्या है। यदि हमें अपने संसाधनों के माध्यम से प्रभावी विकास कार्यों को अनाम देना है तो प्रशासनिक सुधार करने आवश्यक हैं। निचले स्तरों पर आम भादमी बार भानीहारी बढ़ाने में व्यवस्था की जवाबदेही और कुशलता में सुधार आना है।

प्रादेशिक सरकारों को भी अपने नियत्रणों तथा प्रांक्रयाओं ने दिन्तर करने चाहिए। अधिकतर राज्यों में छोटा व्यापार स्थापित करने के लिए भी 30 में 40 प्रकार की स्वीकृतियाँ आवश्यक होती हैं। ये ही प्राय: भ्रष्टाचार सथा श्रीयण कर कारण बनती हैं। राज्यों के 'इंस्पेक्टर राज' को हटाने से छोटे स्तर के व्यापार की काफी लाभ पहुँचेगा और निवेश भी बढ़ेगा।

श्रम कान्न

श्रम बाजारों तथा श्रम कानूनों के क्षेत्र में मुधार की हथा अभा तक नहां पहुँची है, परंतु अब ऐसा करना बेहद आवश्यक है। अर्थशारजं हमेशा यह भानते आए हैं कि भारत के श्रम कानूनों के चलने विभिन्न कंपनियों को प्रतिमाणीं बाजागें में लचीलापन नहीं मिल पाता। उपक्रमों को सरकार की पृत्रांनुमीत निये बगेर श्रमकों की छँटनी करने या बाजारों की बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर किमी विशेष इकाई को बंद करने की छूट नहीं होती। श्रम कानूनों के अंतर्गत 'सेवा नियम' भी निहित होते हैं, जिन्हें आसानी से नहीं बदला जा सकता। इस प्रकार श्रमकों की विभिन्न गतिविधियों में दोबारा तैनाती करना भी काफी कटिन हो जागा है।

इन कानूनों को तैयार करने के पीछे मूल भावना नौकरियों को सुरक्षित रखने की थी, लेकिन मौजूदा रोजगार सुरक्षित रखने के चलते ये नए रोजगारों को निरुत्साहित करते हैं। हमारी पहले की बंद अर्थव्यवस्था या सीमित घरेलू प्रतिस्पर्धा के दौर में इनसे अधिक परेशानी नहीं थी, परंतु मुक्त अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है। नए प्रतिस्पर्धी माहौल मे भारतीय उद्योग को लचीलेपन की जरूरत है। वस्तुत लचीलापन न रहने से व्यापार का आधार व्यापक होना कठिन हो जाता है और साथ ही कुशलता बढ़ाने के लिए आवश्यक पुनर्गठन की प्रक्रिया में भी बाधा पहुँचती है।

अनुबंधित श्रम से संबंधित प्रावधानों को भी मंशोधित करने की आवश्यकता है। इनके चलते विभिन्न संस्थान उन मेवाओं को अनुबंध के आधार पर नहीं ले पाते, जिनकी आवश्यकता परिसर के भीतर होती हैं, जैसे—बागबानी, सफाई, सुरक्षा, कैफेटेरिया आदि। इस क्षेत्र में अधिक लचीलापन आने से छोटे स्तर की व्यापारिक गतिविधियाँ उन मौजूदा प्रतिष्ठानों में पनपेंगी, जो अपनी श्रम-शक्ति का आकार बढ़ाने के अनिच्छुक हैं। इस प्रकार रोजगार के अधिक अवसर जुटाने तथा प्रतिष्ठानों के विकास में भी मदद मिलेगी।

विधि व्यवस्था की कार्यप्रणाली

यदि हम दुनिया के अन्य देशों के साथ एकात्मक होने की इच्छा रखते हैं और भारी मात्रा में विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसे कानूनी तंत्र को आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत अनुबंध सबंधी अधिकारों और दायन्वों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। यह तंत्र ऐमा हो, जिसमें कानून स्पप्ट एवं पारदर्शी हो, प्रक्रियाओं की रफ्तार तेज हो और न्यायिक व्यवस्था राजनीतिक दबावों मे मुक्त होकर इस प्रकार काम कर सके कि उसके फैसलों को न्यायोचित माना जाए। इस क्षेत्र की कुछ आम समस्याएँ इस प्रकार हैं—

- हमारे तंत्र में ऐसे कई पुराने कानून अभी तक बने हुए हैं, जिन्हें समाप्त करने की जरूरत है।
- 2 जो कानून पुराने नहीं पड़े हैं, उनका प्रारूप प्राय: इस प्रकार का होता है कि उन कानूनों की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है। स्पष्टता के इस अभाव के चलते कई अनावश्यक कानुनों की जरूरत पड़ती है।
- 3 हमारी कानूनी प्रक्रियाएँ प्राय. काफी समय खाऊ होती हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रक्रियाएँ उन लोगों की मदद के लिए बनाई गई हैं, जो स्थगन चाहते हैं। यदि न्याय में देरी होना और न्याय न मिलना बराबर है तो यह कहना होगा कि हमारी व्यवस्था पर्याप्त न्याय सुनिश्चित नहीं करती।

4 सरकार भी प्राय कानृन व्यवस्था का रूपण नन से बात नहीं बना। अपने खिलाफ सुनाए गए लगभग सभा फेसला रहा तक कि रबण अपनी न्यायिक एजेसिया के फेसला पर भा कि अदानान का तक्या जा खटखटातों है। इस प्रकार की अपीतों के पीछे मृत्त प्रस्था यह रहनी है कि ऐसा न करने से सर्वाधित प्रशासनिक पाधिकरण को एकानिका प्र संदेह किया जा सकता है।

इन सबका नतीजा यह हुआ है कि हमारी अदानतों में मान राजि के क्यार हो गई है और फैसला आने में काफी लंबर समय लगता है। यहाँ एक आग महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इन समस्याओं का नुकस्पान आप नार्गाण्कां और छोटे व्यापारों को होता है। कई वकीलों की संवाओं का लाभ लेनेवाने अल प्रांतराना को प्रायः इनसे कम नुकसान होता है। इस क्षेत्र में व्यापक रनर पर क्याना करात की जहरत है।

हालाँकि सुधारों का एजेडा काफी व्यापक है, लेकिन यांद शम इनमें मह लागां प्रगति कर सकें तो अगले दशक में 7 या 8 प्रतिशत का विकास का न्याय पास किया जा सकता है। इस प्रकार का विकास वितरण की द्रिश में मन्दित हैं। वेंस् साथ-साथ गरीबी को भी कम करेगा।

[तेरहवॉ जवाहरलाल नेहरू स्पारक व्याख्यान (उपन्हों), नव ३२ १५२५]

の大は野野海の

उच्च आर्थिक विकास के लक्ष्य : राजकोषीय अवरोधक —राकेश मोहन

लंबी अवधि के आर्थिक विकास की आवश्यकता

लगभग 1,000 वर्षों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दमन के बाद सन् 1947 में आजादी प्राप्त करने (देखें तालिका-1) के बाद से अब तक हमने काफी लंबा सफर तय कर लिया है। उस समय देश अंधकार युग में जी रहा था। आज देश में बिजली उत्पादन की क्षमता 85,000 मेगावाट है, जबिक सन् 1947 में यह महज 1,362 मेगावाट थी। जीवन-संभाव्यता मात्र 32 वर्ष और साक्षरता 17 प्रतिशत थी; परंतु सन् 1991 मे ये ही आँकड़े क्रमशः 60 वर्ष और 52 प्रतिशत दर्ज किए गए। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद अगले तीन दशकों तक देश में आधिकारिक तौर पर 50 प्रतिशत गरीबी थी, जो अब घटकर 35 प्रतिशत है। साठ के दशक में देश में खाद्यान्न का गंभीर संकट उत्पन्त हुआ था, लेकिन उसके बाद किए गए उपायों से देश 20 वर्षों से भी अधिक अवधि से खाद्यान्न के मामले में आत्मिनभर हो गया है।

हालाँकि भारत की आजादी के बाद की प्रगित को देखकर हममें से अधिकतर निराश ही हैं, परंतु हमें अपनी सकारात्मक उपलब्धियों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। लगभग एक शताब्दी तक कायम रहे शून्य आर्थिक विकास के बावजूद स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् पहले तीन दशकों ने हो भविष्य के लिए निरतर आर्थिक विकास की आधारशिला रख दी थी; लेकिन प्रति व्यक्ति आय में 1.5 प्रतिशत से भी कम वार्षिक विकास-दर, देश भर में छाई गरीबी से निपटने के लिए अपर्याप्त थी। अलबता, आर्थिक विकास के लिए बुनियाद तैयार की जा चुकी थी और सन् 1980 तथा 1990 के दशकों मे यह विकास तेजी से होता दिखाई भी दिया। अस्सी के दशक मे प्रति व्यक्ति आय वार्षिक विकास-दर 3.5 प्रतिशत तक पहुँची, जिसके चलते गरीबी के अनुपात मे उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई।

बढ़ाने से ही इस मुकाम तक पहुँचना सभव हो सका है अगले 10 20 वर्षों के दौरान दश के आर्थिक विकास में जबस्टस्त तेजी लाकर ही लब्बी अविध तक कायम रहनेवाले आर्थिक विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

तालिका-2 (क) विश्व जी.डी.पी. के अंश, 1700-1995

						प्रतिशत	7
	1700	1820	1890	1952	1978	1995	_
चीन	23 1	32 4	13.2	5.2	5 0	10 9	_
भारत	22 6	15 7	11.0	3.8	3 4	46	
जापान	45	3 0	2.5	3 4	77	8 4	
यूरोप	23 3	26 6	40 3	29 7	27 9	23 8	
अमेरिका	0 0	13	13 8	28 4	21 8	20 9	
यू एस एस आर /रूस	3 2	4.8	63	8.7	9.2	2.2	_

तालिका-2 (ख) विश्व जी.डी.पी. की विकास-दरें (1700-1995)

(वार्षिक औसत चक्रवृद्धि विकास-दरें)

1.	700-1820	1820-1952	1952-78	1978-95
चीन	0.85	0.22	4 40	7.49
भारत	0.26	0 54	4 02	4 63
जापान	0.21	1 74	7 85	3.21
यूरोप	0.68	1 71	4 27	1.74
अमेरिका	2.57	3.78	3 46	2.47
यू एस.एस आर /रू	स 0.86	2.08	4.75	-5 56
विश्व	0,57	1 62	4.52	2.70

स्रोत एगस मेडीमन। लबी अवधि मे चीन का आर्थिक प्रदर्शन। पेरिस ओ ई सी डी. (1998)

पिछले तीन दशकों में जिन देशों ने प्रति व्यक्ति आय में 6 प्रतिशत से अधिक को वार्षिक विकास-दर दर्ज की है, वे अपनी सकल निवेश-दरों में उल्लेखनीय वृद्धि की वजह से ऐसा कर पाए हैं (देखें तालिका-3)। अगले 10 वर्षों में भारत को अपनी प्रति व्यक्ति आय में 6 प्रतिशत से अधिक विकास के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी एन पी.) विकास-दर में प्रतिवर्ष 7 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज कराना हागा। याद भारत इस नक्ष्य को हासिन करन में भारत हो जाना है तो भा सन 2010 में भी दश का प्रति व्यक्ति आय सन 1965 में हिन थाइ ने हैं । दि दणा में रह रहे प्रति व्यक्ति आय के स्तर से आश्रव नहीं हिन सकता। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अपना आर्थिक विकास-दर में महन्त्रपूर्ण बढ़ाचरी करने के बावजूद हम अधिकतर पूर्वी एशियाई देणां से पाले ही गहेगे।

नातिका - 3 मौजूदा मृल्यों में सकल निवेश - देरें : चुनिंदा देश (1952-94)

देश	मकल निवेश/म	न निवेश/सकल घेंग्लृ उत्पाद ('जी डी.पी.) (प्रनिणन)						
	1952-57	1958-77	1978 94					
भारत	12 0	104	23 3					
चीन	23 2	28 ও	34.2					
जापान	26 9	34.3	8.7.3					
कोरिया	1/9s	23.32	32 5					
ताइवान	15.2	24 4	25.9					
फ्रांस	18 8	25.2	210					
जर्मनी	23.4	25.2	206					
ब्रिटेन	15 3	18.7	17.4					
अमेरिका	19.0	18.5	18.7					

स्रोत एगम पेडौरान। लंबी अवधि में जीन का आर्थिक ग्रदर्शन। पेरिस तो वं सा भी १०००।

ऐसे अधिकतर देश, जो अपनी विकाम-दर्ग को 6 ग्रांतगत तक करने में सफल रहे हैं, ने अपने सकल घरेल् पूँजी-निर्माण में जो छा. भी के 30 ग्रांतशत में अधिक की वृद्धि कर ऐसा किया है। भारत का मौज्दा निषेश -अनुगत 25 मे 27 प्रतिशत के आस-पास है। अगले कुछ ही वर्षों में इसे 30 प्रतिशत में अधिक करने की आवश्यकता है। उच्च आर्थिक विकास के लिए ढाँचागत तंत्र में निन्नेण प्रमुख भूमिका निभाता है। भारतीय ढाँचागत रिपोर्ट के अनुसार 7 प्रतिशत से आधिक जी.डी पी के लिए नब्बे के दशक के मध्य में इसके 5.5 प्रतिशत के आंकड़े को

^{1. 1978-91}

^{2, 1960-77}

के 2.5 से 3 प्रतिशत के बराबर वृद्धि करनी होगी। इस मुकाम तक पहुँचने की राह मे मुख्य अडचन राज्यों तथा केंद्र की बिगडती राजकोपीय स्थिति हैं। इसी के चलते सरकार की निवेश-क्षमता में अस्सी

सन् 2005 06 तक 8 प्रतिशत करने की जरूरत है इसके लिए ढाँचागत तत्र में निवश का बढ़ाना होगा रिपोर्ट में कहा गया है कि यह लक्ष्य उस स्थिति म हो प्राप्त हो सकता है, जब सार्वजनिक क्षेत्र ढाँचागत विकास के लिए जी डी पी का 45 से 5 प्रतिशत का अपना मौजूदा निवेश जारी रखे और साथ ही निजी क्षेत्र भी इस निवेश में बढ़ोतरी करे। निजी क्षेत्र को सन् 2005 तक अपने निवेश में जी डी पी

बिगडता राजकापाय स्थिति है। इसी के चलते सरकार का निवेश-क्षमता में अस्सा के दशक से ही लगातार गिरावट हो रही है (देखें तालिका -4)। अलबत्ता, सन् 1991 में लागू सुधारों के बाद से निजी कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा निवेश-स्तर में वृद्धि

काफी उत्साहजनक है, लेकिन सार्वजनिक निवेश म्तर में गिरावट से इस क्षेत्र पर

तालिका-4

सार्वजनिक निवेश में गिरावट सकल पूँजी-निर्माण (जी.डी.पी. का प्रतिशत)

स्रोत भारत सरकार आर्थिक सर्वेक्षण (विभिन्न मृद्दे)।

प्रतिकल प्रभाव पड रहा है।

अवधि निजी कॉरपोरेट क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र कुल 1980-85 219 43 10.2 1985-90 23 7 45 10.5 1990-95 6.0 23.7 91 1995-98 83 70 24 0

केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति (१९८०-२०००)

कद्राय सरकार का वित्ताय स्थित (१९८०-२०००)

केंद्रीय सरकार की मौजूदा राजकोषीय स्थिति को समझने के लिए कम-से-कम पिछले 20 वर्षों के दौरान सरकार के व्यय तथा राजस्व को देखना होगा।

सन् 1980-85 में केंद्रीय सरकार का कुल व्यय जी.डी.पी का औसतन 16 8 प्रतिशत रहा और सन् 1985-90 के दौरान बढ़कर 20 5 प्रतिशत तथा सन

16.8 प्रातशत रहा आर सन् 1985-90 क दारान बढ़कर 20.5 प्रातशत तथा सन् 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में घटकर 16 से 17.5 प्रतिशत रह गया। इसके समानातर अस्सी के दशक के शुरू में गैर-योजनागत खर्च 10 प्रतिशत से बढ़कर

जी डी पी. का 13 प्रतिशत हो गया। यह बढ़ोतरी गैर-योजनागत खर्च की लगभग

सभा श्राणया म देखा गई, जसै—ब्याज- भुगनान, रक्षा क्याय पि आयरें पंत्रन, राज्यों के दिए ऋण आदि। इस अवधि में अन्य गैर-योजनगन म्वनं, जिसमें मुख्य हम सं सरकारी कर्मचारियों को दिए जानेवाला वेगन राचंधी भूगनान आसिन है जी.डी पी के लगभग 2 25 प्रतिशन पर स्थिर बना गरा, अस्यों के दशक से योजनागत खर्च बड़े और जी.डी पी के 6 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत नक चने गर। दूसरी ओर केंद्रीय सरकार का पूँजीगत ब्यय जी डी पी का 6 से 7 प्रतिशन रहा। अब केंद्रीय सरकार के योजनागत ब्यय तथा पूँजीगत ब्यय प्रकर की.डी पी के 4 प्रतिशत रह गए हैं।

यानी अस्सी के दशक में विकास में तेजी से हुए मृश्वर (देखें तालिक: 6) का कुछ हद तक कारण उच्च सरकारी व्यय (यांजनागन एवं गेर यो चनगणना और राजस्व तथा पूँजी रहा। यह विकास प्रक्रिया दिका करनी थी। सन् 199 में भूगतान तथा राजकोषीय संकट के दोहरे सतुलन के औरमें यह स्थब्द भी हा गया। ब्याज के रूप में होनेवाले भुगतान को अब केंद्रीय सरकार के व्यय का महत्त्वपूर्ण अग माना जाता है। पाँचवें वंतन आयोग को इम पूरे परिदृश्य में खलनायक के रूप में देखा जा रहा है और मौजूदा राजकोषीय समस्याओं का कारण भी कही भाग गता है। यहाँ उपलब्ध आँकडों से स्थप्ट है कि केंद्रीय सरकार के सार पर यह यब नहीं है। यहाँ उपलब्ध आँकडों से स्थप्ट है कि केंद्रीय सरकार के सार पर यह यब नहीं है। यहाँ तथा पुलिस विभाग को छोड़कर कुल सरकारी वंतन का औंकड़ों से अपकारी केन्न के रूप में गैर-योजनागत छर्च में इस अवधि में उतनी वृद्धि नहीं पूर्ण जितनी जी, जी, यो में देखी गई है। व्याज-भुगतान अब सेना और पुलिस को छो इकर छोव गैर यो भनामा सरकारी खर्चों का तीन गुने से भी अधिक हो गया है। इस राजकोषीय अमन्तन में सुधार की संभावना केंद्रीय सरकार की बढ़ती ऋण देनदारियों के क्षेत्र में भी गृह हैं।

तालिका- 6 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास

वर्ष	सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.)	प्रति व्यक्ति
1950-1980	3.5	13
1980-1990	S 5	3.5
1990-2000	6.0	4,3
2000-2010	7.5	6.0

^{*} अनुमानितः

इन आँकडों के अध्ययन से एक बात स्पष्ट है कि अस्सी के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश तथा अन्य सरकारी व्यय में काफी बढोतरी दर्ज की गई उस दशक के अंतिम वर्षों में रक्षा-खर्च भी इस दशक के आरभिक वर्षों में दर्ज

जी डी पी के 2.8 प्रतिशत के आँकड़े से बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गया। तत्पश्चात् लगातार गिरावट के बाद 2.5 प्रतिशत के स्तर पर निरतर कायम है।

लगातार गिरावट के बाद 2.5 प्रतिशत के स्तर पर निरतर कायम है। यदि सरकार को उधार ली गई रकम के निवेश से पर्याप्त धनराशि प्राप्त होती रहे तो सरकार पर ऋण-देनदारियों का बोझ कुल व्यय के अनुपात में नहीं

बढेगा। चूँकि सरकार जनता से संसाधन उधार लेकर नई परिसंपत्तियों में निवेश करती है, इमलिए सार्वजनिक परिसपत्तियों मे वृद्धि से कर-राजस्व में भी बढोतरी होनी चाहिए। सार्वजनिक ढाँचागत सुविधाओं में सुधार से कार्यकृशलता में भी

सुधार के साथ-साथ नए निजी निवेश और कर-राजस्व को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसी प्रकार सार्वजनिक उद्यमों द्वारा ढाँचागत तंत्र में निवेश से प्राप्त होनेवाले

लाभ में वृद्धि से गैर-कर राजस्व बढ़ना चाहिए। अलबत्ता, उधार लिये गए ससाधनों को यदि ऐसी गतिविधियों में निवेशित किया जाता है, जहाँ से पर्याप्त वापसी नहीं होती तो कुल राजस्व के अनुपात में ऋण संबंधी भुगतान लगातार बढ़ता रहेगा। भारत में पिछले 20 वर्षों के दौरान यही हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों को छोड़कर

केद्रीय सार्वजिनक उपक्रमों के निवेश पर धन वापसी शून्य के लगभग रही है। मूल्य-निर्धारण की गलत नीतियों, सार्वजिनक उपक्रमों की अकुशल कार्यप्रणाली और अन्य मुश्किलों के चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सन् 1980 के दशक से ही सरकार राजस्व में घाटे की स्थिति से जूझ रही है। फलस्वरूप तमाम सरकारी तथा

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निवेश के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा ऋण से जुटाए गए मसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन निवेशों से कुछ भी प्राप्त न होने की स्थिति में ऋण देनदारियों का बोझ निश्चित तौर पर बढ़ेगा। केंद्रीय सरकार की पिछले 20 वर्षों की राजस्व-प्राप्ति पर नजर डालना

कद्राय सरकार का 1पछल 20 वर्षा का राजस्व-प्राप्त पर नजर डालना जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ऋण सबंधी देनदारियाँ लगातार किस प्रकार बढ़ रही है। अस्सी के दशक के अंतिम वर्षों में व्यय में वृद्धि के समानांतर इस अविध में राजस्व मे भी बढ़ोतरी के प्रयास किए गए। राजस्व में बढ़ोतरी मुख्यत-

सीमा शुल्क के रूप में प्राप्त राशि से हुई, जो अस्सी के दशक के आरंभ में जी डी पी के 2.8 प्रतिशत से बढ़कर इस दशक के अंत मे 3.9 प्रतिशत तक जा पहुँचा। ऐसा आयात में वृद्धि (जिसके कारण भुगतान-संकट उत्पन्न हुआ) तथा सीमा शुल्क के स्तरों में बढ़ोतरी के कारण हुआ। सीमा शुल्क में हुई इस वृद्धि से

ससाधनों के आबटन में कुशलता का अभाव देखा गया जर नियान के जिस में भी मिला कि उगेमन के देशक के अने में भी प्रतिस्पर्धात्मकता में कभी आई। अम्मी के देशक के अने में भी प्रतिस्पर्धात्मकता में कभी आई। अम्मी के देशक के अने में भी निवस की प्रविक्त को स्मृत्य पर भी निवस की प्रविक्त को स्मृत्य विश्व में निवस की प्रतिक्र को में बगवान बहीनों की की की की प्रतिक्र को में बगवान बहीनों की की की की की प्रतिक्र की की अब वहकर है प्रतिक्र के जा पहुँचे हैं। देशे में कभी के बावजृद यह वृद्धि को मिला की का अवस्था की जानका प्राप्तियों में देखी गई (देखें तालिका 7)। कर सावस्थ में कभी अवस्था करा जैसे—सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में कभी के कारण कार में किया शुल्क की कमी के परिणामस्वरूप इसमें गिरावट स्वाधाविक थी, जीन कार कार की वस्ती में आई कभी को समझना काफी किनन हैं।

तालिका-7 (क) केंद्रीय मरकार के कुल गजस्व का स्वरूप (जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में)

1	980-	1985 -	1990 -	1995-	1997	1998	1999-
	85	90	95	99	98	99	00
राजस्व प्राप्ति (कुल)	9.43	11 11	10 07	972	9-46	973	0 59
1. सकल कर-राजस्व	9 93	11 20	10 26	9.75	9 84	9 15	9,28
क. प्रत्यक्ष कर	2.06	2.08	2 36	2 84	2.62	2.98	3,03
कॉरपोरट	1 16	1 07	1.24	1.50	141	106	1 65
आय	0,90	1 01	1 12	1 34	121	1.30	1 38
ख परोक्ष कर	7.50	8 82	7 54	6,45	6.23	5.90	5 98
सीमा शुल्क	2 76	3 92	3 28	3 00	284	260	2.71
उत्पाद शुल्क	4.74	4.89	4 27	3.44	3.39	3 27	3 27
ग. अन्य कर							
राजस्व	0.37	0.30	0.35	0.47	0 49	0.27	0 27
@ कर-राजस्व मे							
राज्यों का अंश	2.64	2.84	2 75	2.71	3,08	241	2.48
2. गैर कर-राजस्व	2 13	2 77	2.57	2 68	2,70	2.98	2 80

स्रोत - भारत स्थाकार, विभिन्न वर्षी के बाजट दस्तावात्र।

नोट: राजस्व प्राप्ति (कुल) = सकल कर-गजम्ब (गुल्मां का संक्षा , मैं: कर गडम्बा

तालिका 7 (ख) केंद्रीय संग्कार के कुल राजस्व का संरचनात्मक स्वरूप (1980-2000) (कुल राजस्व का प्रतिशत)

1980- 1985- 1990- 1995- 1997- 1998- 1999-

			.,	.,	.,,,	. / / 4		,,,,	. , , ,
			85	90	95	99	98	99	00
राज	नस्व	प्राप्ति							
(व	र ्+	गैर कर							
श्व	तस्व) कुल	100 00	100 00	100 00	100 00	100 00	100 00	100 00
1	सव	ज्ल कर-							
	राज	स्व	105 46	100 80	101.84	100 31	103 97	94 31	96 72
	क.	प्रत्यक्ष कर	21.91	18.76	23.60	29.18	27 72	30.75	31.56
		कॉरपोरेट	12 27	9.64	12 42	15 44	14 95	17 16	17 18
		आय	9 64	9.12	11.18	13 74	12 77	13 59	14.38
	ख.	परोक्ष कर	79 64	79.35	74.79	66.29	65.84	60.79	62 35
		सीमा शुल्क	29.27	35.28	32.43	30 87	30 02	27 05	28 23
		उत्पाद शुल्क	50 37	44.07	42.36	35.42	35 82	33 74	34 12
	ग.	अन्य कर							
		राजस्व	3.90	2.69	3.44	4.84	10 42	2 77	2 81
	@	कर-राजस्व	मे						
	राज	यों का अश	28.07	25.61	27.39	27.93	32 52	24 84	25 86
2	गैर	कर-राजस्व	22.55	24.94	25.63	27.62	28.55	30.53	29.14
स्रोत	1 2	गरत सरकार, विर्	भेन वर्षों वे	म बजट द स	तावेज।				

नोट राजस्व प्राप्ति (कुल) = सकल कर-राजस्व (राज्यो का अश) + गैर कर-राजस्व।

मिद्धांत रूप में तो औद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि से उत्पाद शुल्क भी वढ़ना चाहिए, परंतु दो कारणों से आशातीत विकास नहीं हो सका। सन् 1993-96 की अविध को छोडकर शेष वर्षों में औद्योगिक विकास-दर उतनी अधिक नहीं रही, जितनी आर्थिक सुधारों की वजह से होने की संभावना थी। दूसरे, समूचे औद्योगिक क्षेत्र में एम ओ डी.वी ए टी (MODVAT) के प्रगामी विस्तार के कारण भी उत्पाद शुल्क प्राप्ति में कमी हुई। अस्सी के दशक से ही गैर कर-राजस्व का ऑकड़ा 2 6 प्रतिशत से 3 प्रतिशत के बीच कायम है। अधिक निवेश के बावजूद वसूली अधिक नहीं हो पाई है।

पिछले 20 वर्षों में केवल अम्सी के दशक के बाद के 5 वर्षों को छोड़का सकल कर-राजस्व 10 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर है। इसी अर्त्राथ में कुल खर्च काफी ऊँचे स्तर पर जा पहुँचा है।

नालिका-8 केंद्रीय सरकार की पूँजी प्राप्नियों का स्वरूप

2 बाहरी सहायता 0 86 0.66 0 65 0.10 0.08 0 06 0.0 3 ऋण वसूली 1.32 1 15 0.87 0 62 0 59 0 71 0 64 ता वसूली 0 76 1.47 1.29 1.46 1.73 1 78 0 4 5. राज्य भविष्य निधि (कुल) 0 19 0 24 0 22 0 26 0.31 0.33 0 3.0 6. विशेष जमा (कुल) 0.49 1 27 1.07 0.46 0 32 0 57 0 58 0 58 0 59 0 59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59	PIKIP	47431					-			
जी.डी पी. के प्रतिशत के तौर पर 1. आतरिक ऋण (कुल) 193 1.85 179 2.70 230 297 37 2 बाहरी सहायता 086 0.66 0.65 0.10 0.36 0.06 0.0 3 ऋण वसूली 1.32 115 0.87 0.67 0.59 0.71 0.0 4. लघु बचत (कुल) 0.76 1.47 1.29 1.46 1.73 1.78 0.4 5. राज्य भविष्य निधि (कुल) 0.19 0.24 0.22 0.26 0.31 0.33 0.3 6. विशेष जमा (कुल) 0.49 1.27 1.07 0.46 0.32 0.57 0.56 7 विनिवेश 0.00 0.00 0.26 0.17 0.06 0.55 0.56 8. अन्य पूँजी प्राप्ति 0.66 0.66 0.40 0.34 1.55 0.55 0.76 कुल पूँजी प्राप्ति 0.66 0.66 0.40 0.34 1.55 0.55 0.76 प्रतिशत अंश 1. आंतरिक ऋण (कुल) 31.43 25 37 26.39 43 99 33.11 52.64 60 67 2. बाहरी महायता 14.38 9.03 10.26 1.82 1.11 0.75 0.76 3 ऋण वसूली 21.46 15.79 13.65 10.35 8.47 9.51 10.01		1980-1985-1990-1995 -1997-1998-1999								
1. आतरिक ऋण (कुल) 1 93 1.85 1 79 2.70 2 30 3 97 3 7 2 बाहरी सहायता 0 86 0.66 0 65 0.10 0.08 0 06 0.0 3 ऋण वसूली 1.32 1 15 0.87 0 67 0 59 0 71 0 6 4 लघु बचत (कुल) 0 76 1.47 1.29 1.46 1.73 1 78 0 4 5 राज्य भविष्य निधि (कुल) 0 19 0 24 0 22 0 26 0.31 0.33 0 3 6 विशेष जमा (कुल) 0.49 1 27 1.07 0.46 0 32 0 57 0 58 8 अन्य पूँजी प्राप्ति 0.66 0 66 0.40 0 34 1 55 0.59 0.36 3 कुल पूँजी प्राप्ति 6 21 7 30 6 54 6 10 6.94 7 44 6 1 प्रतिशत अंश 1 अतिरिक ऋण (कुल) 31.43 25 37 26.39 43 99 33.11 53 64 60 67 2 बाहरी सहायता 14.38 9.03 10 26 1.82 1 11 0.75 0 76 3 ऋण वसूली 21 46 15.79 13.65 10.35 8.47 9.51 10 01		85	90	95	99	98	99	00		
2 बाहरी सहायता 0 86 0.66 0 65 0.10 0.36 0.06 0.0 3 ऋण वस्तृली 1.32 1 15 0.87 0 67 0 59 0 71 0 6 4. लघु बचत (कुल) 0 76 1.47 1.29 1.46 1.73 1 78 0 4 5. राज्य भविष्य निधि (कुल) 0 19 0 24 0 22 0 26 0.31 0.33 0 3 6. विशेष जमा (कुल) 0.49 1 27 1.07 0.46 0 32 0 57 0 56 7 विनिवेश 0.00 0 00 0 26 0 17 0 00 0 55 0 56 8. अन्य पूँजी प्राप्ति 0.66 0 66 0.40 0 34 1 55 0.59 0.10 कुल पूँजी प्राप्ति 6 21 7 30 6 54 6 10 6.94 7 44 6 1- प्रतिशत अंश 1. आंतरिक ऋण (कुल) 31.43 25 37 26.39 43 99 33.11 53 64 60 67 2. बाहरी सहायता 14.38 9.03 10 26 1.82 1 11 0.75 0 76 3 ऋण वसूली 21 46 15.79 13.65 10.35 8.47 9.51 10 01	जी.डी पी. के प्रतिशत	के तौर प	रर	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		~	***	-		
3 ऋण वसूली 1.32 115 0.87 0.67 0.59 0.71 0.6 4. लघु बचत (कुल) 0.76 1.47 1.29 1.46 1.73 1.78 0.4 5. राज्य भविष्य निधि (कुल) 0.19 0.24 0.22 0.26 0.31 0.33 0.3 6. विशेष जमा (कुल) 0.49 1.27 1.07 0.46 0.32 0.57 0.58 7 विनिवेश 0.00 0.00 0.26 0.17 0.06 0.55 0.58 8. अन्य पूँजी प्राप्ति 0.66 0.66 0.40 0.34 1.55 0.55 0.56 कुल पूँजी प्राप्ति 6.21 7.30 6.54 6.10 6.94 7.44 6.1- प्रतिशत अंश 1. आंतरिक ऋण (कुल) 31.43 25 37 26.39 43 99 33.11 53.64 60.67 2. बाहरी सहायता 14.38 9.03 10.26 1.82 1.11 0.75 0.76 3 ऋण वसुली 21.46 15.79 13.65 10.35 8.47 9.51 10.01				179	2.70	2 30	3.99	3 72		
4. लघु बचत (कुल) 0 76 1.47 1.29 1.46 1.73 1 78 0 4 5. राज्य भविष्य निधि (कुल) 0 19 0 24 0 22 0 26 0.31 0.33 0 3 6. विशेष जमा (कुल) 0.49 1 27 1.07 0.46 0 32 0 57 0 58 7 विनिवेश 0.00 0 00 0 26 0 17 0 00 0 55 0 58 8. अन्य पूँजी प्राप्ति 0.66 0 66 0.40 0 34 1 55 0.50 0.10 कुल पूँजी प्राप्ति 6 21 7 30 6 54 6 10 6.94 7 44 6 1- प्रतिशत अंश 1. आंतरिक ऋण (कुल) 31.43 25 37 26.39 43 99 33.11 53 64 60 67 2. बाहरी सहायता 14.38 9.03 10 26 1.82 1 11 0.75 0 76 3 ऋण वसुली 21 46 15.79 13.65 10.35 8.47 9.51 10 01	2 बाहरी सहायता	0 86	0.66	0.65	0.10	0.08	୍ୟ ଫ୍ର	0.05		
5. राज्य भविष्य निधि (कुल) 019 024 022 026 0.31 0.33 03. 6. विशेष जमा (कुल) 0.49 127 1.07 0.46 032 057 050 7 विनिवेश 0.00 000 026 017 000 055 055 8. अन्य पूँजी प्राप्ति 0.66 066 0.40 034 155 0.55 0.50 कुल पूँजी प्राप्ति 621 730 654 610 6.94 7.44 61- प्रतिशत अंश 1. आंतरिक ऋण (कुल) 31.43 25 37 26.39 43 99 33.11 53 64 60 67 2. बाहरी सहायता 14.38 9.03 10 26 1.82 1 11 0.75 0 76 3 ऋण वसुली 21 46 15.79 13.65 10.35 8.47 9.51 10 01	3 ऋण वसूली	1.32	1 15	0.87	0.62	0.89	07:	301		
(कुल) 0 19 0 24 0 22 0 26 0.31 0.33 0 3. 6. विशेष जमा (कुल) 0.49 1 27 1.07 0.46 0 32 0 57 0 50 7 विनिवेश 0.00 0 00 0 26 0 17 0 06 0 55 0 50 8. अन्य पूँजी प्राप्ति 0.66 0 66 0.40 0 34 1 55 0.50 0.30 कुल पूँजी प्राप्ति 6 21 7 30 6 54 6 10 6.94 7 44 6 1- प्रतिशत अंश 1. आंतरिक ऋण (कुल) 31.43 25 37 26.39 43 99 33.11 53 64 60 67 2. बाहरी सहायता 14.38 9.03 10 26 1.82 1 11 0.75 0 76 3 ऋण वसुली 21 46 15.79 13.65 10.35 8.47 9.51 10 01		0 76	1.47	1.29	1.46	1,73	1.78	0.44		
6. विशेष जमा (कुल) 0.49 1 27 1.07 0.46 0 32 0 57 0 58 7 विनिवेश 0.00 0 00 0 26 0 17 0 0 0 0 55 0 58 8. अन्य पूँजी प्राप्ति 0.66 0 66 0.40 0 34 1 55 0.50 0.70 कुल पूँजी प्राप्ति 6 21 7 30 6 54 6 10 6.94 7 44 6 1- प्रितिशत अंश 1. आंतरिक ऋण (कुल) 31.43 25 37 26.39 43 99 33.11 53 64 60 67 2. बाहरी महायता 14.38 9.03 10 26 1.82 1 11 0.75 0 76 3 ऋण वसूली 21 46 15.79 13.65 10.35 8.47 9.51 10 01	5. राज्य भविष्य निधि									
7 विनिवेश		0 19	0.24	0.22	0.26	0.33	0.33	0 33		
8. अन्य पूँजी प्राप्ति 0.66 0.66 0.40 0.34 : 55 0.50 0.70 कुल पूँजी प्राप्ति 6.21 7.30 6.54 6.10 6.94 7.44 6.1- प्रतिशत अंश 1. आंतरिक ऋण (कुल) 31.43 25 37 26.39 43 99 33.11 53.64 60.67 2. बाहरी सहायता 14.38 9.03 10.26 1.82 1.11 0.75 0.76 3 ऋण वसूली 21.46 15.79 13.65 10.35 8.47 9.51 10.01		0.49	1 27	1.07	0.46	0.32	0.57	0.58		
कुल पूँजी प्राप्ति 621 730 654 610 6.94 7.44 61- प्रतिशत अंश 1. आंतरिक ऋण (कुल) 31.43 25 37 26.39 43 99 53.11 53 64 60 67 2. बाहरी सहायता 14.38 9.03 10 26 1.82 1 11 0.75 0.76 3 ऋण वसूली 21 46 15.79 13.65 10.35 8.47 9.51 10 01	7 विनिवेश	0,00	0 00	0 26	0.17	CRE	0.55	3.55		
प्रतिशत अंश 1. आंतरिक ऋण (कुल) 31.43 25 37 26.39 43 99 33.11 53 64 60 67 2. बाहरी सहायता 14.38 9.03 10 26 1.82 1 11 0.75 0.76 3 ऋण वसूली 21 46 15.79 13.65 10.35 8.47 9.51 10 01	 अन्य पूँजी प्राप्ति 	0.66	0 66	0,40	0.34	1 55	0.59	3.16		
1. आंतरिक ऋण (कुल) 31.43 25 37 26.39 43 99 33.11 53 64 60 67 2. बाहरी सहायता 14.38 9.03 10 26 1.82 1 11 0.75 0 76 3 ऋण वसूली 21 46 15.79 13.65 10.35 8.47 9.51 10 01	कुल पूँजी प्राप्ति	6 21	7 3C	6 54	6 10	6.94	7.44	6 14		
2. बाहरी सहायता 14.38 9.03 10 26 1.82 1 11 0.75 0 76 3 ऋण वसूली 21 46 15.79 13.65 10.35 8.47 9.51 10 01	प्रतिशत अंश						And the state of t			
2. बाहरी सहायता 14.38 9.03 10 26 1.82 1 11 0.75 0 76 3 ऋण वसूली 21 46 15.79 13.65 10.35 8.47 9.51 10 01	1. आंतरिक ऋण (कुल	31.43	25 37	26.39	43 99	33.11	53 64	60 67		
3 ऋण वसूली 21 46 15.79 13.65 10.35 ४.47 ५.51 1001	2. बाहरी सहायता	14.38	9.03	10 26	1.82	1.11	0.75	0.76		
A 200 200 (200)	3 ऋण वसूली	21 46	15.79	13.65	10.35	8.47		10 01		
4. लघु वचत (कुल) 11.48 20 38 19.39 23.90 24.95 23 96 7.22	4. लघु वचत (कुल)	11.48	20 38	19.39	23,90	24.95	23.96	7.22		
5. राज्य भविष्य निधि	5. राज्य भविष्य निधि									
(कुल) 3.14 3.23 3.41 4.14 4.40 4.42 5.42	•	3,14	3.23	3 41	4, 14	4 40	4 42	5 42		
6. विशेष जमा (कुल) 7 96 17.54 16.50 182 456 7.63 9 44	-	7 96	17.54	16.50	7.82					
7. विनिवेश 00.00 0.00 4.12 2.40 0.33 7.44 9.03		00.00								
8. अन्य पूँजी प्राप्ति 10 14 8.65 6 28 5 59 22 40 7.36 2.54		10 14	8.65	6 28	5 59	22 40		2.54		
कुल पूँजी प्राप्ति 100.00 100 00 100.00 100.00 100 00 100.00 100 00	कुल पूँजी प्राप्ति	100,00	100 00	100,00	100.00	100 00	100,00	177 00 .		

स्रोतः भारत सरकार, विभिन्न वर्षों के बजर इस्तावंज।

राजस्व में कमी को भरपाइ केंटाय सरकार ने निरंतर उच्च पूँजी प्राप्तियों जो पिछले 20 वर्षों क दागन जी. डी. पी. का 6 मे 7 5 प्रतिशत तक रही, के जिरये की है। बाहरी सहायता अब सरकार के वित्त- पोषण का महत्त्वपूर्ण स्रोत नहीं रह गई ह। लघ् बचन प्राप्तियाँ धन जुटाने का काफी खर्चीला तरीका है, क्योंकि इनमे बचतकर्मा को काफी अधिक कर राहत प्राप्त होती है। लघु बचत प्राप्तियों का 75

प्रतिशत अंश प्रार्टीशक संग्कारों के राजम्य घाटे के वित्त-पोषण के लिए उपलब्ध कगया जाता है। (यर्की कारण है कि सन 1999-2000 में प्रादेशिक सरकारों को लघ् बचतो में संबंधित प्राप्तियाँ तथा अग्रिम गशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था बद

कर दी गई है।)

मन 1990 के दशक में व्यवस्था में आए दो बदलावों के कारण केंद्रीय

सरकार के लिए रूप लेना और भी महँगा माबित हुआ। पहले, राजस्व घाटे के एक बड़े भाग की भरपार्ट मंर्गिटकीकरण के जिंग्ये हो जाती थी (देखें तालिका-9), परत्

अब ऐसा नहीं है। यही कारण है कि राजस्व घाटे की व्याज सबंधी कीमतें भी बढ गई हैं। दुसरे, ज्याज तरे, के निनियमीकरण के बाद सरकार द्वारा लिये गए ऋण पर

देथ ब्याज दर्ग बाजार दरों के बरावर ही गई है, जबकि पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि

तब बॅंक सरकार को बाजार दरी में कम दर पर ऋण मुहैया कराते थे। पिछले 20 वर्षों से जारों उच्च राजकोषीय घाटे के परिणाम तालिका-10 मे

देखे जा सकते हैं। कंद्रीय सरकार की ऋण मंबंधी देनदारियाँ सन् 1980-85 मे कर राजस्य का लगभग 30 प्रतिशत थीं, जर्वाक अब व्हकर 70 प्रतिशत तक हो गई हैं। वह दिन अब दूर नहीं, जब ऋण देनदारियाँ कर-राजस्व के बराबर हो जाएँगी। ऋणों से ज्डी देनदारियों में युद्धि के कारण राजम्ब-घाटा सन् 1980-85

में राजकोणीय घाट के अनुपान में 17 प्रतिशत रहने के बाद अब 50 प्रतिशत हो गया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मीजूदा ऋणो का आधा भाग हमारे मीजुदा

खर्ची पर ही व्यय हो रहा है। इस प्रकार मीजूदा व्यय से कुछ हाथ नहीं लगनेवाला और भविष्य में भी ऋग संबधी देनदारियों का बढ़ना तब तक जारी रहेगा, जब तक इस स्थिति में सुधार के ठपाय नहीं किए जाएँगे।

केंद्रीय सरकार पिछले 20 वर्षों से निरंतर राजकोषीय घाटेवाली राजकोषीय व्यवस्था पर अमृत्व कर रहाँ हैं। अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध के दौरान यह घाटा

अन्य वर्षों की तुलना में काफी वढ़ गया। सन् 1990-91 में देश के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। राजकोषीय घाटे के स्तर्मे निरंतर वृद्धि के परिणाम कई रूपो मे सामने आते हैं। शुन्य अथवा काफी कम वापसीवाली वित्तीय गतिविधियों को जाता है। इस गैर-उत्पादक चालू खर्च भी बढते हैं, जो राजस्व घाटे को अधिकाधिक ऊँचे स्तर तक धकेलते हैं, यानी और अधिक ऋण लेने की जरूरत पड़ती है। दूसरे, राजस्व तथा व्यय का अधिकांश जब ऋण सबधी अदायगी में खर्च होने लगता रे तो सरकार की अन्य गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। इस प्रक्रिया में मामाजिक तथा ढाँचागत सुविधाओं के क्षेत्र में सरकारी पूँजीगत व्यय सर्वाधिक प्रभावित होता है।

ऋण के माध्यम से वित्त-पोषित करने से व्याज-भुगतान का आकार काफी वढ़

तालिका-9

केंद्रीय सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का संरचनात्मक स्वस्तप तथा वित्त पोषण (जी.डी.पी. के प्रतिशत में)

	1980-	1985-	1990-	1995-	1995~	1996-	 1997-
	81_	86	95	97	96	97	98
1 कुल खर्च (क+ख)	15 20	19 03	17 61	16 27	15 78	15 57	16 39
क. राजस्व खर्च	10 59	12 94	13.27	12 99	12 93	12.87	12 74
ख. पूँजी खर्च	4 60	6 09	4 33	3 28	2 85	2.70	3 65
2. कुल प्राप्ति (क+ख)	9 10	10.69	10 93	10 45	10 39	10.35	10 11
क. राजस्व प्राप्ति	9 10	10.69	10 07	9 94	10 27	10.31	9.46
ख. गैर ऋण पूँजी प्राप्ति	r o oo	0.00	0.86	0 52	0 12	0 04	0 65
3. सकल राजकोषीय	6 10	8.33	6 68	5.82	5.38	5.23	6 28
घाटा वित्त-पोषित							
क. घरेलू वित्त-पोपण	5 16	7,78	5.95	5.51	4 5 1	4.99	6 21
अ. बाजार ऋण	1 97	1.86	1 77	2.70	2.96	1.57	2 30
ब. अन्य देनदारी	1.37	3.89	2.94	2 54	1 52	2.39	3 91
(।) लघु बचत	0 82	1 64	1.20	1 34	0 90	0.95	1 73
(॥) राज्य भवि	ाध्य						
निधि	0 16	0.16	0 22	0 26	0 20	0.18	0 34
स. पारंपरिक घाट	T 1 82	2.03	1.23	0.27	0 03	1 03	0 00
ख बाहरी वित्त-पोषण	T 0 94	0 55	0 74	0.31	0.88	0.23	0.08
पारंपरिक घाटा/घरेलू							
वित्त-पोषण (प्रतिशत)	35 29	26.04	20 85	10.66	0.63	20.68	0 00
स्रोत • भारत सरकार, विभिन्न व	षोँ के बङ	ाट दस्तावे	न ।				

भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा एव वित्तीय, विभिन्न वर्ष।

तालिका 10 केंद्रीय सरकार की बढ़ती ऋण सेवा का बोझ (1980-2000)

	1980-	1985-	1990-	1995-	1997-	1998-	1999-
	85	90	95	99	98	99	00
के तौर पर							
कर-राजस्व के प्रतिशत	30.1	40 5	58 9	65.9	68 6	70 5	71 7
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत	23.5	30 4	43.7	47.6	49 0	49 0	50 8
कुल राजस्व के प्रतिशत	14.3	18.4	26.4	29.3	28 3	27 7	31 0
कुल खर्च के प्रतिशत	13.3	16.5	24 6	28.3	28.3	27 4	31 0
जी डी.पी. के प्रतिशत	2.2	3.4	44	4.6	46	48	4 9
राजस्व घाटा/							
राजकोषीय घाटा प्रतिशत	17.0	32 0	48.0	50.0		_	

स्रोत भारत सरकार, विभिन्न वर्षी के बजट दस्तावेज।

सार्वजिनक ऋणों के लगातार बढ़ते स्तर का प्रभाव शेष अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। सरकार के घाटो का वित्त-पोपण करने की मजबूरी के कारण व्यावसायिक बैंकों की जमा राशियो पर चालू आरक्षित अनुपात (सी आर आर) तथा वैधानिक तरलता अनुपात (एस.एल आर) का स्तर भी भारतीय रिजर्व बैंक को ऊँचा बनाए रखना पड़ता है। इस प्रकार बैंकों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों मे परिवर्तन करना पड़ता है, जिससे शेष अर्थव्यवस्था को अधिक व्याज-दरं झेलनी पडती हैं। इसके अलावा सरकार के सपूर्ण वित्तीय क्षेत्र, जैसे—लघु बचतों, बीमा आदि से संसाधन जुटाने की कवायद के कारण राजकोषीय घाटे के उच्च स्तर से वित्तीय क्षेत्र में लागू सुधारों की राह में भी अड़चन आनी है। इस परिदृश्य में तो 7 प्रतिशत से अधिक की विकास-दर की सभावना ही नहीं है। यह विकास-दर जी.डी.पी के 30 प्रतिशत के बराबर निवेश स्तर प्राप्त करने पर ही संभव है। इसके लिए सार्वजिनक बचत तथा निवेश को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है।

प्रादेशिक सरकारों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति

प्रादेशिक सरकारों के बिगड़ते आर्थिक हालात का जायजा लेने से पहले उनके दायित्वों को जानना जरूरी हैं। सामाजिक सेवाओं के प्रावधान से जुड़े अधिकाश सार्वजनिक खर्च की जिम्मदारा राज्यों की ही होतं. है . प्रादेशिक सरकार दूरसचार, नागरिक-उड्डयन, रेलवे तथा प्रमुख वदरगाहों को छोड़कर अधिकाश

दूरसचार, नागरिक-उड्डयन, रेलवे तथा प्रमुख वदरगाही की छोड़कर आधकाश ढाँचागत सेवाओं को जुटाती है। कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उनकी होती है।

इस लिहाज से राज्यों द्वारा निवेश करने की क्षमता में कमी में मानव-विकास आर अतत. आंतरिक सरक्षा के लिए खतरा खड़ा हो सकता है। इसके अलावा आर्थिक

विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

केंद्र की ही तर्ज पर राज्यों के कुल खर्चों में भी सन् 1980 के दशक में पृद्धि हुई। 1980-85 में इनका स्तर जी डी पी का 16 प्रतिशत रहने के बाद सन् 1935-90 में 17 3 प्रतिशत तक हो गया (देखें तालिका-11)। अलबत्ता अगले दशक में इसमें गिरावट आई और इस दशक के अंतिम वर्षों में यह ऑकड़ा 16 5 प्रतिशत हो गया। केंद्रीय सरकार की ही तरह राज्यों का भी पूँजीगत खर्च अस्सी के दशक में

जी डी.पी का 5 प्रतिशत रहा और अब घटकर लगभग 3 प्रतिशत हो गया है। जहाँ एक ओर अस्सी के दशक के आरंभिक वर्षों में राजस्व ओर पूँजींगत रार्व का अनुपात 70. 30 रहा, वहीं अब यह 83 17 हो गया है। राज्यों के पूँजींगत खर्च में अस्सी के दशक के अंतिम वर्षों में भी गिरावट देखीं गई। टन सरकारों की भी

मुख्य समस्या बढ़ती ऋण-अदायगों को लेकर थी, जो अस्मी के दशक के शुरु आती वर्षों में जी.डी.पी का 09 प्रतिशत रही और अब 23 प्रतिशत हो गढ़ है। इसी प्रकार अन्यें निर्धारित व्यय, जैसे—पेंशन आदि भो बढ़ रहे हैं। इन सबका नतीजा यह निकला है कि कुल खर्चों में गिरावट और गैर विकासात्मक खर्चों में वृद्धि के

कारण प्रादेशिक सरकारों की उत्पादक गतिविधियों में निवेश को क्षमता प्रभावित हुई है। गौरतलब है कि केंद्र की तुलना में राज्यों ने कर के क्षेत्र में बेहतर प्रदेशन

किया है। सन् 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में राज्यों का कर राजस्व

जी डी पी. का 5 7 प्रतिशत रहा, जो अब बढकर लगभग 6 प्रतिशत हो गया है (देखे तालिका-12)। केंद्रीय करो में उनकी हिस्सेदारी भी स्थिर बनी हुई है। इस प्रकार केंद्रीय सरकार की तरह राज्यों के कर-राजस्व में कभी नहीं हुई है। इसके उलट गैर कर-राजस्व (प्रयोगकर्ता शुल्क + राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्ति) में गिरावट आई। नब्बे के दशक में ऋण संबंधी देनदारियों नथा अन्य गैर-विकासात्मक खर्चों में बढ़ोतरी के कारण राज्यों का गजस्य व्यय अर राजस्व घाटा बढ़ा है। इसके कारण राज्यों के योजनागत खर्चों पर प्रतिकृत अमर

पडा है।

	कुल व्यय का प्रतिशत							l
	1. राजस्व व्यय (क+छ+ग)	111	50	13.6	13.5	13.9	14 1	
	(क) विकासात्मक	7.9	9.1	8 9	∞ —	8 5	7.8	
*	(ख) गैर-विकासात्मक	3.1	3.8	4.6	5.2	5 2	09	
भारत	ब्याज अदायगी तथा ऋण	60	1.5	2.0	2.2	2,3	23	
ीय ३	भुगतान पेशन	03	0.5	9.0	0.8	80	60	
म र्घ नी	अन्य व्यय	19	17	2.0	2.2	2 1	28	
ਰਿ ⊁	(ग) अन्य व्यय	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	
	2 पूँजीगत विवरण (क+ख)	5.0	4.3	3.4	2 8	3.0	2.8	

169

164

170

17.3

कुल व्यय (1+2) (편) अन्य

Ĺ

2.9

00

2.0 6:1

2 पूँजीगत विवरण (क+ख) (क) कुल पूँजीगत व्यय विकासात्मक

2.1 2.1 2.1 0.1

	83 6	46 4
	82 1	49.9
	82.7	49.6
	0 08	52.3
	75.5	52.7
	689	48.9
कुल व्यय का प्रतिशत	1. राजस्व व्यय (कनखनग)	(क) विकासात्मक

359

136

52 168 164 164 89 85 75

5.0 1.3 17 9 10 0 9 6 0 4 7 9

4.8 13.7 1.1 17.3 9.5 9.5

268 3.7 11.5 11.5 0 9 20 0 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7

245

21 11.7 0 9 31.1 13.2 12.8 0 3

> (ग्) अन्य व्यय पूँजीगत विवरण (क+ख) (क) कुल पूँजीगत व्यय

भारतीय अर्चनीति 🛊

पेशन अन्य व्यय 11 2

32

0.8

000

04

13.2

17.9

(ख) अन्य

प्रादेशिक सरकारों के कुल राजस्व का स्वरूप (1980-2000) 1980- 1985- 1990- 1995- 1997-

85

স। ভ	। पा. का प्रातशत						
1 रा	जस्व प्राप्ति (क+र	a) 115	12.8	12.8	12 3	12.5	12
क	कर-राजस्व	76	8.5	8 5	86	8.8	8
	राज्य कर से						
	प्राप्त राजस्व	5 1	5.7	5 7	58	6.0	6
	केटीय करों में						

46

27

03

16

17 4

73 6

48 8

32.6

16.2

248

26 4

15 5

1.7

9.1

🛊 भारतीय अर्घनीति 🛊

100.00

तालिका 12

90

95

7

44

43

21

04

18

17.1

750

49 5

33 5

160

25 5

25 0

12.1

2.3

10.6

100.00

99

28

37

39

20

03

16

16.2

759

53 2

36 1

17 1

22 7

24 1

12 4

18

99

100 00

1998-

3 9

0

29

3 4

41

22

0 1

18

16 5

748

54 1

36 7

17 4

20 7

25 2

13 4

08

110

9

100 00

98

2.8

37

4.2

2.2

03

1.7

16.7

74.9

52.9

35.9

16.9

22.0

25.1

13.1

1.6

104

100.00

राज्य कर से			
प्राप्त राजस्व	5 1	5.7	5
केद्रीय करों में			
हिस्सा	2 5	28	2
ख गैर कर-राजस्व	3.9	4.3	4

2 पूँजीगत प्राप्ति

केंद्रीय ऋण

ऋण वसूली

अन्य प्राप्ति

कुल राजस्व का प्रतिशत

क. कर-राजस्व

हिस्सा

2. पॅजीगत प्राप्ति

राज्य कर से प्राप्त राजस्व

केंद्रीय करों में

ख. गैर कर-राजस्व

केंद्रीय ऋण

ऋण वसूली

अन्य प्राप्ति

कुल राजस्व (1+2)

1 राजस्व प्राप्ति (क+ख) 73 7

कुल राजस्व (1+2)

41

2.3

04

15

156

48 6

32 5

162

25.1

263

146

24

9.3

100.00

अस्सी के दशक की शुरुआत से ही राज्यों की विनीय स्थित में काफी गिरावट दिखने लगी थी। परिणामस्वरूप केंद्र की तुलना में उनका योजनागत खर्च सबंधी विकास सुस्त हुआ (देखें तालिका-13)। इससे सामाजिक तथा ढाँचागत तत्र में निवेश की राज्यों की क्षमता प्रभावित हुई।

तालिका-13 योजना व्यय में राज्यों का अंश (1951-2002)

योजना	केंद्र (प्रतिशत)	गन्य (प्रतिशत)
पहली (1951-56)	36	64
दूसरी (1956-61)	54	46
तीसरी (1961-66)	49	51
বাৰ্ষিক (1966-69)	51	49
चौथी (1969-74)	50	50
पॉचर्वी (1974-7 9)	48	52
वार्षिक (1979-80)	46	54
छ ਰੀ (1980-85)	53	47
सातवी (1985-90)	59	41
आठवी (1992-97)	62	38
नोवीं (1997-2002)	58	42

नोट - प्रथम से सातवीं योजना तक वाम्नविक आठवीं योजना - अनुमानिन नौ में योजना मधावित । स्रोत प्रथम पचवर्षीय योजना ने सातवीं पचवर्षीय योजना नक अमरोश काराना अस्य (1992 बी) आठवीं तथा नौवीं पचवर्षीय योजना योजना आयोग (1998)

मौजूदा योजनागत प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय सरकार एक ऐसी वित्तीय एजेंसी के रूप में उभरी है, जो जनता से अलग-अलग तरीकों से ऋग जुटाकर केंद्र तथा राज्यों के स्तरों पर योजनागत खर्चों का विन-पोपण करती है। इस व्यवस्था में परियोजनाओं के औचित्य तथा उनकी वित्तीय कीमनों के बीच कोई नालमेल नहीं है। राज्यों को दी जानेवाली योजनागत खर्च संबंधी केंद्रीय सहायत! के लिए गाडगिल फार्मृला, जिसके तहत राज्यों द्वारा किए जानेवाले व्यय की समीक्षा के बगैर ही उन्हें 70 प्रतिशत तक ऋण दिया जाता है, लागू करने के बाद विन-पोपण के संसाधनों और उनके समुचित इस्तेमाल के संपर्क-सृत्र पृरी तरह समाप्त हो गए हैं। विभिन्न वित्त आयोगों ने राज्यों द्वारा सार्वजनिक तथा निर्जा संसाधनों के लिए वित्त-पोषण में भेदभाव नहीं रखनेवाली इस व्यवस्था के टिकाऊ न होने के बारे में

टिप्पणिया का ह इन सबका परिणाम यह हुआ है कि इस प्रकार के निवेशा पे प्राप्त होनेवाले लाभ काफी कम है।

फार्मूला के अनुसार केंद्रीय सरकार में ऋण लेती है। इन सरकारो द्वारा बाजारों से लिये जानेवाले ऋणों के मामले में भी केंद्रीय सरकार के निर्देश लागू होते है और भारतीय रिजर्व कैंक भी विभिन्न राज्यों के लिए समान ब्याज-दर पर ऋण जुटाना

मौजूदा व्यवस्था के तहत प्रादेशिक सरकारे योजना आयोग के गाडगिल

है। इस प्रकार उनके ऋणों को उनकी ऋण अदायगी की क्षमता से नहीं जोड़ा जाता। दूसरे, ऋण अदायगी मंवधी भुगतान की व्यवस्था उनके बजट में कर दी जाती है। ऐसा करते समय उन परियोजनाओं की सफलता या अन्य स्थितियों पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता, जिनके लिए ऋण के जरियं ससाधन जुटाए जाते हैं। अब तक ऋण अदायगी के मामले में सभी राज्यों का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा है, परंतु इन भुगतानों के चलते चालू खर्चों का पर्याप्त स्तर बनाए रखने या नए निवेश करने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई है। दरअसल, राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य और ऋण जुटाने की क्षमता के बीच कोई सबंध नहीं रहने के कारण वित्तीय क्षेत्र में गैर-

जिम्मेदार साबित हुए है ओर प्रयोगकर्ता शुल्क को लोकप्रिय जनभावनाओं के

आधार पर तय करते है।

सिद्धांत रूप मे देखा जाए तो सार्वजनिक सामान पर किए जानेवाले निवेश से अधिक कर -राजस्व मिलना चाहिए, जबिक निजी सामान पर निवेश से सार्वजनिक सेवाओं के लिए उपभोक्ता शुल्क के जिर्ये अधिक राजस्व प्राप्त होना चाहिए। ऐसा ही प्रादेशिक सरकार के म्तर पर भी होगा। राज्य स्तर पर ज्यादातर सार्वजनिक धन बिजली बोर्डों के जिर्यं बिजली-उत्पादन, वितरण और पोपण पर तथा राज्य सडक निगमों, शहरी बुनियादी सेवा के विकास के लिए शहरी विकास प्राधिकरणो.

सिचाई, आवास आदि मदों पर खर्च हो रहा है। इसमें सिंचाई को छोड़कर बाकी ज्यादातर गतिविधियों सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। राज्य स्तर पर सिचाई सुविधाओं का सचालन सरकार के सिंचाई विभाग करते हैं। अगर ये उपक्रम अपनी सेवाओं के बदले में समुचित आर्थिक मूल्य लेते तो वे लाभ

कमाकर सरकार को दे सकते थे और अपना ऋण खुद निपटा सकते थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये उपक्रम न तो लाभ कमा पा रहे हैं और न ही अपने कर्ज को उतार पा रहे हैं। और तो और ये उपक्रम अपनी सेवाओ के विस्तार के लिए

आंतरिक संसाधन भी नहीं जुटा पा रहे हैं। तालिका-14 में यह स्पष्ट है कि जिसमें छठीं, सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय

			7	りにらずっ	ति ६, (प्रता	राज्या है। वाद्यावाका है। विकास प्राप्त का स्वरंजन	7 5 7				
	म्रोत	छठी योजना	नना 1	सातवीं योजना	गेजना	आठवी योजना ²	गेजना ²		नवी योजना³	नाः³	
		(1980-85) (1979-80 मुल्यू)	85) मल्य)	(1995-90) (1984-85 मृल्य)	-90) 5 मृत्य)	(1992–97) (1991–92 मूल्य)	97) 2 मूल्य)	(1997–98) (चालू मूल्य)	-98) ऱ्रत्य)	1998–99 ⁴ (चालू मूल्य)	₁₉ 4 ल्य)
		करोड़ प्रा	कुल का प्रतिशत	क. करोड़	कुल का प्रतिशत	र करोड़	कुले का प्रतिशत	कतोड	कुल का प्रतिशत	रु. कुलका करोड प्रतिशत	कुल का प्रतिशत
	चालू राजस्व में से शेष	14826	41	17368	23	-2009 -14	च !	-8703	-177	17360	-25
ď	. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों										
भारत	का योगदान	-4620	-13	-3757	ι, S	-2723	6:1-		ŀ		
ന്	. कुल ऋण	12679	50	27644	37	75750	52	38350	78	61110	88
	क. कुल शेष ऋण	3406	δ	9242	12						
	ख लघु निवेश	5901	16	19070	26		1				
	न, विताय संस्थानों से										
	अविभिगत भ्रुण	1887	\$	4445	٥						
	घ विविध पूँजोगत प्राप्ति	-2012	9-	-5113	-7						
	इ. मन्तर घाटा	3407	ç								
	 गम्बों के कुल मंसाधन 	22885	63	41255	55	70335	48	29650	09	43750	63
Auma	🛚 केंद्रीय मदद	13690	200	33264	1/1 1/2"	75795	52	19523	7	25695	т
Street,	॥ कुल सम्प्रधन	36575	100	74519	160	140,035	100	49172	100	69445	100

योजना और नौवी पंचवर्षीय योजना के शुरू के 2 साल की राज्य योजना के वित्तीय ऑकडे दिए गए है। राज्य योजनाओं के लिए मौजूदा राजस्व का अधिशेष योगदान

अकिङ । देए गए है। राज्य योजनाओं के लिए माजूदा राजस्व का आधशष योगदान छठी पचवर्षीय योजना में 40 प्रतिशत के ऊँचे आँकड़े पर था, जो आठवीं योजना में शून्य से कम के स्तर पर आ गया। इसी तरह इस पूरी अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र

के उपक्रमों का योगदान लगातार नकारात्मक रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रादेशिक सरकारों की उधारी लगातार बढ़ती गई है। यह उधारी छठी योजना मे गज्य योजना के कुल संसाधन का 34 प्रतिशत हुआ करती थी, जो आठवीं योजना

में बढ़कर 50 प्रतिशत से ऊपर जा पहुँची। इसी अनुपात में केद्रीय सहायता का हिस्सा भी बढ़ा है। यह छठी योजना में 37 प्रतिशत था, जो आठवीं योजना में बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया।

नौवीं योजना में स्थिति और भी खराब हो गई है। उधारी की इस प्रवृत्ति के कारण बाजार की उधारी में भी इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ साल में बाजार की उधारी तेजी से बढ़ी है।

प्रादेशिक सरकारों की बिगडती वित्तीय स्थिति तालिका-15 से स्पष्ट है।

अस्सी के दशक में सकल राजकोषीय घाटे के अनुपात में पूँजी परिव्यय 62 प्रतिशत था, जो अब 50 प्रतिशत से भी नीचे चला गया है। फलस्वरूप प्रादेशिक सरकारों की उधारी अब ज्यादा से ज्यादा पूँजीगत खर्चों के बजाय राजस्व खर्चों पर हो रही है। इससे आनेवाले वर्षों में वित्तीय स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अगर मौजूदा व्यवस्था को नहीं बदला गया तो निवेश के लिए उपलब्ध संसाधन लगातार सिमटते जाएँगे।

तालिका-15 राज्य सरकारों के चुर्नीदा राजकोषीय अनुपात (1985-98)

	_		
वर्ष	पूंजीगत व्यय/	ब्याज भुगतान/	राजस्व घाटा/
	सकल राजकोषीय घाटा (प्रतिशत)	राजम्ब खर्च (प्रतिशत)	सकल राजकोषीय घाटा (प्रतिशत)
1985-90	62.4	10.8	7.7
1990-95	55.3	13.6	24.6
1996-98	47.5	15.8	35.8

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक का फरवरी 1998 बुलेटिन। पूरक . राज्य सरकारों के वित्त।

राजकोषीय प्रदर्शन करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थीं, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रही है। राजकोषीय समस्या अब समस्त राज्यों की समस्या वन गई है। सन् 1998-99 के वित्त वर्ष मे कर्नाटक को छोडकर बाकी सभी राज्यों की स्थिति नकारात्मक पाई गई। पश्चिम बंगाल तथा कुछ अन्य राज्यों में सार्वजिनक उधारी उनकी कुल योजना राशि से ऊपर निकल गई।

सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि जो राज्य बेहतर और जिम्मेदाराना

मुख्य मुद्दे

भारत मे प्रादेशिक सरकारों की निवेश व्यवस्था टिकाऊ नहीं है। यह समस्या मुख्य रूप से इसलिए पैदा हुई है, क्योंकि उधारी और पूँजींगत निवेश के खर्च के इस्तेमाल के बीच कोई तालमेल नहीं है। यह स्थिति विदंवनापूर्ण ह क्योंकि भारत में केद्रीय सरकार के समुचित नियत्रण में प्रादेशिक मग्कारों की वित्तीय सेहत दुरुस्त रखने की व्यवस्था की गई थी। प्रादेशिक सरकारों को घाटे की वित्तीय गतिविधियाँ चलाने की छूट नहीं दी गई और अतिरिक्त वित्त उपलब्ध हाने की समस्या खड़ी हो गई।

प्रादेशिक सरकारों पर उधारी के बारे में थोपी गई मीमाओं के कारण और खर्च की माँग के दबाव में उन सरकारों में सार्वजनिक उपक्रमों के जिरये उधारी लेने की प्रवृत्ति प्रादेशिक सरकारें बाजार से भी सीथे उधार ले गई। हैं। हाल तक प्रादेशिक सरकारों की गारंटियाँ बाजार से पर्याप्त उधारी के लिए मक्षम थीं, लेकिन इन गार्रिटयों के बढ़ने से उधार देनेवाली संस्थाएँ अब इन गार्रिटयों की विश्वमनीयता पर सवाल खड़े करने लगी हैं। उधारदाताओं से यह माँग भी की जाने लगी हैं कि प्रादेशिक सरकारें अपनी खास ऋण रेटिंग भी तय करे। इस कदम का उद्देश्य प्रादेशिक सरकारों को कुल देनदारियों को पारदर्शी बनाना है:

जिन समस्याओं का जिक्र ऊपर किया गया है, उनसे स्पप्ट है कि ये कदम व्यवस्था के दोनों सिरों पर उठाने होंगे। निजी बस्तुओं पर निवेश के प्रावधान का समुचित उपभोक्ता शुल्क से जोड़ना होगा। अभी समस्या यह है कि उधारी क्षमता और उपभोक्ता शुल्क का निर्धारण राजनीतिक स्तर पर हो रहा है। आशा है कि अगर ससाधन जुटाने की क्षमता किसी निकाय की विर्वाय स्थित पर निर्धर हो तो उससे उपभोक्ता शुल्क के मामले में राजनीतिक सोच में भी बदलाव आएगा।

सार्वजनिक वस्तुओं पर निवेश के लिए संसाधन जुटाने के लिए यह बेहतर होगा कि प्रादेशिक सरकारों की ऋण साख तय हो, ताकि उनकी उधारी लेने की क्षमता राज्य की वित्तीय स्थिति पर आधारित हो। नीति-नियामको को संकेत देने की समुचित व्यवस्था से प्रादेशिक सरकारों को वित्तीय स्थिति ठीक करने में आसानी होगी।

उच्च विकास-दर हासिल करने के लिए संबंधित प्रमुख मुद्दे

हम देख चुके है कि केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों—दोनों की मौजूदा वित्तीय स्थिति डॉवॉडोल है और इससे आर्थिक विकास-दर को गंभीर खतरा है। व्यापक पैमाने पर यह माना जा रहा है कि वित्तीय स्थिति बेहतर नहीं है

लेकिन इसके खतरों को ठीक से महसूस नहीं किया गया है। केंद्र और राज्यों का कुल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के करीब 10 प्रतिशत पर पहुँच चुका है। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारे कुल मिलाकर प्रतिवर्ष

गप्टीय आमदनी का 10 प्रतिशत उधार ले रही हैं।

विकास-दर

इन ससाधनों का लगभग आधा हिस्सा वेतन आदि की अदायगी जैसे खर्च पर लगाया जा रहा है। अगर ऐसा ही क्रम चलता रहा तो एक दिन नाबत यह आएगी कि उधारी का सारा धन इन्हीं खर्ची पर लगेगा और निवेश के लिए कुछ नहीं बचेगा। सार्वजिनक निवेश में कटौनी की रफ्तार को देखते हुए निजी निवेश भी स्थायी नहीं रहेगा। इन सबका असर विकास–दर पर होना निश्चित ही है। विकास– दर घटते जाने में राजकोषीय स्थिति और भी बिगड जाएगी।

इस तरह की राजकोपीय गैर-जिम्मेदारी के कुछ चिह्न ब्राजील के सन् 1998 के मंकट में देखे जा सकते हैं। तब ब्राजील के राज्य वहाँ की सधीय सरकार की देनदारियाँ नहीं चुका पाए थे। इससे ब्राजील की ऋण साख बेहद गिर गई और उसे मुद्रा का अवमृल्यन करना पड़ा। नीतिगत सुधार के आपात उपाय भी ब्राजील को करने पड़े।

तकनीकी तौर पर देखा जाए तो भारत के कुछ राज्य केंद्र की अदायगी में चृक कर रहे हैं। इस स्थिति को पाटने के लिए केंद्र को कई तरह के समायोजन करने पड़ रहे हैं। अगर केंद्रीय स्तर पर राजकोषीय घाटे पर काबू नहीं पाया गया तो केंद्र की उधारी बढ़ेगी, जिससे ब्याज-दरें सख्त होंगी। इसका असर औद्योगिक और कुल मिलाकर आर्थिक विकास-दर पर पड़ेगा। देश के भुगतान-सतुलन की बाह्य

कुल मिलाकर आर्थिक विकास-दर पर पडेगा। देश के भुगतान-सतुलन की बाह्य स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में है। सन् 1991 के बाद से ही विदेशी कर्जों पर कडी निगरानी है। इस ममय की जरूरतों के हिसाब से विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भी पर्याप्त से अधिक है। इसके बावजूद पिछले वर्ष अंतरराष्ट्रीय साख

निर्धारण एजेंसियों ने भारत की साख कम करके आँकी। इसका कारण यह रहा कि वे राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने के बारे मे उठाए गए कदमों से मंतृष्ट नहीं थे।

उच्च विकास-दर हासिल करने के लिए सभी मोरचों पर ठोम कदम उठाने की जरूरत है। लोक स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पोपण आदि मदों में सुधार के लिए प्रमुख प्रावधान करने होंगे। जहाँ तक बुनियादी सुविधाओं का सवाल हे, सड़कों रेल यातायात, बंदरगाहों, दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन तथा शहरी सुविधाओं

पर खास ध्यान देना होगा। इसमें निजी निवेश की अहम भूमिका होगी।

जिन क्षेत्रों में निजी निवेश के लिए आसानी है, वहाँ भी मार्वजनिक निवेश को जारी रखना होगा। आर्थिक विकास की दर बढ़ने के हिसाब में औद्योगिकीकृत शहरीकरण भी बढ़ेगा। ऐसे में शहर की बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ख़ास ध्यान देना होगा। हमारे शहरों और कसबों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव कई सामाजिक समस्याओं को जन्म दे रहा हैं। इससे आंतरिक सुरक्षा पर खर्च भी बढ़ना है। लिहाजा राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थित मजबृत रखने की दृष्टि में भी इन मदो पर निवेश करना बेहतर है।

सेवाओं की अदायगी कम करने पर देना होगा। सार्वजनिक ऋगों को कम करके और राजस्व बढ़ाकर यह लक्ष्य द्दासिल किया जा सकता है। कर दरे वढ़ाकर राजस्व बढ़ाना न तो वांछनीय है और न ही व्यावहारिक। कर-आधार बढ़ाकर और कर-वसूली को कारगर बनाकर ही राजस्व बढ़ाना श्रेयस्कर है। कुल राजस्व बढ़ाने के लिए—1 कर-आधार बढ़ाना होगा, 2. सभी गैर- प्राथमिकतावानी वस्तुओं पर उपभोक्ता शुल्क लगाना होगा, 3 निजीकरण की दिशा में व्यापक और माहसिक कदम उठाने होंगे।

ऐसी स्थिति मे क्या करना चाहिए? राजकोपीय मुधारो का मुख्य जांर ऋण-

कर-आधार का विस्तार

गिरावट आई। आर्थिक उदारीकरण के कारण कस्टम शुल्क में कमी आने में कर-सग्रह भी कम होने और आनेवाले वर्षों में शुल्क-दरे घटने की संभावना है। ऐसी स्थिति में परोक्ष करों की वसूली में तेजी केंद्रीय स्तर पर उत्पाद शुल्क की वस्ली से ही आ सकती है। सकल विकास में कृषि का अंश घटने के साथ राजम्ब में

सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से सन् 1990 में प्रत्यक्ष करों की वस्ति म

बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र कुल मिलाकर टैक्स के दायरे में मुक्त है। सच तो यह है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा सन् 1980-81 के 40 प्रतिशत से घटकर अब 26 प्रतिशत पर आ गया है। इसी हिसाब से दूसरे क्षेत्रों का हिस्सा 24 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है और सेवा क्षेत्र का अंशदान 36 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया है। भविष्य मे भी कृषि का हिस्सा घटने और मेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ने की पुरी सभावना है।

इस स्थिति को देखते हुए कर-राजस्व बढ़ाने की खातिर सेवा क्षेत्र पर परोक्ष-कर लगाना जरूरी हैं। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में मूल्य आधारित-कर लगाकर यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

सार्वजनिक निवेश का एक बडा हिस्सा लोकसेवाओं के प्रावधान मे है। इन

उपभोवता शुल्क का महत्त्व

सुविधाएँ इसमें शामिल हैं। विन मत्रालय के एक आकलन के अनुसार, ऐसे गैर-प्राथमिकतावाले क्षेत्रों पर सरकार मकल घरेलू उत्पाद का 10.5 प्रतिशत अधिक परोक्ष मक्सिडी दे गहीं है। विजली के मामले मे ही 25 हजार करोड रुपए का सालाना घाटा उठाना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि जनसेवाओं का

सगठनों का ढाँचा इस तरह तैयार किया गया है कि जनता उनकी सेवाओं के बदले कोई शुल्क नहीं देने की आदी हो गई है। विजली, पानी, सिंचाई और परिवहन की

समुचित मृल्य नहीं लिया जा रहा है। आँकडों से स्पष्ट है कि सरकारी खर्च के बोझ का मृल कारण वेतन नहीं है। अन्य कारणों से सरकारी तत्र में कटौती करना जरूरी हो सकता है, लेकिन इससे खर्च में कटौती कुछ ज्यादा नहीं होगी।

अगर आम जनता इन सेवाओं का मूल्य नहीं चुकाने की आदी हो गई है तो इसके दो प्रमुख कारण हैं। यह मान लिया गया है कि ये सेवाएँ सरकार देती है। लिहाजा इनका मृल्य चुकाने की जरूरत नहीं है। दूसरे, इन सेवाओं का स्तर इतना खराव है कि लोग समृचित सेवा शुल्क देने का मन नहीं बना पाते। यह ऐसा दुष्वक्र

है, जिसे तत्काल तोड़ने की जरूरत है। सेवाओं पर उपभोक्ता शुल्क बढ़ाने के साथ-साथ इन सेवाओं के स्तर में भी सुधार करने होंगे। सेवाओं की कुशलता बढेगी तो उपभोक्ता शुल्क में भी कमी आने की संभावना है।

सरकार को उधारी से किए जानेवाले निवेश से फायदे होंगे, तभी देश की वित्तीय सेहत ठीक की जा सकेगी।

वतीय सहत ठीक को जा सकेगी। यटि सरकार को उसके द्वारा किए गए निवेश पर आय होगी, तभी वित्तीय

स्थिति स्वग्थ होगी, क्योंकि सरकार यह निवेश उधारी के धन से करती है। सेवाओं पर समुचित शुल्क नहीं लगाने के पीछे तर्क यह दिया जाता है कि देश की गरीब जनता इन जरूरी सेवाओं का उपयोग कैसे कर पाएगी, लेकिन व्यवहां में इस तर्क में कोई दम नहीं है कि गरीब इन सेवाओं के लिए उचित भुगतान नहीं।

*** भारतीय अर्थनीति ***

कर सकते हैं। वास्तव मे समाज का समृद्ध तवका इन सेवाओं का ज्यादा इम्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पर—गाँवों में कम से कम 60 प्रतिशत घरों में और

शहरों में करीब 20 प्रतिशत घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं हैं। यहाँ तक कि शहरों में भी केवल 60 प्रतिशत घरों में ही पानी की टोटियाँ है। इससे भी कम

घरों में भीतर ही शौचालय की व्यवस्था है। इसका अर्थ यह हुआ कि युनियाई सुविधाओं के लिए दी जा रही सब्सिडी गरीबों तक नहीं पहुँच रही है। इसमें यह साबित होता है कि गरीबों के कल्याण-कार्यों को प्रभावित किए बिना उपयक्त

शुल्क लगाया जा सकता है। वास्तव में सचाई यह है कि ऊँचे नयके से यदि पूरी वसूली प्राप्त की जा सके तो गरीबों को आवश्यक सेवार्ण उपलब्ध कराने की

अच्छी संभावनाएँ बन जाएँगी। केद्रीय और प्रादेशिक सरकारों—दोनो की वित्तीय स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। यदि जरूरी सुधार कर लिया जाए तो 5 वर्ष के भीतर ही यह काम

किया जा सकता है। इसके बाद ही ये दोनों मग्कार सामाजिक ऑर भोतिक सुविधाओं के क्षेत्र में उपयुक्त निवेश कर सकेंगी, जो मामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं: लेकिन ये सुभार कार्य केवल घोषणाओं के जिस्ये नहीं किए जा मकते हैं। इनके लिए अनुमंधान, जन-जागण, लोकिशिक्षा आदि की आवश्यकता है। केद्रीय सरकार को इस प्रकार के अभियान का नेतृत्व करना चाहिए और प्रादेशिक सरकारों का भी उनके साथ तालमल नथा सहमित कायम कर इस अभियान में शामिल करना चाहिए। उन्हें भी म्थानीय निकायों के जिस्ये यह काम करना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि जब तक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और क्षमता का विस्तार नहीं होगा, तब तक मेवाओं

के ऊँचे शुल्क के लिए स्वीकार्य वातावरण बनाना मृश्किल होगा। इन सब बातों क लिए सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सुधार लाने होंगे।

विभिन्न सेवाओं के उपयोग शुल्क में वृद्धि म भविष्य में बजद में लाभ हीं होगा। इसके लिए प्रक्रिया में बड़ा बदलाव लाना होगा और वांछित परिणाम हासिल करने में समय लगेगा। सरकार को मृलभृत सुविधाओं के हर क्षेत्र का परीक्षण नजदीक से करना होगा और प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक लागत लगाने के बारे में चरणबद्ध कार्यक्रम बनाना होगा। इस मबंध में स्यतंत्र नियामक प्राधिकरणों को नियुक्ति से पूरी प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने में बचा जा सकेगा: लेकिन यह प्रक्रिया तभी सफल होगी, जब नियामक प्राधिकरणों को स्वतंत्र स्वक्रप का सम्मान

करे . इस प्रकार क कुछ नियामक प्राधिकरणों का गठन पहले भा हो चुका है उम्मीद है कि नई प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। अनुभवी लोगों और विशेषज्ञों की

नियुक्ति कर इन प्राधिकरणों को मजबृत बनाया जाना चाहिए और स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए। यह पुरा अभियान समयबद्ध होना चाहिए।

देश की विनीय स्थिति में सुधार लाने के लिए हम 5 वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति के मध्यकालिक उपायों के तौर पर ऋण चुकाकर संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ये संसाधन निजीकरण से ही प्राप्त

निजीकरण

किए जा सकते है।

सार्वजितक उश्रारी की अदायगी के लिए अथाह पूँजी संसाधनों की जरूरत है। केंद्रीय और प्रादेशिक दोनों—स्तरों पर साहसी और व्यापक निजीकरण से ये

ससाधन जुटाए जा सकते हैं। अब पुरानी मान्यताएँ त्यागकर सामरिक महत्त्व के सार्वजनिक उपक्रमों के अलावा बाकी सभी क्षेत्रों में निर्जाकरण करने का समय आ गया है। इस कार्यक्रम को विनिवंश में अलग रखना चाहिए। विनिवंश की प्रक्रिया आधे-अधरे मन से चलाई गई है। विनिवंश के उद्देश्यों में अस्पष्टता की वजह से

ऐसा हुआ है।

प अवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र का जो विचार दिया था, वह बाद के वर्षों में अलग हो रास्ते पर चल निकला। सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में नेहरू की अवधारणा अर्थव्यवस्था को बेहद ऊँचाई पर ले जाने की थी, अतल गहराई में ले जाने की नहीं। उस समय निजी क्षेत्र को अपर्याप्त समझा गया था और सार्वजनिक

जाने की नहीं। उस समय निजी क्षेत्र को अपयोप्त समझा गया था और सार्वजनिक क्षेत्र से उम्मीद की गई थी कि वह अर्थव्यवस्था में अधिक कार्यकुशलता लाएगा। यह माना गया था कि कार्यकुशल सार्वजनिक क्षेत्र अथाह ससाधन जुटाने में

सहायक सिद्ध होगा, लेकिन हुआ उसका उलटा। हालाँकि यह मानना होगा कि ढाँचागत मामलो और भारी उद्योगों में सार्वजनिक उपक्रमों की अहम भूमिका है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उच्च निवेश एवं उच्च विकास-दर हासिल

करने के लिए व्यापक शेयर भागीदारी की जरूरत होगी। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह उच्च विकास-दर सुनिश्चित कर सके। व्यापार खोलने और पहले आरक्षित माने जानेवाले सार्वजनिक उपक्रमों को अनारक्षित करने तथा

और पहले आरक्षित माने जानेवाले सार्वजनिक उपक्रमों को अनारक्षित करने तथा विदेशी निवेश के लिए उदारीकरण करने से प्रतिस्पर्धा की स्थिति पैदा हुई है। ऐसे प्रतिस्पर्धी वातावरण में मुक्त माहौल और लचीलेपन की जरूरत होती है; वह सरकारी बंदिशों से बाधित होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के बारे में स्थिति एकदम स्पय्ट होनी चाहिए। यह कदम उठाना सिर्फ संसाधन जुटाने के लिए ही जरूरी नही,

बिल्क इन उपक्रमो की दीर्घायु के लिए भी आवश्यक है। ये उपक्रम आगे चलकर भारत की बहुराष्ट्रीय कपनियों का रूप ले सकते हैं। इन उपक्रमो को सरकारी

बेडियों से मुक्त किया जाना चाहिए।

अब यह साफ है कि विनिवेश के लिए अपनाई गई प्रक्रिया सफल नहीं हुई है। विनिवेश के उद्देश्य स्पष्ट नहीं हैं। यह प्रक्रिया नौकरशाही के शिकंजे में हे और विनिवेश के लक्ष्य भी पूरे नहीं हो पाए हैं। निजीकरण की प्रक्रिया सामान्य ढग से नहीं चलाई जा सकती। यह भी स्पष्ट है कि साहसी दृष्टिकोण अपनाना भी

आर विनिवंश के लक्ष्य में पूर नहीं हो पाए हैं नि जानकरण का प्राकृतन पानत्व कर्म से नहीं चलाई जा सकती। यह भी स्पप्ट है कि साहसी दृष्टिकोण अपनाना भी आसान नहीं है। सबसे पहले सरकार को निजीकरण के उद्देश्य स्पप्ट करते हुए आम

सहमित के प्रयास करने होंगे। पहला उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि ये उपक्रम इतने मजबूत हों कि प्रतिस्पर्धा में शामिल होते हुए प्रगित कर सके और देश की वित्तीय स्थिति में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकें। यह सब घोषणाओं में सभव नहीं है। इसके लिए राजनीतिक और नौकरशाही—दोनों स्तरों पर प्रक्रियागत परिवर्तनों की आवश्यकता है, लेकिन अब समय नहीं है और समस्या का सामना करने का वक्त आ गया है।

निजीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त होनेवाले धन का इस्तेमाल मौजूदा खर्च उठाने के लिए कर्त्र नहीं किया जाना चाहिए। इनका इस्तेमाल विशेष रूप से सार्वजनिक ऋण चुकाने में ही किया जाना चाहिए, ताकि ब्याज का बोझ लगातार घटता चला जाए। निजीकरण के परिणाम अतीत के सार्वजनिक निवेश से प्राप्त

घटता चला जाए। निजीकरण के परिणाम अतीत के सावजनिक निवेश से प्राप्त होगे। भविष्य में सार्वजनिक निवेश कैसे सुनिश्चित किया जाए, नाकि सरकार को

वित्तीय स्थिति के सुधार करने में मदद मिलती रहे—यह भी अहम सवाल है। मुझे लगता है कि सार्वजनिक निवेश के पूरे तंत्र की योजना-प्रक्रिया पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। मौजूदा प्रक्रिया में हर स्तर पर जवाबदेही का अभाव झलकता है। निवेश के मौके से निवेश के निर्णय बेहद दूर हैं। केंद्रीय सरकार एक

विशाल वित्तीय मध्यस्थ के रूप में काम करती है। वह जनता में संसाधन उधार लेती है और उन्हें कुछ परपराओं एव फॉर्मृलों के आधार पर ग्रादेशिक सरकारों तथा

अन्य निकायों को देती है। प्रादेशिक सरकारें इन संमाधनों को सरकारो सगठनों को मुहैया कराती हैं। ये संसाधन प्रदर्शन-आधारित नहीं हैं। यह भी सुनिश्चित नहीं

मुहैया कराती हैं। ये संसाधन प्रदर्शन-आधारित नहीं हैं। यह भी सुनिश्चित नहीं किया जाता कि इन संसाधनों का कोई फायटा वापस मिलेगा या नहीं। यह तंत्र अब व्यावहारिक नही रह गया है। इस बारे में नए दुष्टिकोण की जरूरत है।

देश का दीर्घावधि विकास सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक विकास-दर

मे निरंतर तेजी आनी चाहिए। इस मार्ग की सबसे बड़ी अड़चन यह है कि ढाँचागत

शुल्क में सुधार किया जाए और निजीकरण के लिए नए कार्यक्रम अपनाए जाएँ।

भविष्य में ही आर्थिक सुरक्षा खतरे मे पड जाएगी।

इन कदमों के अभाव में राजकोपीय हालत और भी बदतर होती जाएगी और निकट

के अलावा यह भी आवश्यक है कि सभी सार्वजनिक सेवाओं के लिए उपभोक्ता

प्रादेशिक सरकारों की वित्तीय सेहत डाँवॉडोल हो रही है। कर-राजस्व में गतिशीलता

क्षेत्र मे सार्वजनिक निवेश हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, जिससे केंद्रीय और

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान दशा

कुछ झलकियाँ

पिछले कुछ समय से ऐसी आशका जताई जा रही है कि अर्थव्यवस्था मे

—के.मी **घ**त

पिछलं राजकोषीय वर्ष में तेजी के बाद अब फिर मंदी आ रही है और यह भी कि नौवीं योजना के लक्ष्यों को हासिल करना शायद मंभव न हो। सी.एम ओ द्वारा इम राजकोषीय वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए जी डी.पी के आकलन तथा ओंद्योगिक उत्पाद के सूचकाक से भी इस दृष्टिकोण को समर्थन मिलता है। हालाँकि योजना आयोग प्राय: कम अवधि के पूर्वानुमानों के आधार पर कार्य नहीं करना और न ही हाल के रुझानों के मुताबिक अतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। भविष्य में अथंब्यवस्था की संभावित स्थित को मंदी के कारणों तथा आनेवाले महीनां में इन कारको की कार्यप्रणाली के संदर्भों में समझने की कोशिश की जानी चाहिए।

3 वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास में आई मंदी का मुख्य कारण सार्वजनिक निवेश, विशेषकर ढाँचागत क्षेत्र में निवेश मे कमी आना है। इसके अलावा पूर्वी एशियाई संकट के चलते हमारे निर्यात अपेक्षाकृत कम विकास तथा अत्तरराष्ट्रीय

योजना आयोग के मध्यवर्ती मुल्याकन प्रारूप में कहा गया है कि पिछले

व्यापार जगत् में छाई सुस्ती भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हालाँकि अब अंतरराप्ट्रीय स्तर पर व्यापार में छाई मंदी की प्रवृत्ति बदल चुकी है और हमारे नियांत ने भी 20 प्रतिशत का अतिरिक्त विकास कर लिया है। जहाँ तक सार्व जनिक निवेश का

सवाल है तो हमें स्वीकार करना होगा कि हमने पाँचवें वेतन आयोग के प्रभावों का, विशेषकर प्रादेशिक सरकारों का मूल्यांकन किया। परिणामस्वरूप केंद्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने योजना अविध के पहले 3 वर्षों के दौरान ही

निवेश संबंधी अपने लक्ष्य का 47 प्रतिशत जुटा लिया था, वहीं राज्य केवल 28

प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर सके हैं।

अब स्थिति सुधर रही है। वेतन आयोग के प्रभाव भी कमोबेश समाप्त हो चुके हैं और आनेवाले महीनो में सार्वजनिक निवेश में तेजी आने की संभावना है। हालाँकि ऐसा पहले ही हो जाना चाहिए था, परंतु सार्वजनिक निवेश की नई परियोजनाएँ शुरू करने में देरी के कारण इसमे ढिलाई हुई। उदाहरण के लिए, जहाँ एक ओर डीजल अधिकार के जरिये जुटाए संसाधनों के बूते पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना टीक-टाक ढंग से प्रगति कर रही है, वहीं ग्रामीण सडक कार्यक्रम अभी शुरुआती रुकावटों में ही उलझा है। इसी प्रकार केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों की अन्य निवेश परियोजनाएँ भी निर्धारित धनराशि की अनुपलब्धता के कारण अटकी हुई हैं। यह निश्चित रूप से गलती है। राजकोषीय वसूली की सभाव्यता के आधार पर इस बारे में पहले ही पर्याप्त तैयारी की जानी चाहिए थी, लेकिन अब स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया है और लगता है कि निकट भविष्य में सार्वजनिक निवेश में काफी तेजी आएगी। अलबत्ता, यह कितनी जल्दी होगा या विकास की अपेक्षित गति के लिए आवश्यक बल यह जुटा पाएगा या नहीं, इस बारे में अभी से कुछ भी कहना कठिन है।

प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को 9 प्रतिशत विकास-लक्ष्य को हासिल करने की संभावना की जॉच करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। यहाँ यह बताना जरूरी है कि यह लक्ष्य पाना असंभव बिलकुल नहीं है। देखना केवल यह है कि आवश्यक उपाय निर्धारित अविध में लागू किए जा सकते है या नहीं। दूसरे, यह भी देखना होगा कि देश के सभी भाग ऐसी विकास-दरों के लिए तैयार हैं या नहीं, जो सकल लक्ष्यों की राह में सहायक बनेगी।

ज्ञान की सुपर शक्ति के रूप में भारत की भूमिका

डिजिटल प्रौद्योगिकी चुपचाप, परंतु निश्चित तौर पर देश के भीतर सामाजिक ढाँचे को बदलने तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। इसके अपने सिद्धांत और नियम हैं। इन नियमों को अपनानेवाले लाभ कमा रहे हैं और इनसे अनजान विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। भूमडलीकरण के मौजूदा दौर में सूचना प्रौद्योगिकी सभी राष्ट्रों का समान भविष्य तय करने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। दरअसल, वर्तमान सदी में तुलनात्मक फायदो तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के इस्तेमाल के आईने मे पारिभाषित करने की जरूरत है।

विश्व व्यापार सगठन (डब्ल्यू.टी.ओ) की स्थापना के बाद प्रत्येक दश अपनी क्षमता के हिसाब से विश्व अर्थव्यवस्था के अधिकाधिक हिस्से को प्रान्त कर सकता है और इस प्रक्रिया को वे ही देश दिशा-निर्देश देने की स्थिति में हागे

जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति को महत्त्व दिया है। भारत सरकार ने सचना प्रौद्योगिकी को बढावा देने के लिए कई प्रयास किए

है। इनमें काफी महत्त्वपूर्ण हे 'मृचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000', जो ई-कॉमर्स, इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संचार तथा अर्थव्यवस्था के शेत्र म आई टी के प्रवेश को आसान बनाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने ई- कॉमम के क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मंजूरी दी है तथा इस प्रकार के लेन देन को कर-मक्त रखा है।

ई-कॉमर्स को सूचना-क्रांति का महत्त्वपूर्ण अग माना जा रहा है। समय और दूरी की बाधाओं को मिटाकर व्यापार को सहज करने की इसकी वास्तविक शक्ति और क्षमता की अभी शुरुआत ही है।

प्रधानमंत्री की विशेष कार्य योजना का एक महत्त्वपूर्ण एजेंडा भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुपर पावर बनाने तथा अगले 10 वर्षों में सॉफ्टवयर के सबसे बड़े उत्पादक एवं निर्यातक देशों की सूची में स्थान दिलाना है। इस दिशा में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर विकास सबंधी राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया है। दूरसचार नीतियों तथा प्रक्रियाओं, साइबर कानृनों, आई टी उद्योग में श्रम कानृनों, वित्तीय मामलों, स्कुलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रोद्योगिकी

को बढ़ावा देने तथा देश मे कंप्यूटर साक्षरता और कंप्यूटर की पहुँच को बढ़ावा देने संबधी कार्य-बल की 108 सिफारिशे पूर्ण रूप में स्वीकृत कर ली गई हैं और अब उन्हें लागू किया जा रहा है।

अमेरिका ने वर्तमान में अपने सभी उद्योगों में 3 लाख से अधिक पेशेवरों की कमी की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रतिभाएँ अमेरिका मे उस मॉग-आपूर्ति के अतर को पाटने में जुटी हैं।

अन्य देश भी हमारे कुशल पेशेवरों में दिलचम्पी दिखा रहे हैं। भारत ने जर्मन बाजारों के लिए 20,000 पेशेवर, ऑस्ट्रिया के लिए 15,000 तथा जापान के लिए 40,000 विशेषज्ञ उपलब्ध कराए हैं।

आई.टी. मे मानव ससाधन विकास को ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि की नीति तैयार करने के लिए कार्य-बल का गठन किया गया है। कार्य-बल ने मौजूदा आई.आई.टी., क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों (आर ई सी.) तथा अन्य इंजीनियरिंग कॉलेंजों एव शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के जिये अगले शैक्षिक सत्र से उनमें छात्रों की संख्या दोगुनी करने तथा अगले 2 वर्षों में

तिगुनी करने की योजना बनाई है।
भारतीय सॉफ्टवेयर पेशेवर स्वय को ग्लोबल ब्रांड के तौर पर स्थापित कर चुके है और उन्हें आई टी. के क्षेत्र में उच्चस्तरीय तथा भरोसेमंद रिआयती सेवा का

प्रतीक माना जाता है। सुपरशक्ति बनने की भारत की आकांक्षा की राह मे ये सर्वाधिक उपयुक्त वाहन सावित हो सकते हैं। यह निश्चित तौर पर महत्त्वाकाक्षी

प्रयास होगा, क्योंकि फिलहाल दुनिया भर में सॉफ्टवेयर से प्राप्त राजस्व का महज 2 5 प्रतिशत हिस्सा ही भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात की झोली मे आता है। यदि

पिछले 5 वर्षो की ही तरह अगले 5 वर्षो में भी विकास-दर 50 प्रतिशत के आस-पास रही तो भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात सन् 2005 में दुनिया भर के सॉफ्टवेयर राजस्व का 6 प्रतिशत हो जाएगा और आगे भी उसकी स्थिति मजबृत होगी।

भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग हमारे आई टी. आयुध का महत्त्वपूर्ण बाण है। इस उद्योग ने देश-विदेश में अपनी स्थिति सुदृढ की है। इस क्षेत्र मे हाल में पूँजी निवेश की प्रवृत्ति भी देखी गई है।

भारत में इन बदलावों के समानांतर ही डिजिटल प्रौद्योगिकी से उत्पन्न दीवारों की समस्या भी सिर उठाएगी। हालाँकि इस अंतर को पूरी तरह खत्म करना सभव नहीं होगा और अकेले सरकार इस काम को नहीं कर सकती, इसलिए

आई.टी. विशेषज्ञों समेत समाज के सभी वर्गों को यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल-क्रांति के लाभ सभी तक पहुँचें। इस सिलसिले मे सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के 486 ब्लॉक मे सामुदायिक सूचना केंद्र खोलने की परियोजना शुरू की है।

राज्यों के 486 ब्लॉक में सामुदायिक सूचना केंद्र खोलने की परियोजना शुरू की है। ये केंद्र स्वास्थ्य, ऊर्जा, जल, शिक्षा और साक्षरता समेत गरीबी हटाने में भी मददगार होगे; लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से इन पिछड़े राज्यों में अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

उधर कुछ राज्यों, जैसे—कर्नाटक में ई-गवर्नेस के लाभ दिखाई देने लगे हैं। केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के सभी मंत्रालयों और विभागो को आई.टी. एव इंटरनेट का अधिकाधिक इस्तेमाल करने के दिशा-निर्देश जारी किए जा चके हैं.

इंटरनेट का अधिकाधिक इस्तेमाल करने के दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं, ताकि पारदर्शी प्रशासन का लाभ आम आदमी तक पहुँचे। संचार और आई.टी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल मे

सचार और आई.टा क्षेत्र में विकास की बढ़ावा दन के उद्देश्य से हाल में दूरगामी प्रभाववाले कई फैसले लिये गए हैं। अंतरराष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने और विदेशी उपग्रहों से बैंडविड्थ किराए पर लेने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (आई एस पी) को मजूरी दी गई है तािक देश में इटरनट का विस्तार सुनिश्चित हो सके। संचार के क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड का गठन और गष्ट्रीय स्तर पर लंबी दूरी की प्रणाली को मुक्त करने एवं आई.एस डी खोले जाने से संचार तत्र सुदृढ होगा।

ढाँचागत तंत्र में सुधार के बाद आई टी आधारित सेवाओं के स्तर मे भी जबरदस्त वृद्धि होगी। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, कॉल सेंटर्स तथा ऐसे ही अन्य विकल्प देश भर में रोजगार के अनेक अवसरों को जुटाने के अलावा भारतीय माक्षर महिलाओं को घर से कार्य संचालित करने के मोके उपलब्ध कराएँगे।

अब हमें आई.टी. क्रांति को अगले दौर में ले जाने की जरूरत है। इस क्षेत्र के लाभ से 100 प्रतिशत, अधिक रोजगार, उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

[1. आर्थिक संपादकों के सम्मेलन मे भाषण, 17 अक्तूबर, 2000, 2. आई टी. डॉट कॉम 2000, बंगलौर मे भाषण, 1 नवबर, 2000।]

आर्थिक विकास का वित्त-पोषण

—सी. रंगराजन

नई आर्थिक नीति के पहलू

आजाद भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में सन् 1991 को 'मील का पत्थर' कहा जा मकता है। उस समय देश में भुगतान-सतुलन की बिगड़ी हुई स्थिति के कारण भीषण आर्थिक सकट पैदा हो गया था। इस संकट को अवसर में बदलकर आर्थिक नीति में कुछ मृलभृत परिवर्तन किए गए। शुरुआती वर्षों में सुधार की प्रक्रिया तेज थीं, लेकिन बाद में यह मद पड़ गई। वैसे इतना जरूर है कि विभिन्न सरकारों के माये में आर्थिक नीति में निरंतरता बनी हुई है।

जुलाई 1991 के बाट में जो आर्थिक कदम उठाए गए, उनमें एक साझा सूत्र

तलाशा जा सकता है। इन सभी कदमों का उद्देश्य उत्पादकता में सुधार करना और व्यवस्था को कार्यकुशल बनाना रहा है। तरह-तरह के नियंत्रणों से लैस नियमन व्यवस्था से निजी क्षेत्र तक की प्रतिस्पर्धी क्षमता बिखरकर रह गई थी। नई आर्थिक नीति का जोर अडच्वें हटाकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और कपनियों का विकास सुनिश्चित करना रहा। आँद्योगिक नीति में परिवर्तन घरेलू प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाने के लिए किए गए, जबिक व्यापार नीति में किए गए परिवर्तनों का उद्देश्य घटते हुए शुल्क-दरों के वातावरण में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना रहा। निजी क्षेत्र को कदम बढ़ाने के लिए अधिक अवसर दिए गए और कुछ ऐसे क्षेत्रों को भी निजी क्षेत्र के लिए खोला गया, जो कभी मार्वजनिक क्षेत्र की बपौती हुआ करते थे। इन क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को एक-दूसरे से होड़ लेने की स्थितियाँ पैदा कर दी गईं। इन सब उपायों का उद्देश्य विभिन्न निकायों की कार्यकुशलता में सुधार करना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना रहा। इस व्यवस्था में सरकार की भूमिका गीण नहीं हो जाती। हाँ, यह भूमिका नए सिरे से तय जरूर होती है। यह भिमका कछ क्षेत्रों में फैलेगी ओर कुछ में सिमटेगी। समानता और कार्यकुशलता

उदारीकरण के बाद की स्थिति

देखा जाए तो सुधारों के बाद हमारी अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हाल ही में केट्रीय सांख्यिकी संगठन ने कहा है कि सन् 1998-99 में हमारी विकास-दर 6 के बजाय 6 8 प्रतिशत रही। अगर सन् 1992 से 1999 के बीच का ओमत

अगर विशद्ध रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास-दर के हिमाब मे

देखा जाए तो विकास-दर 6 55 प्रतिशत थी, जबिक सन् 1985 में 1990 के बीच विकास-दर 6 04 प्रतिशत रही थी, लेकिन यह भी सच हे कि सिर्फ विकास-दर को ही किसी अर्थव्यवस्था की मजबृती का मापदड नहीं माना जा सकता। विकास

का तौर तरीका भी इतना ही महत्त्वपूर्ण है। फिर भी गणित कहता है कि आर्थिक विकास की दर 7 प्रतिशत होनी चाहिए। अगर श्रमशक्ति को समाहित करना है ओर बेरोजगारी कम करनी है तो यह दर हासिल करना जम्बरी है। आजादी पाने के बाद शरू के वर्षों में बचत-दर कम होना आर्थिक विकास-दर एक बड़ी अड़चन थी।

इस तंगी पर बहुत हद तक काबृ पा लिया गया है। पचाम के दशक के शुरू में बचत-दर 10 प्रतिशत थी। हाल के वर्षों में अर्थव्यवस्था में बचत-दर 25 से 26 प्रतिशत के बीच चल रही है। अगर हम उसमें सकल घरेलृ उन्पाद का 2 प्रतिशत चालू घाटा जोड़ दें तो 7 प्रतिशत विकास-दर का लक्ष्य असभव नहीं लगता। एंसे

चोलू घोटा जाड़ दे तो 7 प्रांतशत विकास-दर को लक्ष्य असमव नहीं लगता। एस में प्रयास इस बात के होने चाहिए कि विकास-दर घीरे-धीरे ही सही, मगर निरंतर बढ़े। सच यह है कि अगर 7 प्रतिशत विकास-दर का लक्ष्य आसान ढग स हासिल करना है तो हमें बचत-दर बढ़ानी होगी।

वित्त-पोषण

प्रतिशत रही, जबिक इसके पिछले साल यह 24.7 प्रतिशत थीं। घरेलू वचत, निजी क्षेत्र की बचत और सार्वजनिक क्षेत्र की बचत—तीनो में ही यह गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 1.4 प्रतिशत गिरावट सार्वजनिक क्षेत्र में आई। तीनो ही क्षेत्रों में बचत–दर बढ़ना जरूरी है; लेकिन राजस्व घाटे की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र

बचत-दर के ताजा ऑकड़ों के अनुसार सन् 1998-99 में यह दर 22 3

की बचत-दर विशेष रूप से बढ़ाई जानी चाहिए। आर्थिक विकास-टर को मजबूत बनाने में एकीकृत वित्तीय संरचना की भूमिका सर्वमान्य है। वित्तीय संस्थाओं का मजबृत ढाँचा हो तो अर्थव्यवस्था में बचत को बढावा मिलता है। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल भी इससे सुनिश्चित होता है। बुनियादी क्षेत्र से फायदे मिलना इस बात पर निर्भर है कि वित्तीय व्यवस्था कारगर हो।

कारगर नियमन

हाल के वर्षों में वित्तव्यवस्था की मजबती और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। वास्त्विकता यह है कि इस बारे में औद्योगिक देशों में चिताएँ अस्सी के दशक में उभरी थीं, जब वित्तीय बाजारों का भमंडलीकरण तेजी से हो रहा था। प्रतिस्पर्धा बढ़ने में मुनाफा तेजी से घट रहा था। इस संदर्भ में बैंक फॉर इटरनेशनल सेटलमेटम ने महसूस किया कि विभिन्न देशों में वैंकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ममुचित नियम म्त्रीकार करना चाहिए। मूलभूत नियम सन् 1988 मे लागू किए गए। तब से इन मानको में सुधार हुए है और नए सिरे से पारिभाषित भी किए गए है। हाल के पूर्वी एशियाई मंकट से भी यह बात सामने आई कि कमजोर वित्त-व्यवस्था किस तरह विकास-दर पर ऑच ला सकती है। सच यह है कि जब अर्थव्यवस्था तेजी मे बढ़ रही हो तो व्यवस्था की कई खामियों छिप जाया करती है. लेकिन जब अर्थव्यवस्था फिमलने लगती है तो ये खामियाँ न सिर्फ उजागर होती है, बल्कि विकरन भी हो जाती हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि बैंको, वित्तीय मम्थाओं और पूँजी वाजारों का नियमन पारदर्शी ढंग से किया जाए। दरअसल, चार आधारभत चिताओं के कारण वित्तीय संस्थानों के नियमन की जरूरत महसुस होती हे-(1) जमाऋती उपभोक्ता और निवेशक का संरक्षण. (2) बाजार की संरचना और प्रतिस्मर्था का चरित्र, (3) सुरक्षा तथा मजबूती और (4) व्यवस्थागत स्थिरता। चुनोती यह है कि एक ऐसी नियमन व्यवस्था कायम की जाए, जिससे ये चारो उददेश्य परे होते हा। पिछले 7 वर्षों से जो वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए गए हैं, उनकी धरी यही सिद्धांत रहे हैं।

समृचित नियमों की जरूरत का महत्त्व भलीभाँति समझा गया है। निरीक्षण व्यवस्था को विनीय सम्थाओं पर नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये संस्थाएँ नियमों के मुताबिक काम कर रही हैं। बैंकों और वितीय सम्थाओं को अलग में जोखिम प्रबंधन व्यवस्था भी कायम करनी चाहिए, ताकि वे ऋण-संबंधी मामलों से जुड़े विभिन्न जोखिमों को भाँप सकें और समुचित कदम उठा सकें। भारतीय रिजर्व वैक महित सेंट्रल बैंकों ने जोखिम-प्रबंधन के बारे मे दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

पूँजी बाजार के स्रोत औद्योगिक और सेवाक्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ ऋण ही नहीं, बल्कि

भी है। अगर सन् 1992-93 के बाद से निवेश में तेजी से विस्तार हुआ तो इसका प्रमुख कारण था प्राथमिक बाजार की गतिशीलता। गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए कैपिटल इश्यू सन् 1890 में 164 करोड़ रुपए के थे. जो बढते-बढते सन 1989 में 3,225 करोड़ रुपए के ऑकड़े पर पहुँच गए। फिर सन् 1991-92 में इसमें तेजी से वृद्धि हुई और यह राशि 6,200 करोड़ रुपए तक पहुँच गई। इसके बाद के 4 वर्षों में तेजी का दौर चलता रहा, लेकिन फिर गिरावट आनी शुरू हो गई। कपनियाँ विलुप्त होने लगी और कंपनी क्षेत्र अपने वायदे पूरे नहीं कर पाया। व्यक्तिगत निवेशक बाजार से भागने लगे। एक समय ऐसा भी आया, जब सन् 1997-98 में कुल पूँजी-उगाही महज 3,100 करोड़ रुपए की हुई। इसके बाद के 2 वर्षों में कुछ बढोतरी हुई है, लेकिन जितनी उगाही हो रही है, वह उस राशि के नजदीक नहीं है, जो कभी सन् 1989-90 में थी। इसकी वजह से पूँजी बाजार के नियमन की दिशा में कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा। हमे प्रतिभूति बाजारों के लिए यह सुनिश्चित करने की जरूरत

इक्विटी की भी जरूरतें बढ़ेंगी। बैंकों का इक्विटी में निवेश सीमित है, जो जायज

बाध्य होना पडा। हमे प्रतिभूति बाजारों के लिए यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि प्रतिभूति उद्योग के लोग मुक्त और निप्पक्ष वातावरण में काम करे, तािक वे अपने ग्राहकों के साथ न्याय कर सकें।

कपनी क्षेत्र को अपने बारे में पूरी सृचना जनता को देनी चाहिए, तािक निवेशक बुद्धिमानी से अपने निवेश के फैसले ले पाएँ। कंपनियों के लिए पूँजी-बाजार वित्त का प्रमुख स्रोत है। यह तर्क दिया जाता है कि दक्षिण कोरिया मे ऋण इक्विटी अनुपात बेहद ऊँचा था। घरेलू बचत बैंकों में जमा हुई जिसका अधिकतर भाग कपनियों को ऋण के रूप में मिल गया, लेकिन ऋण इक्विटी अनुपात बेहद

भाग कपनियों को ऋण के रूप में मिल गया, लेकिन ऋग इक्किटी अनुपात वेहद अधिक होने के भी अपने खतरे हैं। कंपनी क्षेत्र को धन देने में विकास वित्त सस्थाओं ने हमारे देश में अहम भूमिका निभाई है। जर्मनी जैसे देशों में. जहाँ पूँजी बाजार पर निर्भरता अन्य औद्योगिक देशों के मुकाबले कम है, बैंकों का इक्किटी में निवेश काफी अधिक रहा है। अस्सी के दशक के शुरू में और नब्बे के दशक में

भारतीय कपनियों ने लंबी अवधि के वित्त हासिल करने के लिए पूँजी बाजार की ओर रुख किया। पूँजी बाजार और खास तौर से प्राथमिक शेयर बाजार का समुचित विकास कंपनियों के लिए विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। जब तक पँजी

विकास कंपनियों के लिए विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। जब तक पूँजी बाजार मजबूती और लचीलापन प्राप्त नहीं करता, तब तक वित्तीय संस्थाओं की अहम भूमिका रहेगी। कपनी क्षेत्र जब बेहतर प्रदर्शन करेगा और अपने वायदों की पृरा करते हुए निवेशकों का विश्वास हासिल करेगा, तभी पूँजी बाजार फूलेगा-फलेगा। इस लिहाज मे देखें तो जिम्मेदारी कपनी क्षेत्र के कंधों पर है। इस समय हमं पूँजी वाजार ओर विनीय संस्थाओं के संतुलित विकास की आवश्यकता है, तािक कपनी क्षेत्र की लखीं अविध को वित्तीय जरूरतें पूरी हो सकें।

वितीय उत्पाद विनीय मॉग की नई-नई जरूरते पैदा हो रही हैं। ढॉचागत क्षेत्र विकास का

मुख्य क्षेत्र ह। परियाजनाएँ चाहे विजली की हों या दूरसंचार की, इन सभी की वित्तीय आवश्यकताएँ है। अभी तक इस क्षेत्र का ज्यादातर खर्च सरकार उठाती रही ह। अब यह जिस्मेटारी धीर-धीरे निजी क्षेत्र की और खिसक रही है। इसके लिए नए प्रकार के वित्तीय उत्पादों की जरूरत है। कई वित्तीय संस्थाएँ लबी अवधि के ऋण देने के लिए नेयार नहीं हैं, क्योंकि उनकी देनदारियों या जमा पूँजी कम अवधिवाली हैं। ऐसे में कर्ज लेनेवालों के लिए ऋण राशि बढ़ाना जरूरी है। इसके अलावा पेशन बीमा और भविष्यानिध आदि दीर्घावधि के वित्त स्रोत विकसित करने होंगे। ढिचागत बिकास की दृष्टि से ब्राड बाजार की भूमिका भी अहम है।

बाहरी सहायता

पिछले 7 वर्षों में विदेशी निवेश नीति में भारी बदलाव आए हैं। इस दिशा म दृष्टिकोण सकारात्मक और दूरदर्शी हुआ है। विदेशी निवेश नीति में किए गए प्रिवर्तनों से भारत के भ्गतान-सतुलन की दृष्टि से पूँजी खाते में कई महत्त्वपूर्ण बदलाव आए। नब्बे के दशक में इन परिवर्तनों से देश में बिना कर्जवाले धन की आवक हुई और 50 प्रतिशत नक पूँजी-प्रवाह ऐसा था, जिसकी अदाएगी नहीं करनी थी। विकस्ति होती अर्थव्यवस्था में पूँजी-आवक का स्वागत किया जाता है।

इससे बाहरा दबाव कम होते हैं और उच्च विकास-दर प्राप्त होनी है। ऐसे निवेश टेक्नॉलॉर्जा हस्तांतरण और प्रबंधन -कौशल को भी साथ लेकर आते हैं। पूँजी-आवक के बारे में पूर्वी एशियाई सकट ने कुछ आशंकाएँ पैदा की हैं।

एक तरह से देखा जाए तो पूँजी-प्रवाह दुधारी तलवार की तरह है। जब पूँजी आती है तो निवेश योग्य संसाधन और विकास में तेजी से वृद्धि होती है, लेकिन पूँजी जब जानी शुरू होती है तो यह सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को गहरी चोट पहुँचा मकती है, लेकिन पूर्वी एशियाई संकट शुरू होने से पहले पूँजी आने से उन देशों

बीसवीं सदी के अंत में भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक बदलाव और भविष्य की संभावनाएँ

-उमा कपिला

भाग्तीय अर्थव्यवस्था में अस्सी के दशक के मुकाबले उल्लेखनीय सरचनात्मक पश्वितन हुए। सुधारों की प्रक्रिया सन् 1991 में शुरू होने के बाद से

सकल घरेल् उत्पाद के क्षेत्रगत अनुपात में भी भारी बदलाव आया है। जी.डी पी मे योगदान के हिसाब से सेवा-क्षेत्र ने प्रमुखता हासिल कर ली है। यह योगदान

बढ़ने से अर्थव्यवस्था में कई प्रभाव दिखाई दिए और इस व्यवस्था में काफी

लचीलापन भी आया।

में रहा है।

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का अंशदान सन् 1992-93 के 34.5 प्रतिशत में घटकर 27 5 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर उद्योगों का हिस्सा

23 2 प्रतिशत में बद्धकर 25.9 प्रतिशत और सेवा-क्षेत्र का हिस्सा 42 2 प्रतिशत से

बहकर 46 6 प्रांतरात हो गया। नवीन राष्ट्रीय ऑकडो के अनुसार सेवा-क्षेत्र का

योगदान मन् 1993 94 से मन् 1998-99 के बीच 51.1 प्रतिशत रहा।

मुद्रा और वित्तीय स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में अंशदान का यह बदलाव सेवा-क्षेत्र में सन् 1992-93 से

सन् 1997-98 के बीच 8 4 प्रतिशत वृद्धि-दर के कारण हुआ। यह वृद्धि-दर सन् 1980 स 1990 के बीच 6 5 प्रतिशत ही थी। सेवा-क्षेत्र का हिस्सा विकास के साथ

1980 से 1990 के बाब 6 5 प्रांतशत हा था। सवा-क्षत्र की हिस्सा विकास के साथ बढ़ने की देखते हुए दूसरे देशों के अनुभव से समझा जा सकता है, लेकिन अभी यह स्पप्ट नहीं हैं कि नब्बे के दशक में नीतिगत परिवर्तनों का कितना योगदान इस दिशा

भारताय अर्थनाति *

मानसून बेहतर होने के बावजूद नब्बे के दशक में कृषि क्षेत्र में गिरावट आई है। सिचाई का क्षेत्र बढ़ने के बावजूद यह स्थिति देखने को मिली है। संभवत सार्वजनिक निवेश में गिरावट और नई टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल नहीं होना इसका कारण रहा होगा।

लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ने नब्बे के दशक में उच्च विकास-दर हासिल करने का क्रम जारी रखा। मिसाल के तौर पर सन् 1995-96 में 8.6 प्रतिशत विकास-दर हासिल की गई। इस अवधि में कृषि-क्षेत्र ने नगण्य (0.2 प्रतिशत की) वृद्धि-दर ही प्राप्त की थी। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि-क्षेत्र के झटकों को सेवा-क्षेत्र की प्रगति ने झेला है।

सैवा-क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार

निर्भरता से हट रहा है। विकास-दर में मुधार उद्योग और सेवा-क्षेत्र पर निर्भर हो रहा है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में भी निर्माण-क्षेत्र ने विकास में योगदान अधिक किया जबिक खनन, बिजली, जलापूर्ति आदि क्षेत्रों में वृद्धि-दर कम रही। दूसरी ओर सेवा-क्षेत्र में व्यापार, होटल, रेम्तराँ, भडाग्ण और मंचार के क्षेत्र में वृद्धि दर में निरंतरता देखी गई, लेकिन वित्त, बीमा और व्यावसायिक सेवा-क्षेत्र में उच्च वृद्धि-दर दर्ज की गई। शायद इसका कारण यह हो सकता है कि सेवा-क्षेत्र में उन्हीं सेवाओं का अधिक विकास हुआ, जिनका सरोकार उद्योगों से था।

इस तरह देखा जाए तो आर्थिक विकास अब कृषि और मानसून की

इस लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुभव विकसित देशों से भिन्न रहे, क्योंकि हमारे सेवा-क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम समय में कृषि और उद्योगों के अंशदान से आगे निकल गया। दूसरे शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था ने कृषि से जुड़े निम्न गुणवत्ता के स्तर से कॅची छलॉग लगाई और सेवा-क्षेत्र से जुड़े उच्च गुणवत्ता स्तर की ओर रुख किया। भारत का यह सकारात्मक अनुभव एक बड़े फायदे के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि विकास की दौड़ में उसने देरी से होड़ लेना शुरू किया था, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को टेक्नॉलॉजी में सुधार के साथ वृद्धि प्रक्रिया की लंबी हगर पर नहीं चलना पड़ा।

सेवा-क्षेत्र में विस्तार के अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं, मसलन, उत्पादन रोजगार और व्यापारिक सभावनाओं की दृष्टि से फायदे सामने आएँगे—

1 सेवा-क्षेत्र के विकास के साथ इस बात की जरूरत है कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए नीतिगत प्रयास किए जाएँ,

तालिका : जी.डी.पी. के उत्पाद मूल्य का क्षेत्रवार मंयोजन और औसत

			1980-8	1993-94 मूल्य	
		क्षेत्र	अवधि ।	अवधि 🛭 ए	अवधि II बी
		•	1980-81 से	1992-93 से	1993-94 से
			1990-91	1997=96 •	1998-99
1.	कृषि	एवं संबद्ध क्षेत्र	34.5	27.5	28.2
			(4.5)	(3.0)	(4.3)
	1 1	कृषि	318	26.2	26.1
			(48)	(4 1)	_
2	उद्यो	ग	23.2	25.9	21.8
			(7.2)	(8.1)	(8.2)
	2.7	खनन एव खुदाई	18	1.8	2.4
			(8 8)	(3.5)	(3.7)
	2 2	विनिर्माण	19.5	21 5	17.0
			(6 9)	(8 6)	(90)
	23	विद्युत्, गेस एव	2.0	2.5	2 4
		जल आपृति	(8.5)	(72)	(6 9)
3	मेवा	ऍ	42.2	46.6	50.1
			(6.2)	(7.7)	(7.8)
	3 1	होटल, रेस्टोरेट,	17.4	19 3	22.7
		गरिवहन, भंडारण एव संचार	(6.3)	(8 6)	(9 1)
	3.2	वित्त, बीमा,	94	119	112
		भू-संगनि एवं व्यावसायिक सेवा	(6 8)	(8 7)	(7 3)
	3.3	समुदाय सामाजिक	10.8	10 9	114
		एवं व्यक्तिगत सेवाएँ	(60)	(6 5)	(7 3)
	3 4	निर्माण	4.6	44	48
			(5.7)	(4.8)	(45)
	जी.	डी.पी.	100.0	100.0	100.0
			(5.8)	(6.5)	(6.8)

नोट - कोध्टक में दिए गए आकड़े विकास दर के हैं। 'गोत . वित्त एवं मुद्रा पर भारतीय ग्जिर्व बेक की रिपोर्ट (1998-99)। ताकि निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान मुनिश्चित किया जा सके।

- 2. टेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में प्रगति और नए उपायों के कारण कृपि तथा उद्योग की उत्पादकता बढ़ने के साथ-साथ रोजगार के अवसर गैर-सेवा-क्षेत्र के बजाय सेवा-क्षेत्र में बढेगे। इससे वस्तुओ पर खर्च का हिस्सा घटकर मूल्यवर्धित सेवाओं मे ज्यादा हो सकता है।
- 3. सेवा-क्षेत्र का व्यापक कर-आधार हो सकता है, जिसका दोहन नही किया गया है। इस दुप्टि से संवा-क्षेत्र के विकास की राजकोषीय नीतियों पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं।

पिछले तीन दशको में उद्योग जगत् ने अपनी विकास-टर अथवा सकल

उद्योग जगत में संरचनात्मक बदलाव

घरेल उत्पाद (जी.डी.पी) मे अपने योगदान की दृष्टि से किसी खास प्रवृत्ति को नहीं दरशाया है। सत्तर के दशक में औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक विकास-दर 4.4 प्रतिशत थी और अस्सी के दशक में यह 7.2 प्रतिशत रही। सन् 1980-81

के दौरान यह ऑकड़ा (न्यूनतम 1.4 प्रतिशत और सन् 1989-90 में अधिकतम 11 2 प्रतिशत दर्ज किया गया) अलबत्ता, नौवे दशक में इसमे काफी उतार-चढाव

देखे गए और पहले 2 वर्षों मे 11 2 तथा 12 9 प्रतिशत रहने के बाद सन् 1991-92 में यह लुढ़ककर 19 प्रतिशत तक पहुँच गया, लेकिन बाद के वर्षों में यह 6

प्रतिशत से अधिक रहा। नब्बे के दशक में (1998-99 तक) औसत वार्पिक विकास-दर 6 6 प्रतिशत रही। सन् 1970 मे जी.डी.पी मे उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी

18 6 प्रतिशत से बढ़कर सन् 1995-96 में 27 प्रतिशत हो गई, मगर अगले ही वर्ष (1996-97) में यह गिरकर 22 प्रतिशत रह गई। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की दृष्टि से देखें तो सन् 1991-92 से

मन् १९९८-९९ तक उत्पादन की विकास-दर धीमी रही। इस अवधि में औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए।

औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकाक में विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष योगदान में बदलाव भी संरचनात्मक परिवर्तनों के एक अन्य पहलू को उजागर करता है। निर्माण क्षेत्र का सापेक्ष योगदान अस्सी के दशक में 70 प्रतिशत से बढ़कर नौवें दशक में

81 6 प्रतिशत तक जा पहुँचा। अलबत्ता, खनन आदि में काफी गिरावट आई। नौवें दशक में बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र के सापेक्ष योगदान में

कमी आई, परतु मध्यवर्ती और उपभोक्ता सामान से जुड़े क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की

गई। नई शृखला में (आधार : 1993-94 = 100) बुनियादी तथा पूँजीगत वस्तुओं से जुडे क्षेत्रों के वजन में गिरावट आई, वहीं मध्यवर्ती और उपभोक्ता सामान-

सबधी क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई।

तालिका-2 विभिन्न क्षेत्रों का औद्योगिक उत्पादन में तुलनात्मक योगदान

क्षेत्र	1981-82 से 1990-91 (औसत)	1992-93 से 1998-99 (औसत)
निर्माण	70 0	81 6
विद्युत्	14.4	14 4
खनन तथा खुदाई	15.6	4 0
सामान्य सूचकांक	100.0	100 0

वम्तुओं के क्षेत्रों के अपेक्षाकृत कम योगदान का कारण अन्य कारणों के अलावा श्रम उदारीकरण, विशेषकर आयात तथा वित्तीय उदारीकरण का प्रभाव रहा। हाल के वर्षों में भारतीय कॉरपोरेट जगत् की पुनर्सरचना के लिए मुख्य रूप

सं अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक माहौल जिम्मेदार है। नब्बे के दशक के शुरुआती वर्षों में आरभ किए गए संरचनात्मक सुधारों ने भारतीय उद्योग को अधिक कारगर नीतियाँ

अपनाने, गौण गतिविधियाँ बंद करने तथा विलयन और अधिग्रहण के लिए प्रेरित

किया। हाल की अवधि में तो विलयन, अधिग्रहण आदि नीतियाँ विकास की तेज रफ्तार हासिल करने के लिए अपनाई जाती रही हैं। इस संदर्भ में निजी तथा

अपने प्रदर्शन के सापेक्ष स्तरों को बनाए रखने के लिए पुनर्सरचना की प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है। सन् 1991 में आर्थिक सुधारों का दौर शुरू होने के बाद से अर्थव्यवस्था के

सार्वजनिक क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय चुनौती के रूप में उभरने तथा घरेलू बाजार में भी

सन् 1991 में आर्थिक सुधारों का दौर शुरू होने के बाद से अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया में निस्संदेह तेजी आई है। अर्थव्यवस्था तभी से तेज विकास के पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है और एक दशक से कम अविध में ही

^{*} इस अवधि में उत्पादन लगभग स्थिर होने के कारण सन् 1991-92 से संबंधित आँकडों को शामिल नहीं किया गया है।

बृहद्-आर्थिक सकेतको के मद्देनजर बदलाव दर्ज किए गए हैं, लेकिन साथ ही नौवें दशक ने कई चुनौतियाँ भी पेश की है। जैसाकि भारतीय रिजर्व येक की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजकोपीय घाटे को नियत्रण में रखने के साथ-साथ घरल मौद्रिक प्रबंधन तथा विनिमय दरों के मद्देनजर पूँजी-प्रवाह को बढ़ावा देन के लिए नीतियाँ बनाने तथा कानूनी व सस्थागन सुधारों के लिए नीतियाँ तय करने आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने की जरूरत है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति और बैंकिंग क्षेत्र के सुधार

भारतीय रिजर्व वेंक ने अपनी यह नीति दोहराई है कि जहाँ तक परिस्थितियाँ

साथ देगी, उस हद तक ब्याज-दरों को लचीला बनाया जाएगा। साथ ही उसने बेकों की ब्याज-दरों को लेकर ऊहापोह की स्थिति को भी स्पप्ट किया है। ब्याज-दरों के मामले मे फैसले अनुदान लागत, लेन-देन लागत और गैर-बैंकिंग क्षेत्र की ब्याज-दरों के आधार पर स्वय बैंकों को ही लेने हैं। हालाँकि एकल ब्याज-दर या बकों के लिए रिजर्व बैंक का कोई आदेश उद्योगों में निराशाजनक हो सकता है,

—एस.एस. तारापुर

लेकिन रिजर्व बैंक ने बहुत विस्तार से उन बिदशों का जिक्र किया है, जिनके तहत बेंक काम करते हैं। बैंकों में जमा राशि पर आसत लागत 8 प्रतिशत है और 2 5 से 3 प्रतिशत लागन गैर-ब्याज वाली गितिविधियों पर आती है। ऐसे में 10 प्रतिशत का कैश रिजर्व देशों के बैंकिंग उद्योग पर बहुत बड़ा बोझ है और अचल संपत्ति से भी सिस्टम पर दबाव है। इस स्थिति मे ऋण-दरों को घटाना बहुत मुश्किल लगता है, जो प्रमुख बैंको के मामले में 12 में 12.5 प्रतिशत है। ऋण दरों को घटाने का सीधा असर जमा राशि की दरों पर पड़ेगा। सरकार के बचत-उपकरणों पर अच्छा ब्याज मिलता है और म्यूचुअल फड़ों पर आकर्षक कर-रिआयतें मिल रही हैं। अगर जमा पर ब्याज-दर घटाई गई तो निकासी बढ़ने की आशका है। सरकार के निरतर बढ़ते उधारी कार्यक्रम से भी ब्याज-दर ढाँचे पर दबाव बढ़ता जा रहा है। लिहाजा ऋण-

मौद्रिक नीति की घोषणा से पहले प्रमुख बैंकों के अध्ययनों और शीर्ष सलाहकारों ने कैश रिजर्व देशों (सी.आर.आर) मे कटौती के खिलाफ तर्क दिए थे। उनका कहना था कि लिक्विडिटी का अभाव नहीं है। यह तर्क अजीबो-गरीब

दरों में बहुप्रतीक्षित कटौती निकट भविष्य में मुमिकन नहीं लगती।

लगता है। चूँिक सी आर आर. बैंकों पर एक तरह का टैक्स है, इसलिए बैक इसमें कटौती होने का स्वागत ही करेंगे। सी.आर आर 10 से घटाकर 9 प्रतिशत करने

और 10 प्रतिशत का चक्रवृद्धि सी आर आर. समाप्त करने से 8,000 करोड़ रुपए

जारी होगे और अगर इसका 10 प्रतिशत हिस्सा भी बैंकों ने मुनाफे के काम पर लगाया तो उन्हें प्रतिवर्ष 480 करोड़ रुपए की आमदनी होगी।

बैंकों को इस बात की आशंका होगी कि उन्हें ऋण-दरें घटानी पड़ सकती

है, लेकिन इसकी गुंजाइश भी नहीं है। उद्योगो को यह समझना चाहिए कि ब्याज मे मामूलीं कमी से कहीं ज्यादा अहम बात यह है कि कर्ज की उपलब्धता बनी रहे। बैंकों का ब्याज-दर ढाँचा क्या है, इसपर गौर करने की जरूरन है। बैंकों मे

अधिकतम जमा राशि पर ब्याज 10 5 प्रतिशत होना चाहिए और प्रमुख ऋण ब्याज-दर 12.5 प्रतिशत। फिलहाल बैंक-दरें 8 प्रतिशत हैं, जो बहुत कम हैं। इसमें कटौती नहीं की जा सकती। सी आर आर. घटाने का फायदा यह हैं कि ब्याज-दरों पर इसका असर बाजार के माध्यम से होगा और इससे ब्याज-दरों में उतार-चढाव होते रहने की आशंका नहीं है।

छह महीने से एक साल तक की एफ सी.एन.आर (बी) जमा पर न्यूनतम मैच्योरिटी बढ़ाना बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इस जमा पर सी आर.आर पूरी तरह समाप्त कर देना दुर्भाग्यपूर्ण है। सन् 1995–96 में इसे समाप्त किया गया था, जब विनियम-दरों पर दबाव था, लेकिन सन् 1997 में इसे फिर लागु कर दिया

जब विनियम-दरों पर दबाव था, लेकिन सन् 1997 में इसे फिर लागू कर दिया गया। बाहरी अदायगी की स्थिति संतोषजनक होने के बावजूद इन जमा राशियों पर समाप्त करने का औचित्य स्पष्ट नहीं है। फिर यह भी देखना चाहिए कि अगर विनियम-दरों पर दबाव आया तो सरकार क्या कदम उठाएगी।

रिजर्व बैंक ने मुद्रा और प्रतिभृति बाजार की मजबती के लिए कुछ कदम

उठाए हैं; लेकिन सेब्री और रिजर्व बैंक की खींचतान और कर-ढाँचे से स्थिति बैंको के विपरीत हो गई है। यह भी हैरत की बात है कि बैंकों ने इस बारे में शिकायत नहीं की है। बैंकिंग प्रणाली में असमानता से गभीर स्थिनि पैदा हो सकती है। यह बहुत बड़ी असमानता है कि बैंकों से मिलनेवाले मामूली ब्याज पर टेक्स लगाया जाए और म्यूचुअल फंडों से होनेवाली असीमित आय को टेक्स से मुक्त

है। यह बहुत बड़ी असमानता है कि बैंकों से मिलनेवाले मामूली ब्याज पर टेक्स लगाया जाए और म्यूचुअल फंडों से होनेवाली असीमित आय को टैक्स से मुक्त रखा जाए। उद्योगों को इस बात से निराशा होना स्वाभाविक है कि रिजर्व बेंक ने ऋण

दरें कम करने के लिए बैंकों पर दबाव नहीं डाला, लेकिन उद्योगों को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि उनके लिए पूरा वित्तीय परिदृश्य बदल गया है। भारत के कपनी क्षेत्र ने बैंकों के पैसे से अपनी निर्भरता कम की है। अब प्रश्न यह है कि बैंको की ऋण-दरों का भविष्य का ढाँचा क्या होगा? अतीत के अनुभवों से पता चलता है कि जब कभी निजी क्षेत्र ने निचली दरों पर सीधे संसाधन जुटाने शुरू

किए तब-तब प्रमुख ऋण-दरें कम हुई है। फिर भी तुरुप का पत्ता हमेशा सरकारी उधारी पर दिया जानावाला ब्याज ही रहेगा, क्योंकि इससे कम तो प्रमुख ब्याज दरे होने से रहीं।

हान स रहा। संक्षेप में कहे तो मौद्रिक और ऋण-नीति के बारे में जो उपाय किए गए हैं, वे उद्योग के लिए फायदेमंद साबित होंगे।

मौद्रिक प्रबंधन के दीर्घकालीन मुद्दे

भारतीय वित्तीय व्यवस्था का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि मौद्रिक नीति की भूमिका को ठीक से नहीं समझा गया। इसकी समझ के बारे में अस्पष्टता अध्येता समुदाय से लेकर मौद्रिक नीति बनानेवालों तक और सरकार से लेकर मीडिया तक झलकती है। मौद्रिक नीति की बात कोई करता है तो उसे 'मुद्रावादी' करार दे दिया जाता है और उसपर हमले शरू हो जाते हैं।

मौद्रिक नीति का मूल उद्देश्य मुद्रास्फीति को अल्पकाल और दीर्घकाल के

भारत में यह समझ विकसित करने में भी कठिनाई है कि देश स्वतत्र

लिए अंकुश में रखना होता है। अर्थव्यवस्था की वास्तविक विकास-दर और आय के वितरण में भी इसकी भूमिका होती है। मौद्रिक नीति अगर अहम योगदान कर सकती है तो वह है मूल्य। भारत का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में काफी साफ-सुथरा है। भारत की आर्थिक विकास-दर 5 5 प्रतिशत, मुद्रास्फीति 7 प्रतिशत और एम-3 विकास-दर 17 प्रतिशत रही है।

मौद्रिक नीति अपनाने के बावजूद स्वतंत्र विनिमय-दर व्यवस्था कायम नहीं रख सकता है। रॉबर्ट मुडेल ने 40 साल पहले जो बात कही थी, वह आज भारतीय मौद्रिक नीति का मूल तत्त्व बनी हुई है। अगर कोई देश एक स्वाधीन नीति अपनाता है तो वह दूसरी नीति की स्वाधीनता का त्याग करता है। भारतीय मानस इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

एक समस्या इस त्रुटिपूर्ण विश्वास की है कि हम भारतीय बहुत अनोखे हैं और हम मुद्राआपूर्ति पर नियंत्रण रखते हुए भी ब्याज-दरों को काबू मे रख सकते हैं। मूल मौद्रिक अर्थव्यवस्था हमें सिखाती है कि हम दोनों को एक साथ काबू मे

नहीं कर सकते।

हाल के वर्षों में रिजर्व बैंक ने मौद्रिक लक्ष्यो, विनिमय-दर सकेतों, ब्याज-दर संकेतो और मुद्रास्फीति के लक्ष्यों के बारे में जोर देना कम किया है। इससे

नीतिगत मामले मे थोड़ी स्वतत्रता आई है।

अन्य सेट्रल बैको ने भी ऐसी ही स्थितियों का मामना किया है। ब्रक ऑफ इंग्लंड ने 91 सेंट्रल वैंकों के बारे में एक सर्वेक्षण किया और पाया कि सन् 1998 में 54 बैकों ने मुद्रास्फीति के बारे में विशिष्ट लक्ष्य तय किए हुए थे, जर्बाक सन् 1990

ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक के नीतिगत असमजस कोई अनुठे नहीं हैं।

में सिर्फ 8 बैंकों ने इस तरह का लक्ष्य निर्धारित किया था। मुद्रास्फीरित का लक्ष्य तय होने से मुद्रा-नीति में अनुशासन आता है और सेंट्रल नक अभिक जवाबदेह हो जाता है। हालाँकि परिस्थितियों के वशीभृत होकर सरकार लक्ष्य बदल सकती ह

जाता है। हालाक परिस्थातया के परामित होकर सरमार लक्ष्य वर्ष सकता है। और नीति के प्रतिकृत जानेवाले लक्ष्य को तिलांजिल दे सकती है।

परिपक्व वित्तीय प्रणाली में हमे निचली न्यूनतम ब्याज-दरों की सनक में उबरने की जरूरत है। मुद्रास्फीति की दर निग्तर कम रहने से दास्तविक ब्याज-दरे

कम रहेंगी और इससे दीर्घकालिक विकास-दर मुनिश्चित हो सकेगी। यह मानकर चलें कि बचत-दर जी डी पी की 26 प्रतिशत हे और भुगतान

मंतुलन में वालू खाता घाटा 2 प्रतिशत है। इससे 28 प्रतिशत निवेश-दर मुनिश्चित हो सकती है। अगर पूँजी निर्गत अनुपात 4 हो तो आर्थिक विकास-दर 7 प्रतिशन होगी। हम इसमे संतुष्ट नहीं है। हमारा सपना 10 प्रतिशत विकास-दर हामिल करने

का है।

हम एक बार फिर 7-8 प्रतिशत विकास-दर की बताद्री भरी वाने कर रहे
हैं। यही पर खतरा निहित है। हम जल्दी ही आर्थिक विकास-दर के अधिक

हैं। यही पर खतरा निहित है। हम जल्दी ही आर्थिक विकास-दर से आश्विक वास्तविक ब्याज-दरों के अवरोधक से टकरा जाएँगे और अर्थव्यवस्था मंदी से अ जाएगी। इसका नतीजा मुटास्फीति बढ़ने में होगी, जो महनंग्य नहीं होगी। समय पर

ब्याज-दरों में परिवर्तन से हम बदलाव की जरूरतों से निपट सकते हैं। उद्योगों को यह सोचना चाहिए कि बृहद् आर्थिक परिदृश्य में हम न्यूनतम ज्याज -दरों के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गए हैं। अगर इसमें और कटौती की गई तो मुद्रास्फीति बढ़ने की पूरी आशंका है।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

वैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए जिन मुद्दो पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है, वे इस प्रकार है—

केश रिजर्व देशों: हालाँकि यह मुद्रा पूरी तरह से समग्र मौद्रिक नीति का अग हे, फिर भी यह एकमात्र मुद्दा बैको के मुनाफे पर भारी पडता है। सी. अगर आर घटाने की हाल की घोषणा के बाद प्रभावी सी. आर आर 8 प्रतिशत रह जाएगा, लेकिन इसमें और भी कटौती की जरूरत है। अगर 2 साल की अवधि में इसे 3 प्रतिशत क स्तर पर ला दिया गया तो वको के ससाधनों में प्रतिशत 2,100 कगेड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। कानृती संशोधन: कानृनी संशोधन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है, लेकिन यह प्रक्रिया एकदम मधर गति से चल रही है। सन् 1997 और 1998 में गर-वैकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए किए गए कानृनी परिवर्तनों से स्पष्ट है कि हर काम को प्राथमिकता दी जाए तो तंजी से सशोधन किए जा सकते हैं। भारतीय उद्योग जगत् को ऋण वस्तृती के कारण कानृन विकित्तत करने पर विशेष ध्यान देना होगा,

पृंजी-पर्याप्तता और बैंक स्वामित्व: पूँजी-पर्याप्तता के मानको में कसाव लाए बिना भी सपत्ति के सामान्य विस्तार के लिए भारी पूँजी की जरूरत हैं। बेंको में सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी पूँजी लगी है। ऐसी स्थिति में सरकार को बैंक पूँजी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े प्रावधान करने होंगे। ऐसे में बेंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत में घटाकर 33 प्रतिशत करने का सवाल भी अहम हो जाएगा।

नाकि ग्रेंका की स्थिनि में ठोस सुधार आए।

वित्तीय बाजारों का एकी करण: मुद्रा प्रतिभूति और विनिमय बाजारों के एकी करण की जरूरत पूर्वी एशियाई सकट के बाद से खासतौर से महमूम की गई है। रिजर्व बैंक ने इन तीनों बाजारों को मजबृत बनाने में प्रशंमनीय प्रयास किए हैं, लेकिन घरेलू बाजार को विदेशी मुद्रा बाजारों में जोड़ने को लेकर आशंकाएँ रही हैं। इन आशकाओं से पिड लुड़ाने की जरूरत है। मंचालन संबंधी मुद्दे: बैंकों की स्वायत्तता और जवाबदेही पर

मंचालन संबंधी मुद्दे : बैंकों की स्वायत्तता और जवाबदेही पर विचार-विमर्श तथा बहसें हुई हैं, लेकिन भारत में ये मुद्दे एकदम धुँभनाए रहे हैं, क्योंकि बैंकों के नियामक और सरकार—दोनों ही वकों के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में संचालक, स्वामी और प्रबंधन की भूमिका में घालमेल हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बेंकों में जिसे शीर्ष 'प्रबश्चन' कहा जाता है, उसकी भूमिका सिर्फ प्रबंधको की ही है। सरकार को इस बारे में गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। नई सहस्राब्दी

के लिए बैंकिंग क्षेत्र का यह सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।

6 बद क्रेडिट चैनलों को खोलने के उपाय : इस बात के लिए बेको को आलोचना की जाती है कि ऋण देने में उनकी रुचि नहीं रही है ओर वे मरकारी प्रतिभृति में निवेश कर आसान गस्ता चुन रहे है। यह आलोचना सही नहीं है। बैंको का पहला दायित्व जमाकर्ता के धन की

रक्षा करना है। अगर सरकारी प्रतिभृतियों पर अधिक व्याज मिलता है तो बैंकों को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। यदि बैंकों को ऋण देने के लिए प्रेरित करना है तो सभी सबद्ध पक्षों को क्रेडिट चैनल खोलने के

लिए ढाँचागत सुधारो की तरफ बढ़ना होगा और वित्त-पोषण की नई व्यवस्था कायम करनी होगी।

7. कमजोर बैंकों के बारे में वर्मा समिति की रिपोर्ट : कमजोर बेको के बारे में वर्मा समिति ने बेहतरीन नुस्खा सुझाया है। समिति ने इंडियन,

यूको और यूनाइटेड बैक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैको को कमजोर माना है। समिति ने जो प्रमुख सिफारिश की हैं. वे इस प्रकार हैं—

क समिति ने पहले तीन कमजोर बेंकों के लिए सरकार में 5,500 करोड़ रुपए के समर्थन की सिफारिश है, लेकिन में इसके खिलाफ हें। किसी मरे हुए व्यक्ति को कृत्रिम साँस से कब तक जिटा रखा जा सकता है ? अगर इतनी राशि सरकार दे ही सकती है तो इसका इस्तेमाल बैंकिंग क्षेत्र में टेक्नॉलॉजी के सुधार पर करना चाहिए।

ख अगर समिति की सिफारिश के अनुरूप संपदा पूर्नार्नमांण कंपनी बनानी ही है तो उसपर लगनेवाले 15 करोड रुपए की पूरी पँजी निजी क्षेत्र में आनी चाहिए और सरकार को भी इतना ही योगदान करना चाहिए।

ग वित्तीय पुनर्संरचना प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश उचित है, लेकिन इसे रिजर्व बैंक के ढाँचे मे नहीं रखना चाहिए। इस तरह से यह रिजर्व बैंक की विशेष शाखा बन जाएगी और बिना वजह की समस्याएँ पैंदा होंगी।

घ. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी.आर.एस) के लिए कोई वित्तीय सहारा साल में 3 प्रतिशत से अधिक स्टाफ कटौती के लिए ही

दिया जाना चाहिए

- ड पूँजी-पर्याप्तता के मार्च 2000 के मानक के आधार पर इन तीन बैकों को धीरे-धीरे निर्धारित अनुपात की ओर बढ़ने का कार्यक्रम दिया जा सकता हैं, लेकिन सरकार को इनका पूँजी-पोपण नहीं करना चाहिए।
- च यह बात ठीक से समझने की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अमली हिस्सेदार जमाकर्ता ही है। आज नहीं तो कल ये जमाकर्ता इन कमजोर बैंकों में दाँव लगाने पर पुनर्विचार करेंगे। अगर सरकार ने कारगर उपाय नहीं किए तो यह काम जमाकर्ता कर डालेगे।

हमे यह मानना होगा कि दुनिया भर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैक पुनर्सरचना

के कठिन दौर से गुजर रहे हैं और हम भी इस समायोजन से अछूते नहीं रह सकते। बहम का समय चला गया है और काम को अंजाम देने का वक्त आ गया है। अगर कमजोर बैंको के रोग को अभी ठीक नहीं किया गया तो यह रोग पूरी वित्तीय प्रणाली में फेल सकता है। एलन ग्रीनस्पैन ने कहा भी है कि वित्तीय प्रणाली उतनी ही मजबूत होती हे, जितनी इसकी सबसे कमजोर कड़ी।

वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का एजेंडा

है। सन् 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत शुरू की गई उदारीकरण की

बृहद् अर्थव्यवस्था के कुणल प्रबंधन के लिए स्टुड विनीय क्षेत्र पहली शर्त

-एन ए. मजुमदार

प्रक्रिया के समानातर वित्तीय क्षेत्र में भी बदलाव आए। दरअसल, उस क्षेत्र में सन् 1990 के दशक में महत्त्वपूर्ण बदलाव देखे गए। इस अध्ययन में वित्तीय क्षेत्र के चुनिंदा हलको में आए इन बदलावों की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन से एक सामान्य निष्कर्ष यह निकला है कि हमारी ताकत नकलची सृधार लागू करने तक ही सीमित है। साथ ही, भारत के मामाजिक- आर्थिक ताने-बाने के मुताबिक इन सुधारों को दिशा न दे पाना हमारी मुख्य कमजोगे रही है। इसके अलावा सुधार लागू करने की प्रक्रिया के टीरान कड विकृतियाँ भी उसमें देखी गई है। इसलिए भविष्य के लिए सुधारों का स्वरूप तय करने समय इन विकृतियों का

सुधारना तथा उपेक्षित क्षेत्रों पर गौर करना हमारा मृख्य ध्येत्र होना चाहिए।

बैकिंग क्षेत्र

नरिमंहम मिनित की सिफारिशों के अनुसार बुनियादी मानद हो को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। इन उपायों के नहत मार्च 2000 के अत तक न्यूनतम पूँजो-पर्यापता अनुपान को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने, बाजार जोखिम को प्रवासने निश्व प्राचीर कर के प्रवासने निश्व प्राचीर की प्रवासने निश्व प्रवासने

वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का मुख्य ध्यान बेंकिंग क्षेत्र पर रहा है। हमने द्वितीय

पहचानने तथा संग्कार द्वारा स्वीकृत प्रतिभृतियों के लिए मार्च 2000 के अन तक 2.5 प्रतिशत के जोखिम वजन का निर्धारण करने, गरिसंपनि के कठोर वर्गीकरण

की दिशा में बढ़ने, आय की पहचान करने, 1 अप्रेल, 1999 से परिमंपीन अवाबदेही प्रबंधन (ए एल एम) को औपचारिक स्वरूप देने और लेखा तथा आय आदि हा खुलासा करने में पारदर्शिता बहाने का लक्ष्य तय किया गया है।

हालाँकि हमने 'ऋण पर लिये मानदंड' लागू करने की दिशा मे काफी हद तक स्फलता अर्जित की है, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के बुनियादी मुद्दो पर पकड बनाने में हम नाकाम रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों का 'अकुशल तथा गेग-च्यावसायिक' कहने का चलन बढ़ गया है और भारतीय विशेषज्ञो द्वारा ही इस प्रकार के विशेषणों के प्रयोग से इन बैकों का आत्मविश्वास और घटा है। उदाहरण के लिए, मार्त्रजीनक क्षेत्र के कमजोर बेंकों के पुनर्गठन सबधी कार्यदल की रिपोर्ट (अध्यक्ष, एम एम वर्मा) में इन बैंकों की सुद्रवता को इनके ऋणमक्त होने, आय अर्जित करने तथा लाभ कमाने को क्षमता के आधार पर परखने की कोशिश की गड़ है। इन कमोटियो पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ही मुदृढ़ वेंकों के तौर पर उभरे हें, जबकि शेप बैंको को मामुली या अत्यधिक गंभीर रूप से वीमार बैकों की श्रेणी में रखा गया है। इंडियन बैक, युको बैक तथा यूनाइटंड वैक को स्पप्टत. काफी कमजोर घोषित किया गया है और इनक लिए तुरत उपाय करने की जरूरत है, जबकि छह अन्य बैंकों—इलाहबाद बैक, सेंटल बेंक, इंडियन ओवरमीज बैंक, पजाब एड सिध बैंक तथा विजया बैंक की भी पहचान कमजोर बेंकों के रूप में की गई है। इंदिरा गांधी इस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेट रिम्पर्च द्वारा तेयार 'इडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट (1999-2000) ' के अनुसार 'भारतीय येक तथा वित्तीय संस्थान उच्च प्रभाव क्षमता, जोखिम-आकलन तथा प्रबंधन के कमजोर ज्ञान, कर्मचारियों तथा शेयरधारकों के हितों से संबंधित विवादो पर्ग नियंत्रण की अपर्याप्त क्षमता के अनुठे संयोजन दरशाते हैं" । अलबत्ता, इन समस्याओं की गंभीरता का देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बैंकिंग क्षेत्र को अगले 2-3 वर्षों के भीतर समस्यामुक्त कर पाना संभव नहीं है। विनियमनो मे हमारे दुरदर्शी मुधारों के बावजूद आनेवाले वर्षी में भारत की बैंकिंग प्रणाली मे आर मंकट तथा दीवालियापन आ सकता है।' (पृष्ठ 21) ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र

के बैकों को हम कैमे बचा मकते हैं ? क्या कोरिया और थाईलैंड की तीर्थयात्रा के माध्यम से ऐसा किया जाएगा ? दुर्भाग्यवश इनमें से किसी भी भारतीय विशेषज्ञ ने भारतीय सदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-उत्पादक परिसपित्तयों (एन.पी.ए) की उत्पत्ति के बारे में

क्षत्र के वका का गर-उत्पादक पारसपात्तया (एन.पा.ए) का उत्पात्त के बार म जानने का प्रयास नहीं किया है। ये एन पी.ए इन बैंकों द्वारा विदेशों से कम अविध के लिए भारी ऋण लेने और इस राशि को संपत्ति या शेयर-बाजारों में निवेश करने का परिणाम नहीं हैं, जैसाकि आधिकतर पूर्वी एशियाई देशों मे हुआ था। भारत मे इसका कारण राजनीतिक हस्तक्षेप, ऋण-मेले या कुछ व्यापारिक उधारकर्ताओं का दी गई खास सहूलियते है। पेशेवर योग्यता के आधार पर भारतीय बेकर विश्व भर मे अद्वितीय हैं, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्रों के बेंको की खस्ता हालत के लिए उन पर

दोष मढना अनुचित ही होगा। यह ठीक है कि उन्हें जोखिम मापने के अर्थशास्त्रीय मॉडल से उचित प्रकार से निपटना न आता हो, परंतु उन्हे जोखिम-प्रवधन का

भरपूर व्यावहारिक ज्ञान है। दरअसल, दोप उस बृहद् माहौल का है, जिसमे वे काम करते हैं और उसे ही बदलने की जरूरत है। अब भारत सरकार या भारतीय रिजर्व

बैंक को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बैंकों के प्रबंधन में वे सिक्रय भूमिका निभाते हैं। इन वेकों को स्वायत्तता

देना भी व्यावहारिक समाधान हो सकता है। इनके मौजृदा निदेशक मंडलो को बर्खास्त कर उनके स्थान पर ईमानदार और प्रतिष्ठित विशेषज्ञों, जैसे उच्च न्यायालयों के अवकाशप्राप्त न्यायाधीशों, अर्थशास्त्रियों, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि, को बोर्ड मे

के अवकाशप्राप्त न्यायाधीशों, अर्थशास्त्रियों, चार्टर्ड एकाउंटर आदि, को बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए। एन पी ए से निपटने के लिए बैंक ही सबसे सक्षम एजेसी है. न कि परिसंपत्ति प्रबंधन कपनियाँ या परिसंपत्तियाँ पनर्गठन कोए।

एजेसी है, न कि परिसंपत्ति प्रबंधन कपनियाँ या परिसंपत्तियाँ पुनर्गठन कोप।
भूमडलीकरण की अवधारणा की अपर्याप्त समझ के कारण बौद्धिक दासता
उदारीकरण के युग के उप–उत्पाद के रूप में उपजी है। भारतीय स्टेट बेंक अपने

लिए आर्थिक सलाहकार नियुक्त करते समय लंदन स्थित 'इकॉनॉमिस्ट' में इस पद का विज्ञापन देना पसंद करता है। शुक्र है कि अब तक किसी भारतीय विशेषज्ञ ने कमजोर वैंको के प्रबंधन हेतु उन्हे लंबी अवधि के लिए विदेशी बैंकों को मौंपने का सुझाव नहीं दिया है, जैसाकि पोलैंड के मामले में हुआ है। देसी समस्याओं से

देसी उपायों के जरिये बेहतर तरीके से निबटा जा सकता है। आत्मिनंदा से न तो समस्या का हल प्राप्त किया जा सकता है और न ऐसा करना वित्तीय क्षेत्र की छवि के लिए ही ठीक होगा।

सार्वजिनक क्षेत्र के बैकों की समस्याओं की जड में प्रमुख मुद्दा ऋण सबंधी है। बैंकिंग क्षेत्र के संसाधनों का उचित प्रयोग उधार जमा अनुपात से प्रतिबिबित होता है, जो पिछले कई वर्षों से 50 प्रतिशत के आस-पास बना हुआ है। इन संसाधनों के अधिक सार्थक इस्तेमाल से सार्वजिनिक क्षेत्र के बैंकों का लाभ

और अर्थव्यवस्था का विकास भी तेज गति से हो सकता है।

विकास बैंक

बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार के लिए गठित नरसिंहम समिति ने सुझाव दिया था कि विकास वित्त संस्थानों (डी एफ आई) को स्वयं को बदलकर व्यावसायिक वैको या गैर-बैंकिंग वित्त-कपनियों के रूप में ढाल लेना चाहिए। बाद में खान कार्यदल ने भी डी एफ आई को बैंक के रूप में बदलने की अनुमित देने की सिफारिश की। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस विषय पर विचार-विमर्श हेत् एक

सिकारिश करा निरिताय रिजय अके ने मा इस विषय पर विचार-विमश हतु एक परचा जार्ग किया। उपपर हुई प्रतिक्रियाओं के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक का निष्कर्प रहा कि ' हालाँकि यूनीवर्सन बैंकिंग की अवधारणा संसाधनों के कुशलतापूर्वक इस्तेमाल की दृष्टि से वाछनीय है, परंतु इस प्रकार की प्रणाली की

तरफ यहने समय काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। कॉरपोरेट जगत् अब भी परियोजनाओं के विन-पोषण के लिए डी एफ आई. पर निर्भर है। दूसरी तरफ कम अवधि के वित्त पोषण के लिए आवश्यक ढॉचागत सुविधाएँ तथा विशेषज्ञता व्यावसायिक बेंकों के पास है।' (वार्षिक रिपोर्ट, सन् 1998-99, पृष्ठ 149) यह निष्कर्ष तार्किक है। आमतोर पर बैंको तथा डी एफ आई को क्रमश: कम और लबी अवधि के ऋण उपलब्ध कराने की दशा में विशेषज्ञता प्राप्त है। पूर्वी एशिया का अन्भव भी इस निष्कर्ष की ही पृष्टि करता है।

पूँजी बाजार

पूँजी बाजार अब अनुभवी हो चले हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, क्लियरिंग निगमों (शोधन गृह) तथा निक्षेपगृहों (डिपॉजिटरी) के बाद से प्रतिभूति बाजारों में महत्त्वपूर्ण संस्थागन बदलाव आए हैं। मुंबई बाजार अब सचमुच राष्ट्रीय बाजार बन गया है। डिरिवेटिव व्यापार भी शुरू होने की प्रक्रिया में है। इस सदर्भ में जिन दो समस्याओं पर अब तक अधिक ध्यान नहीं गया है, वे हैं—निजी प्लेसमेंट बाजार तथा म्यृचुअल फंड्स से प्राप्त लाभांश और आय को आयकर से मुक्त रखना। पिछले कुछ वर्षों के दौरान निजी प्लेसमेंट बाजार कार्रपोरेट घरानों के लिए

पिछले कुछ वर्षों के दौरान निजी प्लेसमेंट बाजार कारपोरेट घरानों के लिए ससाधन जुटाने के प्रमुख स्रोत के तौर पर उभरे हैं। सन् 1998-99 में बैंकों, वित्तीय सम्थानों ऑर मार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों ने इस तंत्र के जिरये लगभग 50,000 करोड़ रुपए जुटाए, जो प्रोस्पेक्ट्स और राइट्स इश्यू के माध्यम से अर्जित 10,000 करोड़ रुपए से कहीं अधिक हैं। अब सवाल यह उठता है कि बाजार के विकास की कीमत पर निजी प्लेसमेंट मार्गों का विकास क्या स्वास्थ्यकारी है? यह मुद्दा महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि फिलहाल निजी प्लेसमेट, सेबी द्वारा निर्धारित निवेशकों के हित संबंधी मानटंडों की सुरक्षा के दायरे में नहीं आते। नए उद्यमी के लिए निजी

सन् 1998-99 के बजट में म्यूचुअल फंड्स से प्राप्त आय और लाभांश को

प्लेसमेंट तक पहुँचना सरल भी नहीं है।

भेदभाव हुआ, क्योंकि उनसे प्राप्त आय पर आयकर देय है। इस प्रकार यह उपाय गेर-समानतावादी तथा अमीरों के पक्ष में है। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि व्यावसायिक बैंकों ने ही भारत की बचत-दर को जी. डी पी के 12 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में बेंकों के साथ भेदभाव की नीति से इस राष्ट्रीय वचत-दर में कमी आ सकती है। यह देखना होगा कि पूँजी बाजार को विकसित करने का हमारा उत्साह वचन के अन्य उपकरणों को नकसान

न पहुँचाए। यह भेदभाव जितनी जल्दी दर किया जाएगा, अर्थव्यवस्था की दुष्टि से

आयकर के दायरे से मुक्त रखा गया था। एसा ऊपरी तौर पर इक्विटी में निवेश का पोत्साहित करने के लिए किया गया था। दर्भाग्यवश इस कदम से बैकों के साथ

ग्रामीण ऋण-प्रणाली

उतना ही अच्छा है।

ग्रामीण ऋण-व्यवस्था, जिसके अतर्गत व्यावसायिक बंको की ग्रामीण शाखाएँ, सहकारी ऋण संस्थान और क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक शामिल हैं, की लगभग पूर्ण उपेक्षा इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि वित्तीय क्षेत्र के हमारे सुधार नकल पर आधारित है। यह पूरी प्रणाली आज खम्ताहाल है। कृषि तथा लघु क्षेत्र के उद्यम जी डी पी और निर्यात में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार ग्रामीण ऋण प्रणाली भारतीय वित्त क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण अंग है।

ग्रामीण ऋण प्रणाली में जान फूँकने को वित्त क्षेत्र के भविष्य के लिए सुधारों के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए। (रिवाइविंग रूरल क्रेडिट, इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 19 जून, 1999) यहाँ मामला प्रणाली में हलकी-फुल्की छेड़छाड़ का या कुछ सहकारी संस्थानों के साथ महमति के करार करने भर का नहीं है, बल्कि पूरे तत्र को कारगर तथा मिक्रिय बनाने के लिए नई संरचना तैयार करने का है।

निष्कर्ष

दूसरी पीढ़ी के वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में बात करना समझदारी ही होगी। इस संक्षिप्त अध्ययन में इस बात को म्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि सुधार लागू करने की प्रक्रिया के दौरान आई विकृतियों को दूर करना और सुधार-प्रक्रिया के दौरान उपेक्षित रहे क्षेत्रों पर ध्यान देना भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य के सुधारों के एजेंडे में इन पक्षों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

कृषि-नियोजन : इक्कीसवीं शताब्दी की चुनौतियाँ तथा अवसर

-के.सी. पत

हमारे दंश को गरीबी की समस्या से अभी निबटना है। वर्तमान में 1 अरब आबादी में से 35 करोड़ लोग गरीबी-रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं। 60 प्रतिशत से अधिक आबादी अब भी अपने जीवनयापन और रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। चिता का प्रमुख विषय यह है कि राष्ट्रीय आय में कृषि-क्षेत्र के योगदान में तेजी से कमी आई है, परंतु कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में मामूली गिरावट ही देखी गई है। ग्रामीण आबादी के लिए कृषि क्षेत्र में लाभकारी रोजगार अवसरों को जुटाना उस परिदृश्य में और भी चुनौतीपूर्ण कार्य है, जहाँ जोतो का आकार न सिर्फ छोटा है, बल्कि यह लगातार सिकुड़ता जा रहा है और भूमि पर दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों, विशेषकर गरीब तबको के लिए रोजगार जुटाने के लिए जबरदस्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

खाद्यान आत्मनिर्भरता

रचनात्मक नियोजन, कृषि अनुसंधान तथा विकासोन्मुख नीतियों के चलते हमारा देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मिनिर्भर बन सका है। सन् 1960-61 में खाद्यान्न उत्पादन 8.2 करोड़ टन रहा, जबिक पिछले वर्ष 20.3 करोड़ टन का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया। इसी प्रकार नब्बे के दशक में वार्षिक सुरक्षित (बफर) भंडार 2 से 3 करोड़ टन रहा। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हमारी जनसंख्या वृद्धि के मुकाबले अधिक रही है। यही कारण है कि कृषि के क्षेत्र में देश के प्रदर्शन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। तिलहन, व्यापारिक फसले और पशुधन के क्षेत्र में हमारी प्रगति उल्लेखनीय रही है। सन् 1960-61 में तिलहन उत्पादन 70 लाख टन रहा, जो सन् 1999 में बढ़कर 2.5 करोड़ टन तक पहुँच गया। इसी प्रकार गन्ना

उत्पादन भी सन् 1960–61 मे 11 करोड़ टन के मुकाबले बढकर 30 करोड़ टन हो गया। आलू उत्पादन भी 30 लाख टन से बढकर 2 3 करोड टन दर्ज किया गया।

दूध उत्पादन 2 करोड टन से बढ़कर 7 5 करोड़ टन तक जा पहुँचा। इस तरह जहाँ एक ओर आबादी लगातार बढ़ती रही, वहीं खाद्यान-

उपलब्धता सन् 1950-51 में 400 ग्राम प्रतिदिन से कम रहने के बावजृद सन् 1997 में 510 ग्राम तक जा पहुँची। प्रति व्यक्ति दूध-उपलब्धता भी 125 ग्राम प्रतिदिन से

बढ़कर 204 ग्राम हो गई। ये उपलब्धियाँ कम नहीं है और हम निश्चित रूप से इनके मामले मे गर्व महसूस कर सकते हैं।

इन सफलताओं से यह उम्मीद तथा विश्वास और दृढ़ होता है कि हमारे कृषि विशेषज्ञ भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला बखुवी कर सकेंगे।

अलबत्ता हमें यह स्वीकार करना होगा कि आनेवाल दिनो में हमारे कृषि वैज्ञानिकों को और भी अधिक जटिल तथा कठिन समस्याओं से जुझना होगा। हमारे

वैज्ञानिकों को ओर भा आधक जटिल तथा काउन समस्याओं स जूझना हागा। हैमारे समक्ष सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौती खाद्यान्न उत्पादन में समुचित और निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने की है, ताकि लगातार बढती स्वस्थ आबादी की खाद्यान्न की

जरूरत पूरी की जा सके। हमारी आबादी 1 अरब से अधिक हो चुकी है और विशेषज्ञों के पूर्वानुमान के मुताबिक सन् 2035 तक हम इस क्षेत्र में चीन को पीछे छोड देगे। इस बढती आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमें प्रतिवर्ष 50-

60 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान उत्पादन की जरूरत होगी।

इस सदर्भ में हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि कृषि के लिए उपलब्ध भूमि सीमित है। दरअसल, सभावना तो यह भी व्यक्त की जा रही है कि कृषि योग्य क्षेत्रफल कुछ सिकुड़ सकता है। पर्यावरण की दृष्टि से जरूरी है कि वनाच्छादित क्षेत्र को उसके वर्तमान के खतरनाक स्तर के सकाबले बहाया जाए। इसी प्रकार

क्षेत्र को उसके वर्तमान के खतरनाक स्तर के मुकाबले बढ़ाया जाए। इसी प्रकार शहरीकरण और उद्योग भी हमारी कृषि योग्य भूमि को निगलते जा रहे हैं। हम इन तथ्यों से आँखें नहीं मूँद सकते। मौजुदा स्थिति इस बात के मद्देनजर और भी

जिटल हो गई है कि कृषि विकास के हमारे पुराने स्रोत संतुप्त हो गए हैं। इस

परिदृश्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उपायो पर काम करने की जरूरत है। क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर किए जानेवाले नियोजन तथा समुचित नीतियों पर अमल करने से वर्षायुक्त क्षेत्र कृषि-उपज बढ़ाने में योगदान कर सकते

हैं। वर्तमान में ये क्षेत्र हमारी 40 प्रतिशत आबादी तथा देश के 75 प्रतिशत गरीबो के लिए संसाधन उपलब्ध कराते हैं। फिलहाल कुछ राप्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन का 45 प्रतिशत हिस्सा इन क्षेत्रों से ही प्राप्त होता है। वर्षायुक्त क्षेत्रों मे कृषि उत्पादन बढ़ ने के लिए सरिक्षत सिचाई की आवश्यकता होती है। इसिलए नियोजन की प्रक्रिया के दौरान ही सिचाई-प्रबंधन में किसानों की सिक्रय भागीदारी को बढ़ावा देने के उपायो पर विचार करने की जरूरत है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए देश की पारिस्थितिकी में मौजूदा विविधता के मद्देनजर क्षेत्र विशेष का खयाल रखते हुए नियोजन की आवश्यकता है।

हालाँकि हमारे अतीत के प्रयासों ने विकास-प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भरपूर मदट की है, परंतु कृषि उत्पादकता तथा उससे प्राप्त आय में क्षेत्रवार अतर को देखते हुए क्षेत्र विशेष सबंधी नियोजन आवश्यक हो गया है। विकसित और विकासशील क्षेत्रों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। जहाँ एक ओर उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है, वही पूर्वी और पूर्वीत्तर क्षेत्र कृषि-विकास में पिछड़े रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, सन् 1970 के दशक में पंजाब में पूर्वी राज्यों का चावल का उत्पादन रिकॉर्ड किए गए उत्पादन स्तर के बराबर है। पूर्व में प्राय: बेहतर संसाधनयुक्त राज्यों को इस दृष्टि से प्राथमिकता दी जाती रही है कि इन क्षेत्रों में अच्छी पैदावार का लाभ अन्य पिछड़े राज्यों को भी मिलेगा, परतु हमें स्वीकार करना होगा कि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ।

असंतुलित क्षेत्रीय विकास

इस असंतुलित क्षेत्रीय विकास के कारण काफी बड़ी संख्या में ग्रामीणों को विकसित तथा शहरी इलाकों में जाकर बसने के लिए मजबूर होना पड़ा। इक्कीसवीं शताब्दी के दौरान कृषि-नियोजको की प्राथमिकता इस असतुलन को कम करने और अंततः पूरी तरह समाप्त करने तथा रोजगार के नए उत्पादक अवसर जुटाने की होनी चाहिए। सौभाग्यवश पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में भूमिगत जल के बड़े स्रोत मौजूद हैं। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन भी बड़े स्तर पर उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ उत्पादन स्तर काफी कम है। कृषि विकास के लिए इन क्षेत्रों की क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए उचित प्रयास करने की जरूरत है। ये क्षेत्र ढाँचागत विकास की दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं। यहाँ भूमिगत जल विकास, बिजलीकरण, बाजारो तथा सड़को के विकास के लिए किए गए निवेश के निजी तथा सामाजिक स्तर पर काफी भारी मात्रा में लाभ मिल सकते हैं। ढाँचागत सुविधाओं के अभाव के कारण बहत सी विज्ञान-आधारित कृषिगत प्रौद्योगिकी इन क्षेत्रों में नहीं पहुँच पाई है। इस

इन क्षेत्रों के किसानो के सूचना-स्तरों में भी सुधार करने की आवश्यकता

स्थिति में तेजी से सुधार करने की आवश्यकता है।

मती देने के लिए सदढ़ सेवाक्षेत्र भी चाहिए, जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने वश्यक आगत की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इक्कीसवी नियोजन-प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सुचना के जल्द प्रसारण

ना प्रौद्योगिकी की क्षमता का भरपूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

विधीकरण

5º

न इसका कुल 10 प्रतिशत हिस्सा ही इस्तेमाल किया जा रहा है।

55 M. ात्यधिक उपयोग के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसके लिए कुछ 77.5

किसानों की क्षमताओं का कम आकलन भी दोषी है। इसी प्रकार 1.45 Fred day **在**其物水质 THE THE

13器

नें कृषि के विविधीकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था। दरअसल, बानी और मत्स्यपालन के विकास रूप में कृषि के विविधीकरण की नाएँ हैं। पश्धन का क्षेत्र कृषि क्षेत्र की विकास प्रक्रिया मे तेजी लाने भूमिका निभा सकता है। दूध, मांस, ऊन और अडों के उत्पादन की

, इस पूरे क्षेत्र में विस्तार सेवा तंत्र को मजबूत बनाने की जरूरत है। इस

री पशुधन-उत्पादकता विश्व में निम्नतम है। दूध का सबसे बड़ा होने के बावजूद उत्पादकता तथा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता की कई विकसित देशों में पीछे हैं। मत्स्य क्षेत्र अभी तक अधिकसित है। उत्पादन बढाने की भी काफी सभावना है। हमारे पास 14 लाख ारा पानी उपलब्ध है, जो छोटी मछलियों के विकास के अनुकृल है,

जब्दी में इन क्षेत्रों का विकास करना होगा, ताकि देश के आर्थिक महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकें। अलावा पर्यावरण के अनुकूल कृषि क्षेत्र का विकास करने की र्ग में इस बात का ध्यान नहीं रखे जाने के कारण प्राकृतिक ससाधनो है। साठ के दशक के मध्य में शुरू की गई हरित क्रांति भी प्राकृतिक

नाओं पर जोर देने की प्रवृत्ति भी ससाधनों के दोहन और कुप्रबधन है। उदाहरण के लिए—नहरों के पानी, बिजली, नाइट्रोजन उर्वरकों क रिआयतों के चलते किसान इनके खतरों की अनदेखी करते हुए 5 प्रयोग करने के लिए प्रेरित हुए। हरित क्रांतिवाले क्षेत्रों में अकसर , पानी जमाव, जलस्तर में गिरावट, पानी की गुणवत्ता में कमी, भृमि , आदि समस्याएँ सामने आ रही हैं। उधर जीविका-निर्वाह से जुड़े

रण, बन-कटाव, रेगिस्तान में भूमि के बदलना आदि समस्याएँ सिर

भारतीय अर्थनाति *

उठा रही हैं, जहाँ किसानों की निवेश-क्षमता तो कम है ही, साथ ही सरकार की ओर से भी उनपर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

प्राकृतिक संसाधनों के स्तर में गिरावट से कृषि विकास की गित कम हुई है। देश की बढ़ती आबादी की मौजूदा और भिवष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इक्कीसवीं शताब्दी की सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल, कृषि के टिकाऊ उत्पादन के लिए प्रभावी नियोजन के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकृल प्रौद्योगिकी और नीतियों की आवश्यकता है।

कृषि में जनता का घटता निवेश भी चिंता का विषय है। अस्सी के दशक के

कृषि में घटता निवेश

शुरुआती वर्षों में शुद्ध घरेलू उत्पाद का 9 प्रतिशत अंश दोबारा कृषि में पूँजी के तौर पर निवेशित कर दिया गया था; परंतु नब्बे के दशक के दौरान यह घटकर मात्र 5 प्रतिशत रह गया। इस प्रवृत्ति को बदलने की जरूरत है, तािक कृषि विकास और क्षेत्रवार प्रदर्शन पर प्रतिकृल असर न पड़े। नियोजन-प्रक्रिया के तहत सिंचाई, सडकों, परिवहन, ऋण-सस्थाओ, बाजारों, बिजलीकरण, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज आदि से जुड़ी सुविधाओं को विकसित करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन देश की भौगोलिक स्थित तथा आवश्यक निवेश की दृष्टि से देखें तो वर्तमान में उपलब्ध कराए जा रहे संसाधन अपर्याप्त हैं। इस समस्या के समाधान के लिए संरचनात्मक विकास के क्षेत्र तथा प्रसंस्करण उद्योग में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी जरूरी है। इस दिशा में सभी नीतिगत तथा प्रक्रियागत बाधाओं को पहचानकर तुरत आधार पर दूर करने की भी जरूरत है।

भूमंडलीकरण नब्बे के दशक के आरंभ से ही घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक माहौल

तेजी से बदल रहा है। कृषि तथा खाद्यान्न रिआयतों का मुद्दा काफी सवेदनशील है, परंतु बढ़ते राजकोषीय घाटे के मद्देनजर इनपर लगातार बहस होती रही है। कृषि रिआयतो के सामाजिक लक्ष्यों तथा उनकी राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए इस क्षेत्र में सुधार आदि को सावधानीपूर्वक लागू करना होगा। इस

सिलिसिले में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) समझौते को लागू करने के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादों के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय बाजारों को खोले जाने के मुद्दे पर भी विचार करना होगा। डब्ल्यू.टी ओ. का सदस्य होने के नाते हमें मात्रात्मक

प्रतिबंध हटाने के साथ साथ शल्क दरों को घटाना होगा। इसी प्रकार आयात परिदश्य भी पूर्ववत नहीं रहेगा। हालाँकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हम मुक्त रूप से

व्यापार कर सकेगे. परंत हमें इस बात का विश्लेषण और आकलन करना होगा कि

इससे हमारे उत्पादको तथा उपभोक्ताओं पर कैसा असर पड़ेगा। अलबत्ता भुमंडलीकरण से केवल खतरा ही नहीं है। सच तो यह है कि

इसने कई नए अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। हमारे देश में प्राकृतिक मंसाधनो का

तो सम्चित भड़ार है ही, ऋतुओं की विविधता भी है। हमारे यहाँ दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले जैव-विविधता का भी पर्याप्त भंडार है। शायद ही कोई ऐसी फसल होगी, जो हमारे देश में न उगाई जा सके। डब्ल्यू टी ओं समझौते के बाद

विश्व वाजारों तक हमारी पहुँच बढ़ने की संभावना है। वर्तमान मे विश्व-निर्यात मे हमारी भागीदारी 1 प्रतिशत से भी कम है। हमे उन वस्तुओं की पहचान करनी होगी. जिनके मामले में अंतरराष्ट्रीय बाजार मे हम बेहतर स्थिति में हैं। हम अपेक्षाकृत

सस्ती और अत्यधिक मेहनती श्रम शक्ति को लेकर भी लाभ की स्थिति में है। अब हमें यह आकलन करना होगा कि इस महत्त्वपूर्ण संसाधन का बेहतर इस्तेमाल किस

प्रकार किया जाए, ताकि हम अंतरराष्ट्रीय बाजार की प्रतियोगिता में टिक सके। कृषिक्षेत्र में हमारे पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएँ मौजूद हैं, जिन्होंने

अतीत में भी देश के समक्ष मुँह उठाकर खडी हुई चुनौतियों का जमकर मुकाबला किया था। भविष्य में भी आवश्यकता पड़ने पर वे फिर नए समाधान प्रस्तुत करने

में सक्षम हैं। राष्ट्र की भी उनसे यही अपेक्षा है। कृषि के क्षेत्र में यह वह समय है, जब हमे उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा

उपकरणो का इस्तेमाल खाद्यान्न और अन्य फसलों के उत्पादन के लिए करना चाहिए। इसके लिए हमें भारतीय कृषि के संदर्भ में लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए नियोजन करना होगा। इस दिशा में जैव प्रौद्योगिकी जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की जरूरत है, ताकि उत्पादकता संबंधी समस्याओं से प्रभावी तरीके से

निबटा जा सके। ऐसे में संरचनात्मक किमयों से निबटने के लिए सरकार और उद्योग के बीच सहभागिता बढ़ाने की जरूरत है। हमें अपने कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने की उनकी क्षमता पर भी पूरा भरोसा है उम्मीद है कि वे इस मामले में हमें निराश नहीं करेंगे।

[राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के पाँचवें स्थापना दिवस के अवसर पर दिया गया व्याख्यान, 5 जुन. 2000।1

भारतीय उद्योग जगत् : संरचनात्मक बदलाव, पुनर्गठन, प्रदर्शन तथा हाल की नीतिगत पहल

(भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट)

भारतीय उद्योग जगन् नब्बे के दशक में महत्त्वपूर्ण बदलावों के दौर से गुजा है। सगठनात्मक पुनर्गठन तथा अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और चुनौतीपूर्ण औद्योगिक माहौल के निर्माण के उद्देश्य से औद्योगिक नीतियों मे बदलाव की प्रक्रिया जारी ह। संरचनात्मक परिवर्तनों से औद्योगिक प्रदर्शन आमतौर पर सुगठित हुआ है। नब्बे के दशक मे औद्योगिक उत्पादक सूचकांक (आई.आई.पी) पर आधारित औद्योगिक विकास में अस्सी के दशक की तुलना में (3 2 प्रतिशत से 9.3 प्रतिशत तक) व्यापक बदलाव (0.6 प्रतिशत से 12 7 प्रतिशत तक) देखा गया। औद्योगिक पुनर्गठन की आवश्यकता ने निजी कॉरपोरेट क्षेत्र मे विलयन और अधिग्रहण, सार्वजनिक क्षेत्र मे सुधारों तथा कॉरपोरेट जगत् की कार्यप्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और प्रभावी बनाने से जुड़े कई मुद्दों को उठाया है। इस अध्ययन मे इन्हीं पर प्रमुखता से विचार किया गया है।

उद्योग जगत में संरचनात्मक बदलाव

में 11.2 प्रतिशत तक ऊपर उठा।

पिछले तीन दशकों मे उद्योग जगत् मे विकास-दर तथा सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी पी.) में यांगदान की दृष्टि से कोई खास प्रगति नहीं दिखाई पड़ी है। सत्तर के दशक में औद्योगिक उत्पाद की औसत वार्षिक विकास-दर 4.4 प्रतिशत थी। सन् 1979-80 में यह दर मात्र 2.6 प्रतिशत रही थी और सन् 1978-79 में 11 6 प्रतिशत दर्ज की गई। अम्सी के दशक में औसत वार्षिक विकास-दर 7.2 प्रतिशत रही। विकास-दर का ऑंकडा सन् 1980-81 में 1.4 प्रतिशत और सन् 1989-90 दो वर्षों में यह ऑकडा 11.2 और 12 9 प्रतिशत रहा, जबिक सन् 1991-92 में लुढ़ककर यह 1 9 प्रतिशत तक पहुँचा और अगले वर्षों में 6 प्रतिशत से ऊपर रहा इसी दशक में वार्षिक औसत विकास-दर (1998-99 तक) कुछ कम, यानी 6 6 प्रतिशत रही। सन् 1970 में जी डी पी. में उद्योग की हिस्सेदारी 18 6 प्रतिशत थी और सन् 1995-96 में यह बढ़कर 27 प्रतिशत हो गई। सन् 1996-97 में यह घटकर 22 प्रतिशत हो गई। अगले दो वर्षों तक यही ऑकडा कायम रहा।

नौवें दशक में औद्योगिक विकास मे काफी उतार-चढ़ाव देखे गए। पहले

औद्योगिक उत्पादन के सूचकाक की दृष्टि से सन् 1991-92 से 1998-99 तक उत्पादन की विकास-दर धीमी रही। उद्योग जगत् के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर खनन तथा खुदाई में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है (तालिका-1)।

तालिका-1 औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक औसत विकास-दर

			(प्रतिशत)
क्षेत्र	1981-82 से	81-82 से	91-92 से
	98-99 तक	90-91 तक	98-99 तक
सामान्य सूचकाक	69	78	5.8
1. निर्माण	69	7.6	5. 9
2 विद्युत्	8 0	90	68
3 खनन तथा खुदाई	6.0	8 3	3 0

तालिका-2 औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक विकास-दर-प्रयोग आधारित वर्गीकरण (प्रतिशत)

			(NISHIK)
क्षेत्र	1981-82 से	1981-82 से	1991-92 से
	98-99 तक	90-91 तक	98-99 तक
1. बुनियादी वस्तुएँ	7.1	79	6 2
2. पूँजीगत वस्तुएँ	7.7	115	3.0
 मध्यस्थ वस्तुएँ 	6.7	5.9	77
4. उपभोक्ता वस्तुएँ	6 2	6.7	5.5
क. टिकाऊ	11 2	13 9	7.9
ख. गैर-टिकारू	5 3	5.5	5.0
सामान्य सूचकांक	6.9	78	5 8
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

तालिका-2 से स्पप्ट है कि जहाँ एक ओर अस्सी के दशक में बुनियादी तथा पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र ने तेज रफ्तार से विकास किया, वहीं नब्बे के दशक

मे मध्यवर्ती वस्तुओ से जुड़े क्षेत्रों ने विकास की तेज गति दर्ज की। नौवें दशक में बनियादी, पूँजीगत तथा उपभोक्ता वस्तुओं से जुड़े क्षेत्रो की विकास-दर में सापेक्ष

औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक मे विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष योगदान

कुछ उत्पादन में क्षेत्रवार सापेक्ष योगदान

कमी का प्रमुख कारण औद्योगिक क्षेत्र में जारी पुनर्गठन की प्रक्रिया है।

में बदलाव भी ओद्योगिक उत्पादन में हो रहे सरचनात्मक परिवर्तनों के एक अन्य पहलू को ही दरशाते हैं। तालिका-3 में उपलब्ध आँकडे बताते हैं कि अस्सी के दशक के दौरान निर्माण-क्षेत्र का योगदान 70 प्रतिशत से बढ़कर नब्बे के दशक मे

81 6 प्रतिशत हो गया। अलबत्ता, खुदाई और खनन के मामले में महत्त्वपूर्ण गिरावट देखी गई।

किया गया है।

तालिका-3 विभिन्न वर्गो का औद्योगिक उत्पादन में तुलनात्मक योगदान

(प्रतिशत) 1981-82 से 90-91 तक 92-93 से 98-99 तक * क्षेत्र (औसत) (औसत) निर्माण 70 O 81.6 विद्यत 144 144 3 खनन एवं खुदाई 156 40 सामान्य स्चकाक 100.0 100 0

आई आई.पी शृखला निर्माण प्रक्रिया के दौरान विभिन्न क्षेत्रो के लिए निर्धारित वजनों मे भी इन बदलावों की झलक मिलती है। निर्माण-क्षेत्र का वजन, सन् 1980-81 + 100 के आधारवाली पूर्व की आई आई.पी. शृंखला में 77 1

प्रतिशत से बढ़कर मन् 1993-94 = 100 के आधारवाली मौजूदा शृंखला में 79 36 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार खनन और खुदाई तथा बिजली के क्षेत्रों का भी सापेक्ष वजन पुरानी तथा नई शृंखला में 11 46 प्रतिशत से घटकर 11.43 प्रतिशत और 10.47 प्रतिशत से घटकर 10.17 प्रतिशत रह गया।

^{*} इस अवधि में उत्पादन लगभग स्थिर होने के कारण सन् 1991-92 से सर्वधित आँकड़ों को शामिल नहीं

तालिका 4 निर्माण-क्षेत्र का वजन ढाँचा

आधार

आधार

1970=100 80-81=100 93-94=100

आधार

क्षेत्र

श्रेणी-1	खनन एवं खुदाई	9 69	11 46	10 47	
श्रेणी-2 और 3	निर्माण	81 08	77.11	79 36	
श्रेणी-4	विद्युत्	9 23	11.43	10 17	
कुल	सामान्य सूचकांक	100.0	100 0	100 0	
नब्बे के व	दशक के दौरान बुनि	ायादी और	पूँजीगत वस्तुओ सं	——— ने जुड़े क्षेत्रो के	
सापेक्ष योगदान मे	ं गिरावट आई, परंतु	मध्यवर्ती	और उपभो क्ता वस्	नुओं के क्षेत्र मे	
वृद्धि दर्ज की गई	(तालिका-5)।				
	ता	लिका-5			
विभिन	क्षेत्रों का औद्योगि	क उत्पादन	। में तुलनात्मक यें	गिदान	
	(प्रयोग-आ	धारित वर्ग	किरण)		
				(प्रतिशत)	
क्षेत्र	1981-82 से 90-	91 तक	92-93 से 98-	99 तक *	
	(औसत)		(औसत)	
1 बुनियादी वस्त्	एँ 43.6		35.8		
2 पूँजीगत वस्तु	एँ 250		7.1		
3 मध्यस्थ वस्तु	एँ 146		35 2		
4 उपभोक्ता वस्त्	प्रॅि 168		21 9		
सामान्य सूचकाक	100.0		100.0	V-Mpc-Mpc-dat VP-salts developed philosopes per particular services and	
नब्बे के ट	पाक में औसोगिक व	ਪਰਗਟਸ ਸ਼ੇ	නුදිනුව අනු රීනි	ਹਰ ਕੁਸ਼ਰੂਆਂ ਜੋ	
नब्बे के दशक में औद्योगिक उत्पादन में बुनियादी तथा पूँजीगत वस्तुओं में जुड़े क्षेत्रों का अपेक्षाकृत कम योगदान, अन्य बातों के अलावा व्यापार के उदारीकरण,					
जुड़े क्षेत्रो का अपेश					

विशेषकर आयात में तथा वित्तीय उदारीकरण के प्रभाव के कारण रहा। इसके चलते कॉरपोरेट जगत् को 'अन्य आय' से लाभ मिला। माथ ही कई उद्योगों में पुनर्गठन तथा प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण की जरूरत के चलते प्रतिस्पर्शा में कमी के

कारण भी ऐसा हुआ।

एन.आई.सी.

शेणी

^{*} इस अवधि में उत्पादन लगभग स्थिर होने के कारण मन् 1991 -92 में सबक्षित आँक डो को शामिल नहीं किया गया है।

हाल में हुआ संगठनात्मक पुनर्गठन : विलयन तथा अधिग्रहण (एम. ए.)

हाल की अवधि में भारतीय कॉरपोरेट जगत् में हुआ पुनर्गठन अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक माहोल में प्रेरित था। नौवे दशक के शुरुआती वर्षों में शुरू किए गए मरचनात्मक मुधारों ने भारतीय उद्योग जगत् पर कॉरपोरेट पुनर्गठन करने, गौण गतिविधियों को छोडने तथा विलयन और अधिग्रहण के लिए दबाव डाला।

पुनर्गठन की इस प्रक्रिया में शामिल है—(क) प्रमुख गतिविधि में पूर्ण योग्यता/ कुशलता पर जोर. (ख) विदेशों में विस्तार, (ग) ससाधन जुटाना तथा (घ) उत्पाद पोर्टफोलियों को नर्कसगत बनाना। कॉरपोरेट जगत् ने तेजी से विकास के लिए हाल के वर्षों में विलयन आर अधिग्रहण की नीति अपनाई है। यह नीति भारतीय कंपनियों की पूँजी याजार में पहुँच सुगम बनाने, क्षमता बढाने, नई प्रौद्योगिकी शामिल करने तथा निर्यात बाजार विकासत करने में सददगार साबित होगी (बॉक्स-1) इस सदर्भ में निजी तथा मार्वजनिक उपक्रमों के समेकन का विकल्प आवश्यक तार्किक परिणति के रूप में उभरा है।

बॉक्स-1

विलयन तथा अधिग्रहण के सिद्धांत

विलयन तथा अधिग्रहण के पीछे कई कारण होते हैं। अधिग्रहण करनेवाली कंपनी लाभ कमानेवाले प्रचालन, कर-लाभ, प्रवधन या तकनीकी विशेषज्ञता से मिलनेवाले लाभां, उत्पाद-भिन्नता आदि की दृष्टि से ऐसा करती है। वेचनेवाली कंपनी अतिरिक्त वित्त, मार्केटिंग या तकनीकी वदलावों की संभावना, अधिकतर स्टॉकधारकों द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेचने की इच्छा, आकर्षक क्रय-प्रम्ताव या फिर अपना अस्तित्व बनाए रखने की खातिर ऐसा कर सकती है। एक अन्य महत्त्वपृर्ण कारण व्यापारिक इकाई की सोची-समझी रणनीति हो सकती है, जिसके तहत वह मौजूदा उत्पाद को छोड़कर ऐसे नए उत्पाद से जुड़ना चाहता है, जो बदलते प्रतिस्पर्धात्मक और तुलनात्मक अंतरगण्ट्रीय माहौल में अधिक मुनाफेवाले साबित हो सकते हैं। अलबत्ता, विलयन तथा अधिग्रहण ने व्यापारिक फैसलो और सार्वजनिक नीति-निर्धारण के लिए महत्त्वपूर्ण मृद्दे उठाए हैं। विकास और प्रगति के विभिन्न चरणों से गुजरकर सामने आनेवाले ये कदम व्यापारिक फर्मों के लिए काफी महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।

कार्यकुशलता के तर्कों को संदिग्ध माननेवालों का मत है कि ऐसी कपनियों के प्रदर्शन मे अधिग्रहण के बाद कोई सुधार नहीं आता। इसके अलावा

शेयर धारकों को मिलनेवाला लाभ भी दरअसल उनके बीच की पूँजी का

पुनर्वितरण ही है। एक अन्य मत के अनुसार, विलयन और अधिग्रहण सरीखी गतिविधियाँ सट्टेबाजों की जोड़-तोड़ का प्रतिफल होती हं, जो वास्तव में

'आमोद-प्रमोद में डुवे समाज' के उन्माद को दरशाती है। इस प्रकार की सट्टेबाजी संबंधी गतिविधियाँ ऋण बढाने के साथ-साथ इक्विटी का आधार कमजोर करती हैं, जो अंतत- आर्थिक अस्थिरता को जन्म देती हैं।

को लाभ मिलता है। यदि उत्पाद और बाजार एक-दूमरे के पूरक हो तां विलयन तथा अधिग्रहण से दोनों को लाभ मिलता है। यदि दोनों कपनियाँ एक ही क्षेत्र में सक्रिय होती है तो इस प्रकार की गतिविधियों से प्रतिस्पर्धा

विलयन से अधिग्रहण करनेवाली तथा अधिगृहीत कंपनियों—दोनों

कम करने या समाप्त करने में भी मदद मिलती है। जब घाटवाली कंपनी को मुनाफा कमानेवाली कपनी के द्वारा अधिगृहीत किया जाता है तो इससे कर

और घाटे में कमी लाने में भी मदद मिलती है।

अधिग्रहण दोस्ताना या ईर्ष्यालु माहौल में हो सकते हैं। दोस्ताना अधिग्रहण/विलयन कपनियों के बीच मोल-भाव के बाद तय किए जाते हैं.

परंतु ईर्घ्या या कडवाहट को जन्म देनेवाले ऐसे कदम प्राय- कपनी पर नियत्रण हितों को पुख्ता करने के इरादे से शेयरों के अधिग्रहण के जरिये उठाए जाते हैं। विलयन और अधिग्रहण से ऊर्जा-प्राप्ति की सभावना रहती है। इस प्रकार की ऊर्जा प्राय: कीमत घटाने में मददगार होती है। परिमाण

(स्केल) की अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकीय अर्थव्यवस्थाओं के जरिये औसत कीमत घटाने में सहायक होती है, जो किसी उद्योग में संयंत्र के न्यूनतम आकार को प्रभावित करती है या फिर प्रबंधकीय अर्थव्यवस्थाएँ उत्पादन

तथा वितरण कीमतों को घटाती हैं। संभावना (स्कोप) की अर्थव्यवस्थाएँ प्राय• उत्पादों की संख्या में बढ़ोतरी से प्रेरित होती हैं। उधर वित्तीय ऊर्जा विलय होनेवाली इकाइयो की पूँजी की कीमतों

पर विलयन के प्रभाव का नतीजा होती है। अर्थव्यवस्था मे आनेवाले उतार-चढावों के प्रति थीमी प्रतिक्रिया करनेवाली कंपनियों के अधिग्रहण से अधिग्रहण करनेवाली कंपनी को आय का निरंतर स्रोत प्राप्त होता है। एक अन्य कारण अधिग्रहण करनेत्रात्नी कपनी के प्रबंधन का यह विश्वास भी हो सकता है कि वह लक्षित कंपनी के संसाधनों का वेहतर ढंग से प्रबंध कर सकती है। इसके अलावा, लक्षित कंपनी का कर घाटा भी अधिग्रहण करनेवाली कंपनी के लिए लाभग्रद सिद्ध हो सकता है।

विलयन तथा अधिग्रहण गतिविधियों नई उत्पादन सुविधाएँ और नए ब्रांड वाजार मे उतारने से पूर्व प्रतीक्षा-समय को घटाने, उत्पादन पोर्टफोलियों को मजबृत बनाने, आधारभृत अनुमंधान और विकास-खर्ची को दोगुना होने से रोकने के माथ-साथ गेयरधारक का मृल्याधार विस्तृत करने में भी सहायक होती हैं। इन गतिविधियों को 'बुद्धिमानी भरी कॉरपोरेट नीति' माना जाता है। जहाँ तक मंसाधनों के उपयोग का प्रश्न है, तो कई बार आंतरिक विकास की बजाय विलयन अधिक कुशल कदम हो सकता है।

अलबना, विलयन और अधिग्रहण गतिविधियों के साथ कुछ खतरे भी जुड़े हैं—ममलन, अधिगृहीत कंपनी के बारे में अपर्याप्त जॉच, अधिक बोली लगाना, काफी विस्तृत विविधीकरण, असंबद्ध क्षेत्रों की कंपनियों का अधिग्रहण वगैरह। इनमे प्रायः ऐसी गतिविधियों को प्रभावी तरीके से लागू करने के मार्ग में काफी मुश्किलें खड़ी होती है।

भारत में विलयन और अधिग्रहण गतिविधियों में प्रगति

भारतीय उद्योग के पूनर्गठन की प्रक्रिया उदारीकरण के तुरत बाद शुरू नही

हुई थी। दरअसल, सन् 1996 से उद्योग में आई मंदी ने भारतीय कॉरपोरेट इकाइयो का मुनाफा कम किया और अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए उन्हें पुनर्गठन करने को प्रेरित किया। इसी प्रकार वे अपना आकार घटाने, गौण गतिविधियों को समाप्त

करने तथा विलयन आर अधिग्रहण के जिरये आधार को व्यापक बनाने के लिए प्रेरित हुई। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं की मदद से अतिरिक्त मानव शक्ति को कम करने की कोशिश की गई। साथ ही यह भी महसूस किया गया कि बडे

कम करने की कोशिश की गई। साथ ही यह भी महसूस किया गया कि बड़े आकार की कंपानयाँ ही बहुसध्ट्रीय कंपनियों की चुनौतियों से भलीभॉति निपट

सकेंगी। इस लक्ष्य को पाने का एक रास्ता विलयन तथा अधिग्रहण ही था। भगवती समिति की सिफारिश पर भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ने

सन् 1997 मे अधिग्रहण विनियमनों के मुद्दे को सरल बनाया। भगवती समिति रिपोर्ट ने अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता, सभी निवेशकों को बराबर समझने, समयबद्धता और सही मृचना देने, झुठी पेशकशों को रोकने तथा उल्लंघनों के खिलाफ कार्यवाही करने पर जोर दिया है। अधिग्रहण संबंधी नियमों को निवेशकों के अनुकूल बनाने

के लिए इनमे संशोधन जारी हैं।

भारत में वित्तीय संस्थानों ने भारतीय उद्योगों में विलयन तथा अधिग्रहण गतिविधियों को प्रोत्साहन देने तथा उनके लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए व्यापक नीति बनाने की पेशकश की है। इस दिशा में नीतिगत एकरूपता बनाए

रखकर विलयन तथा अधिग्रहण गतिविधियों को सहज बनाया जा सकता है।

रखकर विलयन तथा आध्यक्षण गातावाचया का सहज बनाया जा सकता है। सन 1999-2000 के केद्रीय बजट में भी विलयन ओर अधिग्रहण गतिविधिया

को सरल बनाने के लिए करों में प्रावधान किए गए हैं। बजट में निहित प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि इस प्रकार होनेवाली बिक्री से मिलनेवाले लाभ को पुँजीगत लाभ माना जाए और उसपर उसी प्रकार कर लगाए जाएँ।

प्रस्तावित परिवर्तनों से पुनर्गठन के दौर से गुजर रहे बड़े व्यापारिक समृहों को लाभ मिलेगा। अनुकूल औद्योगिक नीतियों से भारतीय कॉरपोरेट जगत् की पुनर्गठन की प्रक्रिया को बल मिला है। अलबत्ता 'एग्जिट' नीति को औद्योगिक क्षेत्र

के उदारीकरण के निकष पर परखने की जरूरत है। कॉरपोरेट जगत् पर उचित नियत्रण तथा अनुकूल 'एग्जिट' नीति से पुनर्गठन की प्रक्रिया विकास के अधिक

अनुकृल बन सकेगी।

वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान कुल 151 अरब रुपए मूल्य की विलयन/ अधिग्रहण गतिविधियाँ साकार हुई। इनमे से आधी तो पिछली तिमाही मे ही लागू

हुई थीं। पिछले वर्ष के 37 प्रस्तावों के मुकाबले इस वर्ष भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड के पास 66 पेशकश विचाराधीन हैं। सीमेंट, स्टील, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, वित्त, फार्मास्युटिकल्प, उपभोक्ता वस्तुओं, खाद्य-उत्पादों, कृषि-रसायनो

सॉफ्टवेयर, वित्त, फामस्युटिकल्प, उपभोक्ता वस्तुओं, खाद्य-उत्पादों, कृषि-रसायनो और कपड़ा क्षेत्र में इन गतिविधियों का अधिक जोर रहा है। सन् 1999-2000 की पहली छमाही में 103.68 अरव रुपए के विलयन/अधिग्रहण सौदों को अंतिम

रूप दिया गया। आमतौर पर ग्रुप कंपनियों ने व्यापारिक गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए विलयन किया। इसी प्रकार होल्डिंग कंपनियों ने अपना निवेश सुरक्षित करने के लिए घाटा दिखा रही अपनी सहायक कंपनियों का अधिग्रहण

किया। कुशल प्रबंधन का लाभ उठाने के लिए घाटेवाली कंपनियों का विलय मुनाफा कमानेवाली कपनियों में कर दिया गया। इन कंपनियों के साझा निदेशको

ने विलयन को प्रभावी बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई कंपनियाँ गठित करने की वजाय मौजूदा कंपनियों अथवा मौजूदा क्षमताओं के अधिग्रहण के लिए बहुराष्ट्रीय कपनियों को साथ लिया गया। पिछले ढाई वर्षों के दौरान लगभग 400

कपनियों ने इक्विटा पुनर्गठन की प्रक्रिया में हिस्सेदारी की है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन

सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों के सदर्भ में सरकार की नीति सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण इकाइयों को मजबूत बनाने, गैर-महत्त्वपूर्ण इकाइयों में क्रमबद्ध ढंग से विनिवेश या नीतिगत बिक्री के जिरये उनका निजीकरण करने नथा कमजोर इकाइयों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त उपाय करने की रही है। इन उपक्रमों के प्रदर्शन में लबी अविध के लिए सुधार की दृष्टि से पुनर्गठन की नीति के अंतर्गत शामिल गया है—1 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर.) की प्रक्रिया के तहत पुनर्जीवित करना. 2. वित्तीय पुनर्गठन (आवश्यकतानुसार), 3. सयुक्त उपक्रमों का गठन, 4 मानव शिक्त को तर्कसगत बनाना तथा 5. बोर्ड/प्रबंधन को मजबत बनाकर उचित नियंत्रण।

राहर्मति के करार (एम.ओ.यू.)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता देने के साथ-साथ अपने लक्ष्यों और उपलब्धियों के प्रति उन्हें अधिक जवाबदेह बनाते हुए सन् 1988 से सरकार ने सहमित के करार की अवधारणा को स्वीकार किया है। इस उपाय से मकारात्मक नतीजें सामने आए है। उन उपक्रमों द्वारा हस्ताक्षरित सहमित के करारों का ब्योरा तालिका-6 में दिया गया है।

विनिवेश

सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी की विनिवेश-प्रक्रिया मूलत: उन्हें बाजार-ताकतों के अनुशासन के अनुरूप ढालने तथा उनके प्रबंधन को अधिक पेशेवर और परिणामोन्मुख बनाने के लिए शुरू की गई थी। सरकार को विनिवेश के कार्यक्षेत्र, उपयुक्त नीति, प्रक्रिया, समय आदि के बारे में सलाह देने के लिए अगस्त 1996 में विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने अगस्त 1998 तक 8 रिपोर्ट दाखिल कीं, जिनमें सार्वजिनक क्षेत्र के 43 उपक्रमों के बारे में सिफारिशें की गई थीं। वे सिफारिशें निम्नलिखित हैं—

- 1. सार्वजनिक क्षेत्र के 19 उपक्रमों में नीतिगत बिक्री के जरिये विनिवेश।
- 6 उपक्रमो में व्यापारिक बिक्री।
- जी.डी आर के माध्यम से बिक्री की पेशकश और 5 उपक्रमों के लिए घरेल मार्ग।

तालिका-6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सहमति-पत्रों का वर्षगत विवरण

(नबर)

	D D	2 .	*				
वर्ष	•			अति उत्तम	उत्तम	साधारण	खराब
	द्वारा	मूल्यांकन					
	हम्नाक्षरित क	रार					
1991-92	71	59	21	25	10	3	_
1992-93	98	67	28	22	10	7	Post
1993-94	101	97	46	29	12	10	where
1994-95	106	67	39	26	-	-	2
1995-96	104	103	51	31	7	12	2
1996-97	110	110	46	27	19	11	7
1997-98	108	108	45	25	13	21	4
1998-99	109	-	-	1/48	***		-

- 4 1 उपक्रम में कोई निवेश नहीं।
- 5 8 उपक्रमों मे निवेश टालना तथा
- 6 4 उपक्रमों को बंद करना।

इनमें से कई सिफारिशों पर अमल किया जा चुका है, जबकि शेप मामले सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं।

वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 4 उपक्रमों में इक्टिवी के विनिवेश को मजूरी दी। ये हैं—इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आई ओ.सी), गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी.एस.एन.एल.) और कंटिनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर)। सरकार मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एम.आई.एल एल.), भारत अल्युमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड (बाल्को), इंडियन टृरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आई.टी डी सी) और कुद्रमुख आयरन ऑर कंपनी लिमिटेड (के आई.ओ सी एल) में भी मामरिक गठजोड़/बिक्री के जरिये विनिवेश कर रही है।

सन् 1991-92 से 1998-99 की अर्वाध में सरकारी इक्विटी के विनिवेश के जरिये 18,698 करोड़ रुपए की वसृली की गई है (तालिका-7)। सन् 1999-2000 के केंद्रीय बजट में सार्वजनिक उपक्रमों के 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों का विनिवेश का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें से अप्रैल-सितंबर 1999 के दौरान 460 करोड़ रुपए की वसूली कर ली गई है।

तालिका-7 विनिवेश-प्राप्तियों का वर्षगत विवरण

(करोड़ रु में)

वर्ष	विनिवेश-प्राप्ति				
	बजट आकलन	वास्तविक			
1991-92	2,500	3,038			
1992-93	2,500	1,961			
1993-94	3,500	-48			
1994-95	4,000	5,607 *			
1995-96	7,000	1,397 *			
1996-97	5,001	455 *			
1997-98	4,800	912			
1998-99	9,006	5,376 * (अ)			
1999-2000	10,000	460 * *			

अ अस्थायी।

खायतता

सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यकुशलता बढ़ाने और उन्हें अधिक प्रतिम्पर्धी बनाने के लिए सरकार ने मुनाफा कमानेवाले उपक्रमों को अलग-अलग दर्जे की स्वायत्तता प्रदान की है। इस स्वायत्तता के आधार पर इन उपक्रमों को नवरत्नों तथा लघ्-नवरत्नो का दर्जा प्रदान किया गया है।

नवरत्न

सरकार ने सन् 1998-99 (बॉक्स-2) तक नवरत्न श्रेणी के लिए 11 उपक्रमों को चुना है। इन उपक्रमों को कुछ दिशा-निर्देशों के तहत पूँजी व्यय करने,

^{*} मन् 1994-95, 1995-96, 1996-97 तथा 1998-99 के बोनस शेयर क्रमश 530 करोड़ रू. 1,035 करोड़ रू., 75 करोड़ रुपए और 6 करोड़ रुपए शामिल है।

^{**} सितंबर '99 तक।

सयुक्त उपक्रम लगाने और विदेशों में प्रौद्योगिकी तथा सामरिक गठबंधन के उद्देश्य से सहायक कार्यालय स्थापित करने संबंधी फेसले लेने की पृरी आजादी है।

बॉक्स-2

नवरलों की सूची

- 1 इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आई ओ भी)
- 2 इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटंड (आई पी सी एत)
- 3 ऑयल एंड नैनुरल गैस कॉरपोरेशन (ओ एन जी सी.)
- 4 भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी.र्पा सी एल)
- 5. हिद्स्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी,एल)
- 6 नेशनल थर्मल पाँवर काॅरपोरेशन (एन टी.पी सी)
- 7 स्टील ॲथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)
- 8 विदेश सचार निगम लिमिटेड (वी एम.एन एल)
- 9 भारत हेवी इलेक्टिकल लिमिटेड (बी एच ई.एल)
- 10 गेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जी ए आई एल)
- 11 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी.एन.एल)

लघु रटन

सरकार ने अन्य कई लाभ अर्जित करनेवाले उद्यमों को भी वित्तीय, प्रबंधन तथा परिचालन के मामले में अधिक स्वायत्तता प्रदान की है। इन्हें लघु-रत्नों का दर्जा दिया गया है। ऐसे उपक्रमों के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान लगातार लाभ कमाने के अलावा सकारात्मक साख रखना, सरकार से आर्थिक सहयोग या गारटी की अपेक्षा नहीं रखना, सरकार को देय ऋगो/ब्याज आदि की गेर-अदायगी न करना आदि शर्तों का पालन करना आवश्यक है। ये उपक्रम निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पूँजीगत खर्चे करने, सयुक्त उपक्रम लगाने, प्रौद्योगिकीय और सामरिक गठबंधन करने, मानव-संसाधन प्रबंधन संबंधी योजनाएँ तैयार करने के लिए स्वतत्र हैं।

राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष

सरकार ने औद्योगिक पुनर्गटन, प्रौद्योगिकी के उन्नतीकरण तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को मानवीय स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मियों के सुरक्षा कवच के तौर पर सन् 1992 में 'राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष' का गठन किया था इस कोष की मदद स अब तक कंद्र क सार्वजिनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) लागू की गई है। इस योजना का दायरा बढ़ाकर कर्मचारियों को सलाह देने, प्रशिक्षित करने, दोबारा नौकरी पर रखवाने आदि कार्य भी इसमें शामिल किए गए है। इस सिलिसिले में 16 राज्यों में विभिन्न स्थानों पर कर्मचारी सहायता-केंद्र खोले गए हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए 31 अक्तुबर, 1998 तक कुल 2,029.84 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सार्वजिनक उपक्रमों के 1,25,184 कर्मचारियों के लिए जारी की गई।

तालिका-8 राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष का वर्षवार वितरण

(करोड रु)

वर्ष	एन.आर.एफ. को आवंटित राशि	सार्वजनिक खाते में स्थानांतरित राशि
1991-92	200 00	-
1992-93	829 66	829.66
1993-94	1,020 00	700.00
1994-95	500.00	100 00
1995-96	***	140 00
1996-97	250 00	150 00
1997-98	306 91	306.91
1998-99	300 00	278 00

राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

राज्यों के सार्वजिनक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों, जैसे—सड़क यातायात और बिजली बोर्डों को छोड़कर कई में पुनर्गठन की प्रक्रिया लगभग नदारद है। इनमें से अधिकतर उपक्रम बीमार घोषित हो चुके हैं या होने के कगार पर हैं। इनकी अकुशलता के कारण राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर बोझ बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में इन उपक्रमों के पुनर्गठन की सख्त जरूरत है। कुछ राज्यों ने पहले ही इस दिशा में उपाय शुरू कर दिए हैं। उड़ीसा ऐसा पहला राज्य था, जिसने 1 अप्रैल, 1996 को उड़ीसा बिजली सुधार अधिनियम, 1995 लागू कर बिजली क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया शुरू की। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तिमलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात ने भी इस क्षेत्र में सुधार शुरू किए हैं। इसी प्रकार

अलबत्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रिंटिंग आदि गैर-प्रदूषक इकाइयाँ ऐसे शहरों के 25 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थापित की जा सकती थीं। अन्य उद्योगों को 25 जुलाई, 1991 से पहले निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों में ही लगाया जा

सकता है।

बॉक्स-4

सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची

- हथियार तथा गोला-बारूद और रक्षा-उपकरणों से संबंधित सामान, रक्षा एयरक्राफ्ट और युद्धपोत।
- 2 आणविक ऊर्जा।
- 3 भारत सरकार के आणिवक ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या एस.ओ 212 (ई) दिनांक 15 मार्च, 1995 में उल्लिखित पदार्थ।
- 4 रेलवे यातायात।

पूर्वोत्तर के लिए विशेष नीतिगत पैकेज

सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए सन् 1997-98 के दौरान नई औद्योगिक नीति तैयार की है, ताकि इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में जारी विकास की कम रफ्तार से प्रभावी नरीके से निपटा जा सके। इस क्षेत्र के औद्योगीकरण के लिए इस नीति पर सक्रिय रूप से अमल किया जा रहा है।

प्रत्यक्ष विवेशी निवेश नीति सरकार बेहतर प्रौद्योगिक, आधुनिकीकरण, निर्यात और अंतरराष्ट्रीय स्तर

के उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई.) का प्रवाह बढाने के लिए कृतसंकल्प है। इसलिए सरकार की नीति विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने की रही है। इस दिशा में सरकार का प्रयास नीतियों एवं प्रक्रियाओ

प्रोत्साहन देने की रही है। इस दिशा में सरकार का प्रयास नीतियों एवं प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने तथा अधिक गतिशील और निवेशकोन्मुख नीतिगत तंत्र तैयार करना है। इसके साथ ही घरेलू उद्योग को प्रतियोगिता के समान अवसर

उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए लाभांश-संतुलन, विदेशी विनिमय निष्पक्षता, विदेशी इक्विटी पूँजी इत्यादि की शक्ल में समानांतर उपाय भी किए गए हैं। एफ.डी.आई. नीति की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

> 1. एफ.डी.आई. मंजूरी के दो तरीके तय किए गए हैं—(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः मंजूरी तथा (ख) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.बी.पी.)/सरकार द्वारा मंजूरी।

> > 🕊 भगतीय अर्थनीति 🛎

- 2 राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर चिह्नित 34 श्रेणियो/उच्च प्राथमिकतावाले उद्योग समूहों के लिए 50/51/74/100 प्रतिशत
- एफ.डी.आई. को स्वतः मजुरी।
- 3 विद्युत् उत्पादन, प्रेषण और वितरण तथा राजमार्गी, मुरगी (वाहनी क

लिए), पुलो, बंदरगाहो, सड्को के निर्माण और रखरखाव सवधी परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्गों के तहत शत प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी को मजुरी।

- 4 विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के लिए छह सप्ताह की समय-मीमा के भीतर एफ.डी आई संबंधी आवेटनो का निपटारा करना आवश्यक।
- 5 कपि. सपत्ति तथा बीमा क्षेत्र में एफ डी आई को मजुरी नहीं।
- 6 कुछ क्षेत्रों में मूल निवेश और प्राप्तियों (लाभांग सतुलन ओर विदेशी विनिमय निष्पक्षता के अलावा) पूरी वापमी।
- 7 विदेशी प्रौद्योगिकी तक आसान पहेंच। 20 करोड अमेगिकी डॉलर तक के भुगतान और घरेलू विक्री पर 5 प्रतिशन तथा निर्यात पर 8 प्रतिशत को दर से रॉयल्टी के लिए स्वतः मज़री।
- 8 घरेल ऋण तक आसान पहुँच। भारत में निवेश करनेवाली विदेशी कपनियाँ भी घरेल वित्तीय सम्थानों से घरेल ऋण लेकर अपनी क्षमता बढ़ा सकती हैं।
- 9 बाहरी व्यावसायिक ऋण तथा ऋण-भूगतान की उदार शर्ने। 10 ग्लोबल डिपॉजेटरी रिसीट (जी.डी आर), अमेरिकन डिपॉजेटर्ग रिसीट
- (ए डी आर) तथा 'फॉरेन करसी कवर्टिबल बॉइस' (एफ सी मी बी) में वृद्धि की कोई ऊपरी मीमा नहीं।

ात तंत्र

सरकार ने ढाँचागत तंत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार मका की परिभाषा परिसर्पात्तयों के स्वामी से बदलकर रोवा-प्रदाता की

गई हे, ताकि निजी क्षेत्र की भागी से ढॉचागत सेवाओं का विकास स्निरिचत ना सके। सरकार ने कुशल ढाँचागत तंत्र के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई उठाए हैं। सभी प्रमुख ढाँचागत क्षेत्रों को निजी क्षेत्र की परियोजनाओं क

<u>र</u>ुले ही <mark>खोल दिया गया है तथा विद्युत् उत्पादन, दुरमचार सेवाओ, बंदरगाहो,</mark> और हवाई अइडों के क्षेत्र में कई निजी क्षेत्र की परियोजनाएँ लागू की हैं। दूरमंचार नीति में हाल में किए गए बदलावों की जानकारी वॉक्स-5

बॉक्स-5

नई दूरसचार नीति की घोषणा मार्च 1999 में की गई। इसके तहत बुनियादी तथा मृल्यवर्धित सेवाओं के मौजूदा लाइसेंस को 1 अगस्त, 1999 से राजस्व बॅटवारा व्यवस्था के अतर्गत मजूरी दी गई है। नई व्यवस्था को चुनने की स्थिति में, अंतरिम उपाय के तौर पर बुनियादी तथा मेल्युलर टेलीकॉम ऑपरेटरों को उस स्थिति में लाइसेस फीस के रूप में अपने कुल राजस्व के 15 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ेगा, जब भारतीय दूरमंचार विनियमन प्राधिकरण (ट्राई) राजस्व बॅटवारे का प्रतिशत निर्धारण नहीं कर पाता।

नई नीति में मौजूदा शेयरधारको को लाइसेस समझौते की तारीख से अगले 5 साल तक अपने शेयर बेचने की छूट नहीं होगी। इस अवधि मे शेयरों के हस्तातरण की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। नीति में इक्विटी विस्तार के जिरये नए निवेशकों को शामिल करने का प्रावधान है, परतु वर्तमान निवेशक इस व्यवस्था को छोड़कर नहीं जा सकेगे।

सेल्युलर सेवाओं के सदर्भ में यह व्यवस्था की गई है कि दोनों ऑपरेटरों को या तो राजस्व बॅटवारा व्यवस्था को चुनना होगा अथवा पुरानी लाइसेंस फीस व्यवस्था का पालन करना होगा। नई व्यवस्था के अनुसार राजस्व बॅटवारा व्यवस्था को चुननेवाले ऑपरेटरों को मौजूदा द्वि-अधिकार प्रणाली को बजाय बहु-अधिकार प्रणाली को स्वीकार करना पड़ेगा। नई नीति के तहत यह व्यवस्था की गई है कि सरकार (बतौर लाइसेस प्रदानकर्ना) और लाइसेस प्राप्तकर्ताओं के बीच विवाद को सुलझाने में ट्राई की अहम भूमिका होगी। नए लाइसेंस देने के समय और सख्याओं के बारे में सरकार ट्राई से मशिवरा करेगी। अलबत्ता, कार्यप्रणाली के संदर्भ में ट्राई से सलाह लेना सरकार के लिए आवश्यक होगा।

दूरसचार विभाग की नीतियों तथा लाइसेंसिंग कार्यतत्र को अलग करने के बाद तैयार अलग दूरसचार सेवा विभाग को 2001 तक कॉरपोरेट स्वरूप दें दिया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने ढाँचागत क्षेत्र के लिए ऋण-वितरण में तेजी लाग ेतु अप्रैल 1999 में नए दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों के तहर हाँचागत परियोजनाओं आदि के लिए वित्त जुटाने आदि मुद्दे भी शामिल किंग गए भारतीय रिजर्व बैंक की अक्तूबर 1999 म जारी मौद्रिक तथा ऋण नीति घोषणा मे बैंकों द्वारा किसी एक परियोजना (विद्युत् परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड रुपए तथा अन्य परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए) के लिए स्वीकत

ऋण की ऊपरी सीमा संबंधी शर्त भी समाप्त कर दी गई है। बैक अब अपने विवेकाधिकार के अनुसार तय ऊपरी सीमा का पालन करते हुए ढाँचागत परियोजनाओं के लिए अवधि ऋणों को मंजूरी दे सकते हैं। बैंक अब ग्रुप एक्सपोजर नार्भ के अतर्गत 50 प्रतिशत सीमा में 10 प्रतिशत तक बढोतरी कर सकते हैं, बशर्ते अतिरिक्त व्यवस्था ढाँचागत परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए की जाए।

आवास

आवास-विकास को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इसके अतर्गत शहरी भूमि (ऊपरी सीमा और विनियमन) अधिनियम को निरस्त करना भी शामिल है। इस क्षेत्र के लिए ऋण-राशि के प्रवाह में सुधार के

लिए सन् 1999-2000 के केंद्रीय बजट में निम्न उपायों की घोषणा की गई-

विकास के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक अधिनियम में सुधार।
2 आवास के क्षेत्र में सिक्रिय वित्तीय कपनियों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य

1. आवासों को गिरवी रखने की दृष्टि से प्राथमिक तथा गौण बाजारी के

- अवास के क्षेत्र में सिक्रय वित्तीय कैपनियां की सुदृढ़ बनान के उद्देश्य से गैर-उत्पादक परिसंपितियों में प्राप्त आय पर कर संबंधी दृष्टिकोण में बदलाव।
- 3 आवास क्षेत्र के लिए बैंक ऋणों की उपलब्धता में सुधार के उद्देश्य से व्यावसायिक बैंकों को अपनी जमाराशि में से 3 प्रतिशत तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
- 4 नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास विन योजना के अंतर्गत आवासीय इकाइयो की मंख्या सन् 1999-2000 के दौरान बढ़ाकर 1.25 लाख कर दी गई।

लघु क्षेत्र के उद्योग

लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए ऋण-उपलब्धता में सुधार की दृष्टि से सन् 1999-2000 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित उपाय किए गए—

- संयोजित ऋणों की राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई (छोटे ऋणधारकों को व्यावमायिक बैंकों तथा एस आई डी बी.आई द्वारा उपलब्ध कराए जानेवाले ऋण।)
- 2. कामचलाऊ पूँजी सीमा की गणना के लिए वार्षिक टर्न ओवर सीमा को

- 5 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव।
- 3 अत्यंत लघु क्षेत्रों तक बैंकों की पहुँच बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र को भी बैंक-ऋणों की दृष्टि से प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा के दायरे मे लाना।
- 4 ऋणों की वसूली तथा सुरक्षा की दृष्टि से नई ऋण बीमा योजना शुरू की जाएगी।

अत्यंत लघु क्षेत्र

अत्यंत लघु क्षेत्रों की परिभाषा को विस्तार देते हुए इसके लिए संयंत्रों तथा मशीनरी पर निवेश राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई, तािक इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी को उन्तत करने में मदद मिल सके। बैंक-ऋणों के मामले में लघु क्षेत्रों के अतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र के लिए निर्धारित ऋणों का 60 प्रतिशत अत्यंत लघु क्षेत्र के लिए तय किया गया है। इसके अलावा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उत्पाद शुल्क में छूट की सीमा भी 1 जून, 1998 से 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। एकीकृत ढाँचागत विकास योजना के अंतर्गत कम-से-कम 40 प्रतिशत भूखंड अत्यत लघु इकाइयों को आवंटित करने का फैसला किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को अत्यत लघु क्षेत्र की इकाइयों के लिए मशीनरी की खरीद-फरोख्त, मार्केटिंग सहयोग, प्रशिक्षण सुविधाओ आदि के लिए 40 प्रतिशत सहायता राशि उपलब्ध कराने को कहा गया है।

औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन (1998-99 के दौरान) कुल

अनुसार भारतीय उद्योग ने सन् 1998-99 में काफी कम, अर्थात् 4 प्रतिशत की विकास-दर दर्ज कराई, जबिक पिछले वर्ष यह दर 6 6 प्रतिशत रही थी। विचाराधीन वर्ष के दौरान निर्माण क्षेत्र की विकास-दर 4 4 प्रतिशत रही, जबिक उससे पिछले वर्ष यह दर 6 7 प्रतिशत रही थी। खनन तथा खुदाई क्षेत्र में भी सन् 1997-98 मे

औद्योगिक उत्पाद की सुचकांक संख्या (आधार : 1993-94=100) के

5 9 प्रतिशत की सकारात्मक विकास-दर के मुकाबले 1.8 प्रतिशत तक कमी आई। सन् 1997-98 में 6.6 प्रतिशत की तुलना में सन् 1998-99 में विद्युत्-

उत्पादन में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (परिशिष्ट तालिका-1)। संपूर्ण औद्योगिक उत्पादन में धीमी गति का कारण माँग मे कमी, संरचनात्मक क्षेत्र मे अपर्याप्त निवेश, पूजी बाजार की कमजार स्थिति और कुछ हद तक कारपोरेट पनर्सरचना की प्रक्रिया रही है।

सन् 1998-99 के दौरान निर्माण क्षेत्र में सत्रह समृहों में में 51 41 प्रतिशत

निर्माण क्षेत्र

के सयुक्त वजनवाली दस श्रेणियों की विकास-दर कम हुई या नकारात्मक रही। 32 61 प्रतिशत सयुक्त वजन के पाँच समूहों की विकास-दर में कमी दर्ज की गई। इनमे प्रमुख क्षेत्र रहे—वेवरेज (पेय), तंबाकृ तथा तंबाकृ उत्पाद। उधर 18 8 प्रतिशत के संयुक्त वजनवाले पाँच समृहो—आधारभूत धातु तथा मिश्रित धातु उद्योग, टेक्सटाइल उत्पाद, लकड़ी और लकडी-उत्पाद, फर्नीचर, जृट तथा उन्य रेशायुक्त टेक्सटाइल (कपास को छोडकर) और सुनी टेक्सटाइल के क्षेत्रों में भी

रशायुक्त टक्सटाइल (कपास का छाडकर) आर सृगा टक्सटाइल क बता में मा नकारात्मक विकास-दर दर्ज की गई। अलबता, इमी अवधि में 7 ममृहों ने बेहतर विकास-दर का प्रदर्शन किया। ये हैं—धातु उत्पाद तथा हिस्में (मशीनरी और उपकरण को छोडकर), कागज और कागज उत्पाद तथा मुद्रण, प्रकाश एवं सबद्ध उद्योग, परिवहन उपकरण और हिस्से, रबर, प्लाम्टिक, पेट्रोलियम एवं कोयला उत्पाद, चमड़ा एवं चमड़ा तथा फर उत्पाद, अन्य निर्माण उद्योग तथा खाद्य उत्पाद (परिशिष्ट तालिका-2)।

प्रयोग-आधारित वर्गीकरण

सन् 1998-99 के दौरान पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में पिछली वर्ष की 5 3 प्रतिशत की विकास-दर के मुकाबले 12.7 प्रतिशत की दर दर्ज की गई। अन्य मभी समूहों ने कम विकास-दर का प्रदर्शन किया। इस वर्ष बुनियादी, मध्यवर्ती तथा उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्रों की भी विकास-दर कम रही।

हाल का प्रदर्शन (अप्रैल-सितंबर 1999-2000)

कुल

वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन में निश्चित रूप से बदलाव देखा गया। उपलब्ध संकेतों के आधार पर कहा जा सकता है कि बिक्री और मुनाफे की दृष्टि से कुछ कॉरपोरेट घरानी का प्रदर्शन पहली छमाही में शानदार रहा, जिससे लंबे समय से छाई मंदी का माहौल कुछ हद तक छँटा। निर्माण क्षेत्र ने 6 8 प्रतिशत की शानदार विकास-दर दर्ज की, जो इससे पिछले वर्ष इसी अविध में दर्ज 4 1 प्रतिशत के आँकडे के मुकाबले बेहतर रही। खनन और खुदाई क्षेत्र में अप्रैल-सितंबर 1998-99 के दौरान 0 4 प्रतिशत की नकारात्मक विकास-दर की

तलना में 0 4 प्रतिशत की मामली बढोतरी दर्ज की गई। विद्यत-उत्पादन के क्षेत्र मे विकास-दर 7,7 प्रतिशत रहीं, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में दर्ज 7.4 प्रतिशत से

बेहतर रही (परिशिष्ट तालिका-1)।

क्योग-आधारित वर्गीकरण

2 अकीय 17 औद्योगिक समृहों मे मे 11 ने अप्रेल-सितवर, 1999-2000 की अवधि में सकारात्मक विकास-दर दर्ज की। गैर-धात खनिज उत्पादों का

विकास मर्वाधिक रहा और उनके बाद मशीनरी उपकरणो (परिवहन उपकरणो तथा कागज और कागज उद्योगों एवं मुद्रण, प्रकाशन और मवंधित उद्योगों को छोडकर)

का स्थान रहा। इधर लकडी और लकडी उत्पादो, फर्नीचर आदि में सबसे अधिक गिरावट देखी गई। 17 औद्योगिक समहों में से 8 समहों ने विकास में तेजी दज कगई, जबकि 3 समहों में गिरावट देखी गई और शेष 6 समहों ने नकारात्मक

विकास किया (परिशिष्ट तालिका-2)।

प्रयोग-आधारित वर्गीकरण

पँजीगत बस्तओं ने अप्रैल-सितंबर 1999-2000 के दौरान 9 2 प्रतिशत की धीमी रफ्तार से विकास दर्ज किया, जबकि अप्रेल-सितंबर 1998-99 के दोगन यह

दर 11.1 प्रतिशत रही थी। मध्यवर्ती वस्तओं के क्षेत्र में अप्रैल-स्तिबर 1999-

2000 में विकास-दर अधिक, अर्थात 9 1 प्रतिशत रही, जबिक पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 5 6 प्रतिशत रही थी। उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र ने 4 प्रतिशत का

विकाम दग्शाया, जर्याक पिछले वर्ष की इमी अवधि के दौरान यह मात्र 18 प्रतिगत रहा। अलबत्ता, बुनियादी वस्तुओं ने अप्रैल-मितवर 1999-2000 मे 5 1

प्रतिशत विकास का ऑकडा दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष यह ऑकडा 25 प्रतिशत ही रहा था (परिशिष्ट तालिका-3)!

यापेश योगटान

तीन क्षेत्रों में से निर्माण क्षेत्र को योगदान अप्रैल-सितंबर 1998-99 मे

82 9 प्रतिरात रहने के बाद चालू वर्ष मे 87 2 प्रतिरात हा गया। विद्युत् क्षेत्र का

योगदान अप्रैल-सितंबर 1999-2000 में घटकर 12 2 प्रतिशत हो गया, जबिक पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 18.1 प्रतिशत रहा था। अलबत्ता, खनन क्षेत्र का

योगदान अप्रैल-सितंबर 1998-99 में 0.9 प्रतिशत के नकारात्मक योगदान के मुकाबले मामूली रूप से बढ़कर अप्रैल-सितंबर 1999-2000 मे 0 6 प्रतिशत दर्ज किया गया।

उपलब्ध संकेतक से लगता है कि औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन में हो रहा

सुधार जारी रहेगा। गैर-खाद्य ऋणों के क्षेत्र में मौजूदा वित्त वर्ष में 22 अक्तूबर, 1999 तक 18,211 करोड रुपए का निश्चित उटान देखा गया है, जबकि पिछले

वर्ष यह 9,498 करोड़ रुपए रहा था। व्यावसायिक क्षेत्र में ऋणों का कुल प्रवाह बढ़कर 25.699 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अविध में इसमे

18,227 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। चालू वर्प में अब तक कॉरपोरेट क्षेत्र की कामचलाऊ पूँर्जा आवश्यकताएँ भी बढ़ी हैं। ब्लू चिप कपनियो (अर्थात्

जिनकी कामचलाऊ पूँजी सीमा 10 करोड़ रुपए हैं) के लिए 31 अक्तूबर, 1999 तक 32.045 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कामचलाऊ पूँजी को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह राजि 25,251 करोड़ रुपए रही थी।

ढॉचागत उद्योगों का प्रदर्शन

छह ढाँचागत उद्योगों—विद्युत्, कोयला, विक्री योग्य स्टील, सीमेंट, पेट्रोलियम कच्चा तथा पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद (आई आई पी. मे वजन · 26.7 प्रतिशत) के संयुक्त सूचकांक (आधार . 1993-94=100) ने सन् 1998-99 के दौरान 2 7 प्रतिशत की धीमी रफ्तार से विकास दर्ज किया, जो सन् 1997-98 के 5 7 प्रतिशत के ऑकड़े से कम रहा। उद्योगों मे पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों मे सन् 1998-99 के दौरान तेजी आई (प्रिशिष्ट तालिका-4)।

विकास 6 7 प्रतिशत रहा, जबकि इसमे पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह

अप्रैल-सितंबर 1999-2000 की अवधि में छह ढाँचागत उद्योगों का कूल

ऑकड़ा 3 4 प्रतिशत रहा था। इस अवधि में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों की विकास-दर सर्वाधिक 19 1 प्रतिशत रही, जबिक पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह दर 1 7 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई थी। सीमेंट उत्पादन की विकास-दर 18 8 प्रतिशत रही, जबिक पिछले वर्ष इमी अवधि में यह 4.2 प्रतिशत रहीं थी। बिक्री योग्य स्टील के उत्पादन की विकास-दर अप्रैल-सितंबर 1999-2000 के दोरान 4 3 प्रतिशत थी, जबिक अप्रैल-सितंबर 1998-99 में यह 2.6 प्रतिशत रहीं थी। विद्युत् क्षेत्र की विकास-दर में मामृली गिरावट के बाद यह 7.4 प्रतिशत रहीं, जबिक पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 7.7 प्रतिशत थी। कोयला क्षेत्र ने 1 1 प्रतिशत का नकारात्मक विकास दर्ज किया, जबिक पिछले वर्ष की इसी अवधि में

चुनिंदा उद्योगों का प्रदर्शन

उभरते हुए च्निंदा उद्योगों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा-

इस क्षेत्र ने 1.3 प्रतिशत का सकारात्मक विकास किया था।

सूचना प्राधागका

(नासकॉम) के अनुसार, इसका वार्षिक राजस्व सन् 1997-98 में 10,040 करोड़ रुपए की तुलना में 15,890 करोड़ रुपए बढ़ गया। अकेले सॉफ्टवेयर निर्यात से ही 10,940 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जबकि घरेलु सॉफ्टवेयर बाजार ने 4,950

महत्त्वपूर्ण विकास दर्ज किया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज

सन् 1998-99 के दौरान भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग ने 58 3 प्रतिशत का

करोड़ रुपए कमाए। समझा जाता है कि वाई-2के समस्या. ई-कॉमर्स आदि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित मेवाएँ, यूरो मुद्रा परिवर्तन तथा उद्यम संसाधन नियोजन (ई आर.पी) आदि के कारण सॉफ्टवेयर उद्योग में तेजी आई। दरअसल, वाई-2के

समस्या के निराकरण के बाद भी भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग आगे बढ़ता रहेगा। मरकारी कार्यालयों मे कंप्यूटरीकरण की नेज रफ्तार तथा वाई-2के समस्या के निराकरण के लिए खर्चों के कारण सन् 1998-99 में घरेलू सॉफ्टवेयर वाजार ने

लगभग 42 प्रतिशत की विकास-दर दर्ज कराई। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के महत्त्व को पहचानते हुए सरकार ने स्वतंत्र 'सूचना प्रौद्योगिकी विभाग' का गठन किया है। 14 प्रादेशिक सरकारों ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति घोषित करने के

साथ उच्च स्तरीय कार्य-बल का गठन किया है।

द्ररसंचार

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास तथा उसे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकात्म करने में कुशल एवं उन्नत दूरसंचार ढाँचागत तंत्र के महत्त्व को समझने के बाद इस क्षेत्र पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। दूरसंचार-तंत्र को विस्तृत तथा उन्नत बनाने के लिए दूरसंचार विभाग और उसके अंतर्गत कार्यरत सगठनो द्वारा सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास जारी हैं। सन् 1999-2000 के केंद्रीय बजट में दूरसंचार पर 16,801 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, जो सन् 1998-99 के सशोधित अनुमान से 24 5 प्रतिशत अधिक है।

सन् 1988-89 से 1997-98 के दौरान 10 वर्षों की अवधि में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 9,681 से बढ़कर 23,406 हो गई और नवंबर 1998 तक यह 23,624 तक पहुँच गई। उक्त दशक में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या भी 41 74 लाख से बढ़कर 178 02 लाख हो गई और इस प्रकार भारत का टेलीफोन तत्र आकार की दृष्टि से दुनिया भर में बारहवें स्थान पर पहुँच गया, जबिक उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के वर्ग में उसका तीसरा स्थान रहा। इसी अविध मे

टेलीफोन मुविधायुक्त गाँवों की संख्या भी 27,316 से कई गुना बढ़कर 3,10.687

तक पहुँच गई। सन् 1998-99 के दौरान 37 92 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, जबकि सन् 1997-98 में यह संख्या 32 59 लाख दर्ज की

गई। इसी प्रकार गाँवों में उपलब्ध कराए गए कनेक्शनों की सख्या में भी पिछले वर्ष की तलना में 10 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 31 दिसवर, 1998 को

देलीफोन घनत्व प्रति 100 व्यक्तियो पर 2 सीधी एक्सचेंज लाइन (डी.ई एल) रहा तथा सभी जिला मुख्यालयो को एस टी डी से जोड दिया गया। उधर सेल्युलर

फोन सेवा के मोरचे पर मार्च 1999 के अत तक ही सेल्युलर तत्र का आधार 76,000 उपभोक्ताओं का हो गया था। उच्च रफ्तार फैक्स तथा फोटो-फोन सुविधा युक्त इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क (आई एस.डी एन.) सेवाएँ सन् 1997-

98 के दोरान 6 और शहरों में भी उपलब्ध करा दी गई ओर इस प्रकार इनका दायरा कुल 17 कस्बो/शहरों तथा 1,211 उपभोक्ताओं तक विस्तृत हुआ।

अग्रेटोमोबाइल्टा औद्योगिक विकास की तंज रफ्तार के लिए स्नियोजिन परिवहन-तत्र

आवश्यक पूर्व शर्त है। इस दृष्टि से भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने यात्री कारो, हलके, मध्यम तथा भारी व्यावसायिक वाहनो और बहु उपयोगी वाहनों को उपलब्ध कराकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में योगदान सन् 1992-93 में 2 8 प्रतिशत से बढ़कर सन् 1997-98 में 4 4 प्रतिशत हो गया। इस क्षेत्र ने सन् 1997-98 में 4 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष ऋप से तथा लगभग 1 करोड़ की आबादी को परोक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध कराया।

सन् 1998-99 के दौरान व्यावसायिक वाहनों, कारों तथा उपयोगी वाहतों और तिपहिया वाहनों के उत्पादन में काफी गिरावट आई। इनकी विकास-दर क्रमशः (-) 15 5 प्रतिशत, (-) 5.9 प्रतिशत एवं (-) 11 प्रतिशत दर्ज की गई।

दुपहिया वाहनों के उत्पादन में पिछले वर्ष की 3.1 प्रतिशत के मुकावले 98 प्रतिशत की विकास-दर दर्ज की गई। उधर बिक्री के मोरचे पर भी व्यावसायिक वाहनों, कारो तथा उपयोगी वाहनों और तिपहिया वाहनों की विकास दर नकारात्मक रही जबकि दोपहिया वाहनों ने अपनी बिक्री की सामग्र बदाई। विश्वांत के प्रोपने

पहिना, कारा तथा उपयोग विहना आर तिपहिया विहना का विकास दर नकारात्मक रहीं, जबिक दोपिहिया वाहनों ने अपनी बिकी की रफ्तार बढ़ाई। निर्यात के मोरचे पर तिपिहिया वाहनों के अलावा सभी श्रेणियो, जैसे—क्यावसायिक कारों, उपयोगी वाहनों और दोपिहिया वाहनों में सन् 1998-99 के दौरान नकारात्मक विकास-दर दर्ज की गई।

सन् 1999-2000 के पहले पाँच महीनों के दौरान जहाँ एक ओर व्यावसायिक वाहनों, कारों तथा उपयोगी वाहनों के उत्पादन और बिक्री की विकास-दर में तेजी देखी गइ वहा दापहिया तथा तिपहिया वाहनो ने इन मोरचो पर त विकास दर दर्ज की। उधर निर्यात के क्षत्र में कारो तथा उपयोगां वाहनों ने नकारात्मक विकास-दर का प्रदर्शन किया।

खाद्य प्रसंरकरण

सभावनाएँ है। मजबूत तथा प्रभावी खाद्य-प्रसम्करण उद्योग कृषि के विविधीकरण आर व्यावसायीकरण मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ कृषि उत्पाद के मूल्यवर्धन मे हाथ वँटाने, रोजगार जुटाने, किसानो के लिए आय बढाने और कृषि-खाद्य पदार्थों के लिए अतिरिक्त निर्यात जुटाने में प्रभावी हो सकता है। प्रमुख खाद्य प्रसस्करण इकाइयाँ है—

देश में खाद्य प्रमस्करण उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें विकास की पर्याप्त

क. अन प्रसंस्करण,

ख उपभोक्ता खाद्य उद्योग (बेकरी उत्पाद, कोको उत्पाद, सॉफ्ट ड्रिक, ब्रांडेड जस तथा वीयर और अल्कोहल आधारित पेय),

ग फल और सब्जी प्रसस्करण.

घ. दूध तथा दुग्ध उत्पादन,

ड मांस और पोल्ट्री प्रसस्करण,

च. मत्स्य प्रसंस्करण।

आँद्योगिक तथा आर्थिक नीतियों के उदारीकरण ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में काफी मदद की, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा। अगस्त 1991 से दिसबर 1998 तक कुल 53,490 करोड रुपए मूल्य 4,676 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) प्राप्त किए गए।

उपभोक्ता खाद्य उद्योग में बेकरी उद्योग का आकार सबसे बड़ा है। बेकरी

उत्पादों का वार्षिक उत्पादन अनुमानतः 30 लाख टन अतिरिक्त होता है। कोको उत्पादों, जैसे—चॉकलेट, कोको मक्खन, माल्टयुक्त दूध आदि का उत्पादन लगभग 34 हजार टन है जबकि सॉफ्ट ड्रिंक का उत्पादन सन् 1997-98 में 4,920 लाख बोतलों से बढ़कर सन् 1998-99 में 5,670 लाख बोतलो तक पहुँच गया। फलो एव सब्जियो से जुड़े प्रसंस्करण उद्योगों की संस्थापन-क्षमता सन् 1997 में 20 4 लाख टन से बढकर सन् 1998 में 20 8 लाख टन हो गई। प्रसंस्करित फलों एवं

लाख टन से बढ़कर सन् 1998 में 20 8 लाख टन हो गई। प्रसंस्करित फलों एवं सिंड्जियों का उत्पादन सन् 1997 में 9.1 लाख टन के मुकाबले सन् 1998 में 9 4

लाख टन हो गया, दुग्ध उत्पादो (आइसक्रीम, मक्खन और घी के अलावा) का कुल उत्पादन सन् 1997 में 284.8 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर सन् 1998 में लगभग 301 हजार मीट्रिक टन रहा। उधर प्रसंस्करित मछलियों का उत्पादन 1996-97 में 54 3 लाख टन के मुकाबले बढ़कर 1997-98 में 53 8 टन रहा। प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों के निर्यात के क्षेत्र में भी प्रदर्शन शानवार रहा। मत्स्य उत्पादों समेत प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों का कुल निर्यात सन् 1996-97 में 10,407 करोड़ रुपए के मुकाबले सन 1997-98 में बढ़कर 11,014 करोड़ रुपए का हो गया।

अन्य महत्त्वपूर्ण उद्योग

कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों का प्रदर्शन सन् 1998-99 के दौरान काफी फीका रहा। रबर उद्योग ने 1 5 प्रतिशत की धीमी रफ्तार दर्ज कराई। प्राकृतिक रबर उद्योग की विकास-दर में कमी आई और यह महज 3 6 प्रतिशत रही, जबिक सिथेटिक तथा रिक्लेम्ड रबर उद्योगों ने भी धीमी विकास-दर क्रमश 5 6 तथा 8 6 प्रतिशत दर्ज कराई। अन्य उद्योगों में टायर, जूट तथा लौह अयस्क से जुड़े उद्योगों ने नकारात्मक विकास-दर दिखाई। ऑटोमोबाइल टायर उद्योग को 33 प्रतिशत में अधिक का झटका झेलना पड़ा। इसी प्रकार पटमन (जूट) उद्योग का प्रदर्शन भी कुछ खास अच्छा नही रहा। इस क्षेत्र ने 4 9 प्रतिशत की दर से नकारात्मक विकास दरशाया। लौह अयस्क उद्योग में भी मंदी छाई रही। इसने 6 6 प्रतिशत का नकारात्मक विकास किया (परिशिष्ट तालिका-5)।

अनुसंधान तथा विकास

प्रौद्योगिको के विकास, डिजाइन और उत्पादों में सुधार के उद्देश्य से पर्याप्त प्रयासों की आवश्यकता होती है। उद्योग जगत् में अनुसंधान और विकास के लिए विस्तृत आधार जुटाने-हेतु कारगर कोशिशे की जानी चाहिए। 31 मार्च, 1998 तक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त कुल 1,261 अनुसंधान तथा विकास इकाइयों मुख्य रूप से रसायन और संबंधित उद्योगों में कार्यरत थीं। इन इकाइयों पर मौजूदा अनुमानित व्यय लगभग 1,800 करोड रुपए का है। मार्चजनिक और संयुक्त क्षेत्रों की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र की 65 प्रतिशत है। अनुसंधान एव

उदार औद्योगिक माहौल में औद्योगिक गतिशीलता बनाए रखने के लिए नई

विकास में सिक्रिय 256 इकाइयों में से प्रत्येक इन गितिविधियों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक व्यय कर रही है, जर्बाक 350 इकाइयाँ ऐसी हैं, जो प्रत्येक वर्ष 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च करती हैं। शेप इकाइयाँ हर माल 25 लाख रुपए में कम की राशि अनुसंधान तथा विकास-कार्यों पर व्यय करती हैं। अधिकाश अनुसंधान विकास इकाइयाँ बड़े शहरों के आस-पास स्थित हैं। उदारीकरण का लाभ उठाने के लिए कॉरपोरेट जगत् को अपनी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को व्यापक आधार देने की दिशा मे और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है।

लघु क्षेत्र की इकाइयों ने सन् 1998-99 के दौरान 3 6 प्रतिशत की सामान्य

लघु उद्योग क्षेत्र

99 में इस क्षेत्र के उत्पादन की विकास-दर 15 7 प्रतिशत (मौजूदा कीमतों की दृष्टि से) रही, जबिक पिछले वर्ष यह आँकडा 12 7 प्रतिशत रहा था। इस क्षेत्र ने निर्यात में सन् 1998-99 के दौरान 11.3 प्रतिशत की विकास-दर दर्ज कराई, जो पिछले वर्ष की 13 2 प्रतिशत की दर से कम रही। सन् 1998-99 में लघु उद्योग क्षेत्र ने अनुमानत 172 लाख लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराया, जबिक सन् 1997-98

विकास-दर दर्ज कराई, जबकि पिछले वर्ष यह दर 5 5 प्रतिशत रही थी १सन् 1998-

मे इस क्षेत्र ने 167 लाख लोगों को रोजगार दिलाया था। (परिशिष्ट तालिका-6)।

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय उद्योगों में रुग्णता के

औद्योगिक रूग्णता

मामलो में कमी लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तिवारी समिति की सिफारिशे (1981) के बाद रुग्ण औद्योगिक कंपनियाँ (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (एस.आई.सी.ए) पारित किया गया तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई एफ.आर.) का गठन सन् 1987 में किया गया, जो रुग्ण इकाइयों को बचाने संबंधी उपायों पर विचार करने तथा सलाह—मशवरा देने का काम करता है। औद्योगिक पुनर्वास के सभी पहलुओं के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने विस्तृत दिशा—निर्देश जारी किए हैं। बैंको तथा वित्तीय सस्थानों को भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे से बाहर जाकर भी आवश्यकतानुसार राहत/रिआयत उपलब्ध कराने की

शिक्तयाँ/विवेकाधिकार प्रदान किया गया है।

सूचीबद्ध व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त करनेवाला लघु तथा गैर-लघु
क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों की संख्या जहाँ मार्च 1997 के अत में 2,37,400 थी, वहीं
मार्च 1998 के अत में इस संख्या मे 13,388 (5 6 प्रतिशत) की कमी आई। यह
घटकर 2,24,011 रह गई। अलबता, मार्च 1997 के अत में बैंकों की बकाया राशि
13 787 करोड़ रुपए से बढ़कर 15,682 करोड़ रुपए हो गई।

गैर-लघु क्षेत्र की रूग्ण/कमनोर इकाइयाँ

सूचीबद्ध व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त करनेवाली गैर-लघु क्षेत्र की रुग्ण/कमजोर इकाइयों की संख्या मार्च 1997 के अंत में 2,368 से मामूली रूप से बढ़कर मार्च 1998 के अंत तक 2,476 तक जा पहुँची। इन इकाइयों पर बैंकों की बकाया राशि भी मार्च 1997 के अंत में 10,177.81 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 1998 के अंत तक 11,825 25 करोड़ रुपए हो गई (परिशिष्ट तालिका-8)।

1998 के अंत तक 11,825 25 करोड़ रुपए हो गई (परिशिष्ट तालिका-8)। क्षेत्रों के लिहाज से पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक गैर-लघु क्षेत्र को रुग्ण इकाइयाँ (767) हैं. जो इस श्रेणी की कुल रुग्ण इकाइयाँ का 31 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक गैर-लघु क्षेत्र को रुग्ण इकाइयाँ हैं, जबिक उसके बाद आध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तिमलनाडु का स्थान है। बैंकों की बकाया राशि सबसे अधिक टेक्सटाइल उद्योग (1,793 करोड़ रुपए या कुल बकाया का 15.2 प्रतिशत) और उसके बाद इंजीनियरिंग (1,418 करोड़ रुपए या 12 प्रतिशत), रसायन (1,352 करोड़ रुपए या 11 4 करोड़ रुपए), इलेक्ट्रिकल (1,119 करोड़ रुपए या 9.5 प्रतिशत) तथा लोह एवं स्टील उद्योग (1,110 करोड़ रुपए या 9.5 प्रतिशत) पर है (परिशिष्ट तालिका-8)।

लघू क्षेत्र की रागण इकाइयाँ

सूचीबद्ध व्यावसायिक बेंकों से ऋण लेनेवाली लघु क्षेत्र की इकाइयो की संख्या मार्च 1997 के अंत में 2,35,032 से घटकर सन् 1998 के अत तक 2,21,536 हो गई। अलबत्ता, इन इकाइयो पर बैंकों की बकाया राशि मार्च 1997 के अंत में 3,609 करोड़ रुपए से बढ़कर सन् 1998 के अत तक 3,857 करोड़ रुपए हो गई।

लघु क्षेत्र की सर्वाधिक रुग्ण इकाइयाँ पूर्वी क्षेत्र में (44.7 प्रतिशत) और उसके बाद उत्तरी क्षेत्र (21.2 प्रतिशत), दक्षिणी क्षेत्र (17.6 प्रतिशत) तथा पश्चिमी क्षेत्र (16.4 प्रतिशत) मैं हैं। अलबना, बेंकों की राशि सबसे अधिक पश्चिमी क्षेत्र (31.3 प्रतिशत) और उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र (27.8 प्रतिशत), उत्तरी क्षेत्र (23.6 प्रतिशत) तथा पूर्वी क्षेत्र (17.4 प्रतिशत) पर बकाया है (परिशिष्ट तालिका-7)।

केंद्रीय क्षेत्र में परियोजनाओं का प्रदर्शन

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सितंबर 1999 के लिए केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओ¹ की फ्लैश रिपोर्ट के आधार पर सितंबर 1999

केंद्रीय क्षेत्र के 100 करोड़ रुपए या अधिक की परियोजनाओं से संबद्ध।

के अंत तक 11 परियोजनाएँ अनुमानित समय से आगे चल रही थीं, जबिक पिछले वर्ष की इसी अविध में यह संख्या 8 थी। सितंबर 1999 तक 33 परियोजनाएँ निर्धारित समय के अनुसार कार्यरत थीं, जबिक सितंबर 1998 के अंत में ऐसी 42 परियोजनाएँ थीं (परिशिष्ट तालिका-9)।

सितंवर 1999 के अंत तक 201 परियोजनाओं में से 103 परियोजनाएँ समय से पीछे थी। रेलवे में सबसे अधिक (21) परियोजनाएँ पिछडी और उसके बाद पेट्रोलियम (19), विद्युत् (16), भूतल परिवहन (16) और कोयला (15) क्षेत्र का स्थान रहा। कुल 54 परियोजनाओं के पूरा होने की अनुमानित तारीख तय नहीं है, उनमें सर्वाधिक रेलवे (52) में हैं (परिशिष्ट तालिका-9)।

समय से पिछड़ी परियोजनाओं के वर्षवार विश्लेषण से पता चलता है कि सितबर 1999 के अंत तक 103 परियोजनाओं में से—(क) 42 में 2-5 वर्षों की देरी हुई; (ख) 28 परियोजनाओं में 1 वर्ष की देरी हुई, (ग) 17 परियोजनाओं में 5-10 वर्षों की तथा (घ) 16 में 1-2 वर्ष की देरी हुई।

देरी का कारण

परियोजनाओं में देरी¹ के कारणों की समीक्षा से स्पष्ट है कि सर्वाधिक (20) परियोजनाएँ निर्माण-कार्यों में समस्याओं की वजह से पिछड़ीं। 16 परियोजनाओं में देरीं भूमि संबधी समस्याओं के कारण हुई, जबकि धनराशि और ठेका देने सबंधी परेशानियों के चलते कुल मिलाकर 13 परियोजनाएँ निर्धारित समय-सीमा से पिछड़ गई।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.ई.) का प्रदर्शन

सरकार द्वारा सुधार उपाय लागू करने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन-संकेतकों में सकारात्मक सुधार देखा गया है। इन उपक्रमों का शुद्ध लाभ सन् 1996-97 में 9,992 करोड़ रुपए (238 पी एस ई का) से बढ़कर सन् 1997-98 मे 13,725 करोड रुपए (236 पी.एस.ई.) हो गया। नतीजतन पूँजीगत लाभ भी 15 1 प्रतिशत से बढ़कर सन् 1997-98 मे 16.2 प्रतिशत तक बढ़ गया। लाभ कमानेवाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या सन् 1996-97 मे 130 से बढ़कर सन् 1997-98 में 134 हो गई, जबिक घाटा दिखानेवाले उपक्रमों की

संख्या सन् 1996-97 मे 104 से घटकर सन् 1997-98 में 100 हो गई। सन्

परियोजनाओं में देरी कई कारणों से होती है।

1997-98 के दौरान पी एस.ई के मूल्यवर्धन में पिछले वर्ष की तुलना में 27 3 प्रतिशत की जबर्दस्त तेजी देखी गई (परिशिष्ट तालिका-10)।

रोजगार

अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र (अर्थात् 10 या अधिक कर्मियों को रोजगार मुहैया करानेवाले गैर-कृषिगत उपक्रम) में मार्च 1998 के अंत में पिछले वर्ष की इसी अविध की तुलना में 0 5 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज की गई। पिछले वर्ष के मुकाबले मार्च 1999 के अत तक कर्मचारियों की सख्या में भी 1.3 लाख की बढ़ोतरी हुई। सार्वजिनक क्षेत्र में सन् 1997-98 के दौरान रोजगार में मामूली (-0 1 प्रतिशत) गिरावट आई। अलबना, निजी क्षेत्र ने रोजगार में 1 7 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की (मार्च 1997 के अत में 86.85 लाख लोगों के मुकाबले मार्च 1998 के अत तक यह संख्या 88 35 लाख हो गई), संगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त महिलाओं की संख्या मार्च 1997 के अंत में 46.37 लाख रही, जो मार्च 1998 के अंत तक 3.8 प्रतिशत बढ़कर 48 15 लाख तक पहुँच गई। उक्त अविध में संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 16.6 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत तक जा पहुँची (परिशिष्ट तालिका-11)।

			(H) 66-86 (H) 66-86 (H) 0007-6661	56-86(H)	-86 (xe) e	(E) 66-	61	86-2661	199	26-9661
			सूचकांक	मूचकांक	सूचकांक		सूचकांक	विकास में सूचकांक विकास में	la.	पूचकांक विकास में
					מן	योगदान (%) *		योगदान (%) *		योगदान (%) *
	खनन एवं खुदाई	10.47	115.7	115 2	120.3	-42	122.4	8 4	155 6	-35
			(0.4)	(-04)	(-1.8)		(5.9)		(-1.9)	
7	निर्माण	79.36	150.4	1408	146.7	6 88	140.6	82.2	131.8	6.7
			(6.8)	(4.1)	(4.4)		(6.7)		(6.7)	
ተሳ	निद्युत्	10 17	146.7	136 2	138.4	15.5	130.0	9.6	122 0	7.0
			(7.7)	(7 4)	(6.4)		(9.9)		(40)	
	सामान्य सूचकांक	ोक 100 00	146 4	137 6	143 1	100 0** 137.6	137.6	100 0 **	100 0** 129 1	100.0**

भारतीय अर्थनीति 🗯

(9.9)

(9.9)

(4.0)

(4.0)

(6 4)

अ. अस्थायी |

<u> 테</u>

16

^{*} एक क्षेत्र विशेष में सापेक्ष योगदान (उदाहरणस्वरूप 'एस' में) की माप 'एस' के सूचकांक में वृद्धि दरशानेवाले परिवर्तन और कुल सूचकांक के अनुपात के आधार पर की

नीट कोष्टक में दिए गए ऑकडे पिछले वर्ष की तुलना में हुए बदलाब को दरशाते हैं। ** सुरड ऑफ़ के कारण आँकड़ों के 100 तक नहीं हो सकने की सभावना है।

५, न ५५ अप्रैल-मार्च	(Æ) 66-8661 86 7661	13 14	123 37	127 36
-	86-7661	12	& 4	69 1
। जात्त प्रत अप्रैल-मार्च	(E) 66-8661	11	17.8	160
सूचकाक (प्रतिशत) अप्रैल-मार्च	86-7661	2	120 2	12 9 169 8 146 4
	(F) 66-8661	6	-34 182 141.6 120 2	1698
सापक्ष थागदान अप्रैल-सित्.	(FE) 66-8661	ထ	18 2	12 9
	1999-2000 (3 1)	7	, 4£	92
विकास-देर (प्रतिशत) अप्रैल-सितं.	(Fe) 66-8661	9	25.1	2 65 187 1 160 3 16 7 14 9
क्रें हा ब	(€) 0007-666I	2	-67	167
सूचकाक (प्रतिशत) अप्रैल-सितं.	(FE) 66-8661	4	दौरान) 2 81 129.3 138 6 -6 7 25.1	160 3
कें त	(34)	3	129.3	187 1
म ह ग		2	4 .	2 65
કુનાય સમૂહ			 विकास की एफ्तार (1998-99 के क. धातु उत्पादन तथा हिस्से (मशीनरी एवं उपकरणो को छोड़कर) ख. कागत और कागज उत्पादन 	तथा मुद्रण, प्रकाशन एवं संबंधित उद्योग
	# भारतीर	य अध	निर्वित 🛎	

		तथा कायला उत्पाद	5 /3 /39 3 /34.6 33 /0.0 33 // 30 / 34.6 34.6	3.5	10.0	33	JCI C /1	0.671 /	3	7 7	o + 01	
		ड चमड़ा एवं										
		फर उत्पादन	1 14 133.3 116 4 14 5		49 25	2.5	14 119	14 119 9 110.8	8 1	2.2	2104	
		च, अन्य निर्माण उद्योग	2.56 112 0 132 8 -15 7	-157	9 01	69-	7 6 128	7 6 128 4 120.4	99	-2.7	4.2 - 1.2	
		छ खाद्य उत्पाद	9.08 110 3 113.1 -2.5 -3.3 -3 3 -8 3 134.7 133 8	-2.5	53,3	-33	-8 3 134	.7 133 8	0.7	-04	1.7-07	
*	2.	2. रफ्तार में कमी										
भारत		(1998-99 के दौरान)										
ीय उ		ज बेबरेज (पेय), तंबाकू										
र्घेनी		तथा संबद्ध उत्पाद	2 38 192 6 176 2	9.3	17.2	5		14.4 178.5 158 1	12.9 19.4	19.4	9.9 8.7	
ति 🕸		झ. गैर-धातु खनिज उत्पाद	4.40 200 2 161 1	24.3	5 2	22.3	8.1 174	8.1 174.6 161 4	8 2	13.8	11.8 12 4	
		त. बुनियादी रसायन और										
		रासायनिक उत्पाद										
		(पेट्रोलियम तथा कोयला										
		उत्पादों को छोड़कर)	14.00 162 8 146 9 10.8	10.8	7.4	28.9	7.4 28.9 33.0 149 8 140.5	8 140.5	9.9	14.5	6.6 14.5 26.535.7	
		थ. ऊन, सिल्क तथा										
		रेशायन्त वस्त्र	2 26 192 3 172 6 11 4		42	8 8		36 176 8 172 0	28	28 185	2287	

6.7 100*100*		4	100 100* 146 7 140 6 4 4	100		42.	6.8	79 36 150 4 140.8 6.8	79	निर्माण क्षेत्र
23-109 2.2		1	115 9 125 6	-166	42	-10.1	5.0	5 52 121 1 115.3 50 - 10.1 42 - 166 115 9 125 6 - 77		भ. सूती कपड़े
6 - 10 14	3 16	-7.	106 0 114 3	-0.8	-03	-5.4	-38	0.59 101.3 105.3 -38 -5.4 -03 -0.8 106 0 114 3 -7.3 166 -10 14	। छोड़कर)	कित
									जूट तथा अन्य रेशायुक्त	ाव रुष
6 -41-13	8 -2	5.	21 0 128 5	-30	-72	-36	-160	270 106 8 127.2 -16 0 -3 6 -7 2 -3 0 121 0 128 5 -5.8 -2 6 -41-13	उत्पाद, फर्नीचर	अप्त
									फ. लकड़ी और लकड़ी	फ. लक
85 -29 45		-3	-05 -2015311587 -35	-20	-0.5	-21	60-	2 54 151 7 153.1 -0 9 -2 1	कपडा उत्पादन	प कप्
26 -55 39		-2	23 -0.6 31 -1.4 139 9 143 5 -2 5	-1.4	3.1	-0.6	23	7 45 142.5 139.3	य. खुननयादा थातु तथा सिश्रित थातु उद्योग	पू. मिक्र
									4	दौरान)
									3. नकारात्मक (1998–99 के	नकारात्
5.5 5.110.6		1.8	52 1 149 5	-1031	36.4	-32	21.1	9 57 167.9 138.6 21.1 -3 2 36.4 -10 3 152 1 149 5	छोड़कर) 9	छोड़
									(परिबहन उपकरणों को	(परि

•

						5
56	99	4.0	40	64	100 0	सामान्य सूचकांक
(21.9)	(180)	(10.1)	(10 1)	(5 5)		5
	5.2	2,8	18	16	23.24	ग्व उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्त्रएँ
	(7)	(7 /)	(5 9)	(119)		
(5.1)	(1.2)	(1		1		के, उनमावता तिकाल प्रतुर
4.6	7 8	4.7	1,9	12.8	7 13	TOTAL PARTY BEAT
(2/3)	(25 0)	(17.5)	(12.8)	(17.4)		
5.2	5.7	2.4	1.8	4 0	28.36	उपभोवता मामान
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(41.2)	(404)	(41.5)		
(39.3)	(34.2)	(412)	(40.4)			मध्यवदा वामान
ထိ	8 1	5.9	56	9.1	26 44	Control of the contro
(245)	(7.3)	(28 4)	(24.3)	(13 5)		
	ν, ,	12.7	11.1	9.2	69.6	े प्रजीगत सामान
0				(0.12)		
(193)	(33.8)	(12.5)	(21.4)	(0, 20)	, 	
2 /	٠ م	15	2.5	n;	35.51	
-	2000	150 CC 0661 (b) 66-8661 (b) 0002-6661	1778-77 (41)	19992000 (4		

भारतीय अर्थनीति

उद्योग	वयान		अप्रैल-सितंबर		अप्रैल-मार्च	
		1999-2000 (3	1999-2000 (अ) 1998-99 (अ) 1998-99 (अ)	(1998-99 (34)	1997-98 1996-97	1996-97
विद्यत	10 17	146.7	136.5	138 8	130 0	121 9
, ,		(7 4)	(7.7)	(6.8)	(9.9)	(38)
कोयला	3 22	105 6	1068	1178	120 7	1160
		(-1 1)	(13)	(-2.3)	(4 0)	(6 5)
किन्नी योग्य स्टील	5 13	163.9	157.2	162 3	160 6	151 1
		(4.3)	(2.6)	(1.0)	(6.3)	(5.8)
सीमेंट	1 99	169 2	142.3	153 3	145 1	133 0
		(18 8)	(42)	(57)	(6.1)	(96)
पेट्रोलियम कच्चा	4 17	121 4	120 2	1213	125 3	121 8
		(10)	(-40)	(-32)	(5.9)	(47)
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	2 00	146 5	123 0	128.4	122 1	1178
		(19.1)	(17)	(5.1)	(3.7)	(2.0)
And had submitted that the state of the stat	26 68	142.7	133.8	138 3	134 6	127 3
रचना सूचकांक के छह मूचना उह	उद्योग	(67)	(34)	(2.7)	(57)	(37)

परिशिष्ट तालिका-5 प्रमुख उद्योगों के उत्पाद में विकास

(प्रतिशत)

	उद्योग	अप्रै	ल-मार्च
and the same of the same	-	1997-98	1998-99 (अ)
1	कच्चा तेल	2 9	-3 4
2	पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	3 9	5 3
3	रबर उद्योग, जिसमें हैं—	6 6	1.5
	क प्राकृतिक	6.4	3.6
	ख सिंथेटिक	10 8	-5.6
	ग रिक्लेम्ड	4 5	-8 6
4	कोयला	3.9	-16
5	सीमेंट	9.1	5.7
6	विद्युत् शक्ति	6 5	6.6
7	पिग आयरन	2.9	~11.8
8	लोह अयस्क	11 0	-6.6
9	ऑटोमोबाइल टायर	0.0	(-) 33.3
10	जट	19.8	4 9

(अ) अस्थायी।

स्रोत 🕦 पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मत्रालय, भारत सरकार।

- 2 रवर बोर्ड, भारत सरकार।
- 3 कोयला मत्रालय, भारत सरकार।
- 4 उद्योग मन्नालय, भारत सरकार।
- केंद्रीय विधुत् प्राधिकरण, विमुक्त बिजली मंत्रालय, भारत सरकार।
- 6 भाग्तीय खदान ब्यूरो, भारत सरकार।
- 7. केंद्रीय साख्यिकीय संगठन भारत सरकार।
- जूट उत्पादन विकास परिषद्, कोलकाताः

यरिशिष्ट तालिका-6 लघु क्षेत्र का प्रदर्शन

<u>—</u> मद			अप्रैल-म	र्च
,	·	1996-97	1997-98	1998-99 (अ
1.	इकाइयों की सख्या (लाख)	28 57	30 14	31.21*
		(4 9)	(5 5)	(3.6)
2	उत्पादन (1990-91 के मूल्यों			
	के अनुसार करोड़ रुपए)			
	क लक्ष्य	231,020	253,705	278,619
	ख उपलब्धि	247,311	268,159	294,734*
		(11 3)	(8.4)	(9 9)
3	उत्पादन (मौजूदा मूल्यों के			
	अनुसार करोड़ रुपए)			
	क. लक्ष्य	385,454	440,098	508,906
	ন্ত্ৰ ত্তপলক্ষি	412,636	465,171	538,357
		(15 8)	(12 7)	(157)
4	रोजगार (लाख व्यक्ति)			
	क लक्ष्य	158 91	166.86	175 20
	ख उपलब्धि	160 00	167.00	171 58*
		(48)	(4.4)	(27)
5	निर्यात (मौजूदा मूल्यों के			
	अनुसार करोड रुपए)			
	क. लक्ष्य	20,207	47,905	57,488
	ख. उपलब्धि	39,249	44,437	49,481*
		(7 6)	(13.2)	(114)

^{*} अनुमानित।

अ अस्थायी।

नोट • 1 कोध्वक मे दिए गए आँकडे पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में आए बदलाव को दरमाते हैं !

² आँकढ़े विद्युत्चालित करघो तथा पारपरिक उद्योगों समेत आधुनिक रुखु क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है।

स्रोत । विकास आयुक्त का कार्यालय, लघु उद्योग क्षेत्र, उद्योग पत्रालय, भारत सरकार।

² वार्षिक रिपोर्ट, सन् 1998-99, उद्योग मञालय।

परिशिष्ट तालिका-7 लघु क्षेत्र की बीमार इकाइयों की स्थिति

(करोड़ रुपए)

ज्य	ग/केद्रशामित प्रदेश	मार्च 1997	के अंत में	मार्च 1998 वे	अंत में
	7	रीमार इकाइयों	बकाया	बीमार इकाइयों	बकाया
		की संख्या	धनराशि	की सख्या	धनराशि
	1	2	3	4	5
	पूर्वी क्षेत्र	1,05,109	626 60	1,06,756	648 96
	अखिल भारत का % अश	44.72	17 36	44.72	17.36
	अंडमान निकोबार द्वीप स	मूह 13	0 08	45	1 60
	अरुणाचल प्रदेश	26	0 12	456	0 94
	असम	10,133	54.18	15,774	60 62
	विहार	22,702	120.62	24,935	142 74
	मणिपुर	2,707	9 85	1,919	8.79
	मेघालय	5,531	8 20	4,076	6 52
	मिजोरम	1,199	2 76	615	2 45
	नगालै इ	2,738	9.44	1,386	4.98
	उईांमा	3,408	45 08	1,889	35 63
	सिक्कम	30	0 14	33	0 11
	त्रिपुरा	3,171	4 46	2,011	6 26
	प्रिचम बंगाल	53,451	371.67	53,617	378.32
2	उत्तरी क्षेत्र	49,967	850 37	40,579	954.97
	अखिल भारत का % अंश	21.26	23 56	21 26	23.56
	चंडीगढ़	170	14.41	163	16.69
	दिल्ली	3,943	264.81	3,580	298 59
	हरियाणा	2,574	63.95	2,149	92.41
	हिमाचल प्रदेश	2,206	17 68	735	22.15
	जम्मू एव कश्मीर	761	8 10	1,627	25 1
	पंजाब	2,466	84.44	2,376	91 70
	राजस्थान	14,561	97.51	15,655	108.6
	उत्तर पदेश	23,286	299 39	14,294	299.6

	1	2	3	4	5
3	पश्चिमी क्षेत्र	38,549	1,128.94	33,758	1,137 57
	अखिल भारत का % अंग	16 40	31 28	16 40	31 28
	दादरा नागर हवेली	1	0.90	2	1 16
	दमन-दीव	4	1 41	5	3 83
	गोवा	604	13 86	670	10 15
	गुजरात	6,510	196 80	6,808	224 63
	मध्य प्रदेश	12,070	151 44	8,348	141 86
	महाराष्ट्र	19,360	764 53	17,925	749 94
4	दक्षिणी क्षेत्र	41,407	1,003,39	40,443	1,115 14
	अखिल भारत का % अश	17 62	27.80	17.62	27 80
	आंध्र प्रदेश	15,460	214 39	12,074	218 77
	कर्नाटक	6,937	203.26	6,680	223.19
	केरल	8,908	168 28	8,969	190 12
	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00
	पांडिचेरी	293	18 64	431	26 13
	तमिलनाडु	9,809	398.82	12,289	456 93
स	र्गुण भारत (1+2+3+4)	2,35,032	3,609 20	2,21,536	3,856 64

^{*} लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाई को बीमार उस स्थिति में समझा जाएगा, अवॉक । क) उमके ध्रारा लिया गया कोई भी ऋण सदिग्ध अग्रिम बन जाए, अर्थात् उसके ऋण से स्थिति मृत्य का ब्याज राशि ढाई वर्षों से अधिक समय तक बकाया गहे, (ख) जिसके किसी भी लेटडा वर्षों में कुल भाटे के कारण पिछले 4 वर्षों के दौरान उसकी शुद्ध कीमत का 50 प्रतिशक्त किस्मा नन्द्र तो जाए। स्रोत औद्योगिक निर्यात तथा ऋण विभाग, भारतीन टिअव बॅक।

परिशिष्ट तालिका-8 बीमार गैर-लघु/कमजोर इकाइयों की स्थिति

(करोड रुपए)

सञ	व/कें द्रशासित प्रदेश	मार्च 1997	के अंत में	मार्च 1998 व	के अंत मे
		बीमार गेर-	वकाया	बीमार गैर-	बकाया
		लघु/कमजोर	धनराशि	लघु/कमजोर	धनसङ्गि
	इव	ताइयो की मख्य	त इ	काइयो की संख्या	
	1	2	3	4	5
1	पूर्वी क्षेत्र	423	1,754 49	419	1,879.58
	अंग्वल भारत का % अंश	17 86	17 24	16 92	15.89
	अडमान निकोबार द्वीप सम्	्ह O	0.00	0	0.00
	अरुणाचल प्रदेश	2	2 47	2	2.47
	असम	41	167.40	44	157.97
	विहार	64	190 81	63	358.24
	मणिपुर	1	2 45	2	2.42
	मेघालय	1	0 89	2	1.39
	मिजोरम	0	0 00	0	0.00
	नगालँड	2	3.43	2	4.48
	उड़ीमा	62	284 41	57	210.64
	सिक्किम	1	6.35	1	6.35
	त्रिपुरा	6	9 95	6	9.41
	पश्चिम बगाल	243	1,086.33	240	1,126.21
2	उनरी क्षेत्र	511	2,036 96	526	2,472
	अखिल भारत का % अंश	21 58	20 01	21.24	20.91
	चंडीगढ	10	22 73	3	7 54
	दिल्ली	35	172 35	34	233.51
	'हरियाणा	78	328.28	86	394 87
	हिमाचल प्रदेश	31	37 47	32	54 30
	जम्मृ कश्मीर	9	17 95	7	8 91
	पंजा ब	62	200 84	69	203 01
	राजस्थान	84	276 26	87	371.33

		2	3	4	5
	उत्तर प्रदेश	202	981 08	208	1, 198 97
3.	पश्चिमी क्षेत्र	742	2.912	767	3.563
	अखिल भारत का % अंश	31 33	28 61	30 93	30.13
	दादरा नागर हवेली	4	6.43	8	18.47
	दमन-दीव	3	9 37	Ş	27 77
	गोवा	12	31.79	13	51,66
	गुजरात	213	664 81	215	881 34
	मध्य प्रदेश	111	364.75	: 16	491 68
	महाराष्ट्र	399	1,834.77	410	2 092.11
4	दक्षिणी क्षेत्र	692	3,474.44	7e4	3910
	अखिल भारत का % अश	29.22	34 14	30.86	33 97
	आंध प्रदेश	264	1,186 71	295	1 264,15
	कर्नाटक	159	1,024.48	121	1,001.85
	केरल	81	492 81	55	495.73
	लक्षद्वीप	ð	0 00	0	0 00
	पांडिचेरी	13	44 05	15	34,04
	र्तामलनाडु	175	726 39	198	114 43
संप	रूर्ण भारत (1+2+3+4)	2,368	10,177 81	2.476	1,1825.25

^{* (}क) बीमार औद्योगिक इकाई का अर्थ है ऐसी और्धांगक केपना (बी बतीर अपने कम है कम 5 वर्ष से पजीकृत हो) जिसे किसी भी विन वप के अत मे अपनी भपूण पुँजा के बराबर वा 3 मंदि आधक राशि का नुकसान हुआ हो।

स्रोत - औद्योगिक निर्यात तथा ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बँक।

⁽ख) गैर-लघु क्षेत्र की औद्योगिक वह इकार्ट 'कमजार' इकार के 'असके किएते भी साल अप में कृत्य याटे के कारण पिछले चार लेखा वर्षों के दौरान उमकी मर्थान्य शुद्ध कीमन का ६० प्रारम्भ हिस्सा नष्ट हो जाए। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कमजोर इकाइयों के अनगत उन्ने नहीं शामिल किया जाएगा, जो बीमार औद्योगिक कपनियाँ (विशेष प्रायथान) और्धान्यम, 1985 के द्वायर म अती हैं, साथ हो अन्य श्रेणियाँ, जैसे—भागोदारी फम, स्वांमत्य फर्म आदि! कियो 'कमजोर' औद्योगिक कपनी को उस स्थित में 'बोमार' क्यान ममका आध्या जब उसे एम आई मी.ए.. 1985 (फरवरी 1994 तक मंशोधित) के अनुष्केट 23 एक(11 के अनगत बी. आई,एफ आर में शामिल किया जाएगा।

परिशिष्ट तालिका-9 केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थिति (सितंबर 1999 के अंत में)

नोट 1 केंद्रीय क्षर की परियोजनाओं से मबद्ध, 100 करोड रुपए और अधिक मृत्य की।

² प्रारथ क्षेत्र की अनुमानिक निथि के आधार पर देरी की गणना की गई है।

स्रोतः योजना तथा कायक्रम कार्यान्वयन मत्रालय, भारत सरकार।

परिशिष्ट तालिका-10 केद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम प्रदर्शन

(गणि करोड रुपए में)

मद	1993-94	1 94-95	95-96	96-97	97-98
कार्यरत उद्यमों की					The control of the second light of the second
संख्या	241	241	239	248	236
पूॅजी	1,59,836	1,61,311	1,73 765	2,01 496	2,23,047
मूल्यवर्धित	41,486	47,986	57,859	57,116	726,91
सकल मुनाफा	18,556	22,516	27,587	30.609	36 093
शुद्ध मुनाफा	4,545	7,217	9,574	9,992	13,725
मुनाफा कमानेवाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो की सख्या	121	130	132	130	134
घाटा दिखानेवाले सार्वजनिक क्षेत्र के					
उद्यमो की सख्या	116	109	102	104	100
न मुनाफा, न घाटा दिखानेवाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सख		2	5	2	2
पूँजी % के अनुसार	11 2	<u>د</u>	د	2	4
सकल	17.33	20.61	23 11	22 23	23.59
पूँजी % के अनुसार					
संकल मुनाफा	11.61	13 96	15 88	15 19	16 18

स्रोत र सार्वजनिक उद्यमों का मर्वेक्षण 1997-98, (वॉस्यूम 1), भाग्त संग्कार।

परिशिष्ट तालिका-11 संगठित क्षेत्र में रोजगार

सार्वजनिक क्षेत्र

						महिलाऐ		
	प्रादेशिक सरकार	अद्भे सकारी	स्थानीय निकाय	कुल (2 से 5)	निजी क्षेत्र	कुल (6+7)	कुल में से रोजगार प्राप्त महि	रोजगार प्राप्त
	3	4	5	6	. 7	8	9	10
3 5	73 55	65 20	21 97	194 66	80 58	275.25	43 04	15 (
1)	(+0.2)	(+01)	(-0.3)	(+01)	(+16)	(+05)	(+3 6)	
66	74.14	64 58	21 92	194.29	85.12	279 41	44.26	15
9)	(+08)	(-1.0)	(-0.2)	(-0 2)	(+5 6)	(+1 5)	(+28)	
95	74 85	65.35	22.44	195.59	86.85	282,45	46.37	16
1)	(+1 0)	(+1.2)	(+2 4)	(+07)	(+20)	(+1 1)	(+48)	
	-	**	-	195.40	88 35	283.75	48.15	17
				(-01)	(+17)	(+0.5)	(+38)	

दए गए ऑकड़े पिछले वर्ष की तुलना मे प्रतिशत में बदलाव को दरशाते हैं।

, भारत सरकार।

(लाख मे

भारतीय अर्थनीति *

नब्बे के दशक में बाह्य आर्थिक चुनौतियों का प्रबंधन : भविष्य के लिए सबक

–शंकर आचार्य

बहुत असाधारण साबित हुआ। में यहाँ छह विरोध चुनोतियो का उल्लेख विस्तार में करना चाहता हूँ, जिनका सामना भारतीय अर्थव्यवस्था ने किया। उन चुनानियों मं सन् 1991 का भुगतान-सतुलन का सकट, मन् 1993 और 1994 में विदेशी पूँजी का जबरदस्त प्रवाह, व्यापारिक उदारीकरण, बाहरी कर्जों का प्रवथन, पूर्वी एशियाई

सकट फैलने का खतरा, विनिमय-दर प्रबंधन में जुड़े मुद्दे और विकल्प शामिल

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नब्बे का दशक बाह्य चुनौतियों के निए

हैं। इनमें से हर विषय पर अलग से विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। म इनमें से हर विषय पर चुनिदा ढंग ये सक्षेप में विचार करना चाहता हूँ।

1991 का भुगतान-संतुलन का संकट

इस दशक की शुरुआत भयावह ढंग में हुई। भुगतान स्मृतन का भीषण संकट पूरी विकरालता के माथ सामने आया। सन् 1991 की गर्गमया में विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ एक अरब डॉलर रह गए, जो सिर्फ दो मप्ताह के आयान क

लिए ही पर्याप्त थे। निर्यात में भी गिरावट आने लगी। चाणिज्यिक ऋण व्याजार में पहुँच पर रोक लग गई। औद्योगिक विकास-दर 1 3 प्रतिशत के नकागत्मक ऑकट पर आ गई। मुद्रास्कीति का ग्राफ अगस्त 1991 में 16 प्रतिशत को उन्हान भरने

लगा। कुल मिलाकर आर्थिक विकास-दर में भी 1 प्रतिशत की गिगवट आ गई। इस संकट के उत्तरदायीं कई कारण थे। अस्सी के दशक के उत्तरार्व म

राजकोपीय घाटा बेहद बढ़ गया। उद्योग और व्यापार पर जरूरत से ज्यादा नियत्रण था। विदेश व्यापार नीतियों में निर्यात की हतोत्साह किया जा रहा था और उच्च का आयात बढ़ रहा था। बड़े व्यापार घाटे से उबरने के लिए बाहर से ऋण

ो प्रवृत्ति बढ गई थी। विदेशी निवेश के बारे मे दृष्टिकोण नकारात्मक था

र्थव्यवस्था की सेहत नाजुक थी। इन संवेदनशील परिस्थितियों में खाडी युद्ध सके कारण तेल आयात बिल बढ़ने से अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र में जोरदार पैदा हो गया।

जृन 1991 के चुनाव के बाद केंद्र में बनी सरकार ने तुरत स्थिति की इता को भॉपते हुए स्थिरीकरण के लिए मजबूत उपाय किए और राजकोषीय उद्योग नीति, विदेश व्यापार और विनिमय-दर व्यवस्था, विदेशी निवेश-

कर-प्रणाली, वित्तीय क्षेत्र, पूँजी बाजारों, कृषि मूल्य-निर्धारण, वितरण नीति ार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक सुधार के उपाय शुरू किए गए। बाह्य क्षेत्र में सुधार उपाय किए गए, उनकी झलक में यहाँ देना चाहता हुँ—

उपाय किए गए, उनका झलक म यहा दना चाहता हु—
1 विनिमय-दर व्यवस्था को 2 साल के भीतर बदलते हुए बास्केट व्यवस्था को परिवर्तित कर विनिमय-दरों का निर्धारण वाजार से होने लगा। सक्रमण अविध में दोहरी दरें जरूर प्रभावी रहीं।

की व्यवस्था लगभग समाप्त कर दी गई। अधिकतर उपभोक्ता वस्तुओ पर परिमाण संबंधी पाबदियाँ कायम रहीं। 3 बेहद ऊँची कस्टम शुल्क व्यवस्था को घटाने के लिए कार्यक्रम शुरू

पुँजीगत सामान कच्चे माल और कुछ अन्य मामलो में आयात लाइसेंसिंग

किया गया और संरक्षणात्मक शुल्क दरों को मार्च 1993 तक घटाकर 85 प्रतिशत पर ले आया गया। अनेक उद्योगों में 51 प्रतिशत तक सीधे विदेशी निवेश की स्वतः मंजूरी

अनेक उद्योगों में 51 प्रतिशत तक सीधे विदेशी निवेश की स्वतः मंजूरी की व्यवस्था कर दी गई। विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की स्थापना की गई, ताकि अन्य क्षेत्रों और

51 प्रतिशत से अधिक निवेश के लिए मंजूरी की प्रक्रिया तेज की जा सके।
6 विदेशी मुद्रा-विनिमय नियमन कानून को संशोधित किया गया, ताकि क्यों और विदेशी-इक्टिटी के लिए भारतीय व्यवसाय में प्रवेश के

फर्मों और विदेशी-इक्विटी के लिए भारतीय व्यवसाय में प्रवेश के लिए उदार माहौल बनाया जा सके। 7 भारतीय शेयरों के लिए द्वितीयक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु नई

नीति लागू की गई। पोर्टफोलियो विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। तालिका-1, तालिका-2 और रेखाचित्र-1 से स्पष्ट है कि इन सुधारों के तुरत कितने फायदे हुए इनसे सन 1992 93 म कुल मिलाकर आर्थिक विकास दर 5 3 प्रतिशत तक पहुँच गई ओर इसके बाद विकास-दर तेज हो गई। औद्योगिक क्षेत्र में तेजी आने में कुछ समय लगा, लेकिन सन् 1994-95 मे इस क्षेत्र की

क्षेत्र में तेजी आने में कुछ समय लगा, लेकिन सन् 1994-95 मे इस क्षेत्र की विकास-दर 9 3 प्रतिशत तक जा पहुँची। डॉलर के हिसाब से निर्यात वृद्धि दर सन्

1993-94 में बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई। चालु खाता घाटा नेजी से गिग और यह

सन् 1990-91 में 9 7 अरब से गिरकर सकल घरेलू उत्पाद के 1 से 1 5 प्रिनिशन तक सीमित रह गया। आयात वृद्धि-दर भी सुधर गई। विदेशी निवेश में भी तेजी में वृद्धि हुई। यह सन् 1993-94 में 4 अरब डॉलर तक पहुँच गया। विदेशी मुद्रा भंडार में भी जबरदस्त वृद्धि हुई।

दिलचस्य बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सकट में दूसर विकासशील देशों के मुकाबले तेजी से उबरी। नालिका - 3 में स्पष्ट है कि मुधार शुरू होने के पहले 3 वर्ष में औसत आर्थिक विकास-दर 6 4 प्रतिशत धो जर्याक उस समय तीस विकासशील देशों में औसत विकास-दर 2 2 प्रतिशत ही थी।

जबरदस्त पूँजी-आवक का प्रबंधन

था, लेकिन इससे जबरदम्त पूँजी-आवक के प्रवधन की एकतम नई ममस्या मामने आई। हमारे लिए यह पूरी तरह से अबृझ चुनौती थी। इसका समाधान करने के लिए किताबी अवधारणाओं का व्यवहार से सिम्मलन करना था। यह प्रणय था, जा स्वग में नहीं, बल्कि यथार्थ के धगतल पर होना था। इस स्थिति में जो प्रमृग्य मुद्दे उपर उनसे निपटने के लिए अपनाई गई नीतियां में जो परिणाम मामने आए, उमकी एक झलक मैं देना चाहता हैं।

बाह्य क्षेत्र में आमृल-चूल बदलाव आर्थिक स्थारो की सफलता का पूर्ण्य

सितंबर 1993 में अक्तूबर 1994 के बीच विदेशी मुद्रा भंडार में 12 अरब 20 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ, यानी हर महीने करीब । अरब डॉलर बिटेशी मुद्रा आई। दूसरी दृष्टि से देखें तो इन 13 महीने में भंडार सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत के बराबर हो गया (विवरण तालिका-2 में)।

विदेशी मुद्रा के प्रवाह से जी प्रमुख मुद्दे उभर, व इस प्रकार हैं—

- इस प्रवाह के समय न्यूनतम विनिमय-दर को त्रढ़ने दिया जाए या यह धन विदेशी मुद्रा भडार में जमा किया जाए।
- 2. पूँजी-प्रवाह की समस्या को अवसरों में कैसे तब्दील किया जाए, ताकि बाह्य व्यापार और अदायगी का उदारीकरण हो।

इन मुद्दों पर फैसला लेते समय पूजी प्रवाह की भविष्य की तसवीर की अनदेखी की गई और खासतोर से इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि यह प्रवाह स्थायी है या अस्थायी है।

विनिमय-दर के मामले में अतरराष्ट्रीय मुद्रा कोप की सलाह के विपरीत हमने भंडार बढ़ने दिया और न्यृनतम डॉलर-रुपया बराबरी को चढ़ने नहीं दिया। इस फैसले से कई कारण जुड़े थे।

सितंबर 1993 में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 7 6 अरब डॉलर था, जो तीन महीने के आयात के लिए पर्याप्त था। इसे नाकामी समझा गया। फिर सन् 1991 के आघात की काली यादें भी धुंधली नहीं पड़ी थी। इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार को आरामदायक स्थिति में लाने का इरादा बनाया गया। दूसरे, उस समय हम निर्यात में उफान के शुरुआती दौर में थे। न्यूनतम विनिमय दर में तेज वृद्धि से हम उम उफान को नहीं रोकना चाहते थे। पूँजी-प्रवाह के स्थायित्व के बारे में हम सुनिश्चित नहीं थे।

भंडार बढ़ाने के मौद्रिक प्रभावों को कम करने और उदारीकरण से पैदा हुए

अवसरों का लाभ उठाते हुए बाह्य क्षेत्र को मजबूत करने की खातिर हमने कई पहल कीं। मसलन, चीनी, खाद्य तेलों, कपास आदि जरूरी चीजों के आयात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंधों में ढील दी गई। मुद्राकोष के अनुच्छेद-8 का पालन करते हुए अगस्त 1994 में हमने चालृ खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता की ओर कदम बढ़ाया, अल्पकालिक ऋणों की अदायगी के उपाय किए। अप्रवासी विदेशी मुद्रा जमा श्रेणी को चरणबद्ध ढग में समाप्त किया गया, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को विनिमय गारटी का लाभ मिला। इसके साथ ही भारतीय फर्मों के लिए विदेशी निवेश नीति को आंशिक रूप से उदार बनाया गया।

इन नीतिगत पहल के परिणाम और सबक भी हमारे लिए अनुकूल साबित इ.ए.। जैसे—

- 1 मार्च 1995 तक हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार हो गया, जो छह महीने के आयात के लिए पर्याप्त था।
- 2 सन् 1993~94 से 1995~96 के बीच लगातार 3 साल तक निर्यात उफान पर रहा और डॉलर के मुकाबले हर साल 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- 3 विदेशी पूँजी-प्रवाह के लिए वातावरण अनुकूल बना रहा। अलबत्ता, सन् 1994-95 के बाद भडार में आया उफान बराबर हो गया, क्योंकि

औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति से आयात मे भारी वृद्धि हुई थी और चालृ खाते का घाटा भी बढ गया था।

- 4 औद्योगिक क्षेत्र में तेजी के बल पर कुल मिलाकर आधिक विकास दर सन 1994-95 में 7 प्रतिशत की दर पर पहुँच गई।
- 5 अल्पकालिक ऋणों की अदायगी मे बाह्य ऋण सकतकों की स्थित मे सधार आया।

नकारात्मक प्रभाव यह रहा कि मौद्रिक वृद्धि दर और मुद्रारर्फीत--दोना मे तेजी आई, लेकिन सन् 1994-95 के बाद मुद्रास्फीनि की दर भी काफी कम होने लगी (रेखाचित्र-2)।

व्यापार उदारीकरण

नब्बे के दशक की शुरुआत में भारत की विदर्शा त्यापार ध्यवस्था कड़ी विदर्शों की जकड़न में थी। खासतौर से आयात पर बेहद पार्बीदयाँ थीं। जून 1991 में उच्चतम कस्टम-दरे 300 प्रतिशत तक की छू रहीं थी। मात्रात्मक प्रतिबंध और आयात पर लाइसेंस होना आम बात थी। मन् 1991 के मध्य तक 80 प्रतिशत

आयात मदो पर किसी-न-किसी तरह की बदिशे थी। असाधारण उच्च शृन्क-दरो और व्यापक आयात बंदिशों के कारण वर्षों तक उत्पादकता और आर्थिक कार्यकृशलता

प्रभावित रही। ओद्योगिक उत्पादन बढाने, निर्यात के खिलाफ नीनिगत रुझान घटाने और अर्थव्यवस्था को खुला बनाने के लिए व्यापार नीति का उदारीकरण जरूरी था। नब्बे के दशक में व्यापार के उदारीकरण को दो मापकों—आयात शुल्क-

दरों और मात्रात्मक प्रतिबंधों के पैमानों से देखना जरूरी है। रेखाचित्र 3 में सन् 1990 और 1999 के शीर्प कस्टम शुल्क को दरशाया गया है। शीर्प शुल्क 300 प्रतिशत से घटाकर सन् 1991 से 1993 के बीच 85 प्रतिशत तक पर ले आया गया।

फिर जुलाई 1996 में इसे 42 प्रतिशत तक घटा दिया गया। इसके बाद राजस्व तिगयों के कारण कुछ कदम पीछे हटाए गए और सन् 1997 के अंत तक शीर्ष शुक्क बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया। मार्च 1999 के बजट में शीर्ष-दर को घटाकर

फिर से 40 प्रतिशत किया गया। मात्रात्मक प्रतिबंधों के उदारीकरण की दृष्टि से नब्बे के पूरे दशक में एक

ही दिशा में रुझान रहा। सन् 1991-92 के उदारीकरण के दौर में 5000 में से 3000 शुल्क-दरों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। इनमें कच्चा माल, मार्ध्यामक वस्तुएँ और पूँजी सामान से लाइसेंस हटाया गया। बाद के वर्षों में भी उदारीकरण का टोर जारी रहा। इस समय 12 प्रतिशत शुल्क लाइनें ही बंदिश के दायरे में हैं, जिनमें से अधिकतर उपभोक्ता वस्तुएँ है।

व्यापार के उदारीकरण की समीक्षा की दृष्टि से—(क) एकपक्षीय उदारीकरण की पहल, (ख) बहुपक्षीय व्यापार वचनबद्धताओ, (ग) क्षेत्रीय व्यापार सहयोग की पहल की भूमिकाओं पर गीर करना दिलचस्प होगा। शीर्ष कस्टम शुल्क-दरों के हिमाब में एकपक्षीय उदागिकरण वरीयता में सबसे ऊपर रहा है और बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय समझौतों की कोई खास भूमिका नहीं रही है।

बेशक साप्टा और भारत-श्रीलंका व्यापार समझौते जैसी क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के लिए अलग से विशिष्ट मदों के लिए शुल्क-दरें हैं, लेकिन इनसे शीर्ष कस्टम दर कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं हुई।

कुछ पर्यवंक्षकों का कहना है कि भारत की कस्टम शुल्क-दरे, विश्व व्यापार सगउन के पालन से पैदा होनेवाली अनुबंध-दरों से काफी कम हैं। कुछ घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों ने भारतीय दरों को अनुबंध-दरों के स्तर पर लाने की माँग भी उठाई हे, लेकिन घरेलू उद्योग के लिए इस तरह की माँग करनेवालों ने नब्बे के दशक में किए गए कस्टम शुल्क-दर सुधारों को ठीक से नहीं समझा है। सरकार ने बहुपर्शाय व्यापार ममझौतों में कुछ ही स्तरों पर अनुबंधों पर विचार करना उचित समझा, वह भी ऐसी जगह, जहाँ विभिन्न मुद्दों में कस्टम भी एक मुद्दा था। ऐसे में अनुबंध दरों से कस्टम-टरे कम होना कोई विसगति नहीं है।

मात्रात्मक प्रतिबंधों का मामला थोड़ा भिन्न हैं। यहाँ क्षेत्रीय और बहुपक्षीय दोनों ही तरह की पहल ने अहम भृमिका निभाई है। कई दशकों से भारत अपनी भृगनान-मनुलन की स्थिति को देखते हुए मात्रात्मक बंदिशों को जायज ठहराता आ रहा था, लेकिन सन् 1993 में यह स्थिति बहुत सुधर गई और ऐसे में आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को उचित ठहराना मुश्किल होने लगा।

मात्रात्मक प्रतिबंधों में उदारीकरण को सार्क के तहत की गई क्षेत्रीय सहयोग की पहल से काफी बढ़ावा मिला। सार्क के तहत साप्टा समझौते पर सन् 1993 में हस्ताक्षर किए गए। भारत ने सन् 1998 में सभी सार्क देशों के लिए आयात बदिशे हटाने की घोषणा कर दी। लिहाजा अभी तक 20,300 उत्पादों को लाइसेस बदिश से मक्त रखा गया है।

बाह्य ऋण-प्रबंधन

सन् 1991 के भुगतान-संतुलन सकट का मुख्य कारण यह भी था कि बाहरी

- अल्पकालिक बाहरी कर्जों की भरमार से बचा जाए। देश की बाहरी देनदारियों का पूर्ण जान हो।
- 2 वाम्तिवक प्रभावी विनिमय-दर को लगातार बढ़ने से रोका जाए।
- 3 अत्रास्तिवक विनिमय-दरों को समर्थन देने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में खर्च करने में बचा जाए।
- वंग्लृ वित्तीय क्षेत्र को मजबत बनाया जाए।
- 5 वेंकिंग प्रणाली को सट्टा बाजार की चपेट में लाने की सीमाएँ हों।
- 6 चाल् खाते के घाटे पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
- 7 पूँजी खाते की पिक्तिनीयता की ओर बढ़ा जाए।

अगर उक्त उपायों को भारत की दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि पृत्वीं प्रियार्ट संकट शुरू होन से पहले ही भारत ने ये सबक सीख लिये थे। मसन्दन—

- । अल्पकालिक ऋण मख्त नियत्रण में थे।
- 2 बाजार निर्धारित विनिमय-दर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया था।
- विदेशी मृद्रा भंडार का कुछ इस्तेमाल हुआ था, लेकिन दिसवर 1998 तक भंडारण स्तर 27 अरब डॉलर तक बढ़ा लिया गया था।
- मन् 1992 में 1997 के बीच वित्तीय क्षेत्र में सुधार के अनेक उपाय किए गए।
- 5 वितीय मंस्थाओं के शेयर और संपत्ति बाजार में प्रवेश पर सख्त नियत्रण एँ।
- 6 चालू खाते के घाटे को कावू में रखा गया।
- 7 विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेशकों को पूर्ण परिवर्तनीयता का लाभ मिला, मगर रेजीडेंट फर्मी और व्यक्तियों के लिए कडे पूँजी नियत्रण थे!

इन अनुकृत्न परिस्थितियों के बावजूद भारत बाहरी संकट की लहरों में अपने को पूरी तरह नहीं बचा पाया। अगस्त 1997 से जनवरी 1998 के बीच विनिमय बाजार को झटके लगे। बाजार पर माँग का दबाव भी रहा।

पूर्वी एशियाई संकट के प्रभाव से बचने के लिए मौद्रिक प्राधिकार ने जो उपाय किए, वे इस प्रकार है—

- बाजार को स्थिर करने के लिए रिजर्व बैंक ने व्यापक हस्तक्षेप किया।
- 2 8 प्रतिशत तक अवमृत्यन की विनिमय-दर में लचीलापन रखा गया।

मौद्रिक नीतियों को चरणबद्ध ढग से नियत्रित किया गया।

इन उपायों का जबरदस्त असर हुआ। मार्च 1998 तक विदेशी मुद्रा भड़ार 26 अरब डॉलर तक पहुँच गया और फॉरवर्ड टर्रे 10 प्रतिशत गिर गई।

मई से अगस्त 1998 के बीच भारतीय विदेशों मुद्रा बाजार फिर दबाब में आया, क्योंकि परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए

थे। एक वार फिर सरकार ने उक्त उपायों को आजमाया। एसर्जेंट इंडिया छ्रांड से भारत ने 4 अरब डॉलर जुटाए, जिससे बाजार स्थिर हो गया।

विनिमय-दर प्रबंधन : कुछ विकल्प और मुद्दे

विनिमय प्रबंधन के बारे में तीन महत्त्वपृण मुद्दों पर गोर करने की जरूरत है। पहला तो यह कि पिछले कुछ दशकों में अनरराष्ट्रीय प्रणाली किस तरह विकसित हुई? विकासशील देशों पर इसका अगर किस तरह हुआ ? ऐसे में भारत के सामने क्या विकल्प थे? इस दृष्टि में भारतीय अर्थव्ययस्था तीन में में कोड एक व्यवस्था अपना सकती थी—

- 1 ऐसी व्यवस्था, जिसमें मृद्रा बोर्ड हो, जो निजर्व मृद्रा से एक निशासित बराबरी बनाए रखे:
- 2 समायोजन योग्य व्यवस्था, जिसमें किसी एक मुद्रा की कुछ मुदाओ के समृह के हिमाब में दें निर्धारित हो।
- बाजार निर्धारित व्यवस्था, जिसमें रिजर्व वैंक के हस्तक्षेप की ग्रंजादश हो।

इनमें से पहली व्यवस्था ब्राजील, अर्जेटीना ओर कुछ अन्य लैटिन अमेरिकी देशों ने अपनाई। इसका खास कारण मुद्रास्फीति की बेहद उन्च दर को नियंत्रित करना था, लैकिन भारत में पिछले तीन दशकों में गुद्रास्फीर्ति 10 प्रतिणत में नीचे ही चल रही है। ऐसे में यह व्यवस्था अपनाने का कोई ऑफिन्स नहीं था।

भारत ने ममायोजन प्रणाली अपना रखी थी, लेकिन सन् 1991 के संकट के बाद यह प्रणाली त्यागने की माँग उठी। मरकार के फैमलो में देरी में पेग रेट और बाजार-दरों में अनर होने की संभायनाएँ थीं। पूँजी खाने की बढ़ती परिवर्तनीयता के

बाजार-दर्श में अनर होने की संभायनाएँ थीं। पूँजी खाने की बढ़ती पश्चितीयता के दीर में इस प्रणाली को सँभाले रखना संभव नहीं था। भारत ने सन् 1993 में बाजार-निर्धारित विनिमय-दर स्प्रयस्था अपनाई,

जिसमें विदेशी मुद्रा बाजार में माँग और आपृतिं के हिसाब से दरें तय होती हैं। बाजार में रिजर्व बैंक भी हिम्सेदार है, जो बाजार को स्थिग रखने की भूमिका निभाता है। रेग्ब्राचित्र-11 में भारत की न्यूनतम और वास्तविक विनिमय दरों की झलक दी गई है।

इस व्यवस्था से दो मुद्दे जुड़े हैं। एक यह कि रिजर्व बैक मूल बाजार-दरों आर अल्पकालिक परिवर्तनों से बदलनेवाली बाजार दरों में कैसे फर्क करे। यह काम चहत मुश्किल हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक की भूमिका कोई विज्ञान नहीं, बल्कि कता की है। समस्या तब बढ़ जाती है, जब राजनीतिक नेतृत्व अवमूल्यन में घाटा देखना है और मूल्य बढने से उसे कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलता।

र्तामरा प्रमृख मृद्दा बाजार-दरों की उन गतिविधियों से जुड़ा है, जो संतुलन पथ के आस-पाम होनेवाले मूल कारकों के कारण होती है। ये बाजार की भावना और हरकतों से चहुत नजदीकी से जुड़ी होती है। लगातार हस्तक्षेप की स्थिति मॅभाले रखना भी रिजर्व बैंक के लिए मुमिकम नहीं है।

ऐसे में सफल प्रबंधन के लिए तकनीकी कौशल, पारदर्शी नीति और भाग्य का साथ होने की जरूरत है। मूल तत्त्व यह है कि वाजार-निर्धारित व्यवस्था में राजनीतिक नेतृत्व और ग्जिर्व बेक—दोनों को ही विनिमय-दरों में लचीलापन लाने की कला सीखनी होगा।

अगले दशक की चुनौतियाँ

नब्बे के दशक की चुनौतियों के आईने में देखें तो नई सहस्राब्दी के पहले दशक की सबसे बड़ी चुनौनी लगातार वैश्विक होते वातावरण, भारतीय अर्थव्यवस्था की उन्पादकता और स्पर्धा-क्षमता बढ़ाना है। यह निर्यात बढ़ाने और सेवाक्षेत्र की मजबूर्ता के लिए भी जरूरी है। उच्च उत्पादक और स्पर्धा-क्षमता खुद ही पैदा नहीं हार्गा। उसके लिए दूसरी पीढ़ी के सुधारों को निरंतर अपनाने की जरूरत है। इसके लिए वित्तीय कानूनों, श्रम कानूनों, कंपनी सचालन, दीवालियापन संबंधी कानूनों, स्वामित्व, सेवाओं के वितरण, स्वास्थ्य, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे और शासन में स्थार की आवश्यकता है।

दूसरे, नए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वातावरण में विकासशील देशों को नए अनुशासन अपनानं होंगे। इसके अलावा पूँजी खाते में परिवर्तनीयता को बढ़ावा देना समय की माँग है। लेकिन ऐसा करते समय जोखिमों पर विशेष ध्यान रखना होगा।

विनिमय-दर व्यवस्था पर भी विशेष नजर रखनी होगी। चुनौती यह होगी कि लचीलेपन के प्रति बाजार जवाबदेह रहे। भारत अब व्यापार के उदारीकरण के गम्से में दूर दिखाई देता है। इसके लिए बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं और साप्टा, आसियान, एपेक आदि मचों पर सक्रिय भृमिका अपनानी होगी। प्रश्रियाउ स्नर पर कस्टम शुल्क दरो को लाने के लिए साल-दर-माल प्रयाम वरने होगे।

भारत को अमेरिकी आर्थिक मंदी के प्रभावों के लिए भी तेयार रहना चाहिए। पिछले 8 मालों में दुनिया के देशों को अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जवस्दान उफान से काफी फायदा मिला; लेकिन अब मंदी के नुकमान के लिए भी खुद को तैयार रखना चाहिए।

अंत में, भारत को नई टेक्नॉलॉजी आर बाजार क्षेत्रों की चुनीतियी में भी निपटना होंग। इंटरनेट ओर ई-कॉमर्स का इशारा इसी ओर है।

[सेटर फॉर बैंकिंग स्टडीज, सेट्रल बैंक ऑफ श्रीलका, कोलबा में 9 सितंबर, 1999 को दिया गया व्याख्यान।|

-	अंक्रेक	6.0	رب ج	80		6.2	73	9 /	78	8.0	09
ત્ય	जी.वी.प्. (उचीग)	7.5	7.2	£ [-		6.6	6 3	12.2	6.0	5.9	
ฑ์	3. निर्यात (अमेरिकी डॉलर) 114 9.0	114	0.6	1,1	33	20.2	18.4	203	56	45	-39
4	आयात (अमेरिको डॉलर)	9.4	144	-24.5		10.0	343	216	12.1	4.6	-7.1
ń	मुद्रास्मीति	67	103	13.7		8 4	10 9	77	6.4	4.00	6.9
69	विस्तृत मुद्रा (एम 3)	17.6	15.1	19.3		18.4	22 3	13.7	16.2	17.9	178
7.	सकल घरेल् बचत	20.6	24.3	22 9		218	242	24.1	24 4	23.1	ı
ထဲ	सकल घरेल निवेश	23.1	277	23.4		22 4	25 4	258	25 7	24.8	ı
6	चाल लेखा शेप	-2.1	-30	-03		-0.4	-10	9 1-	-1.2	7 3	60-
10	जी.एफ डी. (मेंद्र व राज्य,	87	9.2	6.8		~	69	64	6.2	71	8.4

	198590	199091	1991-92	198590 199091 199192 199293 199394 1994	199394	1994
	का औसत					
नियति विकास (अमेरिको डॉलर में)	11.4	9.0	-11	33	20.2	18.4
भागान विकास	94	14.4	-245	154	10.0	34.3

नियति विकास (अमेरिको डॉलर मे)	11.4	9.0	1	33	20.2	18.4	
आयात विकास	94	14.4	-245	15.4	10.0	34.3	
व्यापार घाटा (जी डी पी का प्रतिशत)	-2.9	50	-10	-21	-1.5	-27	
सैत्)	-21	-30	-03	- 3 7	-04	110	
		103	133	655	4,153	5,138	
8 TAN		(67)	(129)	(315)	(586)	(1,314)	
ख, पोर्टकोलियो (एफ आई. आई.							
	b	Ş	(†)	(244)	(3,567)	(3,824)	
	660'5	8,402	4,563	4,224	9,882	8,013	
	5,022	2,236	5,621	6,434	15,068	20,809	
में बहलाय	500	1,132	3 395	803	8,634	5,741	
विनिमय-दर् (स 'अमेरिको द्यालर)	() ()	17.9	2	200	27.	7 7	

भारतीय अर्थनीति *

[ै] सिनमा दंग अनाध का असिन है।

तालिका 3

सुधार-कार्यक्रम	शुरू होने	के शुरुआती	3 7	वर्षों में	औसत	आर्थिक	विकास
							_

	(प्रतिशत)
गरत (1991-92)	6.4
30 विकासशील देशों का औसत	2.2
केनिया (1981)	2.4
नाइजीरिया (1983)	2.1
नेक्सिको (1983)	06
গার্হলীন্ত (1983)	5.1
तुर्की (1980)	4 1

नोट कोप्टक में दिया गया वर्ष उम वर्ष को दरशाता है, जिसमे मुधार कार्यक्रम शुरू किए गए।

मेत भारत के लिए सा एम औ ! अन्य देशों के लिए—'रीस्ट्रक्चरिंग इकॉनॉमिक्स इन डिस्ट्रेस, पॉलिसी रिफार्म्म एंट द चर्ल्ड बैंक' में (थॉमम, खिच्चर, डैलामी तथा डी मैलो) 'मैक्लोइकॉनॉमिक परफॉरमेस अडर एडजस्टमेंट लेडिंग' (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1991)।

तालिका-4

भारत के आयान पर लगाए गए विभिन्न प्रकार के एन.टी.बी., 1996-97, 1998-99 (प्रशुल्क लाइनों की संख्या, 10 अंकीय*)

पैनल : ए

	1 4.1	996	141	997	1 4 19	98	1.4.19	999
	के अन्	सर	के अन्	सार	के अनु	सार	के अन्	सार
्न टो.बी.	लाइनों की	%	लाइनों की	%	लाइनों व	ती %	लाइनों क	ते %
का प्रकार	सख्या	अंश	संख्या	अंश	संख्या	अंश	संख्या	अंश
निषेधात्मक	59	0.6	59	06	59	0.6	59	0.6
प्रतिबंधिन	2,984	29.6	2,322	22.8	2,314	22 7	1,183	11 5
एकत्रित	127	1 2	129	1.3	129	13	37	0.4
एस आई एल	765	7.6	1,043	10 2	919	9.0	886	87
मुक्त	6,161	610	6,649	65.1	6,781	66 4	8,055	78.8
कुल	10,096	100 0	10,202	100 0	10,202	100.0	10,220	100 0

भारतीय व्यापार वर्गीकरण की हारमोनाइज्य प्रणाली के अनुसार। एच एस -आई टी सी आयात तथा नियात मदो का वर्गीकरण।

स्रोत 'डी भी एफ टी , वाणिण्य मंत्रालय।

पैनल बी

भुगतान संतुलन कवच के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन को अधिसूचित एन.टी.बी. की स्थिति

(1 4.1999 के अनुसार 8 अंकीय *)

विश्व व्यापार संगठन को अधिपूचित मदो की कुल मख्या	2,714
मुक्त सूची में मदों की कुल संख्या	1 298
प्रतिबंधित मर्दे	702
एस आई एल मदें	679
एकत्रित मदे	35
तालिका−5	

तालिका-5 बाहरी ऋण संकेतक

(प्रांतणत मे अनुपात)

वर्ष	1991	1992	1993	1995	1997	1999	
कुल ऋण/सकल घरेलृ उत्पाद	28 0	37 7	36 6	30 0	238	23 7	
ऋण भुगतान/चालू प्राप्तियाँ	35 3	30.2	27 S	26.2	212	18 0	
कम अवधि के ऋण/कुल ऋण	10 2	8.3	7.0	4.3	72	44	
कम अवधि के ऋग/भंडार	382.1	125.6	98.5	20 5	30 1	14 7	
ब्याज का भुगतान/चाल पाप्ति	15.5	13 0	12.5	97	73	80	

नोट स्टॉक ऑंकडे (कुल ऋण, कम अवधि तथा भडार) मर्वानत वर्षों मे 31 मार्च के लिए हैं। प्रेवाह ऑंकड़े (ऋण भुगतान, ब्याज, चालू प्राप्ति तथा सकल घरेलू उत्पाद) वित्त थर्म में, अर्थात् 1991 के ऑंकडे 1 अप्रैल, 1990 से 31 मिर्च, 1991 तक से संबंधित हैं।

^{*} भारतीय व्यापार वर्गीकरण की हारमोनाइज्य प्रणाली के अनुसार। एव, एस - आई टी.सी आयात तथ निर्मात मदो का वर्गीकरण।

तालिका 6 सर्वोच्च ऋणी पंद्रह देशों की अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक स्थिति, 1997

देशों की

11 मलेशिया

12 फिलीपींस

बँगलादेश

श्रीलंका

कुल बाहरी जी.एन.पी. कम अविध वस्तुओं एवं

म	पदानुसार	ऋण	की	से	सेवाओं के
	स्थिति		तुलना में ऋण	कुल ऋण	निर्यात में
					ऋण-सेवा
	(मिलिय	न अमेरिकी डॉर	नर) (प्रति	शित में अनुपात)	
7	ब्राजील	193663	24	19	57
2	मेक्सिको	149690	38	19	32
3	चीन	146697	17	21	9
4	कारिया	143373	33	38	9
5	इंडोनेशिया	136174	65 .	26	30
6	रूसी गणराज्य	125645	26	5	7
7	अर्जेंटीना	123221	39	15	59
8	भारत	94404	25	5	20
9	थाईलैंड	93416	63	37	15
10	तुकीं	91205	47	25	18

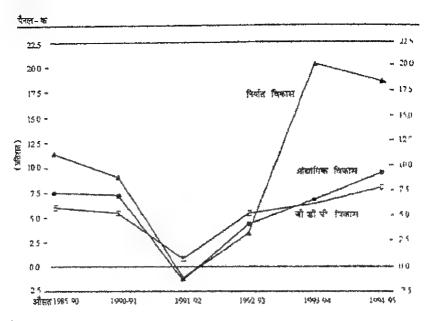
13 पोलैंड	39890	30	10	6
14 वेनेजुएला	35542	42	12	31
15 कोलंबिया	31777	35	18	27
दक्षिण एशिय	II.			
पाकिस्तान	29665	48	8	36

नोट : ऋम संख्या ३ से 15 पर कुल ऋण के आधार पर देशों को रखा गया है।

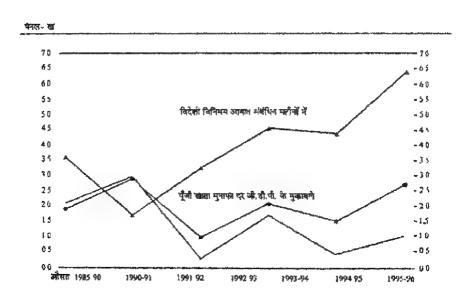
स्रोत . ग्लोबल डेक्लपमेट फाइनेंस, 1999, कट्टी टेबल, वर्ल्ड बैंक।

रेखाचित्र-1: 1991 के सकट स

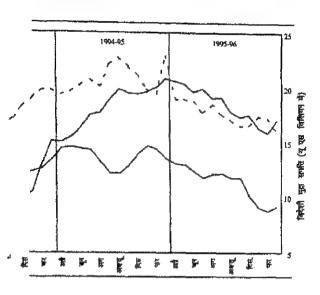
पैनल: क



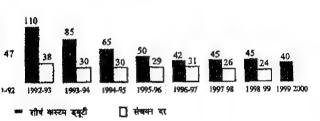
पैनल: ख



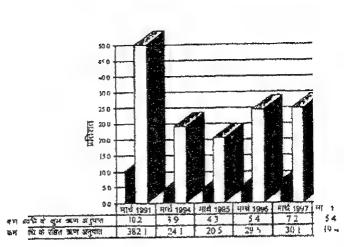
3, डब्ल्यू.पी.आई. और एफ.सी.ए. का माहवार क्रम



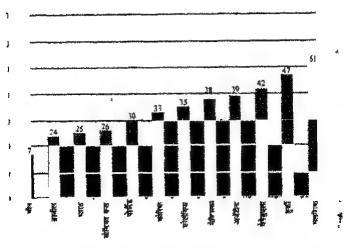
_म शुल्क तथा कस्टम शुल्क वसूली पर 1990-91 से 1999-2000



रेखाचित्र-4 . कम अवधि का ऋण-अनुपात

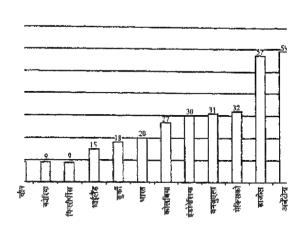


रेखाचित्र-5 : ऋण और जी.एन.पी. अनुपात, 1997 का अत तुलनात्मक अध्ययन

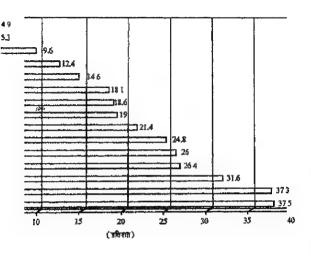


भारतीय अर्थनीति *

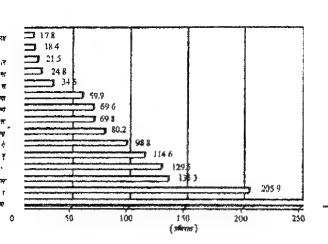
ऋण सेवा और वस्तु तथा सेवा निर्यात अनुपात का अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन



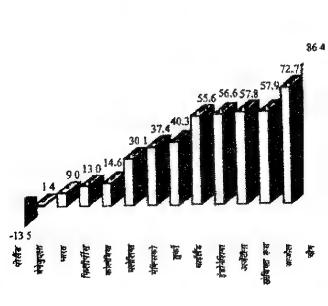
तरराष्ट्रीय तुलना—लघु अवधि और कुल बाहरी ऋण, 1997 का अनुपात



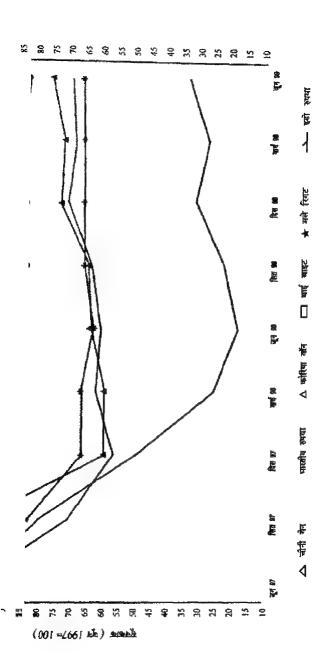
त्र-8 : लघु अवधि के ऋण और भंडारण का अनुपान, अत तुलना, 1997



त्र-9 : 1991 और 1997 के दौरान बाहरी ऋण स्टांक मे ब की अंतरराष्ट्रीय तुलना

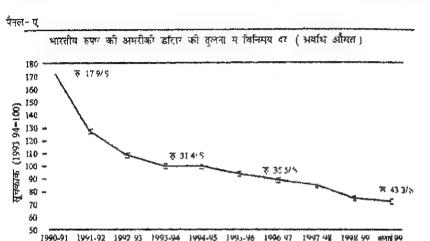


🗱 भारतीय अर्थनीति 🗱

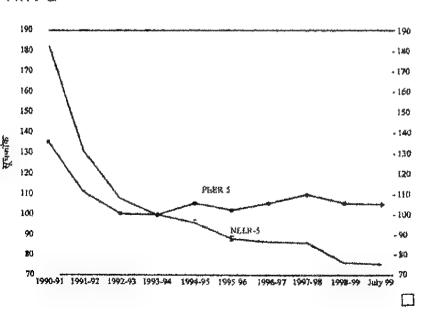


रेखाचित्र-11 : नब्बे के दशक में विनिमय-दर का रुझान

पैनल : क भारतीय रुपए की अमेरिकी डॉलर की तुलना में विनिमय दर (अवधि औसत)







विदेशी मुद्रा-बाजार का विकास तथा प्रबंधन

--बिमल जालान

वाहरी क्षेत्र के प्रबंधन से संबंधित नीतिगत मुद्दों, विशेषकर समुचित विमिन्नय टर प्रणानी, उपयुक्त हस्तक्षेप नीति तथा विदेशी मुद्रा विनिन्नय भड़ारण नीति एन दिनों तमाभ अंतरराष्ट्रीय मंचो, जैसे—अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व वैक, जी 20, जितीय स्थिरता मच तथा बैक ऑफ इटरनेशनल सेटलमेट्स सरीखे मंचो पर जारी विचार- विमर्श मे प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। भारत इन सभी वैचारिक प्रक्रियाओं में सेट्रल बैक के गवर्नरों और औद्योगिक तथा अन्य विकासशील देशों के विन मंत्रियों के साथ भाग लेता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमे विदेशी मुद्रा बाजारों के व्यवहार और उनके विनिम्य संबंधी पहलुओं के बारे में भी अनुभव प्राप्त हुए हे, लेकिन यह बहस सैद्धातिक और व्यावहारिक दृष्टि से अभी अधूरी ही द्रा अर्ड मुद्दों पर विश्वव्यापी स्तर पर सहमित कायम करने की प्रक्रिया जारी है। एम अध्ययन में विदेशी मुद्रा बाजार को प्रभावित करनेवाले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विश्वा जाएगा।

इनमें सबसे प्रमुख समुचित विनिमय-दर व्यवस्था का मुद्दा है, जिसपर माहित्य और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मचों पर भी व्यापक विचार-विमर्श हुआ है। इस सदर्भ में कथित असंभव तिकडी, यानी पूर्ण पूँजी लेखा परिवर्तनशीलता (सी.ए सी), मोहिक आजादी (मुद्रास्फीति नियत्रण के लिए) तथा एक स्थिर मुद्रा का जिक्र किया जा सकता है।

यदि मी ए.सी. को म्बीकार किया जाए तो सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार, मीद्रिक आजादी को छोड़कर मुद्रा बोर्ड के गठन का विकल्प आपके पास बचता है या फिर स्थिर मुद्रा लक्ष्य को छोड़कर विनिमय-दर को मुक्त रखा जाए, ताकि उस स्थिति में मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति नियत्रण के लक्ष्य के मुताबिक निर्देशित किया जा सके। इस परिदृश्य मे विनिमय-दर का महत्त्व तभी है, जब वह घरेलू मुद्रास्फीति का प्रभावित करती हो। ासद्धात रूप म, ऐसे में मुक्न प्रवाह या मुद्रा बोर्ड के गठन संबंधी दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी जग्ती है।

परंतु वास्तव में अधिकाश बैंकों द्वारा अपनाई नई नीति सैद्धातिक दृष्टिकोण

से भिन्न होती है। उदाहरण के तौर पर, अतरराष्ट्रीय मुद्रा कोय के हाल के अध्ययन के मुताबिक, औद्योगिक देशों समेत अधिकतर देशों द्वारा अपनाई गई व्यवस्था न तो

मुद्रा बोर्ड की है ओर न ही मुक्त प्रवाह की। ज्यादातर देशों ने लीच की स्थिति चुनी है, जो कई प्रकार की व्यवस्थाओं का मिश्रण है। कुल मिलाकर कुछेक देशों को छोडकर सभी ने किसी-न-किसी तरह 'फ्लोट' व्यवस्था से काम चलाया है।

ई सी बी के सदर्भ में हाल की अवधि से और जापान के मामले में भी पारपरिक तौर पर यही लागू होता है। अमेरिका ने भी यूरो अथवा येन के पक्ष में ऑभयान के

लिए ई सी बी या बी ओ. जे सहित हस्तक्षेप किया है।

इसलिए यह वास्तविकता है कि मुद्रा बोर्ड या 'फ्री फ्लोट' की विशुद्ध सैद्धातिक स्थिति की परवाह किए बगेर किसी भी मुद्रा का बाहरी मृल्य अधिकाश देशों तथा सेट्ल वेंकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

विभिन्न देश मनोवैज्ञानिक और कुछ हद तक वास्त्रीवक कारणो में विनिमय दर को लेकर चिंतित रहते हैं। दरअसल, मुद्रा की घटती कीमतों को लेकर छणनेवाली

दर को लेकर चिंतित रहते हैं। दरअसल, मुद्रा की घटती कीमतों को लेकर छणनेवाली खबरे—'न्यूनतम स्तर पर' या 'कमजोर' अथवा 'लुढ़कना' आदि किसी भी देश की मुद्रा की स्थिरता पर नकारात्मक असर डालते हैं। आम आदमी इस प्रकार का

बातों से प्रभावित होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने देश की मुद्रा या अर्थव्यवस्था को कमजोर या गिरती हुई नहीं देखना चाहता। ऐसे में बेहतर होगा कि विनिमय-दरों में आनेवाले उतार-चढाव के बारे में बताने के लिए ऐसी नई शब्दावनी तैयार

दरों में आनेवाले उतार-चढ़ाव के बारे में बताने के लिए ऐसी नई शब्दावली तैयार की जाए, जो कम हो। विनिमय दर को लेकर व्यक्त चिंताएँ कुछ हद नक वाम्तविक भी हैं, जैसा पूर्वी एशिया, रूम और अन्य देशों में हुआ। मुद्रा के मुल्य में तंजी में आए परिवर्तन

न्या प्राचा, रून और अन्य दशा न हुआ। मुद्रा क मृत्य म तथा न आए पारवतन वास्तविक अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। जहाँ एक ओर इसमे आई तेजी में निर्यातक प्रभावित होते हैं, वहीं मृत्य में तेज गिरावट होने से बैंकों के बरबाद हाने या दीवालिया होने की आशंका बढ़ जाती है।

हाल के वर्षों में विनिम्य-दर के उतार-चढ़ाव तय करने में व्यापार घाटे तथा आर्थिक विकास की बजाय पूँजी-प्रवाह का महत्त्व बढ़ा है। उदाहरण के लिए, सबसे अधिक व्यापार घाटेवाले देश अमेरिका की मुद्रा आज सबसे मजबूत है।

सबसे अधिक व्यापार घाटेवाले देश अमेरिका की मुद्रा आज सबसे मजबूत है। उधर हाल के वर्षों तक व्यापार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करनेवाले यूरोप की मुद्रा अधिक कम जोर मुद्राओं में से एक है। दुनिया भर में, चाहे वह पूर्वी एशिया हो, न्यूजीलेंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया—सभी जगह यही दोहराया जा रहा है।

विनिमय-दर को प्रभावित करनेवाला 'सकल' पूँजी-प्रवाह किसी भी दिन विशेष में होनेवाल कुल प्रवाह से कई गुना अधिक हो सकता है और विदेशी व्यापार या आर्थिक विकास की तुलना में यह कही अधिक संवेदनशील भी है। एमी स्थित में भीड़ की प्रवृत्ति अपरिहार्य है। दरअसल, प्रत्येक डीलर अकेले गलत होने की बजाय सामृहिक तौर पर गलत होने को उचित मानता है। इस स्थिति में जमा हाल के अनुभव से स्पष्ट है कि सेंट्रल बैंक को किसी-न-किसी प्रकार हम्तक्षेप करना होगा। हालाँकि हस्तक्षेप का दर्जा एक सेंट्रल बैंक में दूसरे से भिन्न हो सकता है, परन् विनिमय-दरों के संबंध में चिंता ऐसा तथ्य है, जिससे आनेवाले कुछ समय नक तो हमारा सामना होना तय है।

भारत किसी निश्चित दर का लक्ष्य निर्धारित किए बगैर ही 'फ्लोटिंग' व्यवस्था में काम चला रहा है। रिजर्व चैंक हर रोज के उतार-चढ़ाव पर नजर रख रहा है। त्रमांग् बाजार फिलहाल सुदृढ़ नहीं हैं और रिजर्व बैंक की घोषित नीति को समय-समय पर उभरनेवाले अस्थायी माँग-आपूर्ति असतुलन का मुकाबला करना पडता है। उदाहरण के लिए, हाल की अवधि में तेल की कीमतों में असाधारण रूप में आई नेजों के बाद रिजर्व बैंक ऋण संबंधी जरूरतों के अलावा आई ओ सी. की तेल- आयात आवश्यकताओं से सीधे निबट रहा है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना होता है कि मुद्रा की तरलता का संकट न हो और अफवाह या आशका से मुद्रा बाजार प्रभावित न हो।

टरअसल, विनिमय-बाजारों के वास्तविक अनुभव को ध्यान में रखते हुए मी ए भी, मीड्रिक आजादी तथा विनिमय-दर स्थिरता की 'नापाक' तिकड़ी की सद्धांतक स्थित में भी बदलाव हुआ है। कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अब सी.ए सी को स्थाया या अस्थायी रूप से छोड़ने के पक्ष में हैं। कुछ अन्य मध्यवर्ती व्यवस्था का ममर्थन करते हैं।

एक अन्य मुद्दा विनिमय-दर के प्रबंधन से संबंधित है। ऐसे में एक स्वार्भावक प्रश्न यह उठता है कि 'नॉमिनल' दरों की निगरानी की जाए या आर इं.ई आर की? प्रतियोगी दृष्टिकोण से तो आर ई.ई आर की ही निगरानी की जानी चाहिए, क्योंकि यह वास्तविक रूप में व्यापारिक भागीदारों और मुद्रा के बाहरों मृत्य में आए बदलाव को दरशाता है। अलबता, कम अवधि की निगरानी के लिए यह सही नहीं हैं—क्योंकि 'नॉमिनल' दरें काफी संवेदनशील होती हैं और

खबरों में भी छाई रहती है। (उदाहरण के लिए—डॉलर-यूगे या डॉलर येन क व्यवहार के सबध में शायद ही कोई इन मुद्राओं की वास्तविक दर्ग के वारे में वान करता हो), यानी कम अवधि के सदर्भ में 'नॉमिनल' दर की निगगर्न करने के

अलावा कोई और चारा नहीं है।

डीलरों की टिप्पणियों डॉलर पर ही टिकी हाती हैं। शायद ही आपने कभी सुना हा कि पाउंड की कीमत यूरो या येन की तुलना में अपने अधिकतम स्तर तक बढ़ पई है। हम हमेशा येन, यूरो या पाउड़ की डॉलर के आईने में ही ऑकने हैं। निश्चित

सभी प्रमुख मुद्राओं के सदर्भ में ऑका जाना चाहिए परंत् खबरों के शार्यक या

हालाँकि इस बात से मभी सहमत हैं कि किमी भी मुद्रा की कीमत का

रूप से इसके पीछे खडा कारण मोजूद है। क्योंकि व्यापार में डॉलर कपी मृहा का ही ज्यादा प्रयोग होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सेटल बैंक पसद करे या नहीं, मगर

ज्यादा प्रयाग हाता है। इसका अथ यह हुआ कि सदल बक पसद कर या नहीं, मगर उन्हें अमेरिकी डॉलर पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा।

विनिमय-बाजारों मे 'स्थिरता' और 'अस्थिरता' का मृद्दा भी अहम है।

सिद्धांत रूप में पूँजी- प्रवाह मजवृत होने की स्थित में विनिमय-दरों के बटने की तथा कमजोर होने पर दरों के घटने की अपेक्षा की जाती है, परंतु दुर्भाग्यवश व्यवहार रूप में अनिश्चितता या उथल-पृथल के दौर में सेंट्रल बैंकों के पास यह विकल्प नहीं रहता, क्योंकि बाजार का व्यवहार दोनों दिशाओं में एक समान नहीं होता।

विदेशी मुद्रा- प्रबंधन पर जारी विचार-विमर्श के दौरान विदेशी मुद्रा भड़ार के प्रबंधन के लिए समृचित नीति का मुद्दा भी काफो महत्वपूर्ण है। 'फ्री फनोट' व्यवस्था के तहत यह तर्क दिया जा सकता है कि भंडारण की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ देश, जिनमें मौद्रिक नीति केवल मुद्रास्फीति नियत्रण के एकमात्र लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करती है, वास्तव में भंडारण ही नहीं करते। अलबना, पूँजी-प्रवाह द्वारा प्रेरित अनिश्चितता को देखते हुए अब उभरते बाजारों में 'पर्याप्त'

भडार रखने के बारे में मर्वसम्मित तैयार हो रही है। 'गिदौती नियम' (Guidotti's Rule) के अनुसार, जिसका उल्लेख एलन ग्रीनस्पैन ने भी किया है, समुचित भड़ार इतना हो कि उससे एक साल के आयात तथा पूँजी -प्रवाह आवश्यकताओं को पृग किया जा सके।

भारत में, हम भंडार-प्रबंधन के क्षेत्र में तरलता तथा आयात जरूरतों का ध्यान रखते हैं। यही कारण है कि हमने पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपने भंडार में 10 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि की है और नेल की कैंची कीमतो के लिहाज य किए हैं। अब हमारा भंडार लंबे समय तक तेल के बोझ तथा पूँजी-शानवाले उतार-चढावों की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त है। हमने ब क अपने ऋणों को घटाने की दिशा में काफी सोच-विचारकर तैयार ति पर अमल किया तथा यह भी सुनिश्चित किया कि अनिवासी भारतीयो अर्वाध की जमा राशि, जो एफ सी.एन आर.बी. खातों में रखी जाती है, म्बीकार करनेवाले वेंको की विदेशी परिसपितयों के मुकाबले की हो। 1 दिसवर, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित इक्कीसवी एशिया-प्रशांत उद्याटन भाषण।

भारतीय अर्थव्यवस्था और भृमंडलीकरण

उमा कपिला

क्या है भूमंडलीकरण?

हम प्रौद्योगिकों के ऐसे युग म भी रहे हैं, जन्में समय और रधान की द्वियाँ सिमट गई हे और परी दिनया एक गाँव में वर्न्सन हा गई ल्याना है। धमदलांकरण

की प्रक्रिया ने विभिन्न देशों की अगने रक्षा फन्म में बादर आने और सेंघ दनिया

के साथ कदम- सं-कदम मिलाकर चलने के ियर मजबर किया है, तारिक एक नड

विश्व - व्यवस्था कायम हो सकै।

परिवहन और सचार के क्षेत्र में हुई तकनात्की क्रार्टि में भागोरिक दरियाँ लॉबने का समय और लागत बहुत कम हो गई है। इस रफ्तार की अध हम देखते ह

तो एहसास होता है कि हम विकास के एक नण दार में प्रतेश कर चुके हैं, दुनिया के देश बहुत निकट तथा एक दूसरे पर परस्थर निधर होते जा रहे हैं।

भुमडलीकरण की इस प्रक्रिया में अतरगार्टीय व्यापार का जबादात विस्तार हुआ है। विश्व भर में निर्यात मन् 1950 के 610 लाख अमेरिकी डॉलर से बढ़कर

सन् 1970 के 31 करोड़ 50 लाख डॉलर ऑर भन् 1990 में ३ अरब 44 करोड़ 70 लाख डॉलर तक पहुँच गया। दिलचस्य बान यह है कि स्थापार में यह मुद्धि विशव

में कुल उत्पादन -वृद्धि से अधिक रही। विश्व के सकल घोल उत्पाद में निर्यात का हिस्सा सन् 1950 के 6 प्रतिशत में बढ़कर मन् 1992 में 16 प्रतिशत हो गया।

अंतरराष्ट्रीय निवेश- प्रवाह में भी इतनी ही आश्चर्यबनक बहोत्सी हुएं। तुनिया की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष वित्तीय निवेश कभी सन् 1960 में 6 करोड़ 80 लाग्न डॉलर

था, जो सन् 1992 में 1 अरब 94 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुँच गया। ये आँकड़े वास्तव में हैरत में डालनेवाले हैं और जिन देशों ने खुद को विश्व अर्थव्यवस्था

से सफलतापूर्वक जोड़ लिया, वहाँ का जीवनस्तर और नौकरी के अवसरी में काफी बढ़ोतरी हुई। ऐसे में भूमंडलीकरण के फायदों को नजरंदाज नहीं किया जा सकता।

। भारतीय अर्चनीनि 🛎

र्लोकन यह भी सच है कि भूमडलीकरण के लाभ सभी देशों को समान रूप से नहीं मिल पाए हैं। असमानताएँ और विभेद भी एकदम स्पष्ट हैं। कुछ को इस

पिक्रिया से बहुत फायदे हुए, कुछ को कम लाभ मिले और कुछ हाशिये पर ही रहे, लेकिन अगर यह सोच लिया जाए कि फायदों के इस असमान वितरण की वजह से

पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था लाँट आएगी तो यह मानवीय इतिहास की इस घटना का गलत आकलन होगा। भूमडलीकरण की प्रक्रिया क्षेत्रीय साम्राज्य के विस्तार

की आकाक्षा से प्रेरित नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ऐसी शक्ति और गति पनप गति है, जो मानव-मन मे अपने से आगे चलनेवालों को पकड़ने और नए

मोरचो पर विजय-पताका फहराने की कुदरती इच्छाशक्ति पैदा कर रही है। इसी का नताजा है कि हम सिम्मलन की एक नई प्रक्रिया का उदय होते देख रहे हैं।

आविद हुसैन का कहना है—भूमंडलीकरण को स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं हे कि हम अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीय बैंकों या वित्तीय संस्थानों से संचालित दवावों, व्यवस्थाओं और जोड़-तोड़ के सामने घुटने टेक दें, जिससे

हमारी चंरल् अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाए। भूमंडलीकरण से जुड़ी असमानताओ, विभेदो, शोपण और अन्य अवांछित बातों पर पैनी नजर रखनी होगी तथा निरतर राजनीतिक प्रयासों द्वारा इन बातों से निपटना होगा, क्योंकि कोई राष्ट्र राज्य इन

नाजुक मुद्दों की ओर से ऑखें नहीं मूँद सकता। राष्ट्र राज्य की अवधारणा से प्रभावित बहुपक्षीय ढाँचे से भूमंडलीकरण के दुष्प्रभावों से निपटा जा सकता है।

प्रभावतं बहुपक्षाय ढाच सं भूमङलाकरण के दुष्प्रभावां सं निपटा जो सकता है। विकस्पित देशों को भूमंडलीकरण से कुल मिलाकर फायदे ही हुए है। इसका कारण यह है कि इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी और वे नई प्रौद्योगिकी

सं उपजी नई परिस्थितियों और अवसरों का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार थे। उन्होंने परिवहन और संचार के क्षेत्र में हुई प्रगतियों का भरपूर लाभ उठाया। विकस्तिन देशों को भूमंडलीकरण से हुए फायदों को देखते हुए विकासशील देशों के मन में अपने हितों को लेकर शंका पैदा होने लगी, लेकिन सरहदों को अब बद

के मन में अपने हितों को लेकर शंका पैदा होने लगी, लेकिन सरहदों को अब बद नहीं रखा जा सकता और विचारों का प्रवाह रोका नहीं जा सकता। हम भूमंडलीकरण में जुड़ी आशंकाओं के कारण कदम पीछे नहीं खींच सकते। हमें आगे बढ़ने के

लिए तैयार होना होगा। इसके फायदे उठाने होंगे और मुनाफों को दूसरों के साथ मिलकर बाँटना होगा।

भूमंडलीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था

ऐसा नहीं है कि बाहरी ताकतों का सामना भारतीय नहीं कर सकते या

धारणा में विश्वास रखते हैं वे वास्तव मे भारत को ताकत मे परिचित नहीं है। भारत के पास दुनिया की बेहतरीन ताकत से मुकावला करने के लिए प्रतिभा, समाधन और बौद्धिक क्षमता है। यह सही है कि भारतीय दूसरों से बेहतर नहीं है, मगर इतना तय है कि वे हर दृष्टि से उनके वराबर जरूर है।

विदेशी हमें खली प्रतियोगिता के दार में आसाना से पछाड़ दंग। जा लीन इस

विश्वास में कमी होने का एक कारण लंबे समय तक जारी लाइसेंस राज के कारण तेयार हमारी मानसिक स्थिति हो सकतो है, जिसने हमें मुक्त बाजार की परिस्थितियों से दूर रखा और हमारे उद्योगों को अत्यधिक स्पृथित माटोल प्रदान किया। दरअसल, यदि हम असाधारण उद्यम क्षमतावाल अपने उद्योग प्रगनों की समीक्षा करे तो हमे सहज ही विश्वास हो जाएगा कि प्रनियोगिता मे हम टिक यकते है। सॉफ्टवेयर जैसी नई प्रौद्योगिकी के मामले मे तो हालान यह ह कि जापान दो या अमेरिका, हर जगह भारतीय विशेषज्ञ की ही तलाश रहनी है, तो हमार्ग शमता का जीता-जागता प्रमाण है, यानी यह विचार सगम्पर गलत है कि प्रनियागिता का मकावला भारतीय मही कर सकते।

भारतीय निर्माण प्रतिभा पर भी किसी ने भ्रेंगृती नहीं उठाई, 'संनृ भारतीय उत्पाद प्राय: दोषपूर्ण पाए गए या फिर वे विश्वस्तरीय नहीं रहे हैं । इसका कारण भी सरकार की मख्त नीतियाँ रही हैं, जिनके चलते भारतीय उद्यमी को अत्याभूनिक प्रौद्योगिकी, उपकरण और निवेश के क्षेत्र में चुनाव की आवार्त नहीं थी। इस बात के पर्याप्त सबूत मौजृद हैं कि जब सरकार ने मुक्त बाजार के पक्ष में नीतियों में बदलाव किया तो भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की टक्कर के रहे। दरअसल, मृल समस्या आर्थिक दौर के कारण थी, न कि भारतीय उद्यापयों के कारण ऐसा था।

वास्तव में प्रतियोगिता भूमंडलीकरण का मूल तत्व है। भूगंडलीकरण के लाभ उस ही मिलते हैं, जो इस प्रतियोगिता में सफल होता है। किमी भी उद्योग के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतरना ओलिपक खेलों में भाग लेने जैमा है। ओलिपक में प्रतियोगियों को न सिर्फ अपने, बल्कि दूसरों के भी रिकॉर्ड तोडने होते हैं।

जैसा आबिद हुसेन का कहना है. खेलने के लिए खिलाड़ियों को ईमानदारी से नियमों का पालन करना होता है। यह देखना रेफरी का काम है कि खेल के नियमों का पालन पूरी तरह किया जा रहा है या नहीं। भारत को इस बात पर जीर देने का पूरा अधिकार है कि सभी के लिए प्रतियोगिता के समान अवसर उपलब्ध हो। यदि ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से यह सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी के लिए एक जैसी पिरिस्थितियाँ सुनिश्चित करे। यह माना जा सकता है कि भारत जमें देश को अपने खिलाड़ी तैयार करने के लिए समय चाहिए, ताकि उन देशों से स्पर्धा करने के लिए वे तैयार हो सके, जिन्हें किसी खेल विशेष में पहले से ही विशयजता प्राप्त है, लेकिन संग्कार को इस तैयारी के लिए अनावश्यक रूप से अधिक समय नहीं लेना चाहिए।

हमें यह भी मुनिश्चित करना होगा कि हमारे उद्यमियों की पहुँच अत्याधुनिक प्राद्योगिकों नक हो, क्योंकि यही अधिक उत्पादकता को ऊर्जा प्रदान करता है। यदि हम ऐसा नहीं करने तो इसका अर्थ यह होगा कि वह मैच शुरू होने से पहले ही हम उससे हार गए।

भूमंडलीकरण ओर इसके विकास के कुछ पहलुओ का विरोध विकासशील देशों तक ही मीमिन नहीं है। विकसित देशों में भी ऐसे कुछ दबाव समूह या लॉबी मिक्रय हैं, जो इस आधार पर भूमडलीकरण का विरोध कर रहे हैं कि गरीब राष्ट्रों के साथ व्यापार बढ़ाने से उनके अपने यहाँ का श्रीमक वर्ग कमजोर होगा तथा नौकरियों आर निवेशों के अवसरों में कमी होगी, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यदि अमेरिका में श्रीमकों की नौकरियों छूटी हैं तो इसका कारण विकासशील टंशों के साथ व्यापार में बढ़ावा नहीं, बिल्क यह है कि इन श्रीमकों ने अन्य उद्योगों के मुकाबले उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक नए कौशल नहीं सीखे। दरअसल, कारण व्यापार नहीं, बिल्क आधुनिक सूचना-आधारित तकनीकी विधियों से युक्त निर्माण-प्रक्रिया है, जिसके तहत अकुशल श्रीमकों का स्थान कंप्यूटरों ने ले लिया, जिनके लिए कुशल श्रीमकों की जरूरत होती है।

अलबता, विकसित देशो द्वारा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए बाल-श्रम और पर्यावरण के संबंध में जाहिर की गई चिंताओं का विरोध नहीं किया जाना चाहिए।

क्या पूर्वी एशियाई संकट का कारण भूमंडलीकरण था?

दक्षिण-पूर्वी एशिया के वित्तीय संकट को भी भूमंडलीकरण से उपजे मकरों में से एक माना जा रहा है। इस संकट को इस धारणा के प्रमाण के रूप में पेश किया जा रहा है कि मौजूदा खराब हालत के लिए भूमंडलीकरण ही दोषी है, जिसने मदद करने की बजाय विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को चौपट कर दिया। आबिद हुसँन का कहना है कि यह दोषारोपण बहुत ही सामान्य है। दरअसल, दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के ढहने और भूमंडलीकरण के बीच ऐसे किसी सपर्क की पुष्टि नहीं की जा सकी है। मच तो यह है कि भूमडर्लीकरण ने प्रौद्योगिकी और निवेश-प्रवाह को बढ़ाने तथा दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के बाजारो

को खोले जाने की दिशा में काफी हद तक सहयोग किया है। यही कारण है कि अन्य कोई भी देश-समृह उतनी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया है, जितनी इतनी

कम अवधि में दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों ने की है। भृमडलीकरण में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को मिले फायदों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नथ्य आर

आंकड़े उपलब्ध हैं। क्या कोई इस तथ्य में इनकार कर सकता है कि कोरिया तथा अन्य 'टाइगर' अर्थव्यवस्थावाले देशों ने भूमंडलीकरण की बदौलत ही विकास की ऊँची रफ्तार दर्ज की।

क्या इस बात पर किसी को कोई सदेह हो सकता है कि टन देशा की अध

व्यवस्थाओं की प्रगति में आए अधिकाश तकनीकी मुधार अभेरिका, जापान आर जर्मनी जैसे देशों से हुए प्रौद्योगिकी-प्रवाह को वजह से ही सधव हो सके हैं, जो दरअसल भूमडलीकरण की ताकतों के कारण हो सका? दक्षिण पूर्वी ए्रीशयाद सकट विश्व अर्थव्यवस्था के साथ घनिष्ठ जुड़ात्र की वजह से नहीं, चल्कि प्रांतस्पर्धी बाजारों में आए बिखराव की उपज था आर इस बिखरात्र ने संसाधनों के आवंदन में भ्रष्टाचार तथा अकुशलता को आमंत्रण दिया, जिसने आर्थिक कुशलता तथा प्रतिस्प्रधा की राह में बाधा डाली और निवंश की उत्पादकता को भी कम किया। इस मंकट के कारण गेर-उत्पादक गतिविधियों में आवश्यकता से अधिक निवंश की प्रज़ित को बढ़ावा मिला, विदेशी पूँजी-प्रवाह को गलत दिशा दी गई तथा साथ ही 'हांट मनी' पर अत्यधिक भरोना करने से कई अन्य समस्यार्ण भी खढ़ी हई।

अकसर कहा जाता है कि भूमडलीकरण के फायदे लेने नथा अपर्गा अर्थव्यवस्था और अपनी जनता के जीवन स्तर में सुधार के लिए भारत को रणनींगि तैयार करनी होगी।

आर्थिक सुधारों की अधूरी कार्यसूची (एजेंडे) को पूरा करना

इसके लिए सबसे पहले आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को नए सिर से गति देने के साथ अधूने एजेंडे को पूरा करना होगा। भारत दौड़ में पिछड़ रहा है, क्योंकि उसने सुधारों की प्रगति की रफ्तार धीमी कर दी है। पूँजी तथा उपभोक्ता वस्तुओं में संबंधित विवाद को खत्म करना होगा। साथ ही उद्यमियों को प्रौद्योगिकी, उत्पाद एवं बाजारों के चयन के मामले में अधिक आजादी देनी होगी। मजबूत बाजार के

लिए सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है, परंतु यह हस्तक्षेप बाजार की आजार्टी को

प्रतिबंधित करने के लिए नहां होना चाहिए। सरकार को अन्य दशों के साथ प्रौद्यंगिकी आदान प्रदान के स्तर पर संबंध तथा गठबंधन बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रगति के लिए उपयुक्त नीतियाँ सुनिश्चित करने नथा आर्थिक मृद्दों पर खुलापन रखने की जरूरत है, ताकि भूमडलीकरण के अधिकतम लाभ बटोरे जा सकें।

कृषि को भी उद्योग के समान दर्जा

दमरे. इस बात का कोई कारण नहीं है कि कृषि को उद्योग से भिन्न दर्जी दिया जाए। भारत में कृषि को विकास के लिए अधिक आजादी दी जानी चाहिए थीं. ताकि किम्पानों को चयन के स्तर पर छुट मिले, परंतु देश में कृषि ही जंजीरों में जकड़ी हुई है। किम्पानों को मनपसंद फसल बोने की आजादी नहीं है। वे अपनी उपज स्वेन्छानृमार बेच नहीं सकते। बेहतर कीमत पाने के लिए वे अपना उत्पाद अतरराष्ट्रीय बाजार में भी नहीं बेच सकते। ऐसे में सवाल उठता है कि किसानों को उनके अधिकारों से वंचित क्यों किया जा रहा है? जब उद्योग में आयात-निर्यात सबधी प्रतिबंध कम हो रहे हैं तो कृषि के क्षेत्र में भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यह क्षेत्र मृक्त व्यापार ऑर भूमंडलीकरण के लाभों से वचित है। यदि भारत में कृषि का यहीं हाल रहा तो हम इससे जुड़े कई उत्पादों के मामले में भूमंडलीकरण से होनेवाले लाभ नहीं ले पाएँगे। अब समय आ गया है कि भूमि सुधार, कृषि का बड़े स्तर पर आधुनिकांकरण आदि मुद्दों पर प्राथमिकता से विचार किया जाए। ऐसा करने से भारतीय कृषि क्षेत्र अतरराष्ट्रीय बाजार में विजेता बनकर उभरेगा और भूमंडलीकरण के अधिक फायदे प्राप्त किए जा सकेगे। हमें कृषि से जुड़े व्यावसायिकों को विश्व अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने की छूट देनी चाहिए।

अनुसंघान तथा विकास के लिए वैज्ञानिक आधार सुदृढ़ करना

एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य देश में अनुसधान तथा विकास के वैज्ञानिक आधार को सुदृढ़ बनाने का है, क्योंकि भविष्य की प्रगति के लिए विज्ञान तथा प्रोंद्योगिकी हो महत्त्वपूर्ण हैं। मौजूदा समय में हथियार, सेना या परमाणु बम किसी देश की ताकत का प्रतीक नहीं हैं। दरअसल, ज्ञान तथा सूचना ही वे ताकत हैं, जो लोगों को उनके जीवन की चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाते हैं। जो शासन-नन्न विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास पर पर्याप्त संसाधनों का निवंश नहीं करता, वह इनपर भरोसा रखनेवाले दूसरे देशो से पिछड जाता है। यह जाना-माना तथ्य है कि साक्षर आवादी किसी भी देश की प्रगति के न्तिए अपिरहार्य है। यदि आवादी का बड़ा हिस्सा शिक्षा के दायरे में बाहर रहता है तो उस स्थिति में विज्ञान आर प्रौद्योगिकी के लाभ समाज के एक वर्ग तक ही सीमित होकर रह जाते है।

हमें शामन -व्यवस्था में पार्टाशंता के महत्त्व का भी स्वीकार करना होगा।

शासन में पारदर्शिता

की गह में रुकावटें भी खड़ी करता है।

लोगों को विश्वास में लेन के उपाय करने वाहिए। व्यापार तथा विकासात्मक गतिविधियाँ खत्म की जाएँ। शीघ लेन देन स्निश्चित करने के लिए व्यवस्था का गतिशील बनाया जाना चाहिए। दरअसल, शासन में अपार्ग्दार्शना और लंग देन म देरी से एक ऐसा दुष्वक्र जन्म लेता है। जो भ्रष्टाचार और भाई भनी जाबाद आदि का बढ़ावा तो देता ही है, माथ ही- माथ घंग्ल तथा अतरगर्शय बाजरों में पातम्पधा

गापनीयता की प्रणाली समाप्त होनी चाहिए तथा विकास की प्रक्रिया में भगोतार

विश्व व्यापार संगठन में भारत की कारगर भूगिका

एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य धार्पार्छीय सगठनो में स्धार तथा पन्ने लोकताहिक बनाने के लिए मंच नैयार करने में सर्बाधत है। भूमंडलांकृत विश्व में न्याय तथा

नियमानुसार लेन देन सुनिश्वित करने के लिए अवस्मार्थाय नियम व संस्थान होन

चाहिए। इनके बगैर नई व्यवस्था के लाभ हम तक नहीं पहुँचंगे आंग हम स्थायी रूप में हाशिये पर पड़े रहेंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था के मार्ग प्रदर्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम होने जरूरी हैं। विश्व व्यापार मगटन की मदम्यना तथा इसमें प्रभावी भागीदारी में ही वह मुनिश्चित किया जा सकता है।

भारत को विश्व व्यापार संगठन का प्रभावी सदस्य बनकर अपने तथा अन्य विकासशील देशों के हितों की यकालत जमकर करनी चाहिए। निग्यक्ष वैश्विक नियमों. विनियमनो तथा सुरक्षा उपायों के निर्धारण में भी भारत की महत्वपूर्ण

भूमिका निभानी चाहिए, ताकि प्रतिकृत व्यवहार को रोका जा सके। हमें केवल विकसित देशो द्वारा प्रस्तृत मुद्दों पर प्रतिक्रिया ध्यक्त करने तक ही सामित न रहकर स्वयं अपने स्तर पर सिक्रय रहना चाहिए।

इसी प्रकार हमे क्षेत्रीय व्यापारिक समुहों के माथ प्रगाढ संबंध विकासत करने की नीति तैयार करनी चाहिए, ताकि हम उनसे प्राप्त होनेवाले लागी में वेचित न रह जाएँ। दरअसल, मुक्त वैश्विक व्यापार प्रणाली के तहत इस प्रकार की क्षेत्रीय

व्यवस्थाः स्वागनयाग्य है। स्थ्यांतर में ये मुक्त व्यापार को नुकसान पहुँचा सकते हैं या उन्हें समाप्त कर सकते हैं। इसिलए जहाँ कहीं भी ऐसे समूह मुक्त और खुले व्यापार की गह में बाधा बने, वहाँ क्षेत्रीय व्यवस्था के मुकाबले वैश्विक नियमों की पमुखता स्विश्चित करनी चाहिए। दिक्षणी-एशियाई वैश्विक व्यवस्था कायम करने का भारत का प्रयास स्वागतयांग्य है, लेकिन ऐसा वैश्विक व्यवस्था के प्रति हमारी वस्तवद्या की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए।

गरल जन्दों में कह तो भूमडलीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था को वेशितक प्रशेष्यवस्था में जोड़ने की प्रक्रिया है। भूमंडलीकरण के अंदर ये चार बाते मर्माहत हं - ; राष्ट्राय मीमाओं के आर-पार वस्तुओं के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के निय न्यापार-याधाओं में कमी 2. ऐसे माहौल का निर्माण करना जिसमें पूँजी प्रनाह अप्याना में हा सके; 3 प्रौद्योगिकी के बेरोक-टोक प्रवाह के लिए वातावरण वनाना तथा 4. विकसित देशों के नजरिए से ऐसे वातावरण का निर्माण करना किसमें विभन्त देशों के बीच श्रीमकों की मुक्त रूप से आवाजाही सुनिश्चित हो। भुमद्रानीकरण की वकालत करनेवाले, विशेषकर विकसित देशों के समर्थकों न धुमंदलांकरण की परिभाषा को तीन तत्त्वों तक मीमित कर दिया है। वे हैं-बर्गक रोक व्यापार प्रवाह, पँजी-प्रवाह तथा प्रोद्योगिकी-प्रवाह। वे विकासशील दशों पर उनकी परिभाषा खीकार करने पर जोर देते हैं और चाहते हैं कि इस विषय पर चरम उनके द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही हो; परंतु विकासशील देशों के कई अथशास्त्री इस परिभाषा को अध्रा समझते है। उनका मानना है कि वैश्विक ग्राम की कल्पना नर्भा माकार हो मकती है, जब चौथे तत्त्व, अर्थात् 'श्रमिकों को मुक्त रूप में आवाजार्हा को भी इस परिभाषा में शामिल किया जाए, परंतु विश्व व्यापार सगठन या अन्य मचो पर होनेवाली तमाम बहसों में प्राय: 'श्रमिक-प्रवाह' को भमंदलीकरण के आवश्यक तत्त्व के तौर पर शामिल ही नहीं किया जाना।

व्यापार तथा शुल्क संबंधी सामान्य समझौते (गैट) का उरुग्वे दौर और बाद की प्रगति

अंतिम अधिनियम मे निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार सगठन की स्थापना हुई और 30 दिसंबर, 1994 को विश्व व्यापार संगठन समझौते की पुष्टि कर भारत इसका संस्थापक सदस्य बना। विश्व बैंक, ओ.ई.सी.डी. तथा गैट सचिवालय के अनुमानों के अनुसार, उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद सन् 2005 तक कुल व्यापार में 745 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होगी। गैट सिख्वालय के मुनाबिक, सबस् ऑधक तेजी कराई :60 प्रीतशतः कृति धार्मिकी तथा मतस्य उत्पादां (20 प्रीतशतः) और प्रसन्कर्तिन भी स्य एडाने एत देव (19 प्रतिशतः) के क्षेत्रों में दर्ज होगी। आधिक सर्वेक्षण (1994 95) के मुनाबिक, 'चूँकि भारत की गीजृदा आर नियान प्रतिस्पशत्मक जनता दन उत्पन्ते में हा है, इमिलए यह कहना नार्किक होगा कि उसे एन क्षेत्रों में ज्यानक जन्म होगा। यह यह माना जाए कि नियन्न नियांत में भारत के नामाने का हिस्सा 05 प्रात्यार में 1 प्रतिशत तक है और हम नए अध्यस्ते का लाभ उद्योग की स्थित में होंगे तो प्रतिशत हमें नियांत व्यापार में 27 अरब अमेरिकी डाल्य का भी रियन तक नाम होन को चान कही गई है।

भारत नियम आधारित ऐसी व्यापार प्रणली को मर्बाधिक महत्य देता आया है, जहाँ समान मिद्धानों का पासन हैं। तथा ज्यापार की मृद्दों से न ओड़ा जाए।